{ संपादकीय }

नई दिल्ली, गुरुवार 26 सितम्बर 2024
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

सवालों के घेरे में दो एनकाउंटर

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुए दो एनकाउंटर सवालों के घेरे में इसलिये आ गये हैं क्योंकि दोनों को लेकर गहरा शक किया जा रहा है कि ये फर्जी हैं। कुछ आगे-पीछे हुए ये दोनों एनकाउंटर जिस तरीके से हुए हैं वे दोनों ही गहन जांच की ज़रूरत बतलाते हैं- चाहे वे दो अलग-अलग राज्यों में ही क्यों न हुए हों। संयोग यह भी है कि दोनों ऐसे राज्य हैं जहां एनकाउंटर संस्कृति पनपती रही हैं और दोनों राज्यों में इसका लम्बा इतिहास रहा है। उप्र के सुलतानपुर में हुई डकैती कांड मामले में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में अक्षय शिंदे नामक उस शख्स का एनकाउंटर हुआ है जिस पर बदलापुर के एक स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप था। उसे तलोजा जेल से ले जाया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि उसने पुलिस की गाड़ी में एक पुलिस इंस्पेक्टर से रिवाल्वर छीन ली और उन पर फायरिंग कर दी। इसमें तीन पुलिस वाले घायल हो गये। उसे नियंत्रित करने के लिये पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी जिससे वह मारा गया।

दोनों ही एनकाउंटर कई कारणों से संदिग्ध माने जा रहे हैं। संयोगवश, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिनका एनकाउंटरों के प्रति अनुराग सर्वज्ञात है। सांसद एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए जांच की मांग की है। उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त को सुलतानपुर के ठठेरी बाजार में भरत सोनी की ज्वेलरी शॉप में 5 लोगों ने डकैती की थी जिनमें अनुज भी शामिल था। यह ईनामी बदमाश था जिस पर एक लाख रुपये का पारितोषिक घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार अनुज एवं उसका एक साथी उन्नाव जिले के अचलगंज इलाके से जा रहे थे। लखनऊ एसटीएफ को इसकी सूचना मिली थी। इस मुठभेड़ में अनुज मारा गया जबकि उसका साथी फरार हो गया। घायल अनुज को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। वैसे बता दें कि इसके पहले इसी डकैती में शामिल दो और लोगों के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई थी। उसमें मंगेश यादव नामक आरोपी की मौत हो गयी थी। एक और आरोपी अजय यादव के पैर में गोली लगी थी जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मंगेश के एनकाउंटर पर भी अखिलेश ने सवाल उठाये थे।

दूसरी ओर महाराष्ट्र में हुए एनकाउंटर की निंदा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले समेत कई नेताओं ने करते हुए इस पर गहन संदेह व्यक्त किया है। सुप्रिया के अनुसार प्रदेश में कानून-व्यवस्था का पूरी तरह से ठप हो जाना ही यह एनकाउंटर दर्शाता है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने इसे 'प्रदेश के लिये काला दिन' निरूपित किया है। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें यकीन नहीं रह गया है कि इस कांड के सही आरोपियों तक कभी भी पुलिस पहुंच पायेगी। शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे ने भी इसी तरह के आरोप लगाये हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूछा है कि जब शिंदे के हाथों में हथकड़ी लगी थी तो उसने पिस्तौल कैसे छीनी और फायरिंग किस प्रकार की? विपक्षी नेताओं का साफ कहना है कि शिंदे का एनकाउंटर यौन शोषण के सबूतों को नष्ट करने के लिये किया गया है। बताया जाता है कि जिस स्कूल में शिंदे ने दुष्कर्म को अंजाम दिया वह एक भाजपा नेता का है। माना जा रहा है कि उस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें बचाने के लिये यह किया गया है। स्वयं शिंदे के परिवार वालों ने कहा है कि अक्षय को इसलिये मारा गया है ताकि असली अपराधियों को बचाया जाये। उन्होंने जांच होते तक शव को लेने से इंकार कर दिया है। परिवार का यह भी कहना है कि पिछले सप्ताह उसे बेरहमी से मारा भी गया था।

दोनों ही एनकाउंटरों के बारे में जिस तरह की शंकाएं जाहिर हो रही हैं, उसमें ज़रूरी है कि इन सभी एनकाउंटरों की गहन जांच हो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर की परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए कहा है कि पहली नजर में गड़बड़ी लग रही है। दरअसल दोनों एनकाउंटर बहुत ही गम्भीर मामले हैं। अपराधियों को कोर्ट की बजाय सीधे पुलिस वालों के हाथों ही सजा दिलाने का चलन खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। स्वयं सरकारों की ओर से इस बात को प्रोत्साहित किया जाने लगा है। यह किसी भी सभ्य समाज के लिये अपराधों पर नियंत्रण पाने का नितांत अशोभनीय तरीका है जो संविधान सम्मत तो है ही नहीं।

दोनों राज्यों की सरकारों को चाहिये कि इन एनकाउंटरों की उच्चस्तरीय जांच करें। कानून के राज का भी यही तकाज़ा होता है कि एक न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत मामलों का निपटारा हो, न कि सड़कों-चौराहों पर आरोपियों को सरेआम उड़ाकर उसे पुलिस एनकाउंटर का नाम दिया जाये। यह आम बात हो गयी है और सभी जानते हैं कि इस प्रकार के एनकाउंटर मामलों पर पर्दा डालने के उपाय होते हैं। किसी भी अपराध में संलिप्त लोगों को बचाने के लिये किसी निरीह की बलि ली जाती है। इससे सच्चाई बाहर आने का रास्ता हमेशा के लिये बन्द हो जाता है। इसके साथ ही अपराधियों द्वारा किये गये अन्य अपराधों का भी पर्दाफाश नहीं होता। एनकाउंटर संस्कृति कानून के खिलाफ है।

धर्मनिरपेक्षता पर हमले का नया तरीका

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने चार दिन पहले 22 सितंबर को कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 'धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा' है और भारत को इसकी जरूरत नहीं है। श्री रवि ने कहा कि भारत के लोगों के साथ कई सारे फ्रॉड (धोखे) हुए हैं और उनमें से एक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है। उन्होंने कहा, 'ये अवधारणा यूरोप में चर्च और राजा के बीच झगड़े के कारण पैदा हुई थी। जबकि भारत एक धर्म केंद्रित राष्ट्र है और इसलिए ये संविधान का हिस्सा नहीं था। लेकिन एक 'असुरक्षित प्रधानमंत्री' ने आपातकाल के दौरान इसे संविधान में जुड़वाया।'

जाहिर है राज्यपाल का इशारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर था। 1976 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही संविधान में संशोधन कर धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तब देश में आपातकाल लागू था। राज्यपाल रवि ने कहा कि स्वतंत्रता के दौरान जब संविधान ड्राफ्ट किया जा रहा था, तब धर्मनिरपेक्षता की चर्चा आई थी। उनका दावा है कि संविधान सभा ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि भारत एक धर्म केंद्रित राष्ट्र है और यहां यूरोप की तरह कोई झगड़ा नहीं है।

राज्यपाल रवि ने अपने भाषण में धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो कुछ कहा, उससे एक बार फिर जाहिर हो गया है कि देश में संविधान पर अब भी खतरे मंडरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी संविधान को सिर-माथे से लगाकर देश को यह दिखलाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने संविधान को भाजपा से खतरे का जो मुद्दा खड़ा किया है, वह गलत है और भाजपा प्राणपण से संविधान की रक्षा करेगी। इसलिए एनडीए सरकार ने संविधान हत्या विरोधी दिवस मनाने का फैसला भी ले लिया है। लेकिन राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान में पूरे नियमों के साथ किए गए एक संशोधन पर उंगली उठाकर साबित कर दिया है कि संविधान को बदलने की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इस भाषण के सामने आने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से इस पर आलोचना की कोई टिप्पणी नहीं आई। सरकार के किसी नुमाइंदे ने यह नहीं कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो कुछ लिखा है, हम उसे उसी तरह अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, न उसके खिलाफ की जा रही टिप्पणियों को बर्दाश्त किया जाएगा।

वैसे आर एन रवि को यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि उन्हें असली तकलीफ किस बात से है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता से, धर्मनिरपेक्षता की यूरोपीय अवधारणा से, इंदिरा गांधी से या इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए ऐसे संशोधन से, जिससे देश के करोड़ों लोगों को इस बात की राहत मिली कि वे किसी भी तरह से दोयम नहीं हैं। क्योंकि भारतीय संविधान जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, उसमें भारतीय संस्कृति की जरूरतों और विशेषताओं का ध्यान रखा गया है, यानी अनेकता में एकता और इसी वजह से हरेक नागरिक को समान होने का अधिकार है। इसके अलावा संविधान में धर्मनिरपेक्षता के जरिए विज्ञान और तर्कवाद को प्रोत्साहन और सरकार को धार्मिक दायित्वों से स्वतंत्र कर सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णु रवैया अपनाने पर जोर दिया गया है।

> **भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक और क्रांतिकारी अवधारणा है जो पश्चिमी अवधारणा से काफी अलग है। श्री रवि जिस यूरोपीय धर्मनिरपेक्ष विचार की बात कर रहे थे, उसमें धर्म का राज्य से कोई संबंध नहीं है। जबकि भारत में धर्मनिरपेक्षता में अंतर-धार्मिक समानता या सर्वधर्म समभाव पर जोर दिया गया है। धर्मों के भीतर होने वाले भेदभाव और दो धर्मों के भीतर होने वाले मतभेदों को भी ध्यान में रखा गया है।**

गौरतलब है कि दुनिया में जितने प्रमुख धर्म हैं, वे सब भारत में भी हैं, और हर धर्म का व्यक्ति अपनी पहचान के प्रति संवेदनशील होता है। उसकी धार्मिक पहचान सुरक्षित रहे, यह जिम्मेदारी केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही पूरी कर सकता है। इसके साथ ही जो नागरिक नास्तिक होते हैं, उन्हें भी अपनी सोच के साथ सुरक्षित जीवन मिले, यह जिम्मा भी सरकार का ही है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा इन्हीं जिम्मेदारियों की अपेक्षा सरकार से करती है।

भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक और क्रांतिकारी अवधारणा है जो पश्चिमी अवधारणा से काफी अलग है। श्री रवि जिस यूरोपीय धर्मनिरपेक्ष विचार की बात कर रहे थे, उसमें धर्म का राज्य से कोई संबंध नहीं है। जबकि भारत में धर्मनिरपेक्षता में अंतर-धार्मिक समानता या सर्वधर्म समभाव पर जोर दिया गया है। धर्मों के भीतर होने वाले भेदभाव और दो धर्मों के भीतर होने वाले मतभेदों को भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए दलित या महिला उत्पीड़न या जातिगत भेदभाव पर सरकार अंकुश लगाती है। पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्ष सरकारें और अदालतें तब भी हस्तक्षेप नहीं करतीं, जब कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिला के लिये कोई निर्देश देती है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर राज्य और न्यायालय दखल दे सकते हैं।

इसलिए धर्मनिरपेक्ष को यूरोपीय अवधारणा बताकर उसे भारतीयों के साथ धोखा कहना, असल में संविधानविरोधी बात है, जिस पर मोदी सरकार संज्ञान ले या न ले, अदालत को संज्ञान लेना ही चाहिए। दरअसल भाजपा कई तरीकों से ऐतिहासिक संदर्भों या फैसलों को तोड़-मरोड़ कर जनता के सामने पेश करती है, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है। नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में मुसलमानों को ज्यादा हक देने या मंगलसूत्र चोरी हो जाने जैसे डर जनता में इसी तरीके से फैलाने की कोशिश थी। हालांकि यह कोशिश कामयाब नहीं हुई। क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने जनता को यह समझा दिया कि ये सारी बातें संविधान बदलने की रणनीति से ध्यान भटकाने की कोशिश हैं। अब आर एन रवि के इस बयान के बाद संविधान में धर्मनिरपेक्षता के विचार का पुन:पाठ कर लेने का अवसर बन गया है।

संविधान निर्माण के समय से ही धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा इसमें मौजूद थी, संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-25 से 28) इसका प्रमाण है। 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़कर इस अधिकार को और विस्तार दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। धर्मनिरपेक्षता से यह सुनिश्चित होता है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है।

अब विचारणीय बात यह है कि आखिर श्री रवि को धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से तकलीफ क्यों हुई। संविधान हर व्यक्ति को उसका धर्म मानने और अपनी मर्जी से उपासना का अधिकार दे रहा है, किसी से कुछ छीन नहीं रहा है, फिर किस बात का डर। और जहां तक यूरोपीय अवधारणा की बात है, तो भारत में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो ब्रिटिश सरकार की देन है। आर एन रवि खुद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं और भारत का संघ लोकसेवा आयोग ब्रिटिश राज की सिविल सेवा से ही प्रेरित है। गर्वनर जैसे पद भी अंग्रेजी राज की उपज हैं। हमारे संविधान को दुनिया के कई संविधानों के अध्ययन के बाद बनाया गया है। तो हम यूरोपीय या पश्चिमी या आयातित के नाम पर आखिर क्या-क्या चीजें छोड़ेंगे और सबसे बड़ा सवाल क्यों छोड़ेंगे। क्या सिर्फ इसलिए कि स्वदेशी, भारतीयता, राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की जुगाली करके भाजपा देश को फिर से मध्ययुग में लौटाना चाहती है। और तब भी सब कुछ विशुद्ध भारतीय कहां था। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा खुले दिमाग और खुली बांहों से लोगों का, विचारों का, परंपराओं और संस्कृतियों का स्वागत किया गया है। इसलिए भारत सारे जहां से अच्छा बना रहा। भारत की यह पहचान अब भी केवल संविधान के कारण बची हुई है, लेकिन भाजपा किसी न किसी तरह संविधान पर आपत्ति दर्ज करा ही रही है।

पेजर और वॉकी-टॉकी विस्फोट मध्य पूर्व में नये तकनीकी युद्ध का संकेत

■ एम ए हुसैन

हाल ही में लेबनान में हज़ारों पेजर तथा वॉक-टॉकी सेटों का विस्फोट एक ख़तरनाक घटना है जो इज़राइली हाथ के लक्षण दर्शाता है, जो संभवत: इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच आसन्न सैन्य युद्ध में वृद्धि के संकेत देता है। यह तनाव हिज़्बुल्लाह की हाल ही में इज़राइली सेना के साथ झड़पों के बाद से बढ़ रहा है, जो 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले घातक हमले के बाद गाजा के खिलाफ़ इज़राइल की तीव्र सैन्य कार्रवाइयों का सीधा जवाब है। लेबनान के पेजर को लक्षित करने के पीछे रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट है: हिज़बुल्लाह के आंतरिक संचार को पंगु बनाना, जो इसके सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण घटक है।

हाल के वर्षों में हिजबुल्लाह ने संचार के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसे संदेह है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने उनके साथ समझौता किया है, जिसके कारण हिज्बुल्लाह के प्रमुख लोगों की पहचान की गयी और उन्हें लक्षित तरीके से मार दिया गया। पेजर नेटवर्क पर हमला करके, इजरायल संभवत: इस नयी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सैन्य कार्रवाई में वृद्धि की स्थिति में समन्वय करने की हिज्बुल्लाह की क्षमता को कम किया जा सके। ऐसा करके, इजरायल अपनी व्यापक क्षेत्रीय रणनीति में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें गाजा में हमास को दबाने के साथ-साथ हिज्बुल्लाह के प्रभाव को बेअसर करना भी शामिल है।

> **स्थिति इस तथ्य से और जटिल हो जाती है कि इजरायल के सैन्य अभियान शून्य में नहीं हो रहे हैं। गाजा में चल रहे संघर्ष, पश्चिमी तट में अशांति के साथ, ने पहले से ही इजरायल के सैन्य संसाधनों को कम कर दिया है। लेबनान में हिज्बुल्लाह से भिड़ने से पहले से ही जटिल और अस्थिर स्थिति में तीसरा महत्वपूर्ण मोर्चा जुड़ जायेगा।**

हालाँकि पेजर विस्फोटों से तत्काल मरने वालों की संख्या नौ थी और यह बढ़ सकती है क्योंकि 2,800 घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन इन विस्फोटों के व्यापक निहितार्थ और भी अधिक चिंताजनक हैं। लेबनान की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, जो पहले से ही तनावग्रस्त है, के चरमराने का खतरा है। अगर इजरायल व्यापक सैन्य हमले के साथ आगे बढ़ता है, तो सैन्य और नागरिक हताहतों की बाढ़ लेबनान के चिकित्सा ढांचे को उसके टूटने के बिंदु पर पहुंचा देगा। चिकित्सा सेवाओं पर यह संभावित दबाव न केवल घायल लड़ाकों के इलाज की देश की क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगा, बल्कि नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ने के कारण मानवीय संकट भी पैदा करेगा।

व्यापक भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से, इज़राइल की कार्रवाइयों को एक उच्च-दांव जुआ के रूप में देखा जा सकता है। उत्तर में हिज्बुल्लाह से भिड़ने से गाजा और वेस्ट बैंक में उनके अभियानों के अलावा, इज़राइली बलों के लिए एक तीसरा मोर्चा खुल जायेगा। सतह पर, यह एक जोखिम भरा कदम प्रतीत होगा, जो इज़राइली संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेगा और इसकी सैन्य रणनीति को जटिल बनायेगा। हालांकि, संकटग्रस्त नेतन्याहू सरकार के लिए, यह वृद्धि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है। नेतन्याहू का प्रशासन महत्वपूर्ण आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव में रहा है, जिसमें चल रहे संघर्ष एक एकीकृत राष्ट्रीय कारण प्रदान करते हैं। एक बहु-मोर्चा युद्ध नेतन्याहू को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने, आलोचना को दूर करने और घरेलू समर्थन जुटाने में सक्षम बना सकता है।

इस संभावित इज़राइली-हिज्बुल्लाह संघर्ष के सबसे खतरनाक तत्वों में से एक आधुनिक युद्ध में प्रौद्योगिकी की भूमिका है। इस पेजर हमले जैसे उन्नत तकनीकी युद्ध का उपयोग, एक व्यापक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है, जहाँ शारीरिक लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मनों को कमज़ोर करने के लिए गैर-पारंपरिक सैन्य रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाता है। हिज़्बुल्लाह के संचार ढांचे को निशाना बनाकर, इज़राइल संभावित ज़मीनी या हवाई हमले का प्रभावी ढंग से जवाब देने की उसकी क्षमता को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है।

इस टकराव के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिणाम भी हैं। ईरान के साथ हिज़्बुल्लाह के घनिष्ठ संबंधों ने इसे लंबे समय से मध्य पूर्व के नाज़ुक शक्ति संतुलन में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। जबकि ईरान ने हमास और इज़राइल के बीच मौजूदा संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने से परहेज़ किया है, हिज़्बुल्लाह के प्राथमिक समर्थक के रूप में इसकी भूमिका इसे लेबनान के खिलाफ़ किसी भी इज़राइली कार्रवाई के बीच में रखती है। कई पर्यवेक्षक हिज़्बुल्लाह को ईरानी हितों के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में देखते हैं, एक रणनीतिक हाथ जो तेहरान को प्रत्यक्ष सैन्य जुड़ाव के बिना शक्ति और प्रभाव को प्रोजेक्ट करने की अनुमति देता है। यह संबंध दांव को काफी हद तक बढ़ा देता है। यदि संघर्ष आगे बढ़ता है, तो ईरान को लड़ाई में खींचा जा सकता है, जिससे एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है।

हाल के हफ्तों में इजरायल की कार्रवाइयों से पता चलता है कि वह ठीक इसी नतीजे को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेबनान में पेजर विस्फोटों के अलावा, इजरायल ने सीरिया में ईरानी संपत्तियों पर हवाई हमले किये हैं, सबसे खास तौर पर दमिश्क में, और ईरान की सीमाओं के भीतर हमास के प्रमुख लोगों की हत्या की है। ये कार्रवाइयां पूरे क्षेत्र में ईरानी हितों को लक्षित करने की इजरायल की व्यापक रणनीति को दर्शाती हैं, जिससे यह चिंता बढ़ रही है कि इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष जल्दी ही ईरान को शामिल करते हुए एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से पश्चिम ने अब तक इजरायल की आक्रामक रणनीति को रोकने के लिए बहुत कम झुकाव दिखाया है। इजरायल के सबसे कट्टर सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा में मानवीय नुकसान की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय निंदा के बावजूद इजरायली सैन्य अभियानों के लिए अपने निरंतर समर्थन का संकेत दिया है। वास्तव में, पश्चिमी शक्तियों की ओर से सार्थक विरोध की कमी इजरायल को अपने रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए खुली छूट देती है, भले ही उन कार्रवाइयों से क्षेत्र में और अराजकता फैलने का जोखिम हो।

अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह नवीनतम प्रकरण – पेजर विस्फोट और आगे की सैन्य कार्रवाई की संभावना – लेबनान और उससे आगे व्यापक संघर्ष को जन्म देगा? हिज्बुल्लाह की प्रतिक्रिया अब तक सीमा पर छिटपुट गोलीबारी तक सीमित रही है, पर पूर्ण युद्ध की संभावना अभी भी है। यदि हिज्बुल्लाह इजरायल की कार्रवाइयों को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, तो वह ईरान सहित अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को शामिल करते हुए, और संघर्ष को पूरे मध्य पूर्व के लिए विनाशकारी परिणामों के साथ एक बहु-मोर्चे के युद्ध में बदलने के लिए मजबूर महसूस कर सकता है।

स्थिति इस तथ्य से और जटिल हो जाती है कि इजरायल के सैन्य अभियान शून्य में नहीं हो रहे हैं। गाजा में चल रहे संघर्ष, पश्चिमी तट में अशांति के साथ, ने पहले से ही इजरायल के सैन्य संसाधनों को कम कर दिया है। लेबनान में हिज्बुल्लाह से भिड़ने से पहले से ही जटिल और अस्थिर स्थिति में तीसरा महत्वपूर्ण मोर्चा जुड़ जायेगा। फिर भी, नेतन्याहू के लिए, यह एक सोचा-समझा जोखिम हो सकता है जिसे उठाया जाना चाहिए। इजरायल सरकार ने लंबे समय से हिज्बुल्लाह को एक बड़ा खतरा माना है, और देश पहले से ही युद्ध की स्थिति में है, अब अपने उत्तरी विरोधी को निर्णायक झटका देने के लिए उपयुक्त समय के रूप में देखा जा सकता है। लेबनान में हजारों पेजर का विस्फोट एक महत्वपूर्ण और खतरनाक घटनाक्रम है जो मध्य पूर्व में वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य की नाजुकता को रेखांकित करता है। इजरायल की कार्रवाइयां, जो संभवत: हिज्बुल्लाह की संचार क्षमताओं को कम करने के उद्देश्य से हैं, एक व्यापक संघर्ष को भड़काने की क्षमता रखती हैं जो ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को आकर्षित कर सकती हैं और क्षेत्र को और अस्थिर कर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बड़े पैमाने पर किनारे पर खड़े होकर देखते रहने के कारण, युद्ध के बढ़ने की संभावना अधिक बनी हुई है, और इस तरह के संघर्ष की मानवीय लागत लेबनान और इजरायल दोनों के लिए विनाशकारी हो सकती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ललित सुरजन की कलम से

प्रधानमंत्री और पत्रकार

'पंडित नेहरू आम जनता के लिए सदैव उपलब्ध ही नहीं थे, बल्कि जनसमुदाय के बीच पहुंचकर मानो वे संजीवनी पाते थे। पंडित जी की पत्रकार वार्ता हर माह हुआ करती थी, जिसके माध्यम से देश की जनता के साथ उनका निरंतर संवाद बने रहता था। आज उस दौर के मुकाबले अखबारों की संख्या कई गुणा बढ़ गई है। दसियों न्यूज चैनल भी आ गए हैं। इस माहौल में हर माह पत्रकार वार्ता करना अव्यवहारिक हो सकता है, लेकिन पत्रकारों से मिला ही न जाए, यह कौन सी बात हुई। इंदिरा गांधी अपने पिता की तरह उदार नहीं थीं, लेकिन आम जनता से उन्होंने भी कभी दूरी बनाकर नहीं रखीं। इंदिरा जी की पत्रवार्ताएं यद्यपि नियमित नहीं होती थीं, लेकिन पत्रकारों से उनका मिलना अत्यंत सुलभ था। वे चाहे देश के दौरे पर हों, चाहे दिल्ली में, एक साधारण सी सूचना पर पत्रकारों को उनसे भेंट का समय मिल जाता था। आपातकाल के दौरान अवश्य दूरी आ गई थी, लेकिन 1980 में सत्ता में लौटते साथ उन्होंने टूटे तार फिर जोड़ने की पहल की थी।'

'अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक सच्चे जननेता के रूप में आम जनता और प्रेस दोनों के साथ संवाद बनाए रखा। इन्द्रकुमार गुजराल के मीडिया के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे। यह रोचक तथ्य है कि दिल्ली के अधिकतर वरिष्ठ पत्रकारों का वाजपेयीजी और गुजराल साहब दोनों के साथ अनौपचारिक स्तर पर भी सम्पर्क बना रहा। वीपी सिंह और चंद्रशेखर ने भी प्रेस के साथ नियमित संपर्कों का ध्यान रखा। यह जानकर पाठकों को आश्चर्य हो सकता है कि एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने भी अंग्रेजी और कन्नड़ ही नहीं, तमाम भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के साथ संवाद स्थापित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में भी हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के संपादकों को आमंत्रित कर उनसे खुली चर्चा की पहल की।'

(7 जुलाई 2011को देशबन्धु में प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2012/05/blog-post_22.html

पावन प्रसंग

एकाकी परिवार में आत्मीयता का अभाव

दंपत्ति अक्सर संकीर्ण भावना का शिकार होकर एकाकी परिवार बसाते हैं। यदि छोटा भाई ज्यादा कमाता है और बड़ा भाई कम तो छोटे भाई के मन में आता है कि मैं तो ज्यादा कमाता हूं और बड़े भैया तो कम कमाते हैं फिर भी सुख-सुविधाओं का पूरा लाभ उठाते हैं। हमारी कमाई पर हमारा अधिकार अधिक है उसमें दूसरा कोई किसी प्रकार का लाभ क्यों उठाए? यह विचार दिनोंदिन गहरे होते जाते हैं अंतत: परिवार बिखर जाता है। अलग होने पर अलग मकान का किराया और अन्य खरचे बढ़ जाते हैं जो सुविधाएं साथ रहने पर मिलजुल रहने से मिलती थी वह भी नहीं मिल पाती।

हम सभी जानते हैं कि एकाकी परिवार में जीवन और भविष्य निश्चित नहीं है तथा सुख-सुविधाएं भी उतनी प्राप्त नहीं हो सकेंगी। फिर भी युवक-युवतियां जल्द से जल्द अपने सास-ससुर, जेठ-जेठानी से अलग रहने की इच्छा रखते हैं। स्पष्ट है जीवन की सुख सुविधा अकेले ही भोगने को एवं वृद्धों के प्रति अश्रद्धा एवं उपेक्षा का भाव होने के कारण ही इस इच्छा का जन्म होता है परन्तु परिवार से अलग होते ही जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं उससे जीवन दूभर होने लगता है और पारिवारिक जीवन में कटुता के अंकुर फूटने लगते हैं। एकाकी परिवार में महिलाओं की व्यस्तता बढ़ जाती है। सम्मिलित सब स्वजनों के साथ रहने पर घर की आंतरिक व्यवस्था परिवार के सभी सदस्य मिल-जुलकर कर लेते हैं। जबकि केवल पति-पत्नी के साथ रहने पर सारी व्यवस्था का दायित्व अकेली पत्नी पर ही आ जाता है। व्यस्त जीवन में बच्चों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सकता। वह प्रेम और ममत्व जो पिता व माता से मिलना चाहिए था, उसमें कमी आ जाती है। फलस्वरूप बालक का मानसिक विकास वैसा नहीं हो पाता- जो सम्मिलित परिवार में संभव था। वहां पिता का प्यार तो मिलता ही दादा-दादी, चाचा-चाची, ताऊ-ताई का स्नेह और मार्गदर्शन भी उसके चंहुमुखी विकास में सहायक सिद्ध होता है। यही कारण है कि आज एकाकी परिवार के बच्चे प्राय: कुंठाग्रस्त देखे गए हैं।

महिलाओं और पुरुषों में वृद्धों के प्रति अवमानना और अविश्वास का भाव तो इस कदर बढ़ रहा है कि वे अपने बच्चों के लिए बाहरी व्यक्तियों पर विश्वास तो कर लेंगे पर घर के वृद्ध माता-पिता पर नहीं। नौकर तो बच्चों की देखभाल कर लेंगे लेकिन जो आत्मीयता बच्चों को मिलनी चाहिए उससे उन्हें वंचित होना पड़ रहा है। आज के समय में दूसरों के बच्चों को शायद ही उतने भाव भरे प्यार से दुलारता हो। अपने सहोदर भाइयों के बच्चे तो फूटी आंख नहीं सुहाते तो दूसरा व्यक्ति कितना प्यार दे सकेगा? देखरेख व अन्य बातों का ध्यान जितने कुशलता से आत्मीयता से घर की वृद्ध अनुभवी महिलाएं कर सकती हैं उतनी आत्मीयता अन्यत्र कहीं मिल सकना असंभव है। यह विज्ञान सिद्ध तथ्य है कि ममत्व व प्रेम की छाया में पला-बढ़ा बालक का चरित्र, क्रियाशीलता, परिश्रम की भावना से ओत-प्रोत होता है।

-अखंड ज्योति

आपके पत्र

जीवित बुजुर्ग माता-पिता की संपूर्ण सेवा ही सच्ची सेवा

मातृ-पितृ ऋण से कभी उबरा नहीं जा सकता है। पितृ पक्ष में माता-पिता के ऋण से ऊबरने के लिए ऐसे व्यक्ति भी जोर-जोर से श्राद्ध कर्म करके लोगों को भोजन से तृप्त करने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपने माता-पिता के जीवित रहते हुए कभी उनके प्रति श्रद्धा के भाव नहीं दिखाए एवं उनकी यथोचित श्रद्धापूर्वक सेवा तथा देखभाल नहीं की थी।जिस संतान ने अपने माता-पिता के जीवित रहते हुए उनकी सच्ची सेवा एवं सर्वांगीण सम्मान किया हो। केवल वे ही मातृ-पितृ ऋण से उबरने के लाभ के हकदार होते हैं। जीवित अवस्था में अभाव में भोजन-पानी को तरसते हुए माता-पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी आत्म संतुष्टि और सामाजिक रूप से दिखावे के लिए संतानों द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म मिथ्या अथवा आडंबर ही हो सकता है सच्ची सेवा नहीं।

वृद्धावस्था को जीवन का अंतिम पड़ाव एवं समस्याओं से घिरी हुई अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्धों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय की रफ्तार के साथ समाज में अनेक परिवर्तन होने लगे हैं। नवीन पीढ़ी के लोग पुराने विचारों के लोगों का उनके जीवन में हस्तक्षेप उचित ना समझ कर बर्दाश्त नहीं करते हैं,इसी कारण युवा पीढ़ी बुजुर्गों और वृद्धों के विचारों की गहन उपेक्षा करने लगते हैं और बुजुर्गों को लगता है कि उनकी समाज में उपयोगिता धीरे-धीरे कम हो रही है। जीवन का सांध्य काल आने पर मनुष्य कई समस्याओं से घिर जाता है। सबसे बड़ी समस्या शारीरिक क्षमता में कमी आ जाने की है, शरीर की सभी इंद्रियां धीमी पड़ जाती हैं,अनेक प्रकार की व्याधियों से शरीर घिर जाता है और मनुष्य धीरे-धीरे शरीर पर नियंत्रण खोता जाता है। उम्र के वृद्धावस्था के पड़ाव पर अनेक शारीरिक बीमारियों के साथ-साथ मूल समस्या मानसिक व्याधि की होती है। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों में वेतन भोगी कर्मचारी को एक निर्धारित आयु के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति अब शारीरिक एवं मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा चाहे वह व्यक्ति स्वस्थ ही क्यों ना हो। इसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाई आने लगती हैं। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता समाज में कम होने लगती है, वह समाज के लिए अनुपयोगी मान लिया जाता है और इस अवस्था में पहुंचने के बाद मानसिक तनाव की स्थिति बनने लगती है। लोगों के संपर्क में न रहना, सहयोगी तथा मित्रों की मृत्यु भी मानसिक तनाव का बड़ा कारण होती है। आत्मविश्वास की धीरे-धीरे कमी होने लगती है, जिससे मानसिक विकृति अकेलापन आदि जैसे रोगों का निर्माण होने लगता है।

वृद्धावस्था में मनुष्य के मानसिक तथा शारीरिक कष्ट के प्रमुख कारणों में से संयुक्त परिवार का विघटन भी है। युवा पीढ़ी द्वारा अपने मां-बाप से अलग होकर रहने की चाहत हमारे देश में एक गंभीर समस्या पैदा करती है। वृद्ध व्यक्ति या दंपत्ति को जिस आयु में पुत्र, पुत्रियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे समय में पुत्र द्वारा उनकी देखभाल छोड़कर अलग रहने के लिए अलग मकान बनाना या किराए पर रहना, उस दंपत्ति या व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करती है। भारत देश वही देश है यहां की संस्कृति में परिवार के बुजुर्ग को भगवान के समान माना जाता था, किंतु संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन के कारण आज की नई युवा पीढ़ी ना तो बड़ों के अनुशासन में रहना चाहती है नहीं उन्हें किसी प्रकार का आदर सम्मान देना चाहती है।

-संजीव ठाकुर

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

पांच नवंबर को जाहिर होगा

शुरुआत से ही बहस उन मुद्दों पर मुड़ गई, जिन पर अमेरिकी मतदाताओं के बीच गहरा विभाजन है। हैरिस ने खुद को प्रगतिशील उम्मीदवार के रूप में पेश किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों को यह बताया कि वे नहीं जीते, तो अमेरिका का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों प्रमुख उम्मीदवारों की बहस में कौन जीता, इस बारे में राय बंटी हुई है। लिबरल मीडिया पर नजर डालें, तो वहां इस पर लेकर शक नहीं है कि कमला हैरिस भारी पड़ीं। लेकिन कंजरवेटिव खेमे में उलटी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दोनों उम्मीदवारों ने बहस के लिए वे मुद्दे उठाए, जिन पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण से उन्होंने उम्मीद जोड़ी हुई है। मसलन, हैरिस ने गर्भपात के अधिकार पर जोर दिया, तो ट्रंप ने गैर-कानूनी आव्रजकों से अमेरिका के लोगों को पैदा हुए कथित खतरों का जिक्र किया। फैक्ट चेकर्स ने ट्रंप के कई दावों को गलत साबित किया, लेकिन कंजरवेटिव खेमे में इससे उलटी प्रतिक्रिया हुई। वहां यह शिकायत देखी गई कि फैक्ट चेकर्स ने हैरिस के प्रति पक्षपात किया। उनके कथित गलत दावों की पोल उन्होंने लगे हाथ नहीं खोली। एक ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। उसमें हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया बंटी हुई होती है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप अपने दावों और आक्रामक अंदाज से अपने समर्थकों के ध्रुवीकरण को किस हद तक मजबूत करने में सफल हुए। कमला हैरिस और डॉनल्ड ट्रंप इस बहस से पहले यह कभी नहीं मिले थे। तो बहस शुरू होने से पहले हैरिस ट्रंप के पास गईं और मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। विश्लेषकों के मुताबिक इस कदम के साथ ही हैरिस ने बहस में बढ़त हासिल कर ली, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप उनके रंग, नस्ल और लिंग को लेकर तीखी और कड़वी टिप्पणियां करते रहे हैं। शुरुआत से ही बहस उन मुद्दों पर मुड़ गई, जिन पर अमेरिकी मतदाताओं के बीच गहरा विभाजन है।हैरिस ने बहस के दौरान खुद को भविष्य की ओर देखने वाली एक प्रगतिशील उम्मीदवार के रूप में पेश किया। ट्रंप ने अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को उठाया और अपने समर्थकों को यह बताया कि वे नहीं जीते, तो महाशक्ति के रूप अमेरिका का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कुल मिलाकर दोनों उम्मीदवार अपनी ताकत पर खेले। इसका क्या असर हुआ, यह पांच नवंबर को ही जाहिर होगा।

वन नेशन-वन इलेक्शन ! आपत्ति और औचित्य??

15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा था कि वे देश में लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव एक साथ करवाएंगे ! इससे श्रम शक्ति, मैन पावर और धन की बचत होगी । आचार संहिता लगने से काम नहीं रुकेंगे ! बात सौ फीसदी ठीक है । 1952 से 1967 तक ऐसा ही होता था विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुये थे । इसके बाद बीच में ही विधानसभाएं भंग होने के कारण, या गवर्नर रूल लगने के के कारण यह व्यवस्था बिगड़ गई । अब साल भर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं ! प्रश्न गंभीर है और इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है । केन्द्रीय सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी की अध्यक्षता में इस विषय पर विचारार्थ एक समिति बनाई थी । इसमें देश के जाने-माने आठ सदस्य थे । विख्यात विधि वेक्ता साल्वे भी थे । कांग्रेस के तब विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी थे । इस कमेटी ने कई हजार पेज की रिपोर्ट सौंपी है । अब रिपोर्ट पढ़कर ही पता चल सकता है कि इस मसले पर कितने हजार रिपोर्ट की जरूरत क्या थी । आज-कल तो रूलिंग पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो बंद कमरे में तय कर लेते हैं उसे लागू कर देते हैं । पर इस देश में दिखावे का चलन है । विशेष उत्सवों पर वधू को, नवजात शिशु को, सम्मान दिए जाने वाले व्यक्ति को लिफाफे दिये जाते हैं । पहले आशीर्वाद दिया जाता था । खैर अब जब मोदी जी ने तय कर लिया है कि इस देश में एक साथ चुनाव होंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूर सन् 2029 के चुनाव से हो जायेगा । यह भी कहा गया है कि इससे धन भी बचेगा । यह बात सौ फ़ीसदी ठीक है । परन्तु इस बार पहली सितम्बर को हिमाचल प्रदेश में वहां के कर्मचारियों को उनका वेतन क्यों नहीं मिला? क्योंकर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को अपने वेतन का त्याग करना पड़ा? अरविन्द केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस में यात्रा, फ्री इलाज, फ्री एजुकेशन, फ्री तोहफा की जो प्रथा शुरू की थी, संक्रामक रोग की तरह सभी राज्यों में फैल चुकी है चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो । शुरू में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे फ्री बी, या फ्री रेबड़ी कहा था । पर आज भाजपा भी उसी रास्ते पर है । मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी महिलाओं को 1250/- महीने का जेब खर्च दिया और कहा कि यह भाई की ओर से बहन को नेग है । अब सरकारी खर्च से भाई बहन को रक्षाबंधन की गिफ्ट दे रहा है । अब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, तेलुगु देशम आदि समेत सभी राज्यों ने भी इस प्रथा को चालू कर दिया । अब हरियाणा में भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में ऐसी ही राशि सभी महिलाओं को देने का वादा किया है ।

भारत-बांग्लादेश क्रिकेट मैच का विरोध क्यों ?

आरती कुमारी

बांग्लादेश इस समय गैर मुस्लिम समुदायों अर्थात अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम बन गया है | चूँकि वहां अल्पसंख्यकों में हिन्दुओं की संख्या अधिक है इसलिए हिंसा और दंगों का असर हिन्दुओं पर ही सर्वाधिक पड़ता है | एक समय था जब बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या लगभग बाईस प्रतिशत हुआ करती थी | किन्तु आज यह संख्या घटकर लगभग आठ प्रतिशत या इससे भी कम रह गई है क्यों ? जानकारों का कहना है कि यदि जिहाद ऐसे ही जारी रहा तो 2050 तक बांग्लादेश हिंदू विहीन हो जाएगा | यहाँ हिन्दू बिहीन का अर्थ केवल हिन्दुओं से नहीं है अपितु सिख, बौद्ध, ईसाई सभी से है | यदि संयुक्तराष्ट्र द्वारा शीघ्र ही कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सब-के-सब धीरे-धीरे मिटा दिए जाएँगे | कुछ की हत्या करदी जाएगी, कुछ का धर्मान्तरण हो जाएगा और कुछ भगा दिए जाएंगें या स्वयं भाग जाएँगे | प्रश्न यह भी है कि देखते ही देखते चौदह प्रतिशत हिन्दू घट गए और संसार में कोई हलचल, कोई प्रतिक्रिया या विरोध नहीं हुआ | भारत में एक मुसलमान की हत्या होती है तो यह जाने बिना,कि इसमें मृतक दोषी था या निर्दोष, हत्या आपसी रंजिश में हुई या अन्य कारण से ,जिहादियों ने भारत के सभी हिन्दुओं को असहिष्णु घोषित कर दिया | कई मुस्लिम देशों ने विरोध प्रदर्शन किया | केवल एक मुसलमान की हत्या पर ? मैं यहाँ किसी हत्या का समर्थन नहीं कर रहा, मेरे कहने का आशय यह है कि एक व्यक्ति की हत्या पर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन होते हैं और यहाँ चौदह प्रतिशत आबादी को मार काट कर समाप्त कर दिया और संसार में कोई हलचल,आन्दोलन या असहिष्णुता नहीं क्यों ? अस्तु, मेरे कहने का आशय यह है कि आज जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिन्दुओं को मारा जा रहा है उस समय हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं ? हम बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं ! जहाँ विरोध होना था वहाँ हँसी खेल चल रहा है |यह नीरसता,निष्ठुरता और पलायनवाद ही जिहादियों को जिहाद करने और कट्टरपंथियों को हिन्दुओं पर अत्याचार करने का हौसल देता है | भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता सबको पता है | हमारे देश में बड़ी संख्या में युवा वर्ग क्रिकेट का दीवाना है ऐसे में जो हाथ बांग्लादेश की हिंसा के विरुद्ध मानवता का झंडा उठाने को तत्पर होने चाहिए वे उस कट्टर देश के लिए ताली बजाते हुए देखे जाएंगें ! किन्तु हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं है | भारत-बांग्लादेश के मध्य मैचों की श्रृंखला में टी-ट्वेंटी सीरीज का पहला मैच ग्वालियर के नवनिर्मित स्टेडियम में 6 अक्टूबर को होने जारहा है | ग्वालियर में अनेक संगठन इस मैच का विरोध कर रहे हैं | सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में इसका विरोध किया जा रहा है | यदि यह मैच रद्द होता है तो पूरी दुनिया में यह सन्देश जाएग कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का भारत की जनता विरोध कर रही है | मैच का विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे बांग्लादेश हिन्दू बौद्ध ईसाई ओइक्यो परिषद की उस माँग को बल मिलेगा जिसमें परिषद संयुक्त राष्ट्र से वर्तमान हिंसा की निष्पक्ष जाँच की मांग कर रही है | यह तो सब जानते ही हैं कि बांग्लादेश के आतंकी इस हिंसा की चर्चा को दबा देना चाहते हैं | कम्युनिस्ट मीडिया और बुद्धिजीवी इसे राजनीतिक हिंसा का रूप देकर मामले को बदलना चाहते हैं | इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट मिलकर इसे सांप्रदायिक या इस्लामिक हिंसा के स्थान पर संपत्ति आदि का झगड़ा सिद्ध करने के प्रयास में हैं | ऐसे में भारत का बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलना कम-से-कम इस समय तो ठीक नहीं है | इससे वहां के अल्पसंख्यकों की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है | यह भी एक विडंबना की बात है कि वहां हिंदू, बौद्ध, ईसाई और सिख चारों को निशाना बनाया जा रहा है | सभी के धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं | सब के घरों में आग लगाई जा रही है | किंतु भारत के हिंदू, बौद्ध, ईसाई और सिख चारों मिलकर इस आतंकवाद का विरोध नहीं कर रहे, क्यों ? यद्यपि सिक्खों ने विरोध किया है किन्तु उतना नहीं जितना अपेक्षित था | सोशल मीडिया पर ऐसी अपीलें भी की जारही हैं कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई और सिख आओ हम सब मिलकर एक साथ बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के समर्थन में खड़े होकर इस मैच को रद्द करने की मांग करें | इस विरोध से यह मैच रद्द होगा कि नहीं यह तो समय बताएगा किन्तु इस विरोध में एक बात बहुत सकारात्मक है वह यह कि बांग्लादेश के सभी गैर इस्लामिक लोग एक साथ भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं | किन्तु भारत में कट्टर इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट गठजोड़ इतना सक्रिय है कि वह हर उस आवाज को दबाने का प्रयास करता है जो हिन्दुओं के पक्ष में उठती है | मैच के पक्ष और विपक्ष में लोगों की अलग-अलग राय हो सकती हैं किन्तु समय के औचित्य पर तो प्रश्न उठता ही है | मान लीजिये बांग्लादेश के स्थान पर यह घटना पाकिस्तान में हुई होती | वहां ठीक इसी प्रकार हिन्दुओं के गाँव-के-गाँव जला दिए जाते,हिन्दू महिलाओं के साथ बलात्कार होते,मंदिर तोड़े जारहे होते (जैसा कि वहाँ भी होता रहता है) तब क्या भारत, पाकिस्तान के साथ ऐसे ही मैच खेलता ? क्या भारत की जनता पाकिस्तानी क्रिकेटरों का ऐसे ही गर्म जोशी से स्वागत करती ? यदि नहीं तो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस आतंकवाद पर विराम लगने से पहले बांग्लादेश के खिलाड़ियों का स्वागत भला कैसे किया जासकता है ?

दिनकर जी के शब्दों में कहें तो –समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।'

भारत को एशिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का प्रमाणपत्र ऐसे ही नहीं मिला है

अशोक भाटिया , मुंबई

हॉल ही में ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के नए सालाना एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग तीसरी हो गई है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में कई एजेंसियों ने इसे लेकर सर्वे भी किए हैं, जो इसका सीधा सा उदाहरण हैं। यह सर्वे बताते हैं कि भारत तेजी से उभर रहा है और 2047 तक हिंदुस्तान 'विकसित भारत' बनेगा।प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपने सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और जल्द ही विश्व गुरु के स्थान को हासिल कर दुनिया का नेतृत्व करेगा।"टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के नए सालाना एशिया पावर इंडेक्स के मुताबिक, भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना है। भारत ने इस इंडेक्स में रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया है। इस इंडेक्स में जापान चौथे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया पांचवें नंबर पर और रूस छठे नंबर पर है। इसके अलावा पाकिस्तान का 16वां नंबर है। इसके साथ ही भारत अब विश्व में सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही अमेरिका का सफल दौरा कर भारत लौटे है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के बीच अमेरिका से उनके पुराने रिश्ते एक बार फिर चर्चा में हैं। मोदी आर्काइव ने प्रधानमंत्री मोदी की करीब 30 वर्ष पहले की यात्रा का ब्यौरा एक्स पर पोस्ट किया है। उस समय नरेन्द्र मोदी एक युवा नेता के तौर पर अमेरिका गए थे। इस यात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल विजन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी की अगुआई में आज भारत वैश्विक कूटनीति की दुनिया का न सिर्फ अहम खिलाड़ी है बल्कि नरेन्द्र मोदी को ऐसे वैश्विक नेता के तौर पर स्वीकार किया जाता है, जो रूस- यूक्रेन संघर्ष को खत्म कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक समुदाय के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत विशाल संभावनाओं और अवसरों का पता लगाने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत की थी । न्यूयॉर्क में एक गोलमेज सम्मेलन में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शीर्ष सीईओ के साथ अपनी बातचीत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता के बारे में आश्वासन दिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 'क्वाड' (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) के सदस्य देशों के शासन प्रमुखों की बैठक और भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' को संबोधित किया। मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। उन्होंने रविवार को 'क्वाड' शिखर सम्मेलन के इतर अपने जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और आपसी लाभ एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ''शांति, स्थिरता और समृद्धि'' के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत के दौरान, यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान तथा क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता की बहाली के लिए भारत का समर्थन दोहराया। कुल मिलाकर मोदी के इस दौरे को काफी सफल बताया जा रहा है। यही कारण है कि मोदी सरकार 3 में भाजपा के सहयोगी दलों ने भी प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की जमकर तारीफ की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट में लिखा कि नरेन्द्र मोदी की अभी हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर लिए गए निर्णय स्वागत योग्य हैं। दोनों देशों के बीच लिए गए निर्णयों से अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। नीतीश ने कहा कि बिहार के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले नये अवसरों से उत्साहित हैं। विश्व के नेताओं और भारतीय प्रवासियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का गर्मजोशी से किया गया। यह स्वागत उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करता है। इस यात्रा के दूरगामी एवं सकारात्मक प्रभाव होंगे। इस सफल यात्रा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी सफल यात्रा के बाद देश लौटने पर मैं नरेंद्र मोदी का स्वागत करता हूं। हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे राजनेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रों के समुदाय में भारत की स्थिति मजबूत की है और समुदायों और देशों को एक साथ लाकर निर्विवाद रूप से एक बड़े विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। संयुक्त राष्ट्र में उनका संबोधन इस बात का प्रमाण है कि विश्व नेता भारत को कितना महत्व देते हैं और आने वाले वर्षों में हम वैश्विक मंच पर क्या भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस यात्रा ने एक बार फिर प्रदर्शित किया कि प्रधान मंत्री एक प्रतिष्ठित वैश्विक राजनेता और असाधारण योग्यता के ट्रेंडसेटर क्यों हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी यात्रा के दौरान प्रौद्योगिकी और व्यापारिक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत पर अपनी सहमति व्यक्त की और कहा कि निवेश आकर्षित करने के प्रधानमंत्री के प्रयासों से अंततः महाराष्ट्र को लाभ होगा। शिंदे ने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान लगभग 300 पुरावशेषों की वापसी सुनिश्चित की। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने लिखा कि वैश्विक नेता और मां भारती के प्रिय पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के समापन के बाद आज वापस भारत लौट रहें हैं। अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में क्वाड लीडर्स समिट और भविष्य के शिखर सम्मेलन (SOTF) में भाग लिया जो अपने आप में अद्वितीय रही,साथ ही, उन्होंने अपनी यात्रा जो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं वह राष्ट्र के प्रगति के लिए सार्थक होंगीं। नरेन्द्र मोदी जी के संयुक्तराष्ट्र महासभा से हटकर वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात और दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने तथा संपर्क, व्यापार और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा से देश के व्यापार को लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी के संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन के संबोधन को दुनिया याद रखेगी। यूएसए यात्रा के दौरान मोदी जी के प्रति दुनिया के प्यार को देखकर हर भारतीय खुद को गौरवांन्वित महसूस कर रहा है। तब ही तो पुरी दुनिया कह रही है, मोदी भारत की आन बान शान है और । एचडी कुमारस्वामी ने लिखा कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की एक और सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करता हूं। इतने कम समय में उन्होंने जिन व्यापक मुद्दों को संभाला, वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। तीन दिनों में उन्होंने परमाणु ऊर्जा, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, सेमीकंडक्टर्स, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की वापसी और कई अन्य विषयों पर चर्चा की। इन सबके अलावा भू-राजनीतिक मामलों पर रणनीतिक विचार-विमर्श भी हुआ। भारतीय प्रवासियों के साथ उनके आत्मीय संबंधों की तस्वीरें भी दिल को छू लेने वाली थीं। धन्यवाद सर, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी निरंतर मेहनत अत्यंत प्रेरणादायक है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने 'एशिया पावर इंडेक्स-2024' में भारत की बढ़त का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक रणनीति को दिया है।केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि यह विश्व मंच पर पीएम मोदी का अथक प्रयास हैं, जिसने भारत को मानचित्र पर वापस ला दिया है। उन्होंने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया है और इसे वैश्विक कूटनीति में लाभ उठाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल दिया है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मेष राशि: आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज निजी जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप किसी महापुरुष का अनुशरण करेंगे। आपकी ज्यादातर योजनाएं पूरी हो सकती है। आज लोगों से मिलने और बात करने में खुशी महसूस करेंगे। आज अन्य गतिविधियों की वजह से आपके व्यक्तिगत काम बीच में अटक सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा।

वृष राशि:आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। परिवार को अधिक समय न दे पाने से परिवार की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। आज अपने व्यक्तिगत काम की ओर आप उचित ध्यान दे पाएंगे। आपका काम-धंधा भी अच्छा चलेगा। आज आप पुराने दोस्तों से मिलने की कोशिश करेंगे।

मिथुन राशि:आज का दिन आपके लिए दिन शुभ रहने वाला है। किसी काम के लिए आज आप कई बड़े फैसले ले सकते हैं। कारोबार में कुछ न कुछ चुनौतियां रहेंगी, हालांकि आपकी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे। रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। लवमेट एक-दूसरे के लिए उचित सामंजस्य और सहयोग की भावना रखें। आज आपका अधिकारियों से व्यवहार अच्छा रहेगा।

कर्क राशि:आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। घर के कामों में आपका पैसा लग सकता है। कोई भी फैसला शांति से लें। आज बातचीत करने में मधुरता रखें तो आपके लिए अच्छा है। आज आपके किसी उच्च्च अधिकारी से मुलाकात के योग बन रहे हैं। आपका कोई नया काम शुरू हो सकता है। अगर किसी वजह से स्ट्रेस बना हुआ है तो आपको मानसिक सुकून मिलेगा।

सिंह राशि:आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज स्टूडेंट अपनी योग्यता से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। पारिवारिक और व्यवसायिक गतिविधियों में संतुलन बना रहेगा। किसी भी काम को जल्दी पूरा करने की सोच रखें। बच्चे की गलती से निराशा हो सकती है। आवेश में आने की बजाय सहजता से मामला सुलझाने की कोशिश करें। अगर किसी विशेष संस्था से जुड़े हैं तो उससे संबंधित गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें, इससे आपको सुकून मिलेगा और मान-सम्मान भी बढ़ेगा।

कन्या राशि:आज का दिन आपके लिये खास होने वाला है। आपके व्यवहार में विनम्रता और लचीलापन ही आपको सम्मान दिलाएगा। पारिवारिक संबंधों में गहराई और अपनापन आपको महसूस हो सकता है। आज किसी समारोह के होने कारण से आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है जिसे आप बखूबी पूरा भी करेंगे।

तुला राशि:आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है। व्यवस्थित दिनचर्या रहने से मानसिक और शारीरिक रूप से आप तनावमुक्त महसूस करेंगे। कोई पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा जिससे आप अपनी अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान अवश्य दें। आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

वृश्चिक राशि:आज का दिन आपके लिये अच्छा रहने वाला है। अगर आज कोई विशेष निर्णय लेने जा रहे हैं तो उससे संबंधित पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें, इससे आपको सफलता मिलेगी। किसी सराहनीय कार्य की वजह से समाज में मान-सम्मान मिलेगा। किसी भी काम में बहुत अधिक सोच-विचार करने और उसमें समय लगाने से आपकी कार्य क्षमता कम हो सकती है।

धनु राशि:आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाल है। आज आपका दिन दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। आपको कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे पूरा करने के लिए आपको ख़ुशी होगी। आज अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना, आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक रहेगा। बच्चों के भविष्य को लेकर चल रही प्लानिंग को साकार करने का अवसर मिलेगा।

मकर राशि:आज का दिन आपके लिए व्यस्ताता से भरा हो सकता हैं। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज कारोबारी व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी और किसी वरिष्ठ सदस्य के मार्गदर्शन में कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। नौकरी में अपना प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से पूरा करने से अधिकारियों के बीच सराहना होगी। परिवार में धार्मिक आयोजन के योग बन रहे हैं।

कुंभ राशि:आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निपटाने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। किसी भी काम में फोकस रहना बहुत जरूरी है। आज जल्दबाजी और लापरवाही में लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। आज आप मान-सम्मान को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे। आज संकोच में अतिरिक्त कार्यभार अपने ऊपर न लें। धैर्य और विनम्रता बनाये रखें। आज आपको नए इनकम सोर्स मिल सकते हैं।

मीन राशि:आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आपको बहुत दिनों से ख्वाहिश थी। आज किसी इम्पोर्टेन्ट विषय में अपने से बड़े या किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही आगे बढने की कोशिश करें। मेहनत, धैर्य और समझदारी से काम निपटा लेंगे। आज आप खुद को लेकर कुछ नियम बनाएंगे और आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य योजना के मुताबिक पूरा हो जाएगा। इससे आपको सुकून मिलेगा।

शब्द सामर्थ्य -189

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं :
1. अनुचित, असत्य, जो ठीक न हो 3. बेवजह, बिनाकारण, व्यर्थ 4. हल्कीनींद, चकमा, धोखा 6. शक्कर पानी आदि का मीठा घोल 10. सोते से उठाना, सावधान करना, प्रदीप्त करना 11. चरमसीमा, सीमांत 14. पानी, आंसू 15. बैठा हुआ, विराजित 16. नृत्य 17. मृतप्राय, मृत्यु के करीब 19. जल, अम्बु 22. उपहार, भेंट 23. खबर, संदेश।

ऊपर से नीचे
1. गणपतिजी, 2. मांगनेवाला, पाने की इच्छा करने वाला 3. मिट्टी के रंग का, मटमैला 5. चला आता हुआ क्रम प्रथा, प्रणाली, रीति-रीवाज, 7. निशाचर, रात में विचरण करने वाला 8. पेड़ का धड़ा जहां से शाखाएं निकलती है, 9. मिठाई, खाने की मीठी चीज 12. शासन, गुप्तबात 13. श्रद्धा, स्त्री, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य 15. विपत्तिग्रस्त, दुखी, अभागा 16. प्रसिद्ध, नामवर 18. स्वप्न, ख्वाब 20. करीब, नज़दीक, समीप 21. सुबह, प्रात:, सबेरा।

1		2	■	■	■	3		
	■		■	4	5		■	■
6	7		8	■		■	■	9
■	10			■	11	12	13	
■	14		■	15				
16		■	■		■	■		■
17			18		■	19		■
	■	■		■	20	■	■	21
22				■	23			

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 188 का हल

अ	भि	षे	क	■	प	स	■	■
जा	त	■	थ	प	थ	पा	ना	■
य	र	का	नी	■	श्र	■	र	श्मि
ब	घा	र	■	क	ष्ट	प्र	द	■
■	त	ना	त	नी	■	र्व	■	ब
अ	■	मा	■	ज	मा	त	■	ल
स	जा	■	■	■	■	क	ज	रा
बा	■	बे	स	हा	रा	■	ग	म
ब	गु	ला	■	रा	ज	दू	त	■

सू- दोकू क्र.189

	1			4			7	
		6	9		2			1
	7			6		8		2
1							8	
	8			5		2		3
3		2			4		1	
	3		2			4		
		8		1	6			7
9			4				2	

नियम
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र 188 का हल

3	9	6	8	2	5	4	7	1
8	2	5	1	7	4	6	3	9
7	1	4	6	9	3		2	5
1	8	9	3	6	7	8	5	4
2	6	7	5	4	8	1	9	3
5	4	3	9	1	2	7	8	6
6	7	2	4	3	9	5	1	8
9	5	1	7	8	6	3	4	2
4	3	8	2	5	1	9	6	7

संकटमें सिद्धरमैया

कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटकके मुख्य मंत्री सिद्धरमैया भूमि घोटाले प्रकरणको लेकर न केवल संकटमें है, बल्कि उनका संकट और गहराता जा रहा है। इस प्रकरणको लेकर सियासत गरमा गयी है। मंगलवारको कर्नाटक उच्च न्यायालयसे सिद्धरमैयाकी याचिका खारिज होनेके बाद उन्हें आनेवाले दिनोंमें और भी परेशानीका सामना करना पड़ सकता है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) पाश क्षेत्रमें अपनी पत्नीको दिये गये १४ भूखण्डोंके आवण्टनमें गड़बड़ीके सिलसिलेमें राज्यपाल थावरचन्द गहलोतने भूमि घोटाले प्रकरणकी जांचकी स्वीकृति प्रदान की थी, जिसे सिद्धरमैयाने उच्च न्यायालयमें चुनौती दी थी लेकिन उच्च न्यायालयसे उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उनकी याचिका भी खारिज हो गयी। उच्च न्यायालयने घोटालेमें राज्यपालके जांच आदेशको बरकरार रखा है। सिद्धरमैयाने अपनी याचिकामें यह भी कहा था कि राज्यपालका निर्णय वैधानिक रूपसे असन्तुलित, प्रक्रियागत खामियोंसे भरा और असम्बद्ध विचारोंसे प्रेरित है। सिद्धरमैयाकी याचिका खारिज होते ही भाजपा प्रवक्ता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखरने उनसे इस्तीफा मांग लिया है। चन्द्रशेखरका कहना है कि घोटालेकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांचके लिए जरूरी है कि सिद्धरमैया पदसे इस्तीफा दे दें। निश्चित रूपसे भूमि घोटालेका प्रकरण काफी गम्भीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जायगी, यह अलग विषय है लेकिन जांचसे इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस हाईकमानके लिए यह गम्भीर मामला है। कांग्रेसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेका गृह प्रान्त कर्नाटक है। इस सम्बन्धमें पार्टी हाईकमान क्या रुख अपनाता है, इसपर भी ध्यान देना होगा। भूमि घोटाले प्रकरणसे पार्टीकी छविपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कर्नाटकमें भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है। पिछली सरकारपर भी भ्रष्टाचारके गम्भीर आरोप लगे थे और इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेसने विधानसभा चुनावमें राजगको पराजित किया था। अब भ्रष्टाचारका मामला कांग्रेसपर गम्भीर बन गया है। इसलिए पार्टी हाईकमानको शीघ्र ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे कि जनताके विश्वासपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। कांग्रेस हाईकमान क्या निर्णय करता है, वह अलग बात है लेकिन नैतिकताके आधारपर सिद्धरमैयाको अपने पदसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। हाईकोर्टने जो निर्णय किया है उसका सम्मान होना चाहिए और सिद्धरमैयाको जांचमें पूरा सहयोग करना होगा। इसमें विलम्ब होनेसे स्थितियां विषम हो सकती हैं जिससे राजनीतिक शुचिता प्रभावित होगी।

योगीका सख्त कदम

खाद्य पदार्थोंमें मिलावटकी खबरें कोई नयी नहीं है, लेकिन इन दिनों जो खबरें आ रही हैं और जो घटनाएं हुई हैं वह सभ्य समाजको झकझोर देनेवाली है। खान-पानकी वस्तुओं मानव अपशिष्ट, अखाद्य एवं गंदी चीजोंकी मिलावटकी जो घटनाएं मिली हैं वह स्वास्थ्यपर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाली है। अधिकसे अधिक लाभ कमानेके लिए मनुष्यका इतना चारित्रिक पतन होगा, इसके बारेमें कभी किसीने कल्पना भी नहीं की होगी। गाजियाबादके लोनीमें एक दुकानदार जूसमें पेशाब मिलाकर बेच रहा था तो शामलीमें एक ठेला दुकानदारका जूसमें थूक मिलाते वीडियो प्रसारित हुआ था। गाजियाबादके ही एक रेस्तरामें खानेमें काकरोचके मिलनेकी घटना वीभत्स मानसिकताको रेखांकित करती हैं जो दूषित मानसिकताका परिचायक है। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। खाद्य पदार्थोंमें इस तरहकी मिलावटखोरीकी घटनाओंको संज्ञानमें लेते हुए उत्तर प्रदेशकी योगी आदित्यनाथ सरकारका खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियममें संशोधनका निर्णय उचित और स्वागतयोग्य है। इसके तहत होटलों, ढाबों और रेस्तराकी न सिर्फ गहन जांच होगी, बल्कि इनपर उनके संचालक, मालिक और मैनेजरके नाम-पते भी प्रदर्शित करना होगा। हालांकि इसके पहले भी कांवड़ यात्राके दौरान मार्गोंपर स्थित होटलों, ढाबों और ठेलोंपर संचालकोंका नाम लिखना अनिवार्य किया गया था जिसपर शीर्ष न्यायालयने अन्तरिम रोक लगा दी थी। लेकिन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियममें संशोधनके बाद अब पूरे प्रदेशमें यह आदेश लागू होगा जो जनहितमें सार्थक पहल है। इसे न तो जाति और धर्मके आधारपर देखा जाना चाहिए और न ही राजनीतिक स्तरपर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्भावनासे हटकर दुकानदारोंको भी ईमानदारीसे अपपने कर्तव्यका निर्वहन करना होगा। योगी सरकारका निर्णय देशके अन्य राज्योंके लिए भी अनुकरणीय है।

लोक संवाद

प्रदर्शनोंकी भूमि

महोदय,- हुकूमतके पास बहुत बड़ी पावर होती है। नोटिस देना हुकूमतका बाएं हाथका खेल होता है, क्योंकि हुकूमतका दांया हाथ बिजी रहता है, इसलिए हुकूमत बाएं हाथसे नोटिस जारी करती रहती है। हुकूमतने जबसे यह बताया है कि हिमाचल प्रदर्शनोंकी धरती है तो खुदा कसम अपने शिक्षकोंसे मेरा भरोसा उठ गया है। मैं तो बचपनसे सुनता आया हूं कि यह देवभूमि है। कहते हैं कि दूधका जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है, इसलिए हुकूमतपर भी एकदमसे भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। जबसे हुकूमतने यह बताया है कि यह तो प्रदर्शनोंकी धरती है, तबसे दिमागमें घंटियां बज रही हैं। अब इस धरतीको नमन करूं या न करूं, इसको लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूं। बंदा कंफ्यूज हो तो अंट-शंट भी सोचने लगता है। यही मेरे साथ भी हो रहा है। मैं शामको चार पैग मार कर भी इतना कंफ्यूज कभी नहीं हुआ जितना हुकूमतके खुलासेसे हो रहा हूं। जहां गलीमें चार आदमियोंको खड़े देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह सब प्रदर्शनकारी हैं और प्रदर्शनकी तैयारी कर रहे हैं। बीच-बीचमें मनमें यह आवेग उठने लगता है कि मैं भी इनके बीच पहुंच जाऊं और दो-चार नारे लगाकर फिर वापस आकर बाथरूममें नहाने चला जाऊं। नहानेसे दिमाग ठंडा रहता है। गलीमें खेलते बच्चोंको आपसमें उलझते देखता हूं तो मुझे लगता है कि नयी पीढ़ी प्रदर्शनकी जबरदस्त तैयारी कर रही है और आनेवाले दिनोंमें स्कूलों-कालेजोंमें बड़े स्तरपर प्रदर्शन हुआ करेंगे, क्योंकि हुकूमतने खुद स्वीकार किया है कि यह प्रदर्शनोंकी धरती है, इसलिए बच्चोंको प्रदर्शनोंकी पूरी छूट होगी। बच्चे घरमें भी कोई डिमांड पूरी न होनेपर प्रदर्शन कर सकते हैं और मां-बाप बच्चोंका कुछ नहीं बिगाड़ पायंगे, क्योंकि बच्चे भी यही दलील देंगे कि हम प्रदर्शनोंकी धरतीमें रह रहे हैं और प्रदर्शन करना हमारा जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार है। हो सकता है आनेवाले टाइममें हुकूमत यह अध्यादेश भी जारी कर दे कि जिन विद्यार्थियोंने ज्यादा प्रदर्शनोंमें हिस्सा लिया होगा, उन्हें वार्षिक परीक्षामें अतिरिक्त अंक दिये जायंगे। ऐसे विद्यार्थी भविष्यमें अच्छे नेता बनकर भी उभरेंगे और प्रदेशका मान सम्मान बढ़ायंगे। प्रदर्शनोंसे ही क्रांतियां आती हैं और क्रांतियोंसे इतिहास बनता है। इसलिए नया इतिहास रचनेके लिए हमें नित नये प्रदर्शनकी रूपरेखा अपने मनमें तैयार रखनी चाहिए। लोग प्रदर्शनमें बिजी रहेंगे तो हुकूमतकी नाकामियोंकी तरफ किसीका ध्यान नहीं जायगा। हुकूमत नीरोकी तरह चैनकी बंसी बजाती रहेगी। प्रदर्शनोंके बीच ऐसी बंसी हुकूमत ही बजा सकती है, कोई दूसरा नहीं। -**गुरमीत बेदी, वाया ईमेल।**

जनसंख्या विस्फोटसे बढ़ता जोखिम

बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। भारतके सन्दर्भमें देखा जाय तो १३ सितंबर, २०२४ को भारतकी जनसंख्या लगभग १,४५३५६७,७३८ थी। यह दुनियाकी कुल जनसंख्या (लगभग ८,१७६,२८३,४८६) का करीब १८ प्रतिशत है, जो विश्वके महज ढाई प्रतिशत भू-भागपर जीवनयापन करनेके लिए विवश है।

❒ **चेतनादित्य आलोक**

दुनियाके कई देशोंमें वहांकी बढ़ती जनसंख्याके अनुपातमें उपलब्ध संसाधन अब कम पड़ने लगे हैं। इसी वर्ष अप्रैलके अंतमें जारी संयुक्त राष्ट्रकी 'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस' के अनुसार आज दुनियाभरके ५९ देशोंके लगभग २८.२ करोड़ लोग भूखे रहनेके लिए मजबूर हैं। रिपोर्टके अनुसार युद्धग्रस्त गाजा पट्टी और सूडानमें बिगड़े खाद्य सुरक्षाके हालातोंके कारण २०२२ में २.४ करोड़से भी अधिक लोगोंको भोजनके अभावमें भूखे रहना पड़ा था। देखा जाय तो संयुक्त राष्ट्रकी रिपोर्ट इस बातकी ओर भी साफ संकेत करती है कि जैसे-जैसे विश्वकी जनसंख्या बढ़ती गयी वैसे-वैसे भूखे लोगोंकी संख्यामें भी लगातार वृद्धि होती गयी। भोजनके अभावपर संयुक्त राष्ट्रकी पहली रिपोर्ट २०१६ में आयी थी, जिसकी तुलनामें हालिया रिपोर्टमें विश्वभरमें भूखे लोगोंकी संख्यामें चार गुणा वृद्धि हो चुकी है। गौरतलब है कि बढ़ती हुई जनसंख्याके अनुपातमें सभी नागरिकोंके लिए भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था, दवाइयां इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओंकी आपूर्ति करना किसी भी सरकारके लिए सरल कार्य नहीं है। बढ़ती आबादीके कारण ऊर्जाके विभिन्न स्रोतों यथा

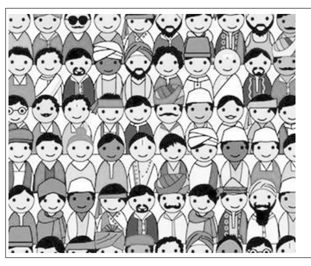

कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों आदिपर भी अत्यधिक दबाव बढ़ गया है, जिसे कम कर ऊर्जाके वैकल्पिक स्रोतोंकी तलाश और उपयोग करना जरूरी है। अंग्रेजी अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थसने सन् १७९८ में गणितीय रूपसे भोजन और मानव जनसंख्याके बीचके संबंधपर विचार करनेके बाद बताया था कि खाद्य आपूर्ति बढ़नेसे जनसंख्या तीव्र गतिसे बढ़ती है और उपलब्ध संसाधनोंको समाप्त कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप मानव पीड़ा बनी रह जाती है, जबतक जनसंख्याको नियंत्रित नहीं किया जाता। १८८८ में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिनने भी यह आशंका व्यक्त की थी कि भारतमें कृषि उत्पादन कम है और तीव्र जनसंख्या वृद्धिके कारण यहां अकाल पैदा होता है। इसके बावजूद १८७१ से १९४१ तक भारतकी औसत जनसंख्या वृद्धि दर ०.६० प्रतिशत रही, जबकि दुनियाका कुल औसत ०.६९ प्रतिशत ही था। हालांकि २०वीं सदीके प्रथम दो दशकोंमें जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही। १९३१ की जनगणनामें जब सामने आया कि भारतमें १९२१-१९३१ के बीच प्रतिवर्ष एक प्रतिशतकी दरसे जनसंख्या बढ़ी है तो सभी चौंक गये, लेकिन १९५१ के बाद यह दर लगभग दो प्रतिशतके आसपास पहुंच गयी। वैसे १९७० के दशकसे देशकी जनसंख्या वृद्धिकी दरमें निरन्तर गिरावट आयी है, जो संभवत: पिछले कुछ दशकोंमें शिक्षा और स्वास्थ्यके स्तरमें किये गये सुधारोंका परिणाम है, क्योंकि अबतक जनसंख्या वृद्धिकी दर सर्वाधिक उन्हीं क्षेत्रोंमें पायी गयी है, जहां लोग शिक्षित और स्वस्थ नहीं होते। हालांकि यह गिरावट अपेक्षाकृत बेहद धीमी रही है। आर्थिक सर्वेक्षणके आंकड़ोंपर गौर करें तो भारतमें वर्ष १९७१-८१ के बीच २.५ प्रतिशत रही वार्षिक जनसंख्या वृद्धिकी दर २०११-१६ के मध्यतक आते-आते १.३ प्रतिशत रह गयी। इसका दूसरा पक्ष यह है कि जनसंख्या बढ़ने और संसाधनोंके घटनेसे देशोंपर कर्जका बोझ भी बढ़ने लगता है। बिजनेस स्टैंडर्डकी एक रिपोर्टके अनुसार सितंबर २०२३ तक भारतपर कुल कर्जका बोझ २०५ लाख करोड़ रुपयेतक पहुंच गया था। वहीं, विश्व आर्थिक मंचकी २०२१ में जारी एक रिपोर्टके अनुसार शिक्षा गुणवत्तामें भारतका स्थान ९०वां है। जनसंख्या संबंधी संयुक्त राष्ट्रकी १५ नवंबर २०२२ को जारी एक रिपोर्टके अनुसार २०२७ में भारत चीनको पछाड़ देगा, जबकि संयुक्त राष्ट्रके आकलनको झुठलाते हुए अप्रैल २०२३ में ही चीनको पछाड़कर भारत दुनियामें सबसे अधिक जनसंख्यावाला देश बन गया। फरवरी २०२४ में संयुक्त राष्ट्रने ही अपनी एक अन्य रिपोर्ट जारी कर इसकी सूचना भी सार्वजनिक की थी। हालांकि २०११ के बादसे भारतमें जनगणना नहीं हुई है। फिलहाल अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धिके कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, बीमारी, गरीबी एवं लाचारी आदि ऐसी समस्याएं हैं, जो किसी भी समाजके नैतिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक एवं नैष्ठिक ताने-बानेको ध्वस्त कर सकती हैं। इसके कारण व्यक्तियोंका सामाजिक विकास, सांस्कृतिक उत्थान और मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नयन बाधित हो सकता है। कमोबेश आज ऐसी ही परिस्थितियोंसे हमारा देश गुजर रहा है। वैसे जनसंख्याको लेकर पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके अलावा देशके किसी भी प्रधान मंत्रीने अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धिपर लगाम लगाने हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। शायद वोट बैंककी राजनीतिके कारण देशकी सरकारें जनताको नाराज करनेसे बचती रही होंगी, क्योंकि स्वतंत्रतासे पूर्व भारतीय समाजमें यह धारणा व्याप्त थी कि अधिक जनसंख्या विकासका पैमाना होता है। दरअसल उन दिनों जनसंख्याका कम होना नकारात्मक परिस्थितियोंकी देन माना जाता था, जो एक बुरी स्थिति थी, किन्तु समयके साथ हमारी सोचमें बदलाव आता गया और हमने इसपर विचार करना शुरू किया कि क्या भारतवर्ष इतनी बड़ी जनसंख्याको संभालनेमें सक्षम है। समय-समयपर आनेवाले भयानक सूखे और अकालकी त्रासदीने भी इस चिन्ताकी तरफ देशवासियोंका ध्यान आकर्षित किया। इसके बावजूद १९७० के दशकतक हमारी सरकारें खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धिका समाधान ढूंढती रहीं, लेकिन आपातकालके समय इंदिरा गांधीकी सरकारने परिवार नियोजन कार्यक्रमको बहुत सख्तीसे अपनाया। हालांकि जबरन नसबंदी कराये जानेसे लोग बेहद नाराज हुए और १९७७ में आपातकालके बाद श्रीमती गांधी चुनाव हार गयीं। उसके बादसे बढ़ती हुई जनसंख्यापर राजनेताओंने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। यही नहीं, भूमंडलीकरणके बाद भी जनसंख्याका मुद्दा भारतमें दबा ही रहा, लेकिन प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने २०१९ में स्वतंत्रता दिवसके अवसरपर लाल किलेकी प्राचीरसे जनसंख्या वृद्धिपर चिन्ता जतायी और राज्योंसे इसे रोकनेके लिए योजनाएं बनानेका आह्वान किया। वहीं, २०२४ का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणने तेजीसे बढ़ती आबादी और डेमोग्राफीमें आये बदलावकी चुनौतियोंसे निबटनेके लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनानेका ऐलान भी किया, जो 'विकसित भारत' बनानेके लक्ष्यको ध्यानमें रखते हुए इन समस्याओंसे निबटनेके लिए सुझाव देगी।

> **अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थसने सन् १७९८ में गणितीय रूपसे भोजन और मानव जनसंख्याके बीचके संबंधपर विचार करनेके बाद बताया था कि खाद्य आपूर्ति बढ़नेसे जनसंख्या तीव्र गतिसे बढ़ती है और उपलब्ध संसाधनोंको समाप्त कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप मानव पीड़ा बनी रह जाती है, जबतक जनसंख्याको नियंत्रित नहीं किया जाता। १८८८ में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिनने भी यह आशंका व्यक्त की थी कि भारतमें कृषि उत्पादन कम है और तीव्र जनसंख्या वृद्धिके कारण यहां अकाल पैदा होता है।**

सवालोंके घेरेमें वक्फबोर्ड

वक्फ अरबी भाषाका शब्द है जिसका अर्थ है परमार्थके लिए दान कर दी गयी सम्पत्ति। लेकिन दानदाताको यह भी स्पष्ट करना होगा कि अब वह या उसके वारिस इस सम्पत्तिको वापस नहीं ले सकेंगे।

❒ **कुलदीप चंद अग्निहोत्री**

वक्फ अरबी भाषाका शब्द है जिसका अर्थ ऐसी सम्पत्तिसे है जो परमार्थके लिए दान कर दी गयी हो। परमार्थ कार्योंमें मजहबी कार्यक्रम भी शामिल किये जा सकते हैं। जो सम्पत्ति कुछ निश्चित समयके लिए दानमें दी जाय और दान देते समय ही स्पष्ट कर दिया जाय कि पांच सालके लिए इस सम्पत्तिकी आयका उपयोग परमार्थके लिए किया जा सकता है, उसके बाद सम्पत्ति दान करनेवालेके पास वापस लौट जायगी तो वह वक्फनहीं माना जाएगा। परोक्ष रूप से वक्फसम्पत्ति अब दान करने वाले की रहती ही नहीं। इसलिए वापस लेनेका प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। यदि वह वक्फ वापस लेना भी चाहे तो यह सम्भव नहीं है। जो व्यक्ति अपनी सम्पत्तिको वक्फके लिए देता है, उसे वाकिफ कहते हैं। वक्फ की गयी सम्पत्तिको प्रबंध करनेके लिए वाकिफ किसी मुतावली (न्यासी) की व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्थाके लिए मुतावली जो मेहनत करेगा, उसकी एवजमें उसी वक्फकी आमदनीका कुछ हिस्सा मिल सकता है। कुल मिलाकर वक्फ किसी व्यक्तिका व्यक्तिगत मामला है। वह अपनी सम्पत्तिके प्रबंधनके लिए किसी मुतावली अर्थात् न्यासीके हवाले कर देता है और उसका प्रयोग केवल परमार्थके लिए हो सकता है। लेकिन वह अपनी सम्पत्ति किसी ऐसे मुतावलीको भी दे सकता है जो पहले ही किसी सम्पत्तिका परमार्थके लिए प्रबंधन कर रहा हो।

यानी पहलेसे ही बने हुए किसी ट्रस्टको भी सम्पत्ति दान की जा सकती है, यदि दानका उद्देश्य एक समान हो। यह पद्धति हिन्दोस्तानमें इस्लामके पैदा होनेसे भी पहलेसे चली आ रही है। भारतमें लाखों मंदिर, अनाथालय, गोशालाएं, पाठशालाएं और गुरुकुल इत्यादि इसी पद्धतिसे चलते थे और अब भी चलते हैं। अंग्रेजोंके आनेसे पहले भी मस्जिदें, दरगाहें, मदरसे, यतीमखाने वगैरह भी इसी पद्धतिसे चलते थे। वक्फ, वाकिफ और मुतावली शब्द, क्योंकि अरबी भाषाके हैं, इसलिए लगता है कि शायद यह कोई नयी योजना है जो इस्लामके पैदा होनेके बादसे ही दुनियामें प्रकट हुई है। लेकिन वक्फको लेकर असली काला धंधा १८५७ के बाद हुआ और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा विशेष उद्देश्यको ध्यानमें रखते हुए किया गया। १८५७ में आजादीकी पहली लड़ाईमें सभी भारतीयोंने मिलकर अंग्रेजोंके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसमें देसी मुसलमान भी शामिल थे। यहांतक एकता थी कि स्वतंत्रता संग्रामियोंने उसी मुगल वंशके बहादुरशाहको हिन्दका बादशाह घोषित कर दिया जिस मुगल वंशसे देशको आजाद करवानेके लिए शिवाजी मराठा, महाराणा प्रताप, गुरु गोबिंद सिंह, बंदा बहादुर, लचित बडफूकन जैसोंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उद्देश्य केवल इतना था कि एकता बनी रहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यसे इस स्वतंत्रता संग्राममें भारतकी हार हुई और भारतपर ब्रिटेनका प्रत्यक्ष कब्जा हो गया। १८८५ में कांग्रेसका जन्म हुआ और उसका उत्तर देनेके लिए अंग्रेजोंने मेजर आप्रेशनसे १९०५ में मुस्लिम लीगको पैदा किया। १८५७ के संग्रामपर मंथन किया गया। एक बात अंग्रेजोंको स्पष्ट होने लगी थी कि भारतमें अरब, तुर्क एवं मुगल (एटीएम) मूलके मुसलमान संख्यामें तो आटेमें नमकके बराबर हैं, लेकिन भारतमेंसे उनकी सत्ताका अंत हो जानेसे उनका कष्ट हजार गुणा बढ़ा हुआ है। वे यह भी समझ चुके हैं कि अब वे अपने बलबूते भारतपर दोबारा कब्जा नहीं कर सकते। अब उनके लिए एक ही रास्ता बचा है कि डूबते जहाजमें से जो बच जाय वही गनीमत है। उनकी अपनी सत्ताका जहाज तो डूब ही चुका था। अब केवल उन्हें तिनकोंका सहारा चाहिए था। ये तिनके देनेमें अंग्रेजोंको भला क्या आपत्ति हो सकती थी। पहला तिनका मुस्लिम लीग थी, जो अंग्रेजोंने उनको १९०५ में दिया था। मुस्लिम लीगपर कब्जा विदेशी मूलके शेखों और सैयदोंका ही था। भारतके देसी मुसलमानोंका उससे कुछ लेना-देना नहीं था। लेकिन ब्रिटिश सरकारकी योजना देसी मुसलमानोंको एटीएम मूलके मुसलमानोंके शिकंजेमें कसना था। उसके लिए मुस्लिम लीग बना भी ली। लेकिन उसके लिए पैसेका बंदोबस्त भी करना जरूरी था। अंग्रेज सरकार अपनी ओरसे पैसा दे सकती थी, लेकिन अंग्रेज यहांका पैसा इंग्लैंड ले जानेके लिए आये थे, न कि यहांके कामोंपर खर्च करनेके लिए। इसका एक ही तरीका हो सकता था। देशभरमें फैले मदरसों, वक्फों, मस्जिदों, दरगाहों, तुर्काक एवं मुगल शासन कालके दौरान इन विदेशी मूलके बादशाहों द्वारा रखी गयी अरबोंकी सम्पत्तियोंका नियंत्रण जनादेश एटीएम मूलके शेखों और सैयदोंके हवाले कर दिया जाय। उससे दो लाभ होंगे। ये सैयद और शेख अंतिम दमतक अंग्रेज सरकारका समर्थन करेंगे। दूसरा ये देसी मुसलमानोंपर नियंत्रण रखेंगे, ताकि वे आजादीके आन्दोलनसे दूर रहें। तीसरी वक्फ सम्पत्तियोंके केन्द्रीयकरणसे एटीएम मूलके मुसलमानोंके हाथमें अपार ताकत आ जायगी और भारतमें ही मजहबके नामपर एक पक्ष खड़ा हो जायगा। चौथा स्थानीय देसी मुसलमानोंके हाथसे दरगाहों, मस्जिदोंके प्रबंधनमें हिस्सेदारीकी संभावना सदाके लिए खत्म हो जायगी और वे कभी भी स्वयंको विदेशी मूलके शेखों और सैयदोंके कब्जेसे मुक्त होनेके बारेमें सोचना भी बंद कर देंगे। इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए अंग्रेज सरकारने मुस्लिम लीगकी स्थापनाके सात-आठ साल बाद ही वक्फ बोर्डोंकी स्थापनाके कानून बना दिये। इस बोर्डमें कुल मिलाकर गिनतीके सदस्य होते हैं। वे मोटे तौरपर एटीएम मूलके सैयद, तुर्क या मुगल ही होते थे। इनके हाथमें देशकी करोड़ोंकी सम्पत्तिका कब्जा दे दिया गया। बादमें जब मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकारकी साजिश और कांग्रेसकी जल्दी सत्ताप्राप्तिकी भूखसे भारतका एक हिस्सा पाकिस्तानके नामसे अलग हो गया तो जो मुसलमान हिन्दोस्तान छोड़कर वहां चले गये, उनकी यहां रह गयी सम्पत्तिका प्रश्न पैदा हुआ। कायदेसे वे सम्पत्तियां पाकिस्तानमें चले गये क्षेत्रोंसे आनेवाले हिंदू-सिखोंमें बांटी जानी चाहिए थीं। कुछ सीमातक ऐसा हुआ भी। लेकिन कांग्रेस सरकारने एक झटकेसे वह सारी सम्पत्ति वक्फ बोर्डके हवाले कर दी। ध्यान रहे वक्फ बोर्डका अभिप्राय है, यानी दस-पंद्रह सैयदों या शेखोंके हवाले कर दी। पाकिस्तान जानेवाले मुसलमान अपनी सम्पत्ति मजहबी संस्थाओंके लिए दान करके नहीं गये थे। वे अपनी इच्छा या विवशतामें भारत विरोधके कारण पाकिस्तान गये थे। इसलिए इस्लामकी मंशाके अनुसार भी उनकी सम्पत्ति वक्फकी तो हो ही नहीं सकती थी। वह सरकारके पास जानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस भी अंग्रेज सरकारकी तरह देसी मुसलमानोंपर शिकंजा बनानेके लिए सैयदों और शेखोंके आगे ही सिजदा करने लगी थी। अंग्रेज चले गये थे, लेकिन सत्ता पानेके लिए कांग्रेसने भी नीति गोरोंकी ही अपनायी। वक्फ बोर्डके नामपर सैयदों और शेखोंको पालनेका यह ब्रिटिश कालसे चला आ रहा काला धंधा है। अब जब भाजपा सरकारने इसको हिलाना-डुलाना शुरू किया है तो भारतके देसी मुसलमान तो खुश हैं कि उनको अपनी दरगाहोंका नियंत्रण मिल जायगा, लेकिन एटीएम और कांग्रेसके मोहल्लेमें रुदाली रुदन शुरू हो गया है। क्या वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होना चाहिए।

आत्मबोध

मातृ नवमी

❒ **सुकन्या**

मातृ नवमी आश्विन माहके कृष्ण पक्षकी नवमी तिथिको कहा जाता है। इस नवमी तिथिका श्राद्ध पक्षमें बहुत ही महत्व है। सनातन धर्मकी मान्यताके अनुसार श्राद्ध करनेके लिए एक पूरा पखवाड़ा ही निश्चित कर दिया गया है। सभी तिथियां इन सोलह दिनोंमें आ जाती हैं। कोई भी पूर्वज जिस तिथिको इस लोकको त्यागकर परलोक गया हो, उसी तिथिको इस पक्षमें उनका श्राद्ध किया जाता है, लेकिन स्त्रियोंके लिए नवमी तिथि विशेष मानी गयी है। मातृ नवमीके दिन पुत्रवधुएं अपनी स्वर्गवासी सास एवं माताके सम्मान एवं मर्यादा हेतु श्रद्धांजलि देती हैं और धार्मिक कृत्य करती हैं। नवमी श्राद्धमें पांच ब्राह्मणों और एक ब्राह्मणीको भोजन करवानेका विधान है। सर्वप्रथम नित्यकर्मसे निवृत्त होकर घरकी दक्षिण दिशामें हरा वस्त्र बिछायें। पितृगणके चित्र अथवा प्रतीक हरे वस्त्रपर स्थापित करें। पितृगणके निमित्त तिलके तेलका दीपक जलायें, सुगंधित धूप करें, जलमें मिश्री और तिल मिलाकर तर्पण करें। अपने पितरोंके समक्ष गोरोचन और तुलसी पत्र समर्पित करना चाहिए। श्राद्धकर्ताको कुशासनपर बैठकर भगवद गीताके नवें अध्यायका पाठ करना चाहिए। इसके उपरांत ब्राह्मणोंको लौकीकी खीर, पालक, मूंग दाल, पूड़ी, हरे फल, लौंग-इलायची तथा मिश्री अर्पित करें। भोजनके बाद सभीको यथाशक्ति वस्त्र, धन-दक्षिणा देकर उनको विदा करनेसे पूर्व आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। आश्विन माहके कृष्ण पक्षकी नवमी तिथिपर पितृगणोंकी प्रसन्नता हेतु नवमीका श्राद्ध किया जाता है। यह तिथि माता और परिवारकी विवाहित महिलाओंके श्राद्धके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। यह तिथि मातृ नवमी भी कहलाती है। कुछ स्थानोंपर इसे डोकरा नवमी भी कहा जाता है। नवमी तिथिका श्राद्ध मूल रूपसे माताके निमित्त किया जाता है। इस श्राद्धके दिनका एक और नियम भी है। इस दिन पुत्रवधुएं भी व्रत रखती हैं, यदि उनकी सास अथवा माता जीवित नहीं हो तो। इस श्राद्धको सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहा जाता है। शास्त्रानुसार नवमीका श्राद्ध करनेपर श्राद्धकर्ताको धन, संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा सौभाग्य सदा बना रहता है। श्राद्धके दौरान कुछ नियमोंका पालन जरूरी है। जैसे इन दिनों मांसाहार नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग इन नियमोंकी अनदेखी करते हैं। वे मांसाहारसे भी नहीं चूकते। कई लोग शराबका सेवन भी करते हैं। इन दिनोंमें स्त्रीगमनकी भी मनाही है, लेकिन आधुनिक युगकी अंधी दौड़में लोग सब कुछ भूल गये हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि लोग मांसाहारपर भी अंकुश नहीं लगाते।

सिर्फ आरक्षणसे उत्कृष्टता नहीं मिलेगी

❒ **पूनम कौशिश**

आरक्षण राशन तमाशा फिरसे राजनीतिक थालीमें परोस दिया गया है, क्योंकि हमारे नेता अपना वोट बैंक हासिल करनेके लिए लोकलुभावन हो-हल्ला मचाना जारी रखते हैंए जो नौकरशाहीमें पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) की एक बड़ी चुनौती बन गया और राजनीतिक तू-तू मैं-मैं का शिकार हो गया। कोटाके चश्मेके माध्यमसे राजनीतिक लड़ाईमें अच्छी नीतियोंके नुकसान होनेका एक क्लासिक मामला। प्रासंगिक रूपसे, यूपीएससीने १८ अगस्तको अनुबंधके आधारपर या प्रतिनियुक्तिके जरिये पार्श्व प्रवेशके माध्यमसे २४ केंद्रीय मंत्रालयोंमें कई भूमिकाओंके लिए ४५ पदोंका विज्ञापन दिया। इनमें दस संयुक्त सचिव और ३५ निदेशक/उप सचिवके पद शामिल थे। जाहिर तौरपर इसने विपक्षके साथ-साथ भाजपाके सहयोगियों (जद (यू), लोजपा) को भी परेशान किया, जिनका कहना था कि भाजपाको आरक्षणके मुद्देने काफी नुकसान पहुंचाया, जैसा कि हालिया लोकसभा चुनावोंमें स्पष्ट हुआ। इससे पार्टीको अहसास हो गया कि आरक्षण अपने आपमें चुनावी दृष्टिसे अति संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए उसने अपना रुख बदल लिया। दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेसके राहुल गांधी आरक्षणको छोटा करने और सरकारी नौकरियोंमें एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणको छीननेके लिए एक राष्ट्रविरोधी कदमके रूपमें लेटरल एंट्रीकी आलोचना कर रहे हैं तो वह यह आसानीसे भूल गये कि उनकी यूपीए सरकारने ही लेटरल एंट्रीकी अवधारणा विकसित की थी और २००५ में वीरप्पा मोइलीकी अध्यक्षतामें दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) स्थापित किया था। वास्तवमें इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूर्व वित्तमंत्री और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह थे, जो बाहरी विशेषज्ञ थे। इसी तरह इंफोसिसके पूर्व प्रमुख नंदन नीलेकणि भी हैं, जिन्होंने आधारकी अगुवाई की। इसके अलावा, सिंहके कार्यकालके दौरान ऊर्जा मंत्रालयने नामांकनके आधारपर एक प्रमुख औद्योगिक घरानेकी पृष्ठभूमिवाले एक वरिष्ठ अधिकारीको नियुक्त किया। छठे वेतन आयोग २०१३, नीति आयोग २०१७ ने भी इसे दोहराया, जिसमें मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तरपर अधिकारियोंको तीन सालके अनुबंधपर शामिल करनेका समर्थन किया गया, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता था, जो तबतक केवल आईएएस और केन्द्रीय सिविल सेवाओंके नौकरशाह ही करते थे। २०१९ में ६,०७७ संयुक्त सचिव आवेदनोंमेंसे नौको नौ मंत्रालयोंमें नियुक्त किया गया, इसके बाद २०२१, २०२३ में तीन दौरकी नियुक्ति की गयी। हालमें सरकारने राज्यसभाको बताया कि पिछले पांच वर्षोंमें ६३ लेटरल एंट्री नियुक्तियां की गयी हैं। वर्तमानमें ५७ लेटरल एंट्री केंद्रीय मंत्रालयोंमें तैनात हैं। निस्संदेह तेजीसे बढ़ती अर्थव्यवस्थामें नये विकासशील क्षेत्रों और हाइब्रिड प्रौद्योगिकियोंमें प्रौद्योगिकीके बढ़ते हस्तक्षेपके कारण सरकारी कार्यकलापोंमें क्षमताओंको समृद्ध करनेके लिए नये विचारों, ऊर्जा और डोमेन विशेषज्ञताके साथ बाहरी लोगोंको शामिल करनेकी आवश्यकता है, ताकि शासनके जटिल कार्योंको तेजीसे पूरा किया जा सके और वितरण तंत्रको तेज और कुशल बनाया जा सके। साथ ही वांछित परिणामोंके लिए सरकारमें सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्रकी संस्कृतिको शामिल किया जा सके। अफसोस, समस्या तब होती है जब बौने नेताओं द्वारा संचालित हमारी क्षुद्र राजनीति सामाजिक न्याय और समानताकी अनिवार्यताओंके खिलाफ संकीर्ण रूपसे परिभाषित आरक्षण शर्तोंमें विशेषज्ञता और योग्यताको समान मानती है। नतीजतन कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसे एसटी, एससी, ओबीसीके हितोंके खिलाफ माना जायगा। जैसा कि हालमें सुप्रीम कोर्टने एससी, एसटी, उपकोटापर रेखांकित किया है कि योग्यताको समानता और समावेशिताके सामाजिक सामानके संदर्भमें समझा जाना चाहिए, न कि संपन्न और वंचितों या योग्यता और वितरण न्यायके बीच संघर्षके रूपमें। नीतिगत दृष्टिसे कोटापर अत्यधिक जोर शासनको प्रभावित कर सकता है। इससे भी बुरी बात यह है कि नौकरशाह भी सरकार चलानेमें निजी क्षेत्रके विशेषज्ञोंको स्थान देनेमें अनिच्छुक हैं। सत्ता और भ्रष्टाचार बाबुओंकी सनकी नियंत्रण मानसिकताके माध्यमसे प्रवाहित होते हैं। इसके अलावा, लगातार बढ़ते आरक्षणका समर्थन नहीं किया जा सकता। मुझे गलत मत समझिये, निश्चित रूपसे सामाजिक न्याय वांछनीय है और समान अवसर और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करनेके सरकारके मौलिक मिशनके साथ-साथ एक प्रशंसनीय लक्ष्य है। फिर भी, गरीबीके दलदलसे उन्हें ऊपर उठानेमें भारतकी सात दशकोंकी ऊब यह दर्शाती है कि असंख्य वर्गों, जातियों, उपजातियों और वंचितोंको आरक्षण प्रदान करनेके लिए कोई भी कानून गरीबोंकी स्थितिमें सुधार नहीं कर पाया है, भले ही कुछ लोगोंको नौकरी मिल गयी हो। इसके अलावा यह पता लगानेके लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है कि कोटाके बाद आरक्षण पानेवालोंका मनोबल बढ़ानेके लिए उन्हें मुख्यधारामें लानेके लिए कोई प्रयास किया जाता है या नहीं। कोटा लोगोंके उत्थानके लिए एकमात्र रामबाण उपाय नहीं है। इसके अलावा इस बहानेसे प्रतिद्वंद्विताको बढ़ावा देना खतरनाक है, कि इससे वंचितोंका उत्थान होगा। लेटरल एंट्री सकारात्मक काररवाईका साधन नहीं है और कभी नहीं थी। यह विशेषज्ञोंके लिए शासनमें भाग लेनेका एक साधन है जो अन्यथा सरकारमें शामिल होनेपर विचार नहीं करेंगे। सच है, लेटरल एंट्रीकर्त्ता प्रणालीगत बीमारियों और कमियोंके लिए कोई जादुई इलाज नहीं हैं और अधिक मौलिक पुनर्गठनके लिए एक मामला बनाया जा सकता है जो विशिष्ट अवधिके लिए अच्छी तरहसे परिभाषित उद्देश्योंके लिए विशेषज्ञता और विशेषज्ञताके अंतरालको भरनेमें मदद कर सकता है। यूएस, यूके जैसे विकसित देश नियमित रूपसे सरकारके बाहरसे विशेषज्ञोंको नियुक्त करते हैं। हमारे नेताओंको पहचाननेकी जरूरत है कि असमानताएं मौजूद हैं और उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। नौकरियोंमें सिर्फ कोटा होनेसे उत्कृष्टता नहीं मिलेगी। इस दिशामें उन्हें योग्य बनानेके लिए अभिनव तरीके विकसित करनेकी जरूरत है, ताकि वे सामान्य श्रेणीके साथ प्रतिस्पर्धा करनेमें सक्षम हो सकें। समयकी मांग है कि सभीको समान अवसर प्रदान किये जायं। हमें ऐसी व्यवस्थाकी जरूरत है जो न तो पीड़ितोंको दंडित करे और न ही विजेताओंको पुरस्कृत। आरक्षणके सार्वभौमिकरणका मतलब होगा उत्कृष्टता और मानकोंको अलविदा, जो किसी भी आधुनिक राष्ट्रके लिए जरूरी हैं, जो आगे बढ़ना चाहता है। समय आ गया है कि केन्द्र-राज्य सरकारें आरक्षण नीतिपर पुनर्विचार करें और आरक्षणके अंधाधुंध इस्तेमालको रोकें। अन्यथा हम अक्षमता और सामान्यताके जालमें फंस सकते हैं। आरक्षणपर बार-बार जोर देनेसे नुकसान हो सकता है और शायद इससे दरारें और बढ़ेंगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

यूएन में पीएम मोदी की दो टूक

संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साढ़े चार मिनट के भाषण की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। उन्होंने प्रतीकों व प्रतिमानों के जरिये संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत, ग्लोबल साउथ की आवाज और चीन की समुद्री क्षेत्रों में दादागिरी व पाक के आतंकवाद पोषण को बिना नाम लिये उजागर किया। एक मायने में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को उसके मुख्यालय में आईना दिखाया कि विश्व में उभरती शक्तियों को संयुक्त राष्ट्र में न्यायोचित स्थान नहीं मिला। उन्होंने भारत की विशाल जनसंख्या, तेजी से बढ़ती आर्थिक हैसियत तथा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका की जरूरत को बताया। संयुक्त राष्ट्र की ह्यसमिट ऑफ द फ्यूचरह्न में दिया गया प्रधानमंत्री का भाषण पहली नजर में सपाट नजर आता है, लेकिन इसके जरिये दुनिया के बड़े देशों के लिये साफ संदेश निहित था। उन्होंने भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिये सुरक्षा परिषद के लिये दरवाजे बंद करने पर सवाल उठाए। उन्होंने भारत द्वारा सफलता से आयोजित जी-20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को भी नये विश्व की आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। उनका आग्रह था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की आवाज को सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की आबादी के छठवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का जिक्र करते हुए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कैसे देश ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का बखूबी आयोजन किया।दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र की संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे विकास का चेहरा मानवीय होना चाहिए। मानव कल्याण के लिये खाद्य, स्वास्थ्य व सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने भारत में गरीबी से निकाले गए करोड़ों लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि यह समावेशी विकास से ही संभव हुआ। मोदी ने कहा कि हम यह अनुभव ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने को तत्पर हैं। ग्लोबल साउथ का अर्थ विकास की दौड़ में पीछे रह गए वे अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी देश, जिन्हें आर्थिक संबल की जरूरत है। जिनके लिये वर्ष 2023 में भारत ह्यवॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिटह्न का आयोजन कर चुका है। भारत ने अपने अनुभवों का लाभ इन देशों के साथ बांटने में उत्सुकता दिखायी। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि विश्व शांति व विकास के लिये जरूरी है कि वैश्विक संस्थाओं के स्वरूप में सुधार किया जाए। दूसरी शब्दों में कहें कि तो प्रधानमंत्री ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिए जाने की वकालत की है। दूसरी ओर उन्होंने पाकिस्तान व चीन का नाम लिए बगैर साफ किया कि दुनिया की शांति व सुरक्षा के लिये आतंकवाद बड़ा खतरा है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर इसके खिलाफ कार्रवाई की वकालत की।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे पं. दीनदयाल उपाध्याय

डॉ. राकेश मिश्र

जयंती पर विशेष

25 सितंबर 1916 को फरह (मथुरा) में जन्मे पं. दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ को सुदृढ़ करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उद्घोष किया। उनका का नाम लेते ही एक ऐसे व्यक्ति का स्मरण हो आता है, जिनका व्यक्तित्व विराट और संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। भारत की धरती पर महामानव के रूप में अवतरित पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र के सजग प्रहरी व सच्चे राष्ट्र भक्त के रूप में भारतवासियों के प्रेरणास्त्रोत रहेंगे। दीनदयाल जी भारत को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में शिखर पर देखना चाहते थे। वे एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा के सूत्रधार थे, जिसमें राजनीति और सरकार, सेवा का साधन हो। राजनीति में कथनी और करनी में अंतर न रखने वाले इस महामानव ने भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी गहरी आस्था बनाए रखी। व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में भी सिद्धान्त और व्यवहार में समानता रखने वाले इस महान व्यक्तित्व को भी काफी विरोधों का सामना करना पड़ा। लेकिन, राष्ट्रभक्ति जिनका ध्येय हो, समाज का कल्याण जिनका चिंतन हो और ईमानदारी जिसका चरित्र हो, उसे कोई भी ताकत उसके उद्देश्यों से डिगा नहीं सकता है। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, उसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं।

भारतीय राजनीति के महामानव अजातशत्रु दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया।वे भारतीय जनसंघ के निमार्ता थे। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एकात्म मानववाद जैसी विचारधारा दी। उनका मानना था कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है। एकात्म मानववाद की अवधारणा पर आधारित राजनीतिक दर्शन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की देन है। इनके अनुसार एकात्म मानववाद मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एकीकृत कार्यक्रम है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जितने भी आंदोलन हुए उसका एकमात्र ध्येय था स्वतंत्रता की प्राप्ति। लेकिन, स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारी दिशा क्या होगी? हम किस मार्ग से अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकेंगे? कौन सा ऐसा विचार होगा जो हमारे समेकित उन्नयन में सहायक होगा? किस सिद्धांत का निरूपण कर हम व्यष्टि से समष्टि के रूप में अपनी खोई गरिमा प्राप्त कर सकेंगे? क्या होगा वह दर्शन जिसके माध्यम से हम अपनी अधुनातन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रेरित हों एवं साथ ही अपनी महान संस्कृति को भी अक्षुण्ण रख सकें? इसका विचार नहीं किया गया।

कई लोगों ने अलग अलग विचार कर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, लेकिन उन सब पर जितना गंभीर चिंतन होना चाहिए था वह नहीं हो पाया था। ऐसी दिशाहीनता की स्थिति में, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद आदि आयातित वादों से मुक्त होकर एकात्म मानववाद का प्रतिपादन पं.दीनदयाल उपाध्याय ने किया। उन्होंने आधुनिक राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा समाज रचना के लिए एक विचार प्रस्तुत किया। एक ऐसा विचार जिस पर खड़े होकर हम गौरवान्वित महसूस कर सकें।

पं. जी ने बुद्धि, व्यक्ति और समाज, स्वदेश और स्वधर्म, परंपरा तथा संस्कृति जैसे गूढ़ विषयों का चिंतन, मनन एवं गंभीर अध्ययन कर उपरोक्त सिद्धांत का निरूपण किया। जनसंघ के सिद्धांतों एवं नीतियों की रचना की और उन्हीं के शब्दों में विदेशी धारणाओं के प्रतिबिंब पर आधारित मानव संबंधी अपुष्ट विचारों के मुकाबले, विशुद्ध भारतीय विचारों पर आधारित मानव कल्याण का संपूर्ण विचार करके एकात्म मानववाद के रूप में नये सिरे से सूत्रबद्ध किया। इसमें भारतीय संस्कृति की इस विशेषता से अपने को एकाकार किया कि वह संपूर्ण जीवन और संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार का दृष्टिकोण एकात्मवादी है। यह एकात्म विचार न केवल संपूर्ण समाज, सृष्टि या संस्कृति के साथ किया गया, वरन् समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति समेकित उन्नयन का भी दर्शन प्रस्तुत करता है यह सिद्धांत। एकात्म मानववाद इस शास्त्रीय अवधारणा पर आधारित है कि व्यक्ति मन, बुद्धि, आत्मा एवं शरीर का एक समुच्चय है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को आधार बना अंत्योदय को लक्ष्य बनाते हुए श्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर कार्य गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान एवं विकास के लिए कर रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए मोदी सरकार ने योजनाओं और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारा है। युवाओं के कौशल विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण और शासन में पारदर्शिता के साथ ही ईमानदार सरकार देश को मिला है। पं. दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जब तक हम समाज के गरीब-से-गरीब व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचाते, तब तक देश की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। गत आठ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने भी अपनी योजनाओं में इसी बात का ध्यान रखा है और अंत्योदय की विचारधारा को साकार करके दिखाया है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों का सबसे ज्यादा लाभ गरीबों को मिल रहा है। जनधन योजना ने देश के गरीबों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा है तो आयुष्मान भारत में गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता की गई है।

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए नरेंद्र मोदी एक उम्मीद बन चुके हैं। मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत आज आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और नस्लभेद समेत तमाम मुद्दों पर दुनिया को राह दिखा रहा है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत आज पिछड़े व विकासशील देशों की आवाज बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर अन्य वैश्विक मंच, विश्व की ज्वलंत समस्याओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण में ही समाधान के मार्ग तलाश रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि एकात्म मानववाद आज विश्व की बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हर नीति की आत्मा एकात्म मानववाद है। हर कार्यक्रम का ध्येय अंत्योदय है। कोरोना जनित वैश्विक आपदा से लड़ने के लिए साझा सहयोग तंत्र विकसित करने से लेकर आतंकवाद के विरुद्ध पूर्ण असहनशीलता की नीति अपनाकर भारत हर जगह विश्व को एकजुट कर रहा है। पं. दीनदयाल जी का कहना था कि कोई भूखा न सोए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 80 करोड़ जनता को खाद्यान्न उपलब्ध करा कर किसी को भूखा नहीं रहने दिया।

पं. दीनदयाल जी का उद्देश्य था कि कोई अशिक्षित न रहे, मोदी सरकार ने सबको सुलभ और सहज शिक्षा देने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति लाकर हर क्षेत्र और वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा को सुगम किया। इसी तरह कोई बेघर न रहे, इसके लिए भी भाजपा सरकार ने आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया। एकात्म मानववाद को सरल शब्दों में समझने के लिये मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को सरकार का मूलमंत्र बनाया। स्वोयं प्रधानमंत्री न कहलाते हुये प्रधानसेवक का उद्घोष किया किया। ऐसे महामानव श्रद्धेय पं. दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती के अवसर पर नमन करते हुए हम सभी सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लें।

सिखों की सहानुभूति बटोरने में नाकाम रहे राहुल गांधी

योगेन्द्र योगी

(वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और समीक्षक)

राहुल गांधी ने कहा था कि वो अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाने और उनको बेखौफ होकर जीने की आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई इस बात की है कि भारत में सिखों को पगड़ी बांधने में डर न लगे, कड़ा पहनने से कोई न रोके, वे गुरुद्वारों में बेखौफ होकर जा सकें। इसके बाद खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को बिल्कुल सही बताया। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो बात पन्नू भी मानता है। राहुल और उसकी लाइन एक है। राहुल गांधी की खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तारीफ कर दी। पन्नू ने एक बयान जारी करके कहा कि राहुल गांधी ने सिखों के बारे में जो कुछ बोला, उसमें खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' की बात का समर्थन है। बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी की बात को उस सिख नौजवान भलिंदर सिंह ने भी गलत बताया जिसका नाम पूछ कर वॉशिंगटन में राहुल ने भारत में सिखों की स्थिति के बारे में गलतबयानी की थी। भलिंदर सिंह विरमानी ने खुद सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उनका नाम पूछकर सिखों को लेकर जो कमेंट किया, वो पूरी तरह गलत था।

लगातार तीन बार लोकसभा चुनावों में हार के बावजूद कांग्रेस का अल्पसंख्यकों के प्रति मोह कम नहीं हुआ है। कांग्रेस ने लोकसभा सहित चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में तीन में करारी शिकस्त खाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा है। कांग्रेस बयानों के जरिए यह साबित करने पर तुली हुई कि वह सही मायने अल्पसंख्यकों की खैरख्वाह है। ऐसी राजनीति की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी है। दो दशक पहले तक दबे-छिपे तरीके से हिन्दुओं की बात करने वाली भाजपा खुल कर सामने आ गई। इससे देश में हिन्दू-मुस्लिम मतदाताओं का स्पष्ट ध्रुवीकरण नजर आता है। अल्पसंख्यकों की हितैषी साबित करने के लिए कांगेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों की भारत में सुरक्षा को लेकर बयान देकर संगठन को मुश्किल में डाल दिया। पहले मुसलमानों और अब सिक्खों को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस भाजपा के निशाने पर आ गई। राहुल गांधी के बयान से खालिस्तान की मांग करने वाले पृथकतावादी संगठन के प्रमुख गुरुपंत सिंह पन्नू को जहर उगलने का मौका मिल गया।

राहुल गांधी ने कहा था कि वो अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाने और उनको बेखौफ होकर जीने की आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई इस बात की है कि भारत में सिखों को पगड़ी बांधने में डर न लगे, कड़ा पहनने से कोई न रोके, वे गुरुद्वारों में बेखौफ होकर जा सकें। इसके बाद खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को बिल्कुल सही बताया। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो बात पन्नू भी मानता है। राहुल और उसकी लाइन एक है। राहुल गांधी की खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तारीफ कर दी। पन्नू ने एक बयान जारी करके कहा कि राहुल गांधी ने सिखों के बारे में जो कुछ बोला, उसमें खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' की बात का समर्थन है। बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी की बात को उस सिख नौजवान भलिंदर सिंह ने भी गलत बताया जिसका नाम पूछ कर वॉशिंगटन में राहुल ने भारत में सिखों की स्थिति के बारे में गलतबयानी की थी। भलिंदर सिंह विरमानी ने खुद सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उनका नाम पूछकर सिखों को लेकर जो कमेंट किया, वो पूरी तरह गलत था। भलिंदर सिंह ने कहा कि वो खुद भारतीय हैं, कुछ दिनों के लिए अमेरिका आए हैं, उन्होंने भारत में कभी नहीं देखा कि किसी सिख को पगड़ी पहनने या कड़ा पहनने से रोका गया हो या किसी को गुरुद्वारे जाने में कोई दिक्कत हुई हो।

देश में सिक्खों को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर की सर्वे रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित हुई थी। प्यू रिसर्च सेंटर ने यह सर्वे 2019 से 2020 के बीच कराया था। इस सर्वे में महज 14 फीसदी सिखों ने ही माना था कि भारत में सिखों के साथ भेदभाव होता है। मगर अधिकतर सिखों का मानना था कि उन्हें भारत में कोई भेदभाव नहीं दिखता। इस रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 95 फीसदी सिख खुद को भारतीय होने पर बहुत गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, बहुमत यानी 70 फीसदी सिखों का मानना है कि जो व्यक्ति भारत का अनादर करता है, वो सिख हो ही नहीं सकता।

वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने दुनिया भर में भारत-विरोधी प्रचार करने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। इल्हान उमर डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं, वो खुले तौर पर पाकिस्तान की हिमायती हैं, हर मंच पर भारत का विरोध करती हैं। राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों के जिस प्रतिनिधिमंडल से मिले, उसमें इल्हान उमर को खासतौर पर बुलाया गया था। इल्हान उमर वही हैं, जिन्होंने 2022 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर कहा था कि कश्मीर पर भारत का कोई हक नहीं है, भारत को कश्मीर छोड?ा ही पड़ेगा। जून 2023 में इल्हान उमर अमेरिका की संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई थीं, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्रालय से अपील की गई थी कि वह भारत को एक ऐसा देश घोषित करे जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है, जहां मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान समर्थक इल्हान उमर से क्यों मिले? इल्हान तो हमेशा से भारत के खिलाफ रही हैं। कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना है। अनुच्छेद 370 पर राहुल गांधी का ढुलमुल रवैया रहा है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पार्टी नेताओं का फीडबैक लेने पहुंचे थे, तब भी वे अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर साइलेंट मोड में दिखे थे। हालांकि कांग्रेस जिस दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही उसका इस मुद्दे पर मत कुछ अलग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली की जाएगी। हालांकि नेशनल कांफ्रेंस किस आधार पर अनुच्छेद 370 की वापसी की बात कर रही है वो समझ से परे है। क्योंकि यह साधारण सी बात है कि केंद्र में सत्ता मिलने पर ही अनुच्छेद 370 की वापसी संभव हो सकती है। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को केंद्र में बहुमत नहीं मिलने जा रहा है।

धारा 370 की तरह सीएए पर भी राहुल गांधी का रुख बदलता रहा है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया। कांग्रेस ने दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। जिसमें सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी सहित सैकड़ों पार्टी समर्थक राजघाट पर सत्याग्रह पर बैठे थे। लेकिन सीएए लागू होने के बाद चुनावों को देखते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली थी। लोकसभा चुनावों के दौरान केरल में सीएए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चुनाव अभियान के दौरान लगातार यह साबित करने में लगे रहे कि राहुल गांधी सीएए पर क्यों नहीं बोल रहे हैं।

कांग्रेस और राहुल गांधी ने मौके-बेमौके अल्पसंख्यकों को लेकर गहरी चिंता जताई है, किन्तु कांग्रेस शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के भले के लिए क्या अतिरिक्त प्रयास किए गए, इसका खुलासा कभी नहीं किया गया। तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार का जमकर विरोध किया। जबकि तीन तलाक के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे लागू करने का निर्णय लिया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक माफिया और गैंगस्टरों के मामलों में भी कांग्रेस का रवैया सहानुभूतिपूर्ण रहा है। इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी ने तो खुलकर इन गैंगस्टर्स का खुलकर समर्थन ही नहीं किया बल्कि सत्ता में रहने के दौरान बहुजन समाज पार्टी और सपा ने मंत्री पद तक के ओहदे से नवाजा था। कांग्रेस को यह समझना होगा कि क्षेत्रीय दलों का जनाधार सीमित है, जबकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल होने के साथ राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को रिझाने की राजनीति से भाजपा को ध्रुवीकरण का मौका मिलता रहेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना राष्ट्रद्रोह के समान

जिन्हें रेलवे ट्रैक की रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी जाए वे ही ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश में शामिल हो जाएं तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? गुजरात में किम और कोसांबा स्टेशनों के बीच रेल पटरी को नुकसान पहुंचाने के मामले में यह चिंताजनक खुलासा हुआ है कि पदोन्नति, पुरस्कार और रात्रि ड्यूटी पाने की चाहत में रेलवे ट्रैक की रखवाली करने वाले ट्रैकमैन ने ही यह साजिश रची थी। इस मामले में तीन ट्रैकमैन गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली-मुम्बई मार्ग पर मध्यप्रदेश में डेटोनेटर चोरी कर रेलवे ट्रैक पर रखने के आरोप में भी रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे के ट्रैक पेट्रोलिंग ड्यूटी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।

रेलवे संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। दोनों ही मामले आपराधिक कृत्य तो हैं ही, यह भी बताते हैं कि आज के दौर में कोई भी किसी भी हद तक गिर सकता है। गुजरात की घटना की प्रारंभिक जांच में इस प्रकरण में तीनों कर्मचारियों की भूमिका की पुष्टि करने वाले तथ्य भी सामने आ गए हैं। यह गनीमत रही कि दोनों ही मामले समय रहते सामने आ गए वरना सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि दिमाग में आए ऐसे फितूर के नतीजे कितने भयावह हो सकते थे। देश के अन्य हिस्सों में भी अलग-अलग तरीकों से रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं पिछले दिनों में सामने आई हैं। कुछ घटनाएं बड़े हादसों की वजह भी बनी हैं। गुजरात के इस मामले में घटना से जुड़े जो प्रारंभिक अनुमान हैं वे आरोपियों से पूछताछ व वीडियो साक्ष्य के आधार पर हैं। पड़ताल का विषय यह अवश्य होना चाहिए कि सिर्फ पुरस्कार व प्रमोशन ही इरादा रहा या यह कोई षडयंत्र का हिस्सा था। डेटोनेटर रेलवे पटरी पर रखने जैसी साजिश में रेलवे कार्मिक का ही शामिल होना तो और भी चिंताजनक है। ऐसे कार्मिकों को रेलवे कार्यबल का हिस्सा भला क्यों रहना चाहिए? सीधे तौर पर ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना राष्ट्रद्रोह जैसा है।

अहम बात रेल पटरियों की सुरक्षा से जुड़ी है। ट्रैक की फिश प्लेट निकालने जैसी घटनाओं को ट्रैक की नियमित निगरानी और तकनीकी उपायों जैसे सेंसर, ड्रोन निगरानी व सीसीटीवी कैमरों की मदद से रोका जा सकता है। समाजकंटकों की पिछली हरकतों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बलों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। संदिग्ध लोगों पर जनसाधारण को भी नजर रखनी होगी। यह भी समझना होगा कि समाज को नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ उसी समाज में नाम कमाने की चाहत कभी सुखद और सार्थक परिणाम नहीं दे सकती।

कानून में हो बदलाव: क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे सरकार के साथ-साथ आदिवासियों की भी आमदनी हो

आदिवासी सम्मान में बने राष्ट्रीय महुआ शराब नीति

शुभ्रांशु चौधरी
आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता
@patrika.com

कुछ राज्यों में महुआ शराब को लेकर अच्छे प्रयास हुए हैं। मध्यप्रदेश ने पिछले साल महुआ को हेरिटेज ड्रिंक घोषित कर आदिवासी सहकारिता समूहों को यह बेचने की अनुमति दी थी, पर यह अब भी उन राज्यों में नहीं बेची जा सकती जहां कानून नहीं बदला है इसलिए एक राष्ट्रीय कानून जरूरी है।

आज से 150 साल पहले अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि अगर गैर-आदिवासी लोग भी महुए की शराब पीने लगे तो भारत में अंग्रेजी शराब की बिक्री कम हो जाएगी और उन्होंने 1878 में बॉम्बे आबकारी एक्ट बनाकर महुए के फूल को इकट्ठा करने और उससे शराब बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। 1892 में महोड़ा एक्ट बनाकर अंग्रेजों ने उस पाबंदी को और मजबूत किया था। आज देश में ही बनी अंग्रेजी शराब का बड़ा व्यापार है। कई राज्य अपनी आमदनी का 15-20 प्रतिशत आबकारी टैक्स से कमाते हैं। कई मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री जैसे ताकतवर लोग इस विषय से जुड़े कथित घोटालों में जेल में हैं या थे, और कुछ के खिलाफ मामले चल रहे हैं। पर हम चर्चा महुए की शराब की करना चाहते हैं।

छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज के नेता अरविन्द नेताम बताते हैं कि 70 के दशक में जब वे इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में शामिल थे तब एक दिन इंदिरा गांधी को आदिवासियों के जीवन में महुए का महत्त्व समझाया था 'और फिर इंदिरा जी ने नया कानून बनवाकर आदिवासियों के लिए महुआ बीनने व अपने उपयोग के लिए शराब बनाने से पाबंदी हटवा दी थी।' आदिवासी सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का कोई भी काम महुए की शराब के बिना नहीं होता है।

आदिवासियों के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा बेहद जरूरी है। इस जीवन में महुआ शराब एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, यदि थोड़ा सोच-समझकर एक कानून बनाया जाए। महुए की शराब बेचने पर 150 साल पहले अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदी आज भी लगभग वैसे ही लागू है। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। (यद्यपि नमक पर लागू उस टैक्स को नेहरू ने हटाया)। अंग्रेजों ने रुई और कपड़े पर भी पाबंदी लगाई थी जिससे इंग्लैंड में बना कपड़ा यहां बिक सके। इंदिरा गांधी के बनाए कानून के बाद महुए की शराब अधिकाधिक आदिवासियों के घर में बनती है। गैर-कानूनी रूप से यह लगभग हर आदिवासी हाट में बिकती भी है पर इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग वाले आदिवासियों को अक्सर परेशान करते हैं। आजकल शहरों में भी अवैध एमडी (महुआ दारू) धड़ल्ले से बिकती है पर उससे सरकार को कोई आमदनी नहीं होती।

क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे सरकार के साथ-साथ आदिवासियों की भी आमदनी हो? गुजरात से अमूल (आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड) का उदाहरण हमारे सामने है जहां घर-घर से दूध इकट्ठा कर देश-विदेश में बेचने का एक सफल प्रयोग किया गया। आजादी के पहले 1946 में यह प्रयोग शुरू हुआ था जब दूध बेचने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी पर किसानों को दूध का सही दाम नहीं मिलता था। वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई जैसे लोगों ने इस यूनियन को शुरू करने में मदद की थी जिसने आजादी के बाद वर्गीज कुरियन को मैनेजर नियुक्त किया। इसके बाद अमूल ने इतिहास रचा, जिसके बारे में सब जानते हैं। क्या दूध की तरह महुआ का भी प्रयोग किया जा सकता है? संभव है कि महुआ आदिवासी सहकारिता समूह को भी एक योग्य मैनेजर की जरूरत पड़े लेकिन इसके पहले इस विषय पर कानून बदलने में क्या केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय या नीति आयोग पहल कर सकता है?

हाल ही में कुछ राज्यों जैसे मध्यप्रदेश में महुआ शराब को लेकर अच्छे प्रयास हुए हैं। पिछले साल मध्यप्रदेश ने महुआ को हेरिटेज ड्रिंक घोषित कर आदिवासी सहकारिता समूहों को महुआ शराब बनाकर राज्य में बेचने की अनुमति दी। पर ये शराब अब भी देश के अन्य राज्यों में नहीं बेची जा सकती जहां कानून नहीं बदला है इसलिए पहले इस विषय पर एक राष्ट्रीय कानून की जरूरत है।

विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि महुआ शराब पर टैक्स कम हो तो यह भविष्य में शराब बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकती है। इस दिशा में कई तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। महुआ शराब की 'शेल्फ लाइफ' बढ़ानी होगी। क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग और प्रमोशन आदि के लिए भी विशेषज्ञों को काम पर लगाना होगा। सहकारिता मंत्रालय इसमें प्रारम्भिक मदद कर सकता है जैसा उन्होंने अमूल के लिए किया था। गुजरात में अमूल का प्रयोग हुआ था पर वहां शराब पर पाबंदी है। शराबबंदी एक जटिल विषय है। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज के एक प्रमुख ने महुआ शराब बनाने पर पाबंदी हटवाई पर उसी समाज के दूसरे प्रमुख और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नन्द कुमार साय ने महुआ शराब का विरोध करने के लिए कई दशकों से नमक नहीं खाया है। वह बताते हैं, 'जब मैं अपनी सामाजिक बैठकों में महुआ शराब का विरोध करता था तो एक दिन किसी ने कहा यदि आप नमक खाना छोड़ दोगे तो हम महुआ छोड़ देंगे। तो उसके बाद से मैंने नमक नहीं खाया।' छत्तीसगढ़ के गैर-आदिवासी इलाकों में भी शराबबंदी के लिए खासकर महिलाओं के बड़े आंदोलन हुए हैं, हो रहे हैं। पर जहां तक आदिवासी समाज का प्रश्न है बहुत से घरों में आज महुआ शराब बनती है। पूजा-पाठ के अलावा मेहमानों को भी इसकी पेशकश की जाती है। आर्थिक लाभ वे ही ले पाते हैं जो गैर-कानूनी रूप से इसे बेचते हैं। महुआ की तरह हर आदिवासी इलाके में माइनिंग भी होता है। जैसे नो-माइनिंग एक अवास्तविक मांग है, वैसे ही शराबबंदी भी। कॉर्पोरेट माइनिंग से आदिवासियों को नुकसान अधिक और फायदा कम हुआ। क्या सहकारिता वाली महुआ नीति से हर आदिवासी महिला का सशक्तीकरण नहीं होगा? छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में सरकारों को माइनिंग के बाद आबकारी टैक्स से ही सर्वाधिक आय होती है। पर यदि किसी बड़ी कंपनी को बस्तर में महुआ शराब की बड़ी डिस्टलरी लगाकर बेचने की नीति बनेगी तो आदिवासियों को माइनिंग की ही तरह अधिक फायदा नहीं होगा। अंग्रेजों ने आते ही आदिवासियों से जंगल छीन लिए थे, जिसके बाद देशभर में विद्रोह भी हुए थे।

हाल में केन्द्रीय गृहमंत्री ने वामपंथी उग्रवाद पर हुई एक बैठक में रायपुर में कहा कि अगले कुछ माह में तेंदूपत्ता नीति में परिवर्तन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता 850 करोड़ का व्यापार है, जबकि महुआ शराब इससे कई गुना बड़ा व्यापार हो सकता है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, पर उनके बाद किसी ने भी महुए पर ध्यान नहीं दिया। 2005 का वनाधिकार कानून 'ऐतिहासिक गलती' को ठीक करता हुआ आदिवासियों को जंगल वापस देने का प्रयास करता है वैसे ही नया महुआ कानून 'आदिवासियों की उपेक्षा' को ठीक करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है। महुए का सम्मान आदिवासी का सम्मान होगा। सहकारिता वाला महुआ उद्योग माओवादी हिंसा से लड़ाई में भी मदद करेगा।

फैक्ट फ्रंट

बार-हेडेड गूज

बार-हेडेड गूज दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। वे सर्दियों में पाकिस्तान, भारत और म्यांमार सहित दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में रहते हैं। ये पक्षी आकार में काफी बड़े होते हैं। उनकी लंबाई 70 से 75 सेमी और वजन 2 से 3 किलोग्राम होता है। पंखों का फैलाव 140 से 160 सेमी होता है। वे हल्के भूरे रंग के होते हैं,

उनके सिर पर धारियां होती हैं। इनके पैर नारंगी रंग के होते हैं। ये पक्षी मुख्य रूप से घास, जड़ों और तनों से अपनी भूख मिटाते हैं। वे मई और जून के दौरान प्रजनन करते हैं। मादा जमीन पर बने घोंसले में तीन से आठ अंडे देती है।

प्रिज्मैटिक स्प्रिंग: यूएस का सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना

अमरीकी राज्य व्योमिंग के येलोस्टोन नेशनल पार्क में यह है यूएस का सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना ग्रैंड प्रिज्मैटिक स्प्रिंग। न्यूजीलैंड की फ्राइंग पैन झील और डोमिनिका की बॉयलिंग झील के बाद दुनिया में ग्रैंड प्रिज्मैटिक स्प्रिंग तीसरे स्थान पर है। यह मिडवे गीजर बेसिन में स्थित है, जो कि फायरहोल नदी के किनारे पाए जाने वाले अन्य बेसिनों की तुलना में हालांकि बहुत छोटा है, पर छोटे आकार के बावजूद जिन विशेषताओं के लिए जाना जाता है, उनमें 370 फुट चौड़ा और 121 फुट गहरा ग्रैंड प्रिज्मैटिक स्प्रिंग भी शामिल है। मिडवे गीजर बेसिन में एक्सेलसियर गीजर, फिरोजी पूल और ओपल पूल भी हैं। ग्रैंड प्रिज्मैटिक स्प्रिंग को 1871 के हेडन जियोलॉजिकल सर्वे में काम करने वाले भूवैज्ञानिकों ने देखा था, और इसके आकर्षक रंग के कारण उन्होंने इसका नाम रखा था। इसके रंग ऑप्टिकल प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के इंद्रधनुषी फैलाव में देखे जाने वाले अधिकांश रंगों से मिलते हैं, जैसे कि लाल, नारंगी, पीला, हरा और नीला।

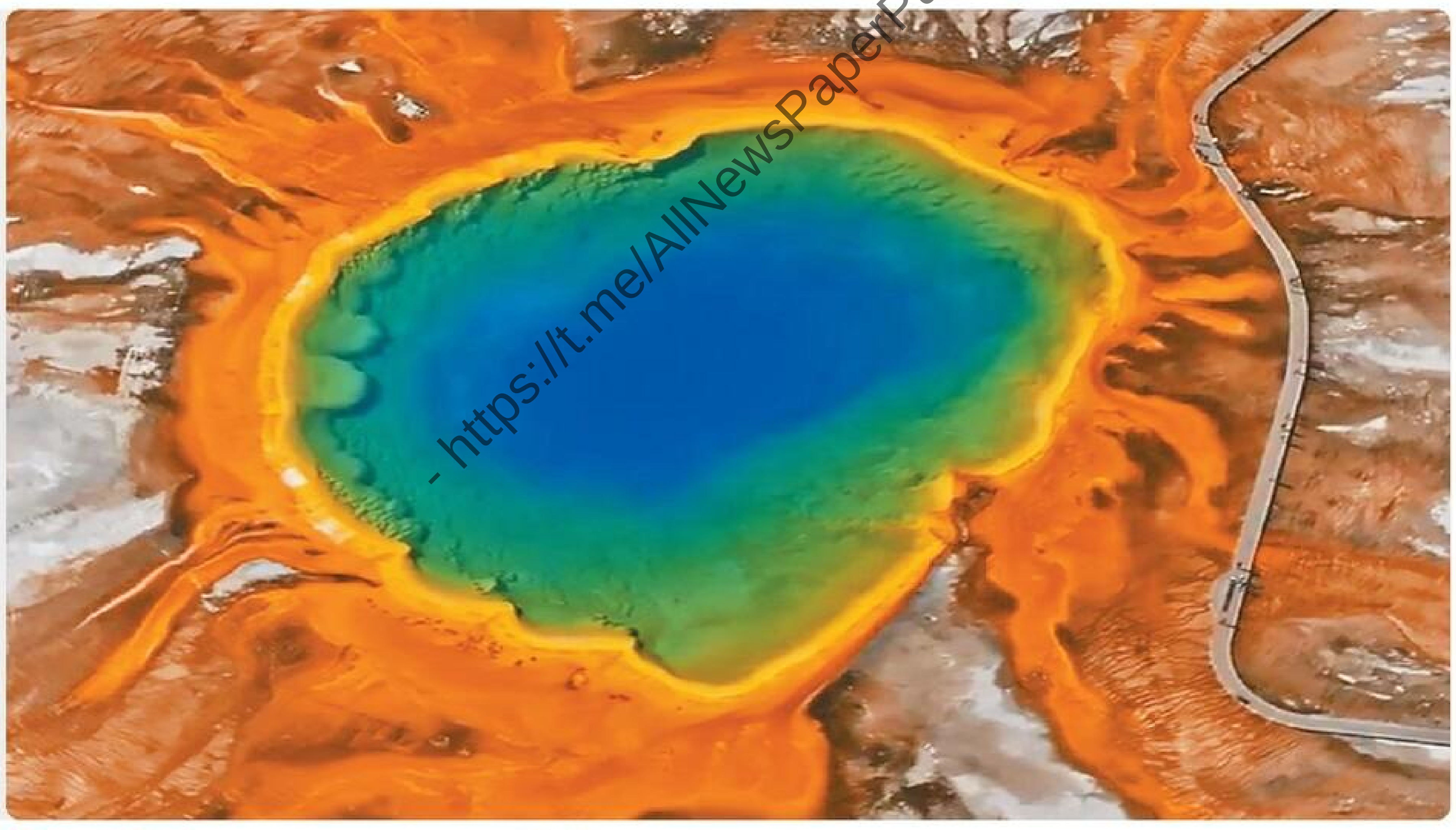

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रसंगवश

कोरी खानापूर्ति न हो मिलावट के खिलाफ सरकारी अभियान में

जांच की कार्रवाई ही इतनी खिंच जाती है कि मिलावट साबित होने तक अशुद्ध उत्पाद बाजार में खप जाते हैं

इन दिनों प्रदेश में खाद्य विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ सक्रिय है। ऐसी सक्रियता होनी भी चाहिए। भगवान के प्रसाद में ही मिलवट की खबरों के बीच जब सेहत से खिलवाड़ करते मिलावटी व दूषित खाद्य पदार्थ के मामले सामने आते हैं तो आम आदमी का विचलित होना स्वाभाविक ही है। मुश्किल यह है कि हमारे यहां चलन सा हो गया है कि जोर-शोर से मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तो चलता है, लेकिन किसे सजा हुई इसकी कभी जानकारी होती ही नहीं। मिलावटखोरी रोकने की खाद्य विभाग और चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी है। जब पूरी ताकत लगाकर कार्रवाई नहीं होगी तो मिलावटखोर तो और 'सेहतमंद' हो ही जाएंगे, वह भी उपभोक्ताओं की सेहत की कीमत पर। मिलावट के मामलों में जांच की कार्रवाई ही इतनी लंबी खिंच जाती है कि जब तक मिलावट साबित होती है, अशुद्ध उत्पाद बाजार में खप जाते हैं।

अब तक के अनुभव बताते हैं कि मिलावट की आशंका पर सेम्पल लेकर तो भेज दिए जाते हैं, लेकिन नतीजे आने में ही काफी समय लग जाता है। ज्यादा ही हुआ तो जुर्माने की खानापूर्ति कर दी जाती है। हैरत की बात यह है कि जो उपभोक्ता मिलावट से परेशान हैं, उनके पास खाद्य उत्पादों की जांच का कोई साधन ही नहीं। न ही संबंधित महकमे लोगों को इस संबंध में जागरूक करने का प्रयास करते कि वे किस तरह से मिलावट का पता लगा सकते हैं।

करीब एक दशक पहले प्रदेश में मोबाइल प्रयोगशालाओं के जरिए कुछ उत्पादों की शुद्धता हाथों-हाथ जांचने का बंदोबस्त किया गया था। मकसद यही था कि उपभोक्ता को उसके दरवाजे पर ही उत्पाद की शुद्धता परखने का मौका मिले। न जाने किसका दबाव रहा कि ये मोबाइल प्रयोगशालाएं ही बंद हो गईं। उपभोक्ता भी इस बात की चर्चा रोज करता है कि हर चीज में मिलावट होती जा रही है, लेकिन मिलावट की जांच अपने स्तर पर ही करने का प्रयास नहीं करता। यदि उपभोक्ताओं को ही उपकरण उपलब्ध करा प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो मसालों, घी, दूध और दुग्ध उत्पादों की शुद्धता जांचने का काम आसानी से हो सकता है। जब तक मिलावट के बाजार पर अंकुश की डोर खुद उपभोक्ता के हाथ में में नहीं थमाई जाएगी मिलावटखोरों की सक्रियता बनी रहेगी, क्योंकि चांदी की खनक के आगे नकली को असली बनाने का काम आसानी से होता आया है। - रतन दवे

ratan.dave@in.patrika.com

पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विशेष

जिन्होंने पद और कद की बजाय विचारधारा को माना सर्वोपरि

राजेन्द्र गहलोत
राज्यसभा सदस्य, भाजपा
@patrika.com

सत्तावन साल पहले कालीकट में हुए जनसंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र में पार्टी अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते हुए अपने पहले उद्बोधन में कहा था कि 'हम किसी समुदाय विशेष नहीं, बल्कि पूरे देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक प्रत्येक भारतवासी को उसका गौरव नहीं दिला देते।' कालीकट में इन शब्दों का उच्चारण करने वाले कोई और नहीं बल्कि जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। उपाध्याय अपने सपने को साकार कर पाते उससे पहले ही 51 साल की आयु में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। जनसंघ के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। उपाध्याय न सिर्फ जनसंघ के बड़े नेता थे बल्कि उनकी गिनती एक पत्रकार, लेखक, विचारक और दार्शनिक के रूप में होती थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1937 में स्वयंसेवक बनने के बाद से उपाध्याय सबसे पिछली पंक्ति में खड़े मानव को आगे लाने के अनुष्ठान में लगे हुए थे। उपाध्याय ने 'राष्ट्र प्रथम' का सिद्धांत प्रेरित किया। एकात्म मानववाद, रामराज्य और अंत्योदय उनके जीवन के आधार बन चुके थे। हर हाथ को काम और हर खेत को पानी उनके राजनीतिक जीवन का लक्ष्य था। वे ऐसी व्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें सामाजिक असमानता का आवरण न चढ़ा हो। उनका जीवन जितना सादा था, उनके विचार उतने ही ऊंचे थे। सत्ता परिवर्तन की बजाय वे व्यवस्था परिवर्तन के पक्षधर थे। 25 सितंबर 1916 को जन्मे उपाध्याय को बिछुड़े 56 वर्ष हो चुके हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के करोड़ों लोगों के लिए उनके विचार आज भी प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। उनका विश्वास पाने में नहीं बल्कि देने में था। चाहते तो उपाध्याय भी सांसद बन सकते थे लेकिन उन्होंने संगठन को हमेशा सत्ता से बड़ा माना। जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में भले सिर्फ डेढ़ महीने आसीन रहे हों, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी कार्यशैली ने भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को नई सोच भी दी और नई ऊर्जा भी। इसी ऊर्जा के सहारे दो से तीन सौ सांसदों का सफर पार्टी तय कर पाई। भारतीय जनता पार्टी कैसे अन्य दलों को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गई? ऐसे सवालों ने राजनीतिक विश्लेषकों के साथ भारतीय जनमानस को लंबे समय तक चिंतन करने पर मजबूर किया है।

पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे जनमानस में अपना स्थान बनाती गई। कह सकते हैं जनसंघ - भाजपा के प्रभावी नेताओं ने जनमानस में इसकी पहचान बनाई। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेई, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, सुंदर सिंह भंडारी और फिर नरेन्द्र मोदी के रूप में मिले नेताओं ने पार्टी को देश के जनमानस तक पहुंचाया। इन सभी नेताओं के प्रेरणास्रोत उपाध्याय ही रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण में उपाध्याय के विचारों का समावेश हमेशा रहा। उपाध्याय राजनीति में 'मैं' की बजाय 'हम' को प्राथमिकता देते थे। उनका मत था कि किसी भी मुद्दे पर सामूहिक चिंतन के बाद लिया गया फैसला अधिक सार्थक होगा। उपाध्याय की सामूहिक निर्णय एवं चिंतन की नीति पर चलते हुए पार्टी ने अपने संस्थापक सदस्यों में से एक एवं जनसंघ के अध्यक्ष रहे बलराज मधोक को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। भाजपा को छोड़कर अधिकतर राजनीतिक दलों में लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है जिसका मुख्य कारण उन दलों में सामूहिक निर्णय की बजाय व्यक्तिगत निर्णयों को प्राथमिकता देना है। उपाध्याय का मानना था कि आंतरिक लोकतंत्र के बिना देश में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उपाध्याय का साफ मत था कि राजनेताओं को पद और कद की चिंता करने की बजाय विचारधारा के प्रति समर्पित भावना से काम करना चाहिए।

अमरीकी चुनाव: प्रजनन अधिकारों का मुद्दा हैरिस का मजबूत पक्ष

आर्थिक नीति पर अर्थ की तलाश के सच से दो-चार डेमोक्रेट्स

मैट बाइ
स्तम्भकार व स्क्रीनराइटर
दवाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

नवीनतम सर्वेक्षणों में कमला हैरिस ने खुद को डॉनल्ड ट्रंप पर केवल मामूली बढ़त लेते हुए और सबसे महत्त्वपूर्ण राज्यों में प्रभावी रूप से बराबरी पर पाया है, जबकि एक कन्वेंशन भाषण के बाद डेमोक्रेट्स के बीच इसी बात की चर्चा थी कि कैसे उन्होंने दौड़ पर काबू पा लिया है। पर अब डेमोक्रेट्स पतन के उस चरण में पहुंच गए हैं जहां वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। कभी वे उन मतदाताओं पर क्रोधित होते हैं जो उनकी नजर में दिमागी रूप से मृत या नस्लवादी हैं, तो कभी एक समाचार मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हैं यह स्पष्ट न करने के लिए कि ट्रंप कितना भयानक है, जबकि समूचा अमरीकी मीडिया केवल इस बारे में ही बात कर रहा है कि ट्रंप कितना भयानक है।

एक कदम पीछे हटने का यह अच्छा क्षण है। वजह, डेमोक्रेट्स के सामने कुछ तीखी वास्तविकताएं सामने आ रही हैं पर सोचने की एक वजह यह भी है कि आप अभी भी ट्रंप के बजाय हैरिस का समर्थक बनना पसंद करेंगे। जहां तक वास्तविकता का सवाल है तो समीक्षा करनी चाहिए कि हम इस बिंदु तक कैसे पहुंचे। पिछले कम से कम 18 महीनों से, अग्रणी डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति बाइडन को फिर से राष्ट्रपति बनाने को लेकर एकजुट थे। हालांकि, वे यह मानते थे कि यह जोखिम भरा प्रयास है और ज्यादातर ने यह अनुमान लगा लिया था कि हैरिस एक विकल्प हैं और वे सभी निश्चित थे कि वह हार जाएंगी। इसलिए नहीं कि वे अश्वेत महिला हैं या फिर उपराष्ट्रपति का पद हर किसी को शक्तिहीन बना देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके बारे में माना गया था कि उनमें राजनीतिक कौशल या स्पष्ट दृढ़ विश्वास की कमी है। कमला हैरिस के नामांकन हासिल करने के बाद उनका ग्राफ बढ़ा और उन्होंने कन्वेंशन में बहुत अच्छा भाषण दिया तो उन्हीं डेमोक्रेट्स ने तुरंत ही ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि वे किसी 'मस्तिष्क आघात परीक्षण' में विफल हो गए हों और उन्हें एक दिन पहले का कुछ भी याद न हो। अचानक ही, हैरिस मात्र पर्याप्त बैकअप के रूप में नहीं थीं, बल्कि वह बहुत प्रभावशाली और प्रेरणादायक बन गई थीं, एक ऐसी उम्मीदवार जिन्हें उदार रूढ़िवादी और स्वतंत्र मतदाता नकार नहीं सकते थे। हैरिस ने आश्चर्यजनक रूप से ठोस अभियान चलाया है - अनुशासित, उत्साहित और स्वाभाविक त्रुटियों से मुक्त। इसके लिए उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए। पर वह सावधान, वैचारिक रूप से अपरिभाषित और घिसी-पिटी बातों से बंधी रहती हैं। कैलिफोर्निया में एक शानदार उम्मीदवार के तौर पर भले ही कौशल उनके पास है पर राष्ट्रपति पद की दौड़ और राष्ट्र की जनता को एजेंडा बेचना अलग बात है। उदाहरण के लिए, पिछले सप्ताह उन्होंने अश्वेत पत्रकारों को इंटरव्यू दिया। उन्होंने रुक-रुक कर अपनी आर्थिक नीतियों का सारांश पेश किया, जो अर्थहीन बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं था। हैरिस चुनाव अभियान के अंतिम छह सप्ताह में ट्रंप के मुकाबले वास्तविक लाभ हासिल कर रही हैं, फिर भी उनसे आर्थिक मोर्चे पर अधिक स्पष्ट नीति संबंधी बयानों की अपेक्षा की जा रही है।

ट्रंप ने 2016 में ही चुनाव जीता, जब वह एक ऐसे अज्ञात व्यक्ति थे जिन पर मतदाता सभी तरह की संभावनाओं का अनुमान लगा सकते थे। पर तब भी ट्रंप लोकप्रिय वोट नहीं जीत पाए थे। 2020 में बाइडन ने ट्रंप को 7 मिलियन वोटों और इलेक्टोरल कॉलेज में 74 वोटों से हराया था। कई राज्यों में मामूली अंतर का मतलब था कि नतीजा पलट भी सकता था। इस बार के लिए भी सच यही है। प्रजनन अधिकारों के मुद्दे पर हैरिस लाभ की स्थिति में हैं, पर रिपब्लिकंस ने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सुविधाओं की बात कर खेल बिगाड़ने की कोशिश की है। महिलाओं के बीच हैरिस, ट्रंप से 10 अंकों से ज्यादा आगे हैं। हाल में वह श्वेत महिलाओं के बीच बढ़त हासिल करती दिख रही हैं जबकि श्वेत पुरुष उनसे दूर हो रहे हैं। जाहिर है कि नए मतदाताओं को प्रेरित और राज्यों को प्रभावित करने की क्षमता इसी मुद्दे में है।

आपकी बात

टारगेट पूरा करने का दबाव

निजी सेक्टर में कंपनियां कर्मचारियों को क्षमता से ज्यादा टारगेट देती हैं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए दबाव बनाती हैं। ओवरटाइम का दबाव भी रहता है।
-लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़

आज का सवाल

ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहे सट्टे को रोका क्यों नहीं जा रहा?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'काम के दबाव के कारण मौत के मामले कैसे रोके जा सकते हैं?' ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/66NoF

प्रेरणा
उन बातों से त्रस्त नहीं हों, जो अभी हुई ही नहीं हैं।
- शुनम्यो मसुनो, ज़ेन बौद्ध भिक्षु

संपादकीय
संस्थाएं सामाजिक चेतना फैलाने का काम भी करें

गवर्नेंस का कोई भी तंत्र रहा हो, कबायली व्यवस्था से लेकर लोकतंत्र तक, लेकिन निरंतर बदलते समाज में नैतिक मूल्य बनाए रखने का काम आध्यात्मिक व धार्मिक रूप से समुन्नत लोगों का रहा है। प्रजातंत्र में राजनीति वोट की याचक होती है और ऐसी याचना में समाज-सुधार करने की नैतिक शक्ति नहीं होती। धार्मिक संस्थाओं के भी अपने हित होते हैं। ऐसे में जो भी सबसे स्वीकार्य संस्था या उसमें लगा व्यक्ति समाज की निःस्वार्थ सेवा करता है वह समाज सुधारक की भूमिका में स्वतः आ जाता है। नैतिकता में गिरावट का संकट मोबाइल फोन के बाद का है। बाल-यौन शोषण पश्चिमी देशों से भारत पहुंचा है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को समाज-सुधारक की भूमिका में आना पड़ा। कोर्ट ने इस सामाजिक-मानसिक बीमारी के इलाज के लिए देश के सभी कोर्ट्स द्वारा 'चाइल्ड पोर्न' शब्द के प्रयोग पर ही रोक लगा दी है और इसकी जगह 'बाल-यौन उत्पीड़न सामग्री' (सीएसईएएम) का प्रयोग करने को कहा है। कोर्ट ने ऐसे वीडियोज देखना 'पॉक्सो' के तहत सजा की श्रेणी में रखा है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ही महिला अधिकार, दहेज व फौरी तलाक सरीखे मुद्दों पर समाज में नई चेतना पैदा की थी। देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को भी चेतना फैलाने का काम करना चाहिए।

जीने की राह
पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

जिस गुण की जरूरत हो उसे जीवन में उतारा जाए

जब से हमारा जीवन डिजिटल हुआ है, हम बहुत सारी बातों की जानकारी आंकड़ों में रखने लग गए हैं। उसके फायदे भी हुए हैं। तीन का आंकड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे त्रिदेव हैं- ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विज्ञान ने भी ट्रिनिटी पर बहुत काम किया है। फिर हमारे यहां त्रिगुण की भी व्यवस्था है। एक मनुष्य का जीवन तीन गुणों से संचालित होता है- सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें से जो भी गुण अधिक होगा, मनुष्य वैसा आचरण करने लगता है। और सामान्य तौर पर किसी भी मनुष्य को उम्र के तीन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। अगर इन तीन के आंकड़े को हम ठीक से समझें और यह जान जाएं कि किस का कब, कैसे उपयोग करना है, तो मनुष्य जीवन बड़ा सरल और आनंददायक हो जाएगा। एक आंकड़ा और महत्वपूर्ण है, उसमें भी तीन की संख्या है- माता, पिता और हम, यानी संतान। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि जब जिस उम्र की, जिस रिश्ते की, जिस गुण की और जिस देवता की जरूरत हो, उसे जीवन में उतारा जाए।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नजरिया • 'आप' की छवि को फिर से सुधारना होगा
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं

सियासत
आरती जेरथ
राजनीतिक टिप्पणीकार
aratijerath@gamil.com

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। चुनाव में पांच महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में उनके सामने 'आप' की सरकार को बचाने की कठिन चुनौती है, जबकि भाजपा आक्रामक प्रचार-अभियान चला रही है। 43 साल की आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और इस पद पर आसीन होने वाली तीसरी महिला हैं। उनके सामने पहली चुनौती पार्टी की छवि को फिर से स्थापित करना है। भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा के रूप में 'आप' की छवि को तब से झटका लगा है, जब से ईडी और सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी कोर टीम की जांच शुरू की है।

पिछले डेढ़ साल में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अंत में खुद अरविंद केजरीवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं के एक-एक करके जेल जाने से पार्टी की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे हैं। आतिशी को एक साफ छवि वाली शख्सियत के रूप में देखा जाता है। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि अगले साल चुनाव से पहले उनकी सरकार पर किसी तरह के घोटाले की बू न आए। चूंकि भाजपा चुनावी-मोड में है और दिल्ली पर पैनी नजर बनाए हुए है, इसलिए उन्हें अपने निर्णयों, फाइल नोटिंग और सार्वजनिक व्यवहार में खासी सतर्कता बरतनी होगी।

उनके लिए दूसरी चुनौती 'आप' के 'दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस' को फिर से पटरी पर लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस' के विकल्प के रूप में इसे विकसित किया गया था। पिछले कई महीनों में 'आप' के रिकॉर्ड में गिरावट आई है। एक तरफ, 'आप' को ईडी और सीबीआई के छापों और पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिससे सरकार और पार्टी दोनों का मनोबल टूट गया। दूसरी ओर, सीएम कार्यालय को एलजी के साथ अनवरत टकराव की स्थिति में पाया गया, खासकर 2023 के संवैधानिक संशोधन के बाद, जिसने एलजी को दिल्ली-प्रशासन के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान कर दी थीं। वास्तव में, इस संशोधन ने समय को पीछे मोड़ दिया और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जैसी स्थिति में वापस आ गई।

एलजी के साथ बढ़ते टकरावों ने केजरीवाल सरकार को लगभग पंगु बना दिया था। पूर्व सीएम असहाय हो गए थे, क्योंकि उन्हें अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग को नियंत्रित करने और नई लोकलुभावन नीतियां लागू करने में असमर्थता का सामना करना पड़ रहा था। 'आप' की हताशा ने छोटे प्रशासनिक फैसलों को भी प्रभावित किया। नतीजतन, दिल्ली जर्जर होती जा रही थी क्योंकि सड़कें ढह रही थीं, कूड़े के ढेर लगे थे, मानसून के समय नालों की सफाई नहीं की गई थी, जिससे बाढ़ आ गई और सर्दियों के महीनों में प्रदूषण को कम करने के प्रयासों में लेतलाली हो रही थी।

हालांकि आतिशी पहली बार की विधायक हैं, लेकिन उन्होंने केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान उनके लिए किला संभालकर बहुत तेजी से सीखने का हुनर दिखाया। अपने बॉस की तरह, वे भी खुद को एलजी के साथ अक्सर टकराव की स्थिति में पाती हैं। शहर में पानी की कमी को लेकर हुए एक संघर्ष में आतिशी को भूख हड़ताल तक पर जाना पड़ा था।

चुनाव सिर पर हैं और भाजपा 'आप' की सरकार को हराने के लिए हर मौके की तलाश में है। ऐसे में आने वाले महीनों में एलजी और नई सीएम के बीच संबंधों में सुधार की संभावना नहीं है। ऐसे में यह आतिशी के लिए अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि वे पार्टी की अपने वादों को पूरा करने और शासन के मोर्चे पर काम करने की क्षमता में लोगों के घटते भरोसे को फिर से बहाल करना चाहती हैं। आतिशी का सबसे मजबूत कार्ड यह है कि वे सत्ता में 'आप' की सबसे बड़ी उपलब्धि का चेहरा हैं : शैक्षिक-सुधार। पहले सलाहकार और फिर शिक्षा मंत्री के रूप में, आतिशी ने दिल्ली सरकार के कई स्कूलों में सुधार की सफलतापूर्वक पटकथा लिखी, ताकि उन्हें सुविधाओं और बोर्ड परीक्षा के अंकों के मामले में निजी स्कूलों के बराबर लाया जा सके। वे शायद आज देश की सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की डिग्री है, जहां वे रोड्स स्कॉलर थीं। यह उनके एक आम राजनेता से कहीं बढ़कर होने का आभास देता है।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार को हराने के लिए हर मौके की तलाश में है। ऐसे में आने वाले महीनों में एलजी और नई मुख्यमंत्री के बीच संबंधों में सुधार की संभावना नहीं है।

दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज प्याज की बढ़ती कीमतों के कारण सत्ता से बाहर हो गई थीं। दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को निर्भया कांड ने बेदखल कर दिया। जब आतिशी 2025 में केजरीवाल को तीसरी बार दिल्ली जीतने में मदद करने का प्रयास कर रही होंगी तो उन्हें इस इतिहास से भी जूझना होगा। **(ये लेखिका के अपने विचार हैं।)**

विश्लेषण • ईरान के खेल में पिस रहे हैं बेरूत के लोग
हिजबुल्ला की हरकतों की कीमत चुका रहा है लेबनान

ग्राउंड जीरो
अभिजीत अय्यर मित्रा
सीनियर फेलो, आईपीसीएस
abhijit@ipcs.org

मैं यह लेख इजराइल के हृदयस्थल यरूशलम से लिख रहा हूं, जहां कल सुबह हिजबुल्ला की ओर से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल के चलते हमें एक बंकर में शरण लेनी पड़ी थी। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच आज जो कुछ भी हो रहा है, उसके कारणों की गहराई से पड़ताल करना जरूरी है। पाकिस्तान की तरह लेबनान को भी एक कृत्रिम-राष्ट्र के रूप में गढ़ा गया था। उसका निर्माण स्थानीय ईसाई बहुसंख्या के लिए सीरिया को तोड़कर किया गया था, लेकिन अपने निर्माण के 50 वर्षों के भीतर ही यह सुन्नी बहुसंख्या वाला देश बन गया और 1990 के दशक में यह शिया बहुसंख्यक बन गया। लेकिन शियाओं के पास राजनीतिक ताकत नहीं थी और वे एक और गृहयुद्ध शुरू नहीं करना चाहते थे। तब उन्होंने हिजबुल्ला का सहारा लिया, जो कि ईरान के रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है।

ईरान हिजबुल्ला की मदद से कई निशाने साधना चाहता है। उसका पहला मकसद है एक क्षेत्रीय शिया-गठजोड़ का नेतृत्व करना, जिसमें 2000 के दशक से इराक, सीरिया और लेबनान शामिल हैं। दूसरा मकसद इजरायल के विरोध में अपने को सबसे आगे दिखाना था, क्योंकि परम्परागत रूप से इसे सुन्नी एकाधिकार के रूप में देखा जाता था। यह 1980 और 1990 के दशक में सऊदी अरब से इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व छीनने के लिए किया गया था, जिसने अमेरिका के सहयोगी के रूप में काम किया था। 2010 के दशक से तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मकसद ईरानी परमाणु हथियारों को कवर प्रदान करना रहा है। इसके लिए प्राथमिक खतरा हमेशा इजराइली हवाई हमले से आता है और आता रहेगा।

लेकिन दुर्भाग्य से, लेबनान के लोगों से इस बारे में कोई राय-मशविरा नहीं किया गया। अगर कोई लेबनानी ईसाई या सुन्नी लेबनान को ईरान के प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ बोलता है, तो उसे मार दिया जाता है और अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता। 2005 में ईरान के हितों की पूर्ति के लिए लेबनान में सीरिया की निरंतर सैन्य उपस्थिति का विरोध करने पर पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी तक की हत्या कर दी गई थी। लेबनान अब हिजबुल्ला की हरकतों की कीमत चुका रहा है। प्रतिरोध की कार्रवाइयां हिजबुल्ला करता है और जान लेबनानी नागरिकों को गंवानी पड़ती है।

मौजूदा तनाव की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए हमलों से हुई। पहले हिजबुल्ला को अधिक सक्षम आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाता था। लेकिन 7/10/23 को हमास ने ऐसा हमला किया, जो इससे पहले किसी भी अरब देश या संगठन ने नहीं किया था। हमास नंबर 1 बन गया। हिजबुल्ला को फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करना था, इसलिए उसने उत्तरी इजराइल में लगातार रॉकेट बमबारी का अभियान शुरू किया। ऊपरी तौर पर यह कहा गया कि यह फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन असली कारण हमास के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता थी। 7/10/23 के बाद से हिजबुल्ला ने इजराइल पर 9000 रॉकेट दागे हैं, लेकिन वह उत्तरी इजराइल से लगभग 70,000 इजराइलियों के पलायन के अलावा और कुछ हासिल नहीं कर पाया है। ये 9000 रॉकेट बेकार में नहीं दागे गए थे, उनका उद्देश्य ईरानी परमाणु कार्यक्रम की रक्षा करना था।

पिछले 30-40 सालों से इजराइल ने हिजबुल्ला को बेअसर करने के कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन उसे पूरी कामयाबी नहीं मिली। कारण, हिजबुल्ला का असली कमांड-सेंटर तेहरान में है और इजराइल ईरान को सीधे निशाना बनाने से परहेज करता रहा है।

अगर कोई लेबनानी अपने देश को ईरान के प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ बोलता है, तो उसे मार दिया जाता है और अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता। 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी तक की हत्या कर दी गई थी।

7/10/23 के बाद यह तस्वीर बदल गई। इजराइल ने सीरिया में कई ईरानी राजनयिकों को मार डाला, जिसके परिणामस्वरूप ईरान की ओर से इजराइल पर पहला सीधा हमला हुआ। फिर इजराइल ने तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हनीये को मार गिराया। तेहरान में लीडरशिप गेस्ट हाउस में हनीये को मारकर इजराइल ने ईरान को यह संदेश दे दिया कि वे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्ला कमांडरों के पेजर और वॉकी-टॉकी में ब्लास्ट करवाके उसके कमांड-सिस्टम पर करारी मार की। फिर हवाई हमलों में हिजबुल्ला के डिप्टी-हेड और मिसाइल-फोर्स के प्रमुख को मार गिराया गया।

इजराइल ने पिछले साल से अब तक कई मोर्चों पर कार्रवाई की है। पर नुकसान लेबनान के लोगों का हो रहा है। ईसाइयों ने 1980 के दशक में लेबनान की सत्ता खो दी थी और अब उनके देश को ईरान की विदेश नीति के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपहृत किया जा रहा है। वहीं सुन्नियों की सियासी ताकत को हिजबुल्ला ने हाईजैक कर लिया है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं।)**

हेल्थ & वेलनेस

मस्तिष्क और इम्यूनिटी
दिमाग भी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है

अश्विनी देसवाल
लाइफ एंड वेलनेस कोच

मस्तिष्क और इम्यून सिस्टम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपस में संवाद करते हैं। यह संचार न्यूरो इम्यून कनेक्शन के माध्यम से होता है। मस्तिष्क से आंतों तक जाने वाली वेगस नर्व इस संवाद के लिए मुख्य मार्ग के रूप में कार्य करती है। जब आप तनाव, चिंता या नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो मस्तिष्क कोर्टिसोल और एड्रेनेलिन जैसे रसायन छोड़ता है, जो इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, सकारात्मक भावनाएं और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं।

ये तरीके बढ़ा सकते हैं इम्यूनिटी

गुनगुनाएं या 'ॐ' का जाप करें

गुनगुनाने या 'ॐ' का जाप करने से होने वाला कंपन वेगस नर्व को सक्रिय करता है। इससे मन शांत होता है। इंफ्लामेशन घटता है। शोध में यह स्पष्ट हो चुका है कि विचारों का हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस अभ्यास को प्रत्येक सुबह 5-10 मिनट करें।

नकारात्मक विचारों की छंटनी करें

जैसे एक माली फूलों को खिलने देने के लिए खरपतवार को हटाता है, आप भी वैसे ही 'विचारों की बागवानी' का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए हर दिन 10 मिनट निकालें। नकारात्मक विचारों की पहचान करें और उन्हें 'खरपतवार' की तरह हटा दें। उनकी जगह खुद में सकारात्मक विचारों को भरें। जैसे 'मैं किसी भी परिस्थिति से बेहतर तरीके से निपट सकता हूं' या 'मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है'। यह सरल अभ्यास मस्तिष्क को री-प्रोग्राम करता है, तनाव हार्मोन को कम करता है। इम्यून सिस्टम के प्रभाव को बढ़ाता है।

रोज तीन अच्छी बातों को लिखें

हर दिन, तीन ऐसी चीजों को नोट करें, जिनसे आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं, विशेष रूप से अपनी सेहत और इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई। उदाहरण के लिए, 'मैं अपने सेहतमंद दिल के लिए आभारी हूं। इसकी वजह से मैं सारे काम अच्छे से कर सकता हूं' या 'मेरा शरीर छोटी-मोटी चोटों को खुद ठीक कर लेता है'। इस प्रकार का आभार सकारात्मक सोच के पैटर्न को मजबूत करता है, जो तनाव को कम करता है। शरीर को रिलैक्स मोड में लेकर जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम बेहतर होता है।

हेल्थ कार्टून

रोज 50 सीढ़ियां चढ़ने से हृदय रोग का खतरा 20% तक कम होता है

जर्नल अथेरोस्क्लेरोसिस में प्रकाशित एक शोध के अनुसार रोज 50 सीढ़ियां चढ़ने से हृदय रोग का खतरा 20 प्रतिशत तक कम होता है। इससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग जैसे हृदय रोग और उससे जुड़े फैक्टर्स कम होते हैं। यह अध्ययन करीब 4.58 लाख लोगों पर किया गया है।

फेफड़ों के अनोखे काम • ब्लड के छोटे क्लॉट भी फिल्टर करते हैं
ट्रैकिंग और सांसों से जुड़े अभ्यास फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं, संक्रमण का खतरा घटता है

डॉ. (कर्नल) एसपी राय
कंसल्टेंट, पल्मोनरी मेडिसिन, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई

फेफड़ों को मुख्य रूप से श्वसन से जुड़े कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने के अलावा इनके कई अनूठे और दिलचस्प काम भी हैं। जो सामान्य सांस लेने से कहीं ज्यादा हैं। जैसे फेफड़े एंजिओटेंसिन-कंवर्टिंग एंजाइम (एसीई) रिलीज करते हैं जो न केवल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि शरीर में तरल पदार्थों को भी संतुलित रखने में उपयोगी है। ऐसे ही इंफ्लामेशन से जुड़ी कुछ दवाओं को पचाने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही नहीं फेफड़े हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने से लेकर, शरीर को रिपेयर करने वाली स्टेम सेल्स तक को स्टोर करते हैं। फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों और उनकी सेहत से जुड़ी जागरूकता को लेकर हाल ही में दुनियाभर में 'वर्ल्ड लंग डे' मनाया गया है। ऐसे में आज जानते हैं कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में, जो फेफड़ों की विशेष क्षमताओं को बढ़ाने में बेहद मददगार हैं।

फेफड़े की क्षमताओं को ऐसे बढ़ा सकते हैं

पहाड़ों पर ट्रेकिंग करें
स्टेम सेल्स स्टोरेज की क्षमता बढ़ती है

कैसे करें : लगभग 2,500 मीटर ऊंचे स्थान का चुनाव करें। ऐसे स्थानों पर ट्रेकिंग या फिर खेल-कूद जैसी गतिविधियां करें।

कैसे फायदा मिलता है : *कम ऑक्सीजन स्तर, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, स्टेम सेल्स के रिलीज को प्रोत्साहित करता है। स्टेम सेल्स शरीर को रिपेयर करती हैं।*

अनुलोम-विलोम का अभ्यास
इससे फेफड़े इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं

कैसे करें : पद्मासन में बैठ जाएं। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करें। बाएं नथुने से सांस लें। अब दाएं नथुने को छोड़ दें। और हाथ की रिंग फिंगर से बाएं नथुने को बंद कर लें। दाएं नथुने से सांस छोड़ दें। अब इसे दूसरी तरफ से दोहराएं।

कैसे फायदा मिलता है : *सांस लेने का यह तरीका शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) के उत्पादन को बढ़ाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो श्वसन से जुड़े संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।*

ब्रीद कंट्रोल एवं इंटरवल ट्रेनिंग
ब्लड को स्टोर करने की क्षमता बढ़ती है

कैसे करें : आपके मूवमेंट के साथ सांसों का मिलान करें। उदाहरण के लिए रनिंग या साइकिलिंग के दो स्टेप के साथ सांस छोड़ें। ऐसे ही दो स्टेप के साथ सांस लें।

कैसे फायदा मिलता है : *इससे फेफड़े की रक्त वाहिकाओं का लचीलापन बढ़ता है। इससे उनके ब्लड को स्टोर करने की क्षमता बढ़ती है।*

डीप ब्रीदिंग के साथ ब्रिस्क वॉक
रक्त के छोटे थक्के फिल्टर करते हैं

कैसे करें : समतल जगह चुनें। अब धीरे-धीरे चलने की रफ्तार इतनी तेज करें कि आप स्पष्ट तरीके से किसी से बात न कर पाएं। वॉक की इस गति के साथ सांसों को 2 से 3 सेकंड तक लें और 3 से 5 सेकंड तक निकालें।

कैसे फायदा मिलता है : *यह व्यायाम ब्लड फ्लो और प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे फेफड़े इन सूक्ष्म थक्कों और बुलबुलों को बेहतर तरीके से फिल्टर कर पाते हैं।*

सेहत का विज्ञान
घर का हेल्दी खाना खाने के बाद भी वजन क्यों बढ़ रहा है?

रेणु रखेजा
न्यूट्रिशनिस्ट एवं हेल्थ कोच
@consciouslivingtips

कई बार घर का बना हुआ और सेहतमंद भोजन करने के बावजूद वजन बढ़ने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे- भोजन में अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों रोटी, चावल और पराठे आदि का अधिक होना, प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों का कम होना। इससे असंतुलन पैदा होता है, जिससे हम अधिक कैलोरी ग्रहण करते हैं। वहीं संतुलित भोजन से पेट भरा रहता है और ओवरईटिंग की आशंका कम होती है। इसके अलावा बहुत बार खाने, बिना भूख के आदतन खाने, स्नैक के रूप में अधिक कैलोरी वाले फूड लेने से भी शरीर में अतिरिक्त कैलोरी पहुंचती है। इससे वजन बढ़ता है। आज जानते हैं वजन बढ़ने के कुछ ऐसे ही और कारणों को।

रोजमर्रा के कामों में तनाव अधिक रहना

तनाव भी वजन बढ़ने के कारणों में से एक है। दरअसल तनाव इमोशनल ईटिंग को बढ़ा सकता है। यह कॉर्टिसोल हार्मोन के स्तर को भी बढ़ाता है, जो मीठे या फैटी फूड्स की क्रेविंग्स को बढ़ाता है। भले ही आप घर का बना खाना खा रहे हों, लेकिन तनाव के अधिक होने के कारण आप अधिक खा सकते हैं या ऐसे भोजन ज्यादा कर सकते हैं जिनमें कैलोरी ज्यादा होती हैं। ऐसे में तनाव को मैनेज करने के लिए योग, ध्यान या वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह तनाव के साथ ही वजन को मैनेज करने में मदद करेगा।

'हेल्दी' फूड में भी हो सकती है अधिक कैलोरी

सिर्फ इसलिए कि किसी चीज को हेल्दी कहा गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह वजन नहीं बढ़ा सकती। नट्स, बीज, सूखे मेवे और एनर्जी बार जैसे फूड हेल्दी तो होते हैं लेकिन उनमें काफी कैलोरी भी होती है। इन स्नैक्स को अधिक मात्रा में खाने से ओवरईटिंग हो सकती है। स्नैकिंग करते समय, उसकी मात्रा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नट्स या एनर्जी बार का अधिक सेवन करने से एक दिन में बड़ी संख्या में अतिरिक्त कैलोरी शरीर में पहुंच सकती हैं।

आपका अधिकांश समय बैठे हुए गुजरता है

विशेष रूप से जिन लोगों की डेस्क जॉब्स होती हैं, वे लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वजन बढ़ सकता है, भले ही वे हेल्दी खा रहे हों। लंबे समय तक बैठने से खराब पॉस्चर और मांसपेशियों का नुकसान भी हो सकता है, जो वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए हर घंटे थोड़ा चलें, स्ट्रेच करें, और दिनभर हल्की शारीरिक गतिविधियां जैसे चलना या स्टैंडिंग डेस्क का उपयोग करना आदि अपनाएं।

रोज देर से सोते हैं या नींद पूरी नहीं हो पाती है

वजन नियंत्रित करने में नींद की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर देर से सोते हैं या शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता है, तो यह शरीर की फैट बर्न करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो शरीर भूख बढ़ाने वाले हार्मोन जैसे कि घ्रेलिन का उत्पादन अधिक करता है, जिससे आप ज्यादा खाते हैं। वहीं तृप्ति का संकेत देने वाला हार्मोन लेप्टिन कम बनने लगता है। इसके अलावा, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब शरीर की फैट बर्न करने वाली प्रक्रिया बेहतर काम करती है। अगर आप लगातार देर से सो रहे हैं या पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर उस महत्वपूर्ण फैट-बर्निंग चरण को मिस कर देता है, जिससे वजन बढ़ सकता है। ऐसे में हर रात 7-8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लेने का प्रयास करें।

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024

संयुक्त राष्ट्र महासभा

मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'भविष्य के लिए समझौता' प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रकट की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रभावशाली भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल वैश्विक शांति तथा सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में समग्र सुधारों की पैरवी की। न्यूयार्क में संरा. मुख्यालय में 'भविष्य के सम्मेलन' को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 'सुधार प्रासांगिकता की कुंजी हैं।' उनका संदेश जटिल वैश्विक परिदृश्य में बहुत प्रभावी है जिसका कारण उभरते टकराव तथा वर्तमान चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है और उन्होंने टकराव के बजाय एकता का समर्थन किया। उन्होंने घोषणा की, 'विश्व शांति और विकास के लिए वैश्विक संगठनों में सुधार जरूरी है।' वे स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ में सुधार की आवश्यकता की ओर इशारा कर रहे थे। सुधार का यह आह्वान खासकर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान समय में अनेक चुनौतियां अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित कर रही हैं। इनमें आतंकवाद से लेकर टकराव के नए क्षेत्र, जैसे, साइबर खतरे, समुद्री विवाद और अंतरिक्ष की खोज शामिल हैं। मोदी ने जोर दिया कि 'वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षाओं से मेल खानी चाहिए।' इस प्रकार उन्होंने महत्वपूर्ण समस्याओं को संबोधित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका शांति का संदेश संरा. महासभा द्वारा 'भविष्य के लिए समझौता' स्वीकार करने के बाद आया जिसमें जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकारों व टकरावों समेत 21वीं शताब्दी की चुनौतियों को संबोधित किया गया है।

लेकिन इस समझौते का रूस के नेतृत्व में सात देशों द्वारा विरोध किया गया जो वर्तमान समय में यूक्रेन के साथ सशस्त्र संघर्ष में उलझा है। रूस के प्रतिनिधि ने इस समझौते से असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह विविधतापूर्ण दृष्टिकोणों को समाहित करने में विफल रहा है तथा इसने वार्ताओं को कुचला है। संरा. में रूस के प्रथम उप-स्थाई प्रतिनिधि दिमित्री पोल्यान्स्की ने समझौते की आलोचना करते हुए कहा, 'ब्यूटीफुल गार्डन से प्रतिनिधियों के समूह से विचार कर संयुक्त राष्ट्रसंघ ने स्वयं अपने सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है, जिन्होंने वार्ताओं पर शुरू से कब्जा जमा लिया था।' यह टिप्पणी वर्तमान भू-राजनीतिक तनावों को रेखांकित करती है जो वैश्विक एकता को चुनौती दे रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संरा. संबोधन से स्पष्ट है कि विश्व स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। सुधारों तथा विश्व शांति को प्राथमिकता देने की पैरोकारी कर भारत ने अंतरराष्ट्रीय राजनय में अपने एक प्रमुख पक्ष होने की घोषणा कर दी है। मोदी के नेतृत्व ने न केवल ज्यादा समतापूर्ण विश्व व्यवस्था बनाने के प्रति भारत की इच्छा प्रकट की है, बल्कि उसने सहयोग तथा संवाद के माध्यम से समकालीन चुनौतियां संबोधित करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। अनेक जटिल समस्याओं का सामना करने वाली दुनिया में मोदी का सुधार व शांति का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रूप से याद दिलाता है कि भविष्य का रास्ता अवश्य खोजा जाना चाहिए जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई, परस्पर सम्मान और लोकतंत्र व न्याय के सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है। इस महत्वपूर्ण समय में भारत ज्यादा स्थिर तथा सद्भावनापूर्ण विश्व समुदाय बनाने के लिए नेतृत्व व योगदान के लिए तैयार है। भारत ने शांति संस्थापक के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की है और वह विश्व परिदृश्य में बड़े वार्ताकार के रूप में उभर सकता है।

उथलपुथल भरे समय में शांति की खोज

पच्चीस साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'शांति की संस्कृति की घोषणा तथा कार्ययोजना' प्रस्ताव मंजूर किया था। यह हमें अहिंसा और न्याय का महत्व याद दिलाता है।

राजदीप पाठक
(लेखक, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति से संबद्ध हैं)

पच्चीस साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'शांति की संस्कृति की घोषणा तथा कार्ययोजना' प्रस्ताव मंजूर किया था। यह हमें अहिंसा और न्याय का महत्व याद दिलाता है। इस बीच दुनिया ने काफी लंबी यात्रा की है जिससे संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका की प्रासांगिकता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'भविष्य के सम्मेलन' की अवधारणा पर अपना विशेष सत्र आयोजित करना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर, 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए मानव-केन्द्रित विकास स्वीकार करने पर जोर दिया। 'भविष्य के सम्मेलन' में उपस्थित महानुभावों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर दिया कि शांति, विकास और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सुधार आवश्यक हैं।

उन्होंने यह तथ्य महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किया कि मानवता की सफलता टकराव के बजाय अपनी सामूहिक शक्ति का लाभ उठाने से ही सुनिश्चित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 'अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस' मनाने के बाद हुआ जिसे विश्व हर साल 21 सितंबर को मनाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हमें अहिंसा, संवाद और सुलह-समझौते की शक्ति और उसकी आवश्यकता की याद दिलाता है। वर्तमान समय में दुनिया अनेक प्रकार की हिंसा की शिकार है। ऐसे में शांति के आह्वान की वैश्विक स्वीकार्यता मजबूत करने के लिए निरंतर सुनियोजित प्रयासों की जरूरत है।

हाल ही में लेबेनान में हत्याओं के प्रयास ने लंबे समय पहले भुला दी गई एक तकनीक-पेजर को पुनः सुर्खियों में ला दिया। 17 सितंबर, 2024 को एक समन्वित हमले ने पूरे क्षेत्र में भय की लहर पैदा कर दी, जब हिजबुल्ला के सदस्यों और चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सैकड़ों पेजरों में अचानक और एकसाथ विस्फोट हो गया। इन विनाशकारी विस्फोटों में कम से कम 9 लोगों की जान गई तथा लगभग 3,000 बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि, इस घटना के राजनीतिक प्रभाव बहुत विस्तृत हैं, पर इस हमले की संवेदनशीलता और भयावहता डरा देने वाली है। ऐसे घातक सटीक हमले के लिए एक पुरानी पड़ चुकी तकनीक का प्रयोग आधुनिक युद्ध तथा उसकी लगातार विकसित हो रही तकनीकों के बारे में सवाल उठाते हैं। वर्तमान समय में जारी उथलपुथल के बीच सुलह-समझौते के प्रयासों के साथ ही इस प्रकार के अदृश्य खतरे निश्चित रूप से चिन्ताजनक हैं जो समस्याओं और परेशानियों को बढ़ा सकते हैं।

इन परिस्थितियों में महात्मा गांधी का शांति का दृष्टिकोण उम्मीद की किरण जगाता है। गांधीजी का विश्वास था कि सच्ची शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील शक्ति है जिसकी जड़ें न्याय, सत्य एवं अहिंसा में निहित हैं। महात्मा गांधी के लिए शांति एक जीवनशैली थी जो आत्मानुशासन, सहानुभूति तथा सबके कल्याण के प्रति अडिग प्रतिबद्धता से ही प्राप्त की जा सकती है। गांधीजी की विचार प्रक्रिया में जोर दिया गया था कि स्थाई शांति केवल सत्य और अहिंसा की नीव पर ही स्थापित की जा सकती है। इस स्थिति में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाइयां सहानुभूति, सम्मान और सहयोग से निर्देशित होती हैं। उन्होंने 'सर्वोदय', यानी सबके कल्याण और प्रगति की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए सभी लोगों का आह्वान किया था कि वे साझा भलाई के लिए अपना योगदान करें। गांधीजी ने यह तथ्य स्वीकार किया था कि शांति अलग-थलग होकर नहीं रह सकती है, बल्कि इसके लिए हर व्यक्ति की बेहतरी जरूरी है। महात्मा गांधी की विरासत हमें याद दिलाती है कि यह संवेदनशील व अमूल्य स्थिति प्राप्त करना हमारे अपने प्रयासों पर निर्भर है।

'शांति एवं टकराव अध्ययनों' को स्थापित करने वाले राजनीति विज्ञानी के रूप में विख्यात 'जान गाल्टुंग' ने शांति और टकरावों की स्थिति परिभाषित करते हुए लिखा है-'शांति केवल टकराव की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह टकराव की स्थितियों का शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान निकालना है।' इसके लिए गाल्टुंग ने संवाद, सहानुभूति तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को रेखांकित किया है। ये सिद्धान्त ऐसी दुनिया में खासकर महत्वपूर्ण है जो बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों, आंतरिक टकरावों तथा बढ़ते ध्रुवीकरण का शिकार है। अपनी उल्लेखनीय रचना 'टेरर इन द माइंड आफ गाड' में इतिहासकार और अमेरिकन समाजशास्त्री 'मार्क जर्गन्समेयर' ने तर्क दिया है कि अक्सर आतंकी कृत्यों को अच्छाई और बुराई के बीच परिकल्पित ईश्वरीय युद्ध के रूप में पेश किया जाता है अथवा उसकी जड़ें इस सोच में होती हैं।

उन्होंने जोर दिया कि 'केवल सैनिक तरीकों से शांति का अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए हिंसा के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना जरूरी है। इन कारणों में राजनीतिक पृथक्करण, आर्थिक असमानतायें तथा सामाजिक अन्याय हो सकते हैं।' उनका यह कथन एक व्यापक रणनीति की ओर संकेत करता है जिसमें संवाद, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक समझदारी शामिल हैं। 11 सितंबर के पहले गांधीजी का 'पीसलांग' के लिए सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। इसने एक शक्तिशाली, पर शांतिपूर्ण क्रांतिकारी शक्ति को जन्म दिया।

11 सितंबर, 1906 को जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी ने अपना पहला 'सत्याग्रह' अभियान शुरू किया था जिसकी जड़ें सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस में निहित हैं। गांधीजी के दर्शन का प्रयोग कर अफ्रीका में रंगभेदी शासकों के खिलाफ अभियान चलाने और उसमें सफल होने वाले प्रख्यात नेता नेल्सन मंडेला ने एक बार का था कि गांधीजी के दर्शन ने न केवल दक्षिण अफ्रीमा, बल्कि सारी दुनिया को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक 'गांधी: प्रिजनर आफ होप' में सत्याग्रह को एक 'नैतिक प्रयोग' बताया है जहां टकराव का समाधान हिंसक रूप से नहीं, बल्कि नैतिक रूप से किया जाता है।

टकरावों के समाधान का यह नैतिकतावादी दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख अंग था। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक अनोखा स्वरूप प्रदान किया था। गांधीजी का यह दृष्टिकोण एक विभाजित दुनिया में शांति स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है जहां टकराव बढ़ने के साथ जटिलता भी और बढ़ती है। ऐसे में शांति और अहिंसा के सिद्धान्तों की दिशा में वापसी जरूरी है। राजनीति विज्ञानी माइकेल हावर्ड हमें याद दिलाते हैं कि 'शांति ऊपर से नहीं थोपी जा सकती है, बल्कि इसकी रचना नीचे से होती है'। इसके लिए विश्वास, शिक्षा और संवाद जरूरी है। इन मूल्यों को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव 'शांति की संस्कृति' में केन्द्रीय स्थान दिया गया है। हम महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें दुनिया में वर्तमान समय में जारी युद्धों और टकरावों से सबक लेते हुए महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा सिद्धान्तों पर पुनः जोर देते हुए नैतिक रूप से सुलह-समझौते का मार्ग प्रशस्त करने के प्रयास करने चाहिए।

वर्तमान समय में हमारे सामने चयन के लिए दो विकल्प हैं। हम वर्तमान समय में जारी विभाजन के रास्ते पर चलते रह सकते हैं या संवाद, सद्भावना व न्याय का रास्ता अपना सकते हैं जिसकी पैरवी महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, विनोबा भावे, मार्टिन लूथर किंग तथा देश-विदेश के अनेक मौन शांति यात्रियों ने की है। शांतिपूर्ण दुनिया के अनेक लाभ हैं जिनमें स्थायित्व व समृद्धि को बढ़ावा तथा मानवता का समग्र कल्याण शामिल हैं। शांति यात्रियों ने हमें याद दिलाया है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि इससे आगे जाती हे। इसके लिए न्याय, सहयोग तथा सम्मान की लगातार खोज करनी होती है।

ब्रिटिश इतिहासकार एजेपी टेलर ने कहा है कि 'युद्ध राजनय और शांति की विफलता है।' समय आ गया है कि हम सामूहिक रूप से इसके लिए प्रयास और तेज करें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बोरियत से बचना है तो समाज के लिए कार्य करें

शाइनी शर्मा
(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

> सार्थक सामाजिक कार्य में संलग्न होना बोरियत को दूर करने में सहायक हो सकता है और अपार आनंद दे सकता है।

बोरियत एक आम अनुभव है जिसका सामना कई लोग करते हैं, जो अक्सर बेचैनी, अनुत्पादकता और प्रेरणा की कमी की ओर ले जाता है। जबकि बोरियत से निपटने के कई तरीके हैं, एक बेहद प्रभावी और संतुष्टिदायक तरीका सामुदायिक सेवा में संलग्न होना है। समुदाय के भीतर स्वयंसेवा करने से न केवल बोरियत दूर हो सकती है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक लाभ भी मिल सकते हैं।

सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देकर, सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देकर और सीखने और बढ़ने के अवसर प्रदान करके, सामुदायिक सेवा व्यक्तियों को व्यस्त और संतुष्ट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामुदायिक सेवा लोगों को उद्देश्य की भावना देती है, क्योंकि वे किसी सार्थक चीज़ में योगदान देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, तो यह उनके दिमाग को व्यस्त रखता है और उत्पादक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उन्हें उनकी दिनचर्या में विविधता लाने का परिचय देता है, जिससे वे दोहराव या सांसारिक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं जो अक्सर बोरियत का कारण बनती हैं। बोरियत- एक ऐसा शब्द जो अक्सर लक्ष्यहीनता या दिशा की कमी महसूस करने से उत्पन्न होता है, लेकिन जब लोग अपना समय दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित करते हैं, तो वे पाते हैं कि वे अपनी दिनचर्या से बड़े कारण में योगदान दे रहे हैं।

चाहे वह किसी स्थानीय आश्रय में स्वयंसेवा करना हो, पड़ोस की सफाई में भाग लेना हो या धर्मार्थ कार्यक्रम आयोजित करना हो, सामुदायिक सेवा व्यक्तियों को सक्रिय रहने का एक सार्थक कारण देती है। उद्देश्य की यह भावना न केवल समय को

रचनात्मक रूप से भरती है, बल्कि व्यक्तिगत संतुष्टि भी देती है, क्योंकि व्यक्ति अपने समुदायों में उनके द्वारा किए जा रहे ठोस सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। सामुदायिक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार यह एहसास है कि व्यक्ति समाज की भलाई में योगदान दे रहे हैं। सामुदायिक सेवा स्वयंसेवकों को उनके कार्यों के तत्काल प्रभाव को दिखाकर इसे उलट देती है। चाहे वह भूख को कम करना हो, स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार करना हो या कमजोर आबादी का समर्थन करना हो, सामुदायिक सेवा में बिताया गया हर घंटा एक सार्थक अंतर पैदा करता है। यह योगदान स्वयंसेवकों को यह जानकर संतुष्टि और गर्व की गहरी भावना देता है कि वे खुद से बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा हैं। अपने समुदाय की बेहतरी में सक्रिय रूप से भाग लेने से, व्यक्ति अपने आस-पास के लोगों के प्रति जिम्मेदारी और जुड़ाव की भावना विकसित करते हैं, जिससे उनके ऊबने या विमुख होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सामुदायिक सेवा ऊब के लिए एक शक्तिशाली मारक साबित हुई है। यह व्यक्तियों को सार्थक काम में लगाता है, सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देता है, नए कौशल सीखने के अवसर प्रदान करता है और मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से जुड़ाव की अनुमति देता है।

दूसरों की मदद करने से जो उद्देश्य और संतुष्टि की भावना आती है, वह बोरियत की खालीपन को उत्पादकता और संतुष्टि से बदल देती है। इसके अतिरिक्त, स्वयंसेवकों का अपने समुदायों पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह एक मजबूत और अधिक जुड़े हुए समाज में योगदान देता है।

सामुदायिक सेवा में संलग्न होना न केवल पुरानी पीढ़ी को बल्कि युवा पीढ़ी को भी उद्देश्यपूर्ण गतिविधियाँ प्रदान करता है जो न केवल बोरियत से लड़ती हैं बल्कि व्यक्तिगत विकास, सामाजिक संबंध और कौशल विकास भी प्रदान करती हैं। यह युवा लोगों को ऐसे अनुभवों से अवगत कराता है जो उन्हें अन्यथा नहीं मिल सकते हैं। चाहे वह विदेश में स्वयंसेवा करना हो, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मदद करना हो या विविध समुदायों के साथ बातचीत करना हो, ये अनुभव उनके जीवन में उत्साह और विविधता लाते हैं। स्वयंसेवा युवाओं को नए सामाजिक दायरे से भी परिचित कराती है, जिससे उन्हें समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने में मदद मिलती है जो दूसरों की मदद करने के उनके जुनून को साझा करते हैं। यह बातचीत अकेलेपन की भावनाओं को कम कर सकती है, जो बोरियत का एक सामान्य कारण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास व्यापक सामाजिक नेटवर्क या उत्तेजक वातावरण नहीं हो सकता है।

यह युवाओं को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर और नई चुनौतियों का सामना करके व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में भी मदद करेगा। जब वे विभिन्न परियोजनाओं और पहलों में योगदान देंगे, तो उनमें आत्मविश्वास और लचीलापन बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि वे दुनिया में एक ठोस बदलाव ला सकते हैं।

आप की बात

दिल्ली में प्रदूषण

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यह सवाल उच्चतम न्यायालय ने पूछा है। उसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से पूछा है कि आखिर उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? लगता है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना भी शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जिस तरह आम आदमी-आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी प्रयोग की उससे भी फैलने वाले प्रदूषण की खबरें एलेक्ट्रानिक मीडिया की सुर्खियां बनीं। लेकिन लगता है कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी को इसकी चिन्ता नहीं है। पराली जलाने के मुख्य दोषी हरियाणा और पंजाब के किसान माने जाते हैं, लेकिन जहां हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं वहीं पंजाब में आप की सरकार है। पहले केजरीवाल पंजाब व हरियाणा को दोषी ठहरा कर वायु प्रदूषण नियंत्रण में दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेते थे। लेकिन इस बार कुछ महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव होने हैं जिनमें विजय केजरीवाल की नाक का सवाल है। ऐसे में देखना होगा कि पंजाब सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने में कहां तक सफल होती है।

–**मनमोहन राजावत,** शाजापुर

रिमोट-चालित सरकार

दस साल तक केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार को रिमोट कंट्रोल से सोनिया गाँधी ने चलाया। विपक्ष ने भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार पर तब खूब बयानबाजी की थी। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी-आप की आतिशी सरकार भी अरविन्द केजरीवाल के रिमोट कंट्रोल से 4 महीने चलेगी। तेज तर्रार समझी जाने वाली आतिशी ने अपने राजनीतिक गुरु की कुर्सी पर उनके सम्मान में न बैठकर दूसरी कुर्सी से सरकार चलानी शुरू की है। उन्होंने भगवान राम और भरत का उदाहरण देते हुए कहा कि केजरीवाल खुद 4 महीने बाद उस पर बैठेंगे। लेकिन कहाँ मर्यादा पुरषोत्तम राम और उनके आज्ञाकारी भरत औरं कहाँ घोटालों में लिप्त केजरीवाल और उनकी शिष्या आतिशी।अगर केजरीवाल में नैतिकता होती तो जेल जाते ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था। अब गुरु और शिष्या मिल कर नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा के नेता इसे नौटंकी और कुर्सी का अपमान बता रहे हैं। दिल्ली की जनता इस दूसरी रिमोट-चालित सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी और नौटंकी के बजाय उसके कामकाज के आधार पर फैसला देगी। कांग्रेस भी पूरे प्रकरण को बड़े मजे से देख रही है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

अनुरा बने राष्ट्रपति

श्रीलंका भारी मुद्रास्फीति, दैनिक जीवन के बढ़ते खर्च, गरीबी जैसे कई संकटों से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों में एनपीपी के वामपंथी झुकाव वाले अनुरा कुमारा दिसानायके देश के राष्ट्रपति बने हैं। दिसानायके की जेवीपी-जन विमुक्ति पेरामुना पार्टी ने 1971 व 1987-89 में लोकप्रियता हासिल की। उस समय वह सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह में शामिल थी। इसने 2022 में सरकार को अस्थिर करने में खास भूमिका निभाई थी। दिसानायके का उदय 2022 के संकट का परिणाम है। प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों ने लंबे समय से प्रचलित पारंपरिक वंशवादी पार्टियों में लोगों का विश्वास घटाया था। हालांकि, अनुरा कुमारा दिसानायके मतगणना के दूसरे चरण में सफल हुए हैं क्योंकि पहले चरण में किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को आवश्यक पचास प्रतिशत मत नहीं मिले थे। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने कहा है कि वे अपनी भूमि का प्रयोग किसी को भी भारत के खिलाफ नहीं करने देंगे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक उनको वामपंथी के बजाय राष्ट्रवादी मानते हैं। चीन ने उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, ऐसे में देखना होगा कि अनुरा के नेतृत्व में भारत-श्रीलंका संबंध कैसे होंगे। यह भारतीय राजनय की एक और परीक्षा होगी।

विजय सिंह अधिकारी, नैनीताल

शानदार सोलर प्लांट

रीवा में स्थापित किए गए अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट की सफलता के किस्से दुनिया भर में फैल रहे हैं। अमेरिका के हावर्ड विश्वविद्यालय में इसके बारे में स्टडी करवाया जाना मध्य प्रदेश के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अभी तक सभी नई वैज्ञानिक तकनीकें विदेश से भारत में आती थी। एक प्रकार से हमारे अपने शोध बहुत पिछड़े हुए थे। बिजली आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत है। बिना बिजली के कहीं पर भी किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता, बल्कि अब तो बिजली के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की सकती। सोलर पावर प्लांट प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भविष्य में ऊर्जा के लिए सूर्य का ही सहारा लेना होगा क्योंकि अगले कुछ दशकों में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत खत्म हो जाएंगे। ऐसे में हमारा अभी से जाग जाना सराहनीय है। सरकार भी इसके लिए पर्याप्त सहायता दे रही है। रीवा का पावर प्लांट भारत सहित पूरे विश्व के लिए एक मॉडल का काम करेगा। देश के दूसरे प्रदेश भी इससे प्रेरित होकर विशाल सोलर संयंत्र लगाएंगे।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 190

श्रम बाजार के संकेत

जुलाई 2023-जून 2024 तक के ताजा वार्षिक सावधिक श्रम शक्ति सर्वे (पीएलएफएस) की रिपोर्ट इसी सप्ताह जारी की गई। उससे पता चला कि बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के समान यानी 3.2 फीसदी रही।

बहरहाल कुल श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) की बात करें तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए यह 60.1 फीसदी के साथ सात वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई जबकि 2017-18 में यह 49.8 फीसदी थी। महिलाओं के एलएफपीआर की बात करें तो शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिलाकर यह 2017-18 के 23.3 फीसदी से बढ़कर ताजा सर्वे में 78.8 फीसदी तक पहुंच गई।

चूंकि श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ी है और बेरोजगारी उसी स्तर पर है, इससे संकेत निकलता है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद कई ऐसे कारक हैं जो देश के श्रम बाजार को पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। रोजगार में इजाफा होने के बावजूद उन रोजगारों की गुणवत्ता चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए महिलाओं की बेरोजगारी दर 2022-23 के 2.9 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में 3.2 फीसदी हो गई है।

श्रम भागीदारी में इजाफा जहां सकारात्मक है, वहीं हालिया अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि एलएफपीआर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी मुश्किल हालात की वजह से भी हो सकती है। अपने परिवार की आय में इजाफा करने के लिए भी महिलाएं श्रम शक्ति में शामिल हो रही हैं। नियमित वेतन वाले रोजगार में उनकी हिस्सेदारी भी 15.9 फीसदी पर स्थिर है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में नियमित रोजगार वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 2022-23 के 50.8 फीसदी से कम होकर 2023-24 में 49.4 फीसदी रह गई।

भारत में स्वरोजगार निरंतर बढ़ता जा रहा है और देश की आधी से अधिक श्रम शक्ति को घरेलू उपक्रमों में सहायक और अपने ही काम में कर्मचारी और नियोक्ता के रूप में ही काम करने का अवसर मिल रहा है। 2023-24 में 58 फीसदी से अधिक कर्मचारी स्वरोजगार में थे। वर्ष 2022-23 और 2021-22 में स्वरोजगार की दर क्रमशः 57.3 फीसदी और 55.8 फीसदी थी। इससे भी बुरी बात यह है कि स्वरोजगार की श्रेणी में होने वाला इजाफा ज्यादातर 'घरेलू उपक्रमों में बिना वेतन के काम करने वाले सहायकों 'के रूप में है। वर्ष 2023-24 में श्रम शक्ति में इनकी हिस्सेदारी 19.4 फीसदी थी जो 2022-23 के 18.3 फीसदी और 2017-18 के 13.6 फीसदी से अधिक थी। स्पष्ट है कि स्वरोजगार और पारिवारिक व्यवसाय में इजाफा यह दर्शाता है कि देश में वेतन-भत्ते वाले रोजगार के अवसरों की कमी है। इन श्रेणियों में होने वाला रोजगार आमतौर पर किसी लिखित रोजगार अनुबंध वाला नहीं होता और आय भी कम होती है। भारतीय श्रम बाजार एक और कमी से दो चार है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान जहां वर्तमान मूल्य पर 18.2 फीसदी है वहीं 2023-24 में कुल श्रम शक्ति का 46.1 फीसदी हिस्सा यहां रोजगार शुदा था। यह संख्या इससे पिछले वर्ष से 0.3 फीसदी अधिक था। इससे पता चलता है कि देश में रोजगार तैयार होने की गति अभी भी अपर्याप्त है।

यह बात भी ध्यान देने वाली है कि अलग-अलग राज्यों में इसमें अंतर है। कई उच्च आय वाले राज्य मसलन केरल, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी कम है। इन राज्यों में यह दर 22 से 28 फीसदी के बीच है। यह आंकड़ा तुलनात्मक रूप से मध्य आय वाले देशों के स्तर के आसपास है।

कृषि में रोजगार समग्र अर्थव्यवस्था में उसके योगदान के अनुरूप होना चाहिए। दशकों से बुनियादी तौर पर जो नीतिगत नाकामी रही है वह है भारत की कम कुशल विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की अक्षमता। यदि इस क्षेत्र में रोजगार तैयार होते तो लोग कृषि से बाहर निकल पाते। इससे उत्पादकता और वृद्धि को गति मिलती। श्रम बाजार की स्थिति की मांग यह है कि विनिर्माण पर ध्यान दिया जाए। खेती में और स्वरोजगार में लोग बड़ी तादाद में शामिल हैं लेकिन आय का स्तर बहुत कम है। इससे देश में आर्थिक और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।

अजय मोहंती

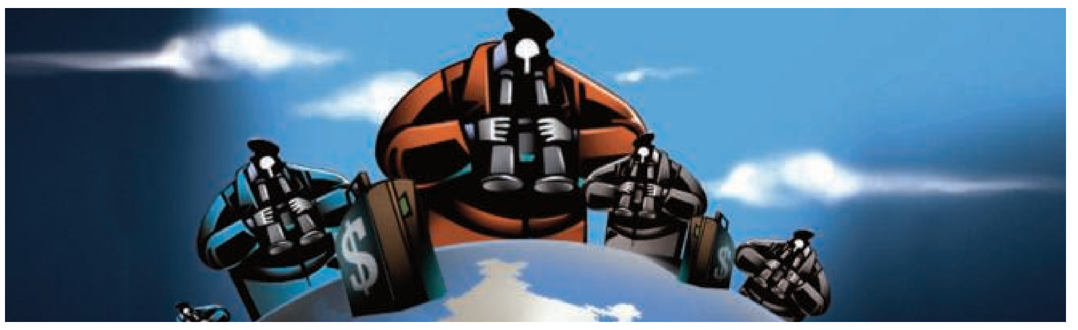

आखिर कैसे आए देश में 10 गुना एफडीआई

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बड़ी बढ़त देश में वृद्धि की प्रक्रिया के लिहाज से आवश्यक है। बता रहे हैं अजय शाह

शी चिनफिंग ने 2013 में चीन की सत्ता संभाली और राष्ट्रवाद तथा राज्य की शक्ति के मनमाने प्रयोग पर नए सिरे से जोर दिया। इससे ज्यादा समृद्धि और अधिक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ने के 'चीन मॉडल' में बाधा उत्पन्न हुई। कई आर्थिक संकेतक बताते हैं कि चीन मॉडल 2017 के बाद से किस तरह बेपटरी हो गया। 2013 में चीन में 291 अरब डॉलर का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया था मगर हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक 2023 में केवल 43 अरब डॉलर का शुद्ध एफडीआई आया।

12 सितंबर को एलीनॉर ऑलकॉट और वांग शुएछाओ ने फाइनैंशियल टाइम्स में एक आलेख लिखकर बताया कि कैसे चीन ने अपने निजी क्षेत्र का दम घोंट दिया। यह दिखाने के लिए उन्होंने वेंचर कैपिटल की रकम से कंपनियां बनने की रफ्तार का उदाहरण दिया। 2018 में ऐसी कंपनियां बनने की रफ्तार चरम पर थी और उस साल वेंचर कैपिटल की मदद से 51,032 कंपनियां बनीं मगर 2023 में ऐसी केवल 1,202 कंपनियां बन पाईं। यह 97.6 फीसदी की हैरतअंगेज गिरावट थी। इस प्रकार एक जीवंत क्षेत्र का अंत हो गया।

अगर कोई वैश्विक कंपनी अपना ज्यादातर उत्पादन चीन से करना शुरू कर देती है तो सामान्य परिस्थितियों में बदलाव बहुत धीमी गति से ही हो पाता है क्योंकि किसी भी कंपनी का नेतृत्व बनी-बनाई उत्पादन व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। जब चीन में वेतन बढ़े तब भी इसी सोच के कारण कंपनियों की बहुत कम उत्पादन गतिविधियां उस देश से बाहर गईं। कंपनियों ने इस पर पुनर्विचार तब शुरू किया, जब चीन की सत्ता ताकत के मनमाने इस्तेमाल और राष्ट्रवाद मे डूब गई। तब ज्यादातर वैश्विक कंपनियों को अहसास हुआ कि विविधता के मोर्चे पर वे बहुत पिछड़ी हैं। उसके बाद अनूठा मौका आया, जब कई वैश्विक कंपनियों ने अपनी गतिविधियां चीन से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। अपनी उत्पादन व्यवस्था को नया रूप देने का वैश्विक कंपनियों का विचार 2018 से 2028 के बीच की अवधि का सबसे बड़ा रुझान रहा।

राष्ट्र के विकास के लिए एफडीआई क्यों आवश्यक है? विकसित देशों की कंपनियों के पास उन्नत ज्ञान होता है। जब वे भारत में काम करती हैं तो उनके साथ बेहतरीन प्रबंधन तकनीक और प्रौद्योगिकी आती है तथा भारतीय श्रम एवं पूंजी का इस्तेमाल कर वे उत्पादन में प्रत्यक्ष वृद्धि हासिल करती हैं। वे जिस बाजार में जाती हैं, वहां पहले से काम कर रही कंपनियों को चुनौती देती हैं और पूरे उद्योग की सूरत सुधार देती हैं। भारतीय कर्मचारी उनसे ज्ञान पा लेते हैं और दूसरी कंपनियों के लिए काम करने चले जाते हैं। इससे बेहतरीन ज्ञान पूरी अर्थव्यवस्था में फैलता रहता है। एफडीआई कंपनियों के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए जरूरी है, जिससे कंपनियों की उत्पादकता बढ़ती है।

वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों में आर्थिक नीति निर्माता वैश्विक एफडीआई माहौल में बदलाव लाने का सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। भारत की आर्थिक नीति बनाने वालों के लिए यही बेहतर होगा कि वे देश में विशुद्ध एफडीआई आवक को मौजूदा 26 अरब डॉलर का 10 गुना यानी 260 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय करें।

जिस समय वैश्विक कंपनियां चीन से उत्पादन बाहर ले जा रही हैं तब भारत को क्या फायदा हो रहा है? भारत से वस्तु निर्यात और देश में एफडीआई आवक के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एफडीआई पर चर्चा करते समय सतर्कता बरतते हुए भारत में एफडीआई और भारत द्वारा एफडीआई में अंतर करना होगा। जब भारत में एफडीआई की बात आती है तो उस पूंजी को घटा दें, जो वैश्विक कंपनियां यहां से अपने देश वापस ले गईं। इस तरह देश में शुद्ध एफडीआई प्राप्त होता है।

देश में एफडीआई दो तरह से आता है: विनिर्माण या बुनियादी ढांचे के लिए भौतिक संपत्तियां और देश में होने वाला सेवा उत्पादन जैसे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (जीसीसी)। पिछले एक दशक के दौरान सेवा निर्यात में अपेक्षाकृत बेहतर वृद्धि रही है। नॉमिनल डॉलर में इसने 8.45 फीसदी की चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी की है। ऐसे में सेवा क्षेत्र में एफडीआई का प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है और विनिर्माण तथा बुनियादी ढांचे में एफडीआई नॉमिनल डॉलर में -1.5 फीसदी (अर्थात् ऋणात्मक) चक्रवृद्धि दर से बढ़ा।

जब देश के वस्तु निर्यात में हुई 3.3 फीसदी की वृद्धि और शुद्ध एफडीआई में 1.5 फीसदी की ऋणात्मक वृद्धि को उस दौरान अमेरिका में तकरीबन 3 फीसदी की मुद्रास्फीति दर के साथ देखा जाता है तो प्रदर्शन और भी कमजोर लगता है। इस प्रकार हमें पता लगता है कि चीन मॉडल में बिखराव के समय जब बड़ी तादाद में वैश्विक कंपनियां वहां से हट रही थीं तब भारत में विनिर्माण तथा बुनियादी ढांचे में एफडीआई कमजोर रहा। इससे साबित होता है कि पहले से चली आ रही नीति (यानी बुनियादी ढांचे और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पर जोर) से सकारात्मक वृद्धि नहीं हो रही। यह बड़ी समस्या है, जिस पर ध्यान देने और समाधान करने की जरूरत है। क्या देश में आने वाले एफडीआई में 10 गुना बढ़ोतरी के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है? भारत के राजकोषीय संसाधन बहुत सीमित हैं और उनसे बड़ा अंतर नहीं आने वाला। अगर हमें लगता है कि भारत में काम करने में आने वाली दिक्कतों से निर्यात में 10 फीसदी की कमी आ जाती है और हम 1 लाख करोड़ डॉलर का निर्यात करना चाहते हैं तो यह सब्सिडी करीब 100 अरब डॉलर या 8.5 लाख करोड़ रुपये सालाना हो जाती है। यह एकदम अव्यावहारिक है।

एफडीआई 10 गुना करने के लिए हमें गहरी दिक्कतों से निपटना होगा। हमारे देश में वही दिक्कते हैं जो चीन में देखी गई थीं मगर छोटे पैमाने पर हैं। वर्क वीजा, पूंजी पर नियंत्रण, संरक्षणवाद, कर नीति और कर प्रशासन की दिक्कतें हैं। नियामक सरकार का अहम हिस्सा बन गए हैं और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाकर उनके पास मनमानी ताकत आ गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक राष्ट्रवाद (विदेशी फर्मों के साथ बराबरी का बरताव नहीं करना), केंद्र द्वारा नियोजन और विधि के शासन की कमी की। अलग किस्म के तकनीकी मानक और एकाधिकार तैयार करने की चीन और भारत सरकार की कोशिशें वैश्वीकरण की राह में बाधा पैदा करती हैं। जब कार्यपालिका किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है तो अदालत से राहत मिलना मुश्किल होता है क्योंकि देर भी होती है और गलत फैसला आने का अंदेशा भी रहता है। भारत में बौद्धिक संपदा की चोरी चीन की तुलना में बहुत छोटे स्तर पर होती है। नीति निर्माताओं को विदेशी तकनीक और प्रक्रिया के ज्ञान को सम्मान देते हुए इस पर सख्ती करनी चाहिए।

इन सभी समस्याओं को आर्थिक सुधारों की बेहतर प्रक्रिया के जरिये सुलझाया जा सकता है। सरकारी विभागों में क्रियान्वन करने वाली टीमों को उपाय सुझाने के लिए सक्षम अनुसंधान संगठनों की सेवा की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए ऊपर बताई गई समस्याओं का समाधान सुझाने वाले माहिर लोग पाना संभव है। जनता के धन का इस्तेमाल राजनीतिक अर्थव्यवस्था की दिक्कतें दूर करने के लिए भी किया जाना चाहिए। इन दोनों पर खर्च काफी कम होगा।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

आर्थिक लोकलुभावनवाद की नाकामी

नीति नियम

मिहिर शर्मा

अमेरिका में राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व प्रयोग हुआ है, जिसका परिणाम जल्द ही हमारे सामने होगा। वहां उप राष्ट्रपति कमला हैरिस अब डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और राष्ट्रपति चुनाव में वह पूर्व राष्ट्रपति तथा रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डॉनल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रही हैं। कई लोग इस चुनाव को इस बात की परीक्षा बताएंगे कि हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा की जा रही उदार मध्यमार्गी राजनीति क्या ट्रंप के लोकलुभावनवादी आंदोलनों के खतरे को विफल कर पाएंगी या नहीं।

परंतु इन चुनावों को एक और तरह से देखा जा सकता है। बाइडन और हैरिस ने बीते साढ़े तीन साल में जिस तरह प्रशासन चलाया है, उसने भी लोकलुभावनवाद को ही अंगीकार किया है - पुनर्वितरण की आर्थिक और अलग-थलग करने की विदेश नीति। ऐसे प्रशासन की 2016 में बराक ओबामा का कार्यकाल खत्म होते समय कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

बाइडन का आर्थिक लोकलुभावनवादी में बदलना असंभव प्रतीत हो सकता है। आखिर उन्होंने राजनीति में ही अपना करियर बनाया और उनका अधिकांश समय अमेरिकी सीनेट में गुजरा। वह विदेश नीति में अमेरिका को असाधारण मानने के शीत युद्ध कालीन विचार के अंतिम प्रतिपादक थे मगर अपने गृह राज्य डेलावेयर को अमेरिका में बेहद कम कर दर वाला एवं विनियामकों से बचाने वाला ठिकाना बनाने के प्रयासों का बचाव भी करते रहे। जिस सरकार में वह उपराष्ट्रपति रहे, वह अपने संयम और द्विदलीय व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयासों के नाम पर ही याद की जाती है।

इसके बावजूद पद पर रहते उनके पृथकतावादी प्रदर्शन की तुलना विश्व युद्ध के बाद के अमेरिकी इतिहास में केवल ट्रंप से हो सकती है। उनके कदम इसकी गवाही भी देते हैं: तमाम सलाहों के उलट अफगानिस्तान को बिना किसी तैयारी के तालिबान के हाथों में छोड़ देना, ट्रंप के दौर की शुल्क दरों को बरकरार रखना और पिछले राष्ट्रपतियों द्वारा विश्व व्यापार संगठन को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए पहल करने से इनकार करना।

हालांकि उन्होंने रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा लेकिन यूक्रेन की हर उस मांग (बेहतर हथियारों से लेकर लड़ाकू विमानों तक) को व्हाइट हाउस ने नकार दिया, जिससे उसे युद्ध में रूस को जवाब देने में मदद मिलती। बाइडन ने ऐसी मांगें तब मानीं, जब देर हो चुकी थी और उनका कोई फायदा नहीं होने वाला था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की और विभिन्न यूरोपीय नेताओं के साथ इस हफ्ते खिंचवाई गई तस्वीरें इस बात पर पर्दा नहीं डाल सकतीं कि यूक्रेन के लिए बाइडन उपयुक्त साझेदार नहीं साबित हुए और यूरोप के लिए भी वह सही कारोबारी साझेदार नहीं हो पाए।

बाइडन ने व्यापारिक समझौतों पर ट्रंप जैसा ही सख्त रुख अपनाया। अमेरिकी राजनयिकों ने 'मध्य वर्ग की विदेश नीति' वाला बाइडन का एजेंडा कहकर अक्सर इसे सही ठहराया। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि वैश्विक संबंधों और वित्तीय बाजारों के प्रति अविश्वास खत्म करने के इरादे से 'नई वॉशिंगटन सहमति' बनी है।

असाधारण स्तर का व्यय, लक्षित औद्योगिक नीति, शुल्क और प्रतिबंध, कठोर नियमन तथा एकाधिकार के इस डर को अमेरिकी प्रशासन ने 'बाइडनॉमिक्स' का नाम दिया है। इस रास्ते को डेमोक्रेटिक पार्टी ने तब चुना, जब 2016 में ट्रंप ने मामूली अंतर से जीत हासिल कर उन्हें स्तब्ध कर दिया। कभी औद्योगिक इलाके रह चुके मध्य-पश्चिम (मिडवेस्ट) अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का पुराना गढ़ था और पार्टी के कुछ लोगों को विस्कॉन्सिन तथा मिशिगन जैसे राज्यों में समर्थन के बिना जीत का कोई रास्ता नहीं दिखा। उन्होंने नतीजा निकाला कि इन राज्यों को वापस जीतने का एक ही तरीका है- क्षेत्र के लोगों और उद्योगों को भारी सब्सिडी। विनिर्माण को वापस गति देने की अमेरिकी कोशिश को इसी राजनीतिक अनिवार्यता के चश्मे से देखना चाहिए। 2016 में ट्रंप को तीन राज्यों में एक लाख मतों से जीत मिली थी और यह प्रशासन इन्हें वापस हासिल करने के लिए लाखों करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है।

बहरहाल इस विकल्प ने एक अन्य बदलाव को वैचारिक गहराई प्रदान की। पिछले डेमोक्रेटिक शासन के नए प्रशिक्षित टेक्नोक्रेट्स को बाइडन की टीम में जगह नहीं मिली। इसके बजाय बाइडन ने अपने चारों ओर युवा और गहन वैचारिक कार्यकर्ताओं को रखा, जिनमें से कई अर्थशास्त्री नहीं बल्कि अधिवक्ता या राजनयिक थे। उदाहरण के लिए मिडवेस्ट को वापस जीतने के लिए यह धारणा शायद ही जरूरी है कि अमेरिका के प्रतिस्पर्धा नियामक को कंपनियां केवल इसीलिए भंग कर देनी चाहिए क्योंकि वे बड़ी हैं, जबकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उनका आकार उपभोक्ताओं को लिए खराब साबित हो रहा है। इसके पीछे यह मान्यता काम कर रही है कि आर्थिक सिद्धांत से प्रेरित नीति ने ही 'हमारा यह हाल किया' यानी यही मुख्यधारा के दलों की अलोकप्रियता का कारण बनी और ट्रंप को जिता दिया। ऐसे में कंपनियों को तोड़ा जा सकता है या उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं चाहे उपभोक्ता मूल्यों पर उसका कोई भी असर पड़े।

कर्ज या घाटा बढ़ने की परवाह किए बगैर धन को इस उम्मीद में बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा कि इससे विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होंगे। यूनियन वाली कंपनियों को खरीद और सब्सिडी जैसे मामलों में प्राथमिकता मिलेगी चाहे उससे महंगाई क्यों न बढ़ जाए। सबसे महत्त्वपूर्ण बात थी 'मूल अमेरिकियों' को अपने साथ वापस लाना और विदेश जा चुकी वास्तविक अमेरिकी नौकरियों को लौटा लाना। ऐसे में बीते चार सालों में किए गए खर्च और सब्सिडी के अनेक उपाय तथा अमेरिकी कंपनी जगत की बढ़ती छानबीन इस बात का बड़ा और महंगाई प्रयोग है कि आर्थिक लोकलुभावनवाद राजनीतिक तौर पर कितना कारगर रहता है।

सवाल यह है कि क्या इससे कामयाबी मिलेगी? मैं कहूंगा कि यह पहले ही साबित हो चुका है कि इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक लोकलुभावनवाद मत दिलाने में कामयाब नहीं है। लोगों को लोकलुभावनवाद देखने में अच्छा लगता है मगर इसके नतीजों से वे नाखुश होते हैं। ऐसे व्यय पैकेज से महंगाई बढ़ती है और महंगाई किसी नेता के दोबारा चुनाव जीतने की संभावनाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है।

राष्ट्रपति चुनाव के लिए बहस में घटिया प्रदर्शन करने के बाद बाइडन चुनावी दौड़ से बाहर हुए हैं मगर वास्तव में उनकी लोकप्रियता पहले ही कम हो गई थी। महंगाई विशेष चिंता का विषय रही है। ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार महंगाई पर शिकायत कर सकते हैं किंतु ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक नस्ली और लैंगिक शिकायतों पर ही बोलते हैं। उनके अभियान को इसी बात ने जीवित भी रखा है। आर्थिक लोकलुभावनवाद शायद कारगर नहीं रहे-उदारवादियों की हार की असली वजह सामाजिक लोकलुभावनवाद और बहुसंख्यकवाद ही हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

मणिपुर में शांति व्यवस्था के लिए विश्वसनीय मंच जरूरी

मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए पुलिस, सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) और सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए। प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के अलावा समाज-सेवियों, महिला समूहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और राज्य की प्रमुख शख्सियतों के साथ बैठकें की जाएं। सर्वदलीय व सभी समाज प्रमुखों की बैठक भी बुलाई जानी चाहिए। वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखने वाला कोई भी देश आंतरिक गृहयुद्ध जैसी स्थिति का समर्थन नहीं कर सकता है। यह जितना लंबा चलता है, दो संघर्षरत समुदायों के बीच शांति और विश्वास बहाल करना उतना ही कठिन हो जाता है। यह एक संवेदनशील और अस्थिर सीमा क्षेत्र में गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, जिसमें भारत के विरोधी अपने लाभ के लिए शोषण कर सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बढ़ती चुनौती पैदा कर सकते हैं और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में अपने राजनयिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय उपायों के साथ जो अब तक स्पष्ट रूप से अपर्याप्त रहा है, उसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच बातचीत के लिए एक विश्वसनीय मंच बनाने की आवश्यकता है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

मणिपुर में शांति बहाल करने की मांग के साथ कुकी समुदाय के लोगों ने अगस्त में नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था

बजट के अनुसार ही हो लुभावनी योजनाएं

आजकल राजनीति में चुनाव जीतने के लिए जनता को लुभाने के लिए अनेक ऐसी योजनाओं की घोषणा की जाती है जो चुनाव जीतने और सरकार बनने पर पूरी करनी पड़ती हैं। इससे राज्य सरकारों को वित्तीय संकट से जूझना पड़ता है। पार्टियों और राज्य सरकारों को पहले अपने राज्य के बजट का अनुमान लगाना चाहिए। फिर योजनाएं बनानी चाहिए।

डॉ उमेश मित्तल, सहारनपुर

वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करना होगा।

जब तक राज्य सरकारें चुनावी लाभ के दृष्टिगत मतदाताओं को लुभाने के लिए बनाई गई योजनाओं और अनुत्पादक व्यय जैसे अनुदान तथा मुफ्त उपहार वाली योजना से परहेज नहीं करती तब तक राज्यों को वित्तीय संकट से रूबरू होना ही पड़ेगा। राज्यों को अपने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करना होगा। वेतन और पेंशन पर अधिक खर्च पर काबू करने के साहसिक फैसले लेने होंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए समुचित उपाय जरूरी है।

विमलेश पगारिया, बदनावर

लोकलुभावन योजनाओं पर नियंत्रण रखना होगा

राज्य सरकारों को चाहिए कि वे लोकलुभावन योजनाओं पर नियंत्रण रखे व राजस्व व्यय को तर्कसंगत बनाए। कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं के कारण राज्य सरकारों पर वित्तीय दबाव अधिक बढ़ रहा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वे राज्यों को एफआरबीएम एक्ट का कड़ाई से पालन के निर्देश दें। राज्य सरकारों को औद्योगिक विकास व पूंजीगत अधोसंरचना निर्माण पर बल देना चाहिए जिससे राज्य में राजस्व आय में वृद्धि हो सके।

शुभम ठाकरे, सिवनी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के छात्रों ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

विनिर्माण में वृद्धि

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रहे 'मेक इन इंडिया' अभियान के दस साल पूरे हो गये हैं. इस अवधि में घरेलू उद्योगों का विस्तार करने के साथ-साथ विदेशी निवेश और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय हुए हैं. लगातार होते सुधारों, नीतिगत परिवर्तन एवं पारदर्शिता, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े कदम, प्रक्रियाओं को सरल बनाने आदि के कारण कारोबारी सुगमता में शानदार प्रगति हुई है. वर्ष 2014 में 25 सितंबर को जब 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत की गयी थी, तब भारत की गिनती ऐसी पांच अर्थव्यवस्थाओं में होती थी, जिनके विकास का सिलसिला कभी भी टूट सकता था, पर आज भारत शीर्षस्थ पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है तथा कुछ ही वर्ष में उसके तीसरे स्थान पर पहुंचने की पूरी संभावना है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सही ही रेखांकित किया है कि तब सबसे बड़ी चुनौती उद्योगों का भरोसा जीतना था और इसमें कुछ समय भी लगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक की इस यात्रा की उपलब्धियों को बताते हुए कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है तथा उत्पादन क्षमता में विकास हुआ है. इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है. 'मेक इन इंडिया' अभियान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस कड़ी में 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों को भी जोड़ा है. उक्त अभियान में 25 क्षेत्रों को शामिल किया गया है. उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना से वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, रक्षा आदि क्षेत्रों में निर्यात में बड़ी वृद्धि हुई है. ये उपलब्धियां इसलिए और महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा है. उत्पादन बढ़ने से घरेलू बाजार की कई जरूरतों के लिए आयात पर से निर्भरता घटी है और भारत विनिर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है. यदि कोरोना महामारी, गंभीर भू-राजनीतिक संकट, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अस्थिरता जैसी बाधाएं नहीं आतीं, तो 'मेक इन इंडिया' अभियान की उपलब्धियां बहुत अधिक हो सकती थीं. इन उपलब्धियों से यह तो स्पष्ट है कि भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. आर्थिक आधार मजबूत होने तथा वैश्विक पटल पर छवि एवं प्रभाव में बढ़ोतरी से आज भारत निवेशकों और कंपनियों का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है. दस वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 119 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. बीते वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का निर्यात 778 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो एक रिकॉर्ड है. इससे इंगित होता है कि भारत में निर्मित वस्तुओं में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भरोसा बढ़ता जा रहा है. विनिर्माण की इस वृद्धि को गति देने की आवश्यकता है ताकि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सके.

बीते वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का निर्यात 778 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो एक रिकॉर्ड है.

श्रीलंका में नयी सरकार और भारत

डॉ धनंजय त्रिपाठी
प्राध्यापक, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी
नयी दिल्ली
dhananjay@sau.ac.in

पड़ोसी देशों, विशेष रूप से भारत और चीन, के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना नयी सरकार की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम होगा. अनुरा दिसानायके ने अपने भाषणों और साक्षात्कारों में यह रेखांकित किया है कि उनके नेतृत्व में श्रीलंका न तो किसी खेमे का हिस्सा होगा और न ही भू-राजनीतिक रस्साकशी से कोई मतलब रखेगा. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे चीन और भारत से संतुलित संबंध बनाने का प्रयास करेंगे. दिसानायके के सत्ता में आने को किसी भी तरह से भारत के लिए चिंता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

जब 2022 में श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा हुआ था, तब लोगों का सबसे अधिक रोष दशकों से सत्ता पर काबिज पारंपरिक परिवारों और पार्टियों के विरुद्ध था. उस समय महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति थे और उनकी सरकार के सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उनके परिवार के सदस्य ही बैठे हुए थे. सरकार में दो-तिहाई से अधिक पद उनके परिजनों और संबंधियों के पास थे. जनता के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि देश में फैला भ्रष्टाचार इसी कारण है और वे एक बड़ा बदलाव चाहते थे. जन विद्रोह के बाद सत्ता में आये रानिल विक्रमसिंघे लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे. ऐसे में मुख्य मुकाबला विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा और अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच हुआ तथा दिसानायके अंततः श्रीलंका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए. दिसानायके की जीत यह इंगित करती है कि वहां बड़े बदलाव की उम्मीद लोग रखते हैं. नयी सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो पिछली सरकार के समक्ष भी थे, कि देश की आर्थिक स्थिति में ठोस सुधार हो.

दो साल पहले श्रीलंका की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी थी. उस समय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत समेत अनेक देशों और संस्थानों के सहयोग से स्थिति को संभाला जा सका था. दिसानायके के लिए सबसे बड़ी परीक्षा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ही होगी. दूसरी बड़ी चुनौती है कि आम जनता के मन में शासन और संबंधित संस्थाओं में फिर से भरोसा बहाल करना. यह भरोसा राजपक्षे के दौर में पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके कारण व्यापक जन विद्रोह हुआ था. हालांकि कुछ समय से पर्यटन के क्षेत्र में उत्साहजनक बढ़ोतरी देखी गयी है, पर इसे मजबूत बनाने की एक प्रमुख जिम्मेदारी नयी सरकार के सामने होगी. पर्यटन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है. इस क्षेत्र को विकसित किये बिना आर्थिक परिदृश्य को बेहतर कर पाना संभव नहीं होगा. तमिल समेत विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों तथा समाज के अन्य हिस्सों के बीच सद्भाव और विश्वास बढ़ाना भी दिसानायके सरकार के लिए एक बड़ा कार्य है. राजपक्षे के कार्यकाल में सामाजिक और सामुदायिक ताने-बाने को भी बड़ा नुकसान हुआ था. उस समय बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आये थे. श्रीलंका जैसा छोटा देश दशकों तक तरह-तरह की हिंसा का शिकार रहा है. इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान नयी सरकार को रखना होगा. ये प्रमुख मुद्दे ही दिसानायके की प्राथमिकताओं में होंगे और इनसे संबंधित कार्यों से ही उनकी सफलता या असफलता का निर्धारण होगा.

पड़ोसी देशों, विशेष रूप से भारत और चीन, के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना नयी सरकार की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम होगा. अनुरा दिसानायके ने अपने भाषणों और साक्षात्कारों में यह रेखांकित किया है कि उनके नेतृत्व में श्रीलंका न तो किसी खेमे का हिस्सा होगा और न ही भू-राजनीतिक रस्साकशी से कोई मतलब रखेगा. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे चीन और भारत से संतुलित संबंध बनाने का प्रयास करेंगे. दिसानायके के सत्ता में आने को किसी भी तरह से भारत के लिए चिंता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. वे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुने गये हैं तथा उनका निर्वाचन उनके देश की आंतरिक स्थिति और राजनीतिक परिस्थिति का परिणाम है. वामपंथी रुझान के दिसानायके को जीत के बाद भारत के शीर्ष नेताओं तथा भारतीय उच्चायोग ने गर्मजोशी के साथ बधाई दी है तथा परस्पर संबंधों में बेहतरी की उम्मीद जतायी है. कहीं से भी ऐसे संकेत नहीं हैं कि भारत उनके साथ गहरा संपर्क नहीं रखना चाहता है या वे भारत से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं. अगर आप दक्षिण एशिया को देखें, तो केवल श्रीलंका ही नहीं, बल्कि सभी देश यह मानते हैं कि भारत और चीन दोनों से ही अच्छे संबंध आज के समय में उनकी आवश्यकता है. श्रीलंका पर चीन का खासा कर्ज है और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वह भी उसकी आर्थिक दुर्दशा का एक कारक रहा है. ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि नये नेतृत्व का झुकाव पूरी तरह से केवल चीन की ओर होगा.

उल्लेखनीय है कि जब श्रीलंका में आर्थिक संकट आया था, तब भारत ने सबसे पहले आगे आकर मदद मुहैया करायी थी. तत्काल तेल, अनाज, दवाइयां आदि भेजी गयीं थी तथा मौद्रिक सहयोग भी दिया गया था. इससे श्रीलंका में एक संदेश तो गया है कि भारत एक ऐसा पड़ोसी देश है, जो संकट में तुरंत सहायता पहुंचा सकता है. इस संदर्भ में हमें मालदीव का ध्यान रखना चाहिए, जहां नयी सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के संबंध बिगड़ जायेंगे, लेकिन बहुत जल्दी ही नकारात्मक पहलुओं को किनारे रखकर निकटता बढ़ाने के प्रयास हुए. मालदीव भी भारत से लगातार संपर्क में है और भारत भी सहायता उपलब्ध करा रहा है. अगर तमिल मुद्दे को छोड़ दें, तो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई गंभीर मसला कभी नहीं रहा है. राजपक्षे के दौर में उनका चीन के प्रति अधिक झुकाव रणनीतिक रूप से भारत के लिए एक असहज स्थिति थी, पर पीछे की बात हो चुकी है. संकट के बाद श्रीलंका को यह अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि केवल चीन के भरोसे रहने से फायदा नहीं है और भारत से भी नजदीकी रहना जरूरी है. तो ऐसी कोई खास चिंता की बात नहीं है, जैसा कि हमारी मीडिया में कभी-कभी बताया जाता है.

यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति दिसानायके ने हरिणी अमरसुरिया को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और भारत से अच्छी तरह से परिचित हैं. वे श्रीलंका की एक प्रतिष्ठित विद्वान भी हैं. यह भी स्वागतयोग्य है कि एक महिला विद्वान को प्रधानमंत्री बनाया गया है. यह भी उल्लेखनीय है कि अनुरा कुमारा दिसानायके और उनकी पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना भारत के लिए कोई अनजान नहीं है. सरकार और विपक्ष के अनेक दलों से उनका संवाद होता रहा है. चुनाव अभियान के दौरान उनके नेशनल पीपुल्स पॉवर गठबंधन की तरफ से ऐसी कोई बात भी नहीं कही गयी, जिससे यह अंदेशा हो कि भारत के साथ नयी सरकार के संबंध अच्छे नहीं होंगे. हमें ऐसी कोई सोच भी इस समय नहीं बनानी चाहिए और यह इंतजार करना चाहिए कि उनकी विदेश नीति की दिशा क्या होती है. देशों के आपसी संबंध एक-दो दिन के लिए नहीं होते हैं. मालदीव को लेकर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि परस्पर संबंध पहले की तरह ही हैं. हमें उम्मीद रखनी चाहिए.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

पर्यावरण की बेहतरी के प्रयास की समीक्षा जरूरी

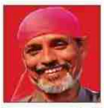

अनिल प्रकाश जोशी
प्रतिष्ठित पर्यावरण कार्यकर्ता
dranilpjoshi@gmail.com

पारिस्थितिकी से जुड़े कार्यों का सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की तरह कोई एक आकलन या सूचक नहीं है. यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में है. पारिस्थितिकी विकास कार्यों का व्यवस्थित विवरण आना चाहिए. एक सकल पर्यावरणीय उत्पादन सूचक जैसा कुछ बनाया जाए, जिससे पता चले कि प्रकृति और पर्यावरण की बेहतरी के लिए क्या क्या प्रयत्न हो रहे हैं और उनके परिणाम क्या हैं.

अब जब देश-दुनिया को मुख्यतः आर्थिक दृष्टिकोण से ही आंका जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि पर्यावरण और प्रकृति को समुचित प्राथमिकता नहीं दी जाती. हमारा देश भी तेजी से प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की होड़ में है. पर पारिस्थितिकी, जो आर्थिक विकास का मूल आधार है, उस पर उतनी चिंता नहीं की जाती, जितनी आवश्यक है. जबकि इस पर व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए. मौजूदा समय में जब मानसून के खिसकते हुए अक्तूबर तक पहुंचने की संभावना है, इस वर्ष गर्मी भी प्रचंड रही हो और साथ ही इस बार ठंड भी नये तर्ज में पड़ने की आशंका हो, तब यह आवश्यक हो जाता है कि विकास को विनाशकारी बनने से बचाया जाए. जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे किसी भी तरह से अनदेखा और अनसुना नहीं किया जाना चाहिए.

यह सब कुछ मानवीय लालच की वजह से ही हो रहा है. यदि हम आज नहीं समझे, तो कल स्थिति का बेहद भयावह होना निश्चित है. इस बार की बारिश को ही देखिए कि इसने कैसे देश के कई हिस्सों में तबाही मचायी है. इस साल गर्मी ने सारी दुनिया में पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये हैं. मतलब अब कोई देश या स्थान विशेष ही प्रकृति के प्रकोप को नहीं झेलेगा, हर जगह हालात बिगड़ते जायेंगे. ऐसे में दुनिया में विकास को विनाशकारी होने से बचाया जाना चाहिए. इसके लिए पारिस्थितिकी पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, जितना कि आर्थिक विकास पर. यह तभी संभव होगा, जब हम पारिस्थितिकी का भी बराबर ब्यौरा रखें. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस मामले में सरकारें कुछ नही करतीं, बस अंतर यही है कि उन्हें यह नहीं पता है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था के सापेक्ष उन्हें पारिस्थितिकी के लिए कितना करना चाहिए. उदाहरण के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जो लगातार आपदाओं का सामना कर रहे हैं, और साथ में भरपाई का भी काम करते हैं, पर कितनी भरपाई हुई, इससे संबंधित आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता. यह स्थिति विशेष रूप से बिहार में है, जिसने दशकों से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है. हाल में बिजली गिरने की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है, जो पारिस्थितिकी में हो रहे बदलावों का संकेत देती है.

इन राज्यों का एक और महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने आर्थिक विकास के साथ-साथ अपनी पारिस्थितिकी को बेहतर बनाने के प्रयास किये हैं. मसलन, बिहार में 'जल जीवन अभियान' के तहत नदियों की सुरक्षा और संरक्षण पर उल्लेखनीय ध्यान दिया गया है. खास तौर पर गंगा नदी, जो बिहार में लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है, न केवल आर्थिक, बल्कि पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है. पिछले एक दशक में बिहार में वनों के विस्तार के लिए भी गंभीर प्रयास हुए हैं. लेकिन इन प्रयासों का उचित आकलन नहीं किया गया है. बिहार में पारिस्थितिकी को सुधारने के लिए सरकार और आम जनता ने मिलकर कोशिशें की हैं. यहां की संस्कृति में नदियों का पूजन और वनों की देखभाल का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है. पिछले दशक में सरकार की विभिन्न योजनाओं, विशेषकर जल जीवन और वन संरक्षण की दिशा में की गयी पहलों ने जल संरक्षण और वनों के विस्तार पर जोर दिया है. जल जीवन हरियाली योजना में सभी विभागों को जोड़कर कार्य योजना तैयार की गयी है, जिससे स्वतः जंगल, मिट्टी, पानी एक साथ जुड़ गये.

बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का यह मानना कि नदियों की जल निर्मलता से ज्यादा इनका जल प्रवाह बने रहना जरूरी है, महत्वपूर्ण बात है. जब तक नदियों का प्रवाह और जल स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक उन्हें सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सकता. बिहार से यह आवाज उठी है कि गंगा और अन्य नदियों के प्रवाह को गंभीरता से लेना चाहिए. असल में पारिस्थितिकी से जुड़े कार्यों का सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की तरह कोई एक आकलन या सूचक नहीं है. यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में है. पारिस्थितिकी विकास कार्यों का व्यवस्थित विवरण आना चाहिए. एक सकल पर्यावरणीय उत्पादन सूचक जैसा कुछ बनाया जाए, जिससे पता चले कि प्रकृति और पर्यावरण की बेहतरी के लिए क्या-क्या प्रयत्न हो रहे हैं और उनके परिणाम क्या हैं. इससे समुचित लेखा-जोखा मिला जायेगा, जिससे आगे की कार्य-योजना और रणनीति बनाने में बड़ी मदद मिलेगी. उत्तराखंड ने इस वर्ष पहली बार सकल घरेलू उत्पादन के समानांतर अपने वनों, मिट्टी, पानी और हवा का आकलन सकल पर्यावरण उत्पादन के रूप में दिया है. यह एक संकेत है कि आर्थिक उत्थान के साथ पारिस्थितिकी उत्थान भी होना चाहिए. यह पहल न केवल देश के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो सकती है. अब यह तो किसी बहस का विषय नहीं रहा है कि हम एक गंभीर पर्यावरणीय संकट से घिर चुके हैं. ऐसे में समाधान की दिशा में बढ़ने और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों और परिणामों का ब्यौरा और उसकी ठोस समीक्षा की आवश्यकता बहुत बढ़ गयी है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

श्रीलंका को सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान देने की जरूरत

श्रीलंका के नेता अनुरा दिसानायके ने चुनाव में आसान जीत दर्ज कर सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली. पचपन वर्षीय दिसानायके ने पूर्व में ही श्रीलंकाई लोगों से वादा किया था कि वह आइएमएफ बेलआउट पैकेज की शर्तों- जिसने यहां के लोगों की कठिनाइयों को काफी बढ़ा दिया है- पर फिर से बातचीत करेंगे. वर्ष 2022 में श्रीलंका सरकार के कर्ज चुकाने में असफल रहने के बाद बीते वर्ष आइएमएफ ने देश के लिए तीन अरब डॉलर के वित्तीय सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी थी. जिनमें से अब तक एक अरब डॉलर से अधिक का वितरण हो चुका है. हालांकि श्रीलंका को यह सहायता कड़ी शर्तों के साथ मिली है, जिससे लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों की कठिनाई और बढ़ गयी है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की पूर्व डीन, अनुराधा चिनॉय की मानें, तो अर्थव्यवस्था पर आइएमएफ की पकड़ के मजबूत होने से पश्चिमी शक्तियों के लिए हस्तक्षेप करना आसान हो गया है. गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने विनाशकारी आर्थिक नीतियां अपनायीं. गोटाबाया ने धनिकों के लिए करों को कम किया और कृषि क्षेत्र को जैविक खेती की ओर स्थानांतरित करने का प्रयास किया, जिसका व्यापक विरोध हुआ. ये प्रदर्शन न केवल राजपक्षे शासन, बल्कि आइएमएफ के भी विरुद्ध थे. ऐसे में दिसानायके के लिए सबसे बड़ी चुनौती आइएमएफ और अन्य पश्चिमी ऋणदाताओं द्वारा लगायी गयी शर्तों का विरोध करना होगा. ये संस्थाएं अक्सर छोटे देशों को कर्ज और बढ़ती असमानता के चक्र में फंसा देती हैं, जहां छोटे से अभिजात वर्ग के पास सर्वाधिक संपत्ति होती है, जबकि अधिकांश लोग गरीब ही रहते हैं. ऐसे में श्रीलंका की नवनियुक्त सरकार को सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान देने और आइएमएफ द्वारा डाले गये दबाव को एक बड़ा मुद्दा बनाने एवं इसका प्रतिकार करने के तरीकों की तलाश करने की आवश्यकता है.

-पवन अत्री

बोधि वृक्ष

सच्चे मन से पश्चाताप

जगत में प्रत्येक वस्तु का अपना मूल्य है, एक महत्व है. किसी भी वस्तु का तिरस्कार नहीं किया जा सकता. भगवान और भागवत भिन्न नहीं हैं. इसी प्रकार जगत और ईश्वर भी पृथक नहीं हैं. अतः हमें विश्व की प्रत्येक वस्तु की आधारभूत एकता पर दृष्टि रखनी चाहिए. हमें उन सब विधि-विधानों का आदर करना चाहिए जो व्यक्ति के आत्मबोध के लक्ष्य की ओर प्रगति में सहायक होते हैं. चाहे आपने कितने ही पाप क्यों न किये हों, उन्हें सत्कर्मों तथा आत्मशुद्धि के लिए किये गये साधनाओं द्वारा धोया जा सकता है और अंततः आत्मबोध की प्राप्ति की जा सकती है. सच्चे हृदय से पश्चाताप करने पर प्रत्येक पापी के लिए मुक्ति की संभावना है. ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसे पश्चाताप से धोया न जा सके. किंतु हम स्नान करते हुए हाथी जैसे न बनें, जो पानी से बाहर आते ही मिट्टी लेकर फिर से अपने शरीर पर उड़ेल लेता है. बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं. जीवन की राह पर चलते-चलते हमसे भूलें हो सकती हैं. भूल हो जाए, तो निराश हो कर न बैठ जाएं. यदि हम फिसल कर गिर जाएं, तो हमें यह सोच कर वहीं पड़े नहीं रहना चाहिए कि यहां जमीन पर पड़े रहने में कितना सुख है. हमें उठकर फिर से अपने गंतव्य की ओर चल देना चाहिए. गिरने पर निराश होने की जगह उठ खड़े हों और आगे चलें. यदि आप पेंसिल से लिख रहे हैं और कोई गलती हो जाए, तो उसे रबर से मिटा कर ठीक कर सकते हैं. परंतु यदि इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराते रहेंगे तो कागज फट जायेगा. जब हम भूल करें, तब भी सच्चे मन से प्रयास करें कि उन्हें फिर से न दोहराएं. गलती मनुष्य से हो जाती है, किंतु हमें सावधान रहना चाहिए तथा हार नहीं मानना चाहिए. अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी को अयोग्य घोषित कर नकारना नहीं चाहिए. स्वीकारने का दृष्टिकोण अपनाएं. लोग भूलें करते हैं क्योंकि वे अपने सत स्वरूप से अनभिज्ञ हैं. अतः उनकी उपेक्षा अथवा निंदा करना कोई समाधान नहीं है. बल्कि, हमें उन्हें सही ज्ञान दे कर उनका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा सहित इस ओर प्रयास करना चाहिए.

-श्री माता अमृतानंदमयी देवी

जयंती विशेष

समाज सुधार के अग्रदूत थे ईश्वरचंद्र

देवेंद्रराज सुथार
टिप्पणीकार
devendrakavi1@gmail.com

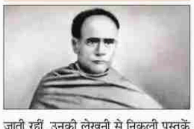

छब्बीस सितंबर, 1820 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के बिरसिंघा गांव में जन्मे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने रूढ़िवादी मान्यताओं और कुरीतियों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया. उन्होंने निर्धनता के बावजूद अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की. उनका असली नाम 'ईश्वरचंद्र बंद्योपाध्याय' था. उन्होंने संस्कृत कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने व्याकरण, साहित्य, अलंकारशास्त्र, वेदांत, स्मृति, न्याय आदि विषयों में महारत हासिल की. उनकी असाधारण विद्वत्ता के कारण उन्हें 'विद्यासागर' की उपाधि से सम्मानित किया गया. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया. न केवल बंगाली भाषा और साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि शिक्षा प्रणाली में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किये. बंगाली वर्णमाला को पुनर्व्यवस्थित किया और बंगाली भाषा में अक्षरों को समझाने वाली पहली व्याकरण पुस्तक 'वर्ण परिचय' लिखी.

उन्होंने कई पाठ्य-पुस्तकें भी लिखीं जो लंबे समय तक बंगाल के स्कूलों में पढ़ाई जाती रहीं. उनकी लेखनी से निकली पुस्तकें 'बोधोदय', 'कथामाला', 'चरितावली' और 'आख्यान मंजरी' बंगाली साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं. शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ समाज सुधार के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किये. उनके प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ. उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध भी आवाज उठायी. महिला शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल खोले. उन्होंने संस्कृत कॉलेज में प्रवेश के नियमों में परिवर्तन पर जोर देकर जाति के आधार पर प्रवेश की प्रथा को समाप्त किया. मेट्रोपॉलिटन कॉलेज (वर्तमान में विद्यासागर कॉलेज) की स्थापना भी की. वे केवल एक शिक्षाविद या समाज सुधारक ही नहीं थे, कुशल प्रशासक और करुणा सिंधु भी थे. उन्होंने संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य किया और फोर्ट विलियम कॉलेज में भी महत्वपूर्ण पद संभाला. उनकी प्रशासनिक क्षमताओं ने इन संस्थानों को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उनका व्यक्तिगत जीवन सादगी और परोपकार का अप्रतिम उदाहरण था. वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा गरीबों पर खर्च करते थे.

उन्होंने बंगाली गद्य को एक नया स्वरूप दिया और इसे आम लोगों की भाषा बनाया. उन्होंने संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों का बंगाली में अनुवाद किया, जिससे ये रचनाएं आम जनता तक पहुंच सकीं. उनकी भाषा शैली ने बाद के कई लेखकों को प्रभावित किया और बंगाली साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. 29 जुलाई, 1891 को उन्होंने कलकत्ता (अब कोलकाता) में अंतिम सांस ली.

आपके पत्र

शिक्षा और स्वास्थ्य की सुलभता

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ ही जनसंख्या में भी प्रथम स्थान पर है. सो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुलभता के मामलों में भारत को और मजबूत होना होगा. स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी अभी तक देश के सभी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी है. यह कमी देश के विकास को बाधित कर रही है. शिक्षा और चिकित्सा को देश के अंतिम छोर तक पहुंचाना सरकार का कर्तव्य है. ऐसा होने पर ही भारत तेज गति से विकास कर सकेगा.

विवेक कुमार, रांची

क्वाड की सक्रियता और चीन

क्वाड की सक्रियता से चीन की चिंता बढ़ी है. यह विडंबना ही है कि क्वाड के किसी भी सदस्य देशों से चीन की नहीं बनती. इसका कारण चीन की विस्तारवादी सोच है. क्वाड नेताओं ने चीन का सीधे नाम लिये बिना ही दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के जल क्षेत्र की स्थिति पर गंभीर चिंता जतायी है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर साझा चिंताओं के मद्देनजर क्वाड नेताओं ने ऐसी किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है, जो यथास्थिति को बदलने का प्रयास करता है.

युगल किशोर राही, छपरा

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ फैक्स करें : 0651-2544006 ■ मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 26 सितंबर 2024

ज़बान संभाल के

कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की ओर से हाल में एक सुनवाई के दौरान की गई अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जो सख्त हिदायत दी, वह जूडिशरी के साथ ही शासन और समाज के अन्य हिस्सों पर भी लागू होती है। संबंधित जज की ओर से माफी मांग लिए जाने के बाद इस केस को ठीक ही बंद कर दिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस की अगुआई वाली पांच सदस्यीय बेंच के इस दौरान दिए गए ऑब्जर्वेशन खास तौर पर गौर करने लायक हैं।

AI Image
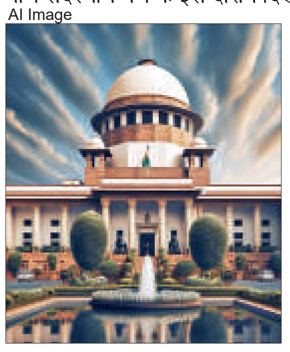
सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत

टिप्पणी में पूर्वाग्रह | यह मामला महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हाईकोर्ट के जज की जो टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, उनमें दिखने वाला पूर्वाग्रह समाज के व्यापक दायरे में प्रचलित है। रोजमर्रा की जिंदगी में आम तौर पर लोग शहर के किसी खास हिस्से का पाकिस्तान या मिनी पाकिस्तान के रूप में जिक्र करते पाए जाते हैं। महिला विरोधी पूर्वाग्रह भी हमारे समाज की एक पुरानी और गहरी बीमारी है। ऐसे में जब हाईकोर्ट का जज किसी महिला वकील पर अशोभनीय टिप्पणी करता या शहर के किसी खास हिस्से को पाकिस्तान बताता दिखेगा तो उसके दुष्प्रभावों की सहज ही कल्पना की जा सकती है।

तत्पर कार्रवाई | निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू करना शुभ संकेत है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का यह कहना भी अहम है कि देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान बताना हमारी क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख से न केवल न्यायपालिका को बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे सभी लोगों को यह संदेश दिया है कि उन्हें अपनी टिप्पणियों को लेकर गंभीर होना चाहिए।

पारदर्शिता जरूरी | इस मामले का एक और अहम पहलू है पारदर्शिता। चूंकि यह मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आई टिप्पणी के सोशल मीडिया पर वायरल होने का था और जज का कहना था कि उनकी टिप्पणी को संदर्भों से काटकर पेश किया गया है, इसलिए कुछ हलकों में यह बात भी होने लगी थी कि हाईकोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न रखते हुए साफ कर दिया कि अगर पारदर्शिता से कोई समस्या आती है तो उसका एकमात्र जवाब है और ज्यादा पारदर्शिता।

सोशल मीडिया का दौर | सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि सोशल मीडिया आज के दौर की हकीकत है और इससे बचने का प्रयास करने के बजाय इसकी मौजूदगी को स्वीकार करते हुए बेहतर तैयारी के साथ इससे पेश आने की जरूरत है।

साड्डी दिल्ली

उर्दू में रामलीला

विवेक शुक्ला

सुरेंद्र गंभीर ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, लेकिन बीते कई बरसों से वह अपने घर के आसपास आयोजित होने वाली रामलीला नहीं देख रहे। वह फरीदाबाद जाते हैं रामलीला देखने। वहां की रामलीला के संवाद और माहौल को देखकर उन्हें लगता है कि वह अपने पुरखों के शहर मुल्तान में हैं। फरीदाबाद के सेक्टर-12 में होने वाली श्री श्रद्धा रामलीला देश में इकलौती है, जिसके अधिकतर संवाद उर्दू में होते हैं। इसके कलाकार आजकल फरीदाबाद में दिन-रात तैयारी कर रहे हैं। एक संवाद पढ़िए, इसमें राम ललकारते हैं रावण को, 'जुल्म, तू जुल्म की निशानी है। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी मौत बहुत करीब है।' अब रावण का जवाब भी सुनिए, 'राम, मैंने मौत पर फतेह पा ली है। पूरी कायनात में मेरे से ज्यादा बड़ा और ताकतवर शख्स कोई नहीं है। मेरे से फलक भी खौफ खाता है। तू जा अपना काम कर।' एक संवाद हनुमान जी का भी देखें। वह रावण से कह रहे हैं, 'बेशक, अभी तक गुण और ज्ञान आपके पास जरूर है, मगर आपका गुरूर आपको मिट्टी में मिला देगा।'

फरीदाबाद में पाकिस्तान के मुल्तान, बन्नू और खैबर पख्तूनख्वा के लाखों लोग बसे हुए हैं। अब इनकी तीसरी पीढ़ी भी बड़ी हो गई है। ये वही रामलीला करते हैं जो इनके बड़े-बुजुर्ग अपने शहरों में किया करते थे। देश के बंटवारे के बाद भी इन्होंने अपनी रवायत को बचाकर रखा। अपने अलग तरह के संवादों की वजह से मशहूर हो गई इस रामलीला में फरीदाबाद के चावला परिवार के पांच सदस्य अलग-अलग किरदारों में नजर आते हैं। पेशे से बिजनेसमैन अनिल चावला पिछले 16 बरसों से लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं और इसके डायरेक्टर भी हैं। इसमें उनके दो छोटे भाई रावण और हनुमान जी का रोल निभाते हैं। पेश है हनुमान जी का एक और मार्मिक संवाद। वह सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और दंडवत प्रणाम करने के बाद अपना परिचय देते हुए कहते हैं, 'मां, आप कतई फिक्र न करें। मैं आपको हिफाजत के साथ भगवान राम के पास ले जाऊंगा।' ऐसे ही एक संवाद में सीता जी से रावण कहता है, 'अब भूल जा अपने शौहर को। मैं ही हूं तेरा शौहर।' सीता जी यह सुनते ही चीखते हुए कहती हैं, 'दगा-फरेब से मुझको ले आया तू। जलील शख्स। मनहूस इंसान। तू खाक हो जाएगा।'

पिछले कुछ बरसों से उर्दू रामलीला ने फरीदाबाद की सीमाओं को पार करना भी शुरू कर दिया है। इसने 2017 में मुंबई के पृथ्वी थिएटर में रामलीला का मंचन किया और खूब वाहवाही हासिल की। इसके बाद 2018 में राजधानी के ध्यानचंद स्टेडियम में जश्न-ए-रेख्ता में उर्दू रामलीला का मंचन हुआ। इसी साल दिल्ली उर्दू अकादमी की तरफ से सुंदर नर्सरी में भी रामलीला का दर्शकों ने लुत्फ उठाया।

एकदा

साहित्य की लगन

पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक गांव है, महिषादल। उस गांव का एक बालक 8वीं की बोर्ड परीक्षा दे चुका था। रिजल्ट का समय धीरे-धीरे नजदीक आ रहा था। उस बच्चे ने अपने पिता से कह दिया कि इस बार सूबे में पहला स्थान उसी का होगा। पुत्र की बात से पिता पं. रामसहाय त्रिपाठी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हीं दिनों जमींदार के यहां किसी की शादी थी। सूबे में पहले स्थान का दावा करने वाले इस छात्र ने अपने पिता से कहा कि उसे बारात का निमंत्रण मिला है। पिता ने झटपट पोशाक सिलवा दी। बारात के दिन वह घर से निकला, लेकिन ससुराल पहुंच गया। सास-ससुर से बोला कि जमीन के विवाद में उसके पिता की पड़ोसियों से मारपीट हो गई है और वह जेल में हैं। जमानत के लिए 300 रुपये चाहिए। 150 रुपये का ही इंतजाम हो पाया। लड़के ने भक्ति भाव से सास-ससुर के चरण छुए और स्टेशन पहुंच गया। कलकत्ता का टिकट खरीदा। उसे पता था कि गणित की नीरस उत्तर पुस्तिका को पद्माकर के आह्लादित करने वाले कवित्तों से भरने पर अध्यापक उसे क्यों नंबर देंगे। उसका फेल होना पक्का था, लेकिन उसे अब पिता का सामना नहीं करना पड़ेगा। 8वीं में फेल होने वाला यह बालक उस समय पद्मावत पढ़ रहा था, जब उसके साथी गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और भाषा पढ़ते थे। परीक्षा परिणाम और पिता के भय से घर छोड़ने वाला यह बालक आगे चलकर जो साहित्य लिखता है उसे 8वीं का, 16वीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसे हम निराला साहित्य कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने अभिरुचि के महत्व को दुनिया को समझा दिया।

Subrata Dhar
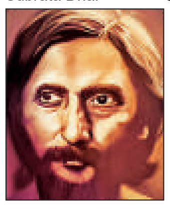

संकलन : हरिप्रसाद राय

नब्बे के दशक की राजनीतिक अस्थिरता पीछे छूट चुकी है, यही समय है ONOE की ओर बढ़ने का

बार-बार चुनाव के चक्र से निकले देश

अवधेश कुमार

एक देश एक चुनाव (ONOE) पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी उस दिशा में आगे बढ़ने के मोदी सरकार के निश्चय का संदेश है। हालांकि विरोधियों की प्रतिक्रियाएं वैसी ही हैं, जैसी पहले दिन से रही हैं। इस 8 सदस्यीय समिति ने सारे प्रासंगिक सवालों पर विचार कर उनके उत्तर तलाशने की अधिकतम संभव कोशिश की है।

समिति के 7 कार्य | समिति को मुख्यतः सात कार्य दिए गए थे।

1. संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायत चुनाव साथ कराने की संभावना तलाशना।
2. इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना।
3. त्रिशंकु सदन, दलबदल या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण बनने वाले गतिरोध का समाधान तलाशना।
4. एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना। अगर साथ चुनाव संभव न हों तो इसके अलग-अलग चरणों और समयसीमा का सुझाव देना।
5. एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद यह चक्र न टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना।
6. चुनाव कराने के लिए EVM, VVPAT, मानवबल सहित अन्य जरूरत का आकलन करना।
7. पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल मतदाता सूची और पहचानपत्र बनाए जाने की सिफारिश करना।

साल 2029 तक एक देश एक चुनाव लागू करने का है इरादा

2029 की समय सीमा | समिति का सुझाव है कि पहले चरण में आठ राज्यों के चुनावों को एक साथ लाकर लोकसभा के साथ आयोजित किया जाए और उसके 100 दिन बाद स्थानीय निकायों के चुनाव हों। तीन चरणों के प्रयासों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा।

कोविंद समिति के सुझाव
- कई देशों की चुनाव प्रणालियों पर विचार
- गतिरोध की संभावनाओं पर खास ध्यान
- साथ चुनाव तक पहुंचने के लिए 5 साल

विदेशी चुनाव प्रणालियां | समिति ने रिपोर्ट तैयार करने के पहले कई देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया। ये देश हैं, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में नैशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ मतदान होता है। स्वीडन में आनुपातिक चुनाव प्रणाली के तहत संसद (रिक्सडैग), काउंटी और नगर परिषदों के चुनाव एक ही समय में होते हैं। इंडोनेशिया में भी 2019 से एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। जो कुछ अन्य देश कर सकते हैं वह हम क्यों नहीं कर सकते?

पहले की सिफारिशें | 1999 में ही विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने की बात कही गई थी। उसके बाद 2015 में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय मामलों की संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की। अगस्त, 2018 में फिर विधि आयोग की रिपोर्ट आई, जिसमें दो चरणों में चुनाव कराने का सुझाव था। विधि आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद- 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाए-घटाए जा सकते हैं तथा राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे वांछित समय पर भंग किया जा सकता है।

दो दशक तक साथ चुनाव | आजादी के बाद से 1967 तक सभी चुनाव निश्चित समयावधि में साथ ही होते थे। 1967 में कांग्रेस का एकाधिकार टूटने, आठ राज्यों में गठबंधन सरकारें (जिन्हें संविद सरकार कहा गया) बनने और उनके असमय गिर जाने से समस्या बढ़ी।

अस्थिरता का दशक | 1989 से 1999 का दशक भारतीय राजनीति में बड़े अस्थिरता का था जिसमें केंद्र और राज्यों की सरकारें असमय जाती रहीं। कुल मिलाकर, असामान्य स्थिति के कारण पूरा चुनावी चक्र गड्ड-मड्ड हो गया। दुर्भाग्य से इसे ही हम सामान्य मानकर बदलने की कल्पना से डरते हैं।

हर साल चार चुनाव | हर वर्ष हमारे यहां औसतन चार विधानसभा चुनाव होते हैं। चुनाव के कारण राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा अनेक बार दुश्मनी में बदल जाती है और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक राजनीतिक एकता नहीं हो पाती।

यही समय है | देश अस्थिर राजनीति के दौर से काफी हद तक बाहर दिख रहा है। 1999 से केंद्र सरकारें कार्यकाल पूरा कर रही हैं। राज्यों में भी 2010 के बाद से पूर्ण बहुमत की सरकारें बन रही हैं। तो यह उचित समय है जब हम बार-बार चुनावों की स्थिति से बाहर निकल आएं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक हैं)

एक्शन मिलावटी तो खाना शुद्ध कैसे मिलेगा

शैलेंद्र पांडेय

बड़े मंदिरों में प्रवेश के पहले श्रद्धालुओं से चमड़े की बेल्ट और पर्स तक बाहर रखवा लिया जाता है, ऐसे में जब तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ने वाले लड्डुओं में चर्बी की मिलावट की खबर आई तो बवेला मचना लाजिमी था। इस मामले में यह हैरानी हो सकती है कि अब मंदिर का प्रसाद भी सुरक्षित नहीं बचा, लेकिन कम से कम देश में मिलावट को लेकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह ऐसा खुला सच है, जिसके बारे में जानते सभी हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं। घातक पेस्टिसाइड्स से लेकर सड़े-गले अनाज और ईंट-मिट्टी तक, यह पूछिए कि क्या वह चीज नहीं है, जिसे मिलावटखोर रंग-पोत कर हमारे सामने नहीं परोस रहे।

शुद्धता का सवाल | तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में चर्बी मिलने की बात कही जा रही है। सरकार ने उन वेंडर्स से घी लेना बंद कर दिया है, जो अभी तक सप्लाई कर रहे थे। जांच चल रही है और साथ में राजनीति भी। इस घटना ने तमाम दूसरे मंदिरों में चढ़ रहे प्रसाद को लेकर भी आम जनता के मन में संशय डाल दिया है। लेकिन, सवाल केवल प्रसाद को लेकर नहीं, बल्कि बाजार में बिक रहे तमाम खाद्य पदार्थों को लेकर होना चाहिए।

घातक नेटवर्क | देश में बात होती है भूमाफिया, कालाबाजारियों, भ्रष्टाचारियों और आर्थिक घोटाले करने वालों की, लेकिन हकीकत में मिलावटखोरों का नेटवर्क भी इतना ही बड़ा है। एक संगठित अपराध की तरह इस काम को अंजाम दिया जा रहा, जिससे देश का कोई हिस्सा बचा नहीं रहा है। हाल ही में स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी ने कई देशों के खाद्य पदार्थों में घातक मेटल लेड क्रोमेट की मौजूदगी को लेकर स्टडी की। भारत के 17 शहरों से सैंपल लिए गए थे और 14% में यह घातक तत्व मिला। गुवाहाटी और चेन्नै से लिए नमूनों में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा थी।

मसालों में मिलावट | आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में 15 टन नकली मसाला पकड़ा गया था। इन मसालों को सड़े हुए चावल, लकड़ी के बुरादे, चोकर, सिट्रिक एसिड वगैरह से तैयार किया गया था। और उसी दौरान सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग से रिपोर्ट आई थी कि भारतीय ब्रैंड के कुछ मसालों की लॉट स्थानीय मानक के अनुरूप नहीं पाई गई।

AI Image

कॉमन रूम

स्वास्थ्य से खिलवाड़ | तिरुपति विवाद ने भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाई है। मसला इससे भी बड़ा, स्वास्थ्य का है। जो चीजें वाकई जहर हैं, मिलावटखोर उन्हें भी खाने-पीने की चीजों में मिलाने से बाज नहीं आते। बताइए, क्या कोई सीसा खा सकता है, या फिर एसिड, या वॉशिंग पाउडर जिससे आप कपड़े धोते हैं? ये सारी चीजें मिलाई जा रही हैं। हल्दी की चमक को बढ़ाने के लिए लेड का इस्तेमाल होता है। यही नहीं, पुराने आलू को एसिड से धो देते हैं ताकि वह नया लगे और महंगा बिके। सब्जियों और अनाज पर रंग चढ़ाया जाता है और दूध में डिटर्जेंट पाउडर घोला जाता है।

संसद में उठा मुद्दा | साल 2016 में संसद में यह जानकारी दी गई थी कि हर तीन में से दो भारतीय मिलावट वाला दूध पी रहा है। और मिलावट भी किसकी, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट, यूरिया और पेंट की। संसद में ही पिछले साल अगस्त में 2022-2023 में हुई जांच के हवाले से बताया गया था कि 25% नमूने मिलावटी मिले। इसका मतलब कि हर चौथा शख्स 'जहर' खा रहा है।

कोरम नहीं, एक्शन चाहिए | फेस्टिवल सीजन आ रहा है। इस दौरान अचानक नकली मावा, मिठाइयां, घी वगैरह पकड़े जाने की खबरें बढ़ जाएंगी। इस तरह की खबरें आपने पिछले साल भी पढ़ी होंगी और गारंटी है कि अगले साल फिर पढ़ेंगे। इसकी वजह है कि मिलावटखोरी का काला धंधा जितना संगठित है, इसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई उतनी संगठित नहीं। आमतौर पर यह होता है कि किसी बड़ी घटना के बाद या त्योहारों में रैंडम सैंपलिंग और चेकिंग का मौसम चलता है, फिर सब शांत हो जाता है। मिलावट को जड़ से खत्म करने के लिए कभी ऑपरेशन नहीं चल पाता। इसकी एक वजह संसाधनों की कमी तो है, लेकिन ये कार्रवाइयां कई बार खुद 'मिलावटी' होती हैं। तो जब तक शुद्ध एक्शन नहीं होता, तब तक शुद्ध घी भूल जाइए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ब्लास्ट कर आतंकी से लिया बदला

अभिलाष गौर

लेबनान में पेजर और वॉकी-टॉकी में हुए विस्फोटों ने इस्राइल-हमास जंग की दिशा बदल दी है। सवाल उठ रहा है कि इस्राइल ने यह किया तो कैसे? इसका जवाब करीब तीन दशक पहले अंजाम दिए गए उस ऑपरेशन में है, जिसमें इस्राइल ने अपने तब के सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया था।

ऐसे पनपी नफरत | याह्या अब्दुल-तिफ-अय्याश की पहचान अपने गांव में ऐसे मेधावी लड़के की थी, जो खराब पड़े पुराने रेडियो, टीवी को फिर से चलने लायक बना देता। उसका परिवार रफा में रहता था। साल 1991 में उसने रामल्ला की Birzeit University से बीएससी ऑनर्स पूरा किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वह विदेश जाना चाहता था, लेकिन इस्राइली अथॉरिटी ने उसे रफा से निकलने की परमिशन नहीं दी। इस बात ने 25 साल के उस लड़के के अंदर गुस्सा भर दिया और इसका फायदा हमास ने उठाया।

हमले में माहिर | याह्या इंजिनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच उसे 'इंजिनियर' नाम ही मिला। इस्राइल के प्रति नफरत ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खेलने वाले युवा को आत्मघाती दस्ते तैयार करने में माहिर आतंकवादी में बदल दिया। उसने जिन हमलों की साजिश रची, उनमें लगभग 150 इस्राइली नागरिकों को जान गंवानी पड़ी और 500 से ज्यादा घायल हुए। सबसे घातक अटैक हुआ था 19 अक्टूबर 1994 को। इसमें 21 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। यह इस्राइल के तब तक के इतिहास की सबसे भयानक आतंकी वारदात थी।

सबसे बड़ी टिप | मोस्ट वॉन्टेड याह्या को पकड़ने के लिए इस्राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट ने पूरा जोर लगा दिया, पर वह बार-बार चूक जा रही थी। याह्या को मानने वाले बहुत थे, वह कहीं भी एक रात से ज्यादा नहीं रुकता और सब पर भरोसा नहीं करता। हालांकि उसकी कमजोरी थी कि वह रफा में अपने परिवार से मिले बिना नहीं रह पाता था। साल 1995 के आखिरी महीनों में उसके गाजा में छिपे होने की जानकारी मिली। तब तक वह थोड़ा लापरवाह हो गया था और कॉलेज में साथ पढ़े ओसामा हमद के चाचा कमाल हमद के यहां रह रहा था। बेपरवाही में उसने ओसामा का मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यही गलती उस पर भारी पड़ गई। कमाल लंबे वक्त से इस्राइली खुफिया एजेंसियों के लिए खबरी का काम कर रहे थे। याह्या की लोकेशन मिल चुकी थी, लेकिन समस्या थी कि फलस्तीनी इलाके में घुसकर ऑपरेशन कैसे चलाया जाए।

टाइम मशीन

मिशन पूरा | शिन बेट को जानकारी मिली कि याह्या 5 जनवरी 1996 को अपने परिवार से बात करने वाला है। अब उन्हें उस मोबाइल फोन तक पहुंच बनानी थी। यह काम किया कमाल ने। कमाल कई बार अपने भतीजे से मोबाइल लेकर बात करते थे, तो 3 जनवरी को जब उन्होंने फिर फोन मांगा तो किसी को शक नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान ही फोन में 57 ग्राम रेडियो कंट्रोल्ड बम लगा दिया गया। 5 तारीख को जब याह्या ने अपने घर पर कॉल किया, तो चंद मिनट बाद ही फोन बम की तरह फट गया और उसकी मौत हो गई। तब भी यह सवाल था कि फोन याह्या के ही पास है, इसकी पुष्टि कैसे हुई? दावा किया गया कि कॉल ट्रेस कर पहले याह्या की आवाज कंफर्म की गई, फिर पास में उड़ान भर रहे एक प्लेन से रेडियो सिग्नल भेज धमाका कराया गया।

आसान बना दी राह

प्रणव प्रियदर्शी

केयरलोन (carelon) ग्लोबल सॉल्यूशंस में सीनियर डायरेक्टर ऑफ टेक्नॉलजी की पोजिशन अचीव कर चुकी लिनेट डी'सूजा की शुरुआती जिंदगी इस लिहाज से अलग कही जा सकती है कि बचपन में उन्हें वे दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ीं, जो अपने देश में अक्सर मध्यमवर्गीय परिवार की लड़कियों को झेलनी पड़ती हैं। पिता बेहद उदार और आधुनिक विचारों वाले थे। उन्होंने कभी बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया। अपने दो भाई-बहनों के साथ बड़ी होती लिनेट को कभी यह नहीं महसूस हुआ कि लड़की होने की वजह से परिवार में उनकी जिम्मेदारी कम है या उनके अधिकार किसी भी मायने में कम हैं। मगर इसी का एक नतीजा यह भी हुआ कि जब परिवार के माहौल से निकलने के बाद काम-काज की दुनिया में उनका इन पूर्वाग्रहों से सामना हुआ तो लिनेट का जेहन उसके लिए तैयार नहीं था। उनके लिए वे पूर्वाग्रह ज्यादा चौंकाने वाले साबित हुए। पर इसी का नतीजा कहिए कि लिनेट ने इनके सामने समर्पण करने के बजाय उनका पूरी हिम्मत से मुकाबला किया। न सिर्फ उन्होंने अपनी राह की इन बाधाओं को खुद पार किया बल्कि यह भी प्रयास किया कि उनके बाद आने वाली लड़कियों को ये बाधाएं ज्यादा परेशान न कर सकें। उनके प्रयासों से केयरलोन ग्लोबल सॉल्यूशंस और पैरंट ऑर्गनाइजेशंस में विमिन इंस्पायर्ड नेटवर्क (WIN) नाम की मजबूत कम्युनिटी बनाई जा सकी जिसका काम था महिला सहयोगियों की खास जरूरतों का ख्याल रखना। जहां तक करियर ग्रोथ की बात है तो लिनेट का शुरू से मानना रहा है कि अगर कहीं नाकामी दिख रही है तो उसे टालने के बजाय जल्द से जल्द स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इस नजरिए का फायदा यह हुआ कि वे असफलताओं में अटकी नहीं रहीं। उनसे जरूरी सीख लेकर वह नए-नए क्षेत्रों में कामयाबी की ओर कदम बढ़ाती रहीं और इस ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकीं।

लिनेट डी'सूजा

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

धर्म इंसान को ईश्वर की राह पर आगे बढ़ाता है

श्री श्री आनंदमूर्ति

धर्म जीवन जीने का सलीका है, लेकिन समय-समय पर इसे लेकर बहस छिड़ी रहती है। धर्म का अर्थ है, अपनी स्वाभाविक क्षमता के अनुसार नियमित साधना के माध्यम से आनंद प्राप्त करने का प्रयास। बड़े फलक पर देखें तो आनंद की इस स्थिति को विद्वान ब्रह्म के रूप में मानते हैं, जबकि भक्त इसे आत्मा के रूप में देखते हैं।

विश्व के लगभग सभी धर्मों के संस्थापकों ने अपनी-अपनी शिक्षाओं को यह दावा करते हुए आम लोगों के बीच फैलाया कि यह भगवान का संदेश है। लेकिन इसमें तर्क का अभाव दिखा। उनके इरादे चाहे जो भी रहे हों, लोगों ने धर्म को समझने में अपनी सर्वोच्च धरोहर, तर्कशक्ति ही मानो खो दी। सवाल है कि क्या इस प्रकार के धर्म के सिद्धांतों से मानवता को कोई लाभ हुआ? लगभग हर धर्म ने दावा किया है कि केवल इसके अनुयायी ही ईश्वर के चुने हुए लोग हैं, और बाकी मानवता शैतान की बेड़ियों में बंधी हुई है।

धर्म के अनुयायी अपने-अपने धर्मों के भव्य नारे लेकर सामूहिक नफरत का उन्माद फैलाते हैं। मध्यकाल में होने वाली अधिकांश रक्तपात की घटनाएं इस बारे में सोचने को मजबूर करती हैं। यदि उनके संस्थापकों ने ऐसी स्थितियों को देखा होता, तो वे शर्म से अपना चेहरा छिपा लेते। ज्यादातर धर्म सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, जिसका अर्थ है धर्म के आधार पर समूह मनोविज्ञान।

अतीत में, 'सच्चे धर्म' ने बार-बार अज्ञानी लोगों को रोशनी दिखाने की कोशिश की, और ऐसा नहीं है कि आज ऐसा बिलकुल नहीं है। धर्म मानव मन को स्थिरता की स्थिति में बदलने की कोशिश करता है। यह जड़ता मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत है। धार्मिक संस्थापकों ने चाहा कि मनुष्य अपनी गतिशील प्रकृति को छोड़ दे और भय या भ्रांति के आधार पर, बिना किसी प्रश्न के, कुछ विचारों को अटल सत्य के रूप में स्वीकार कर ले।

हालांकि, नैतिकता मानव की जीवित शक्ति है और यह आध्यात्मिक अभ्यासों के मार्ग में एक प्रारंभिक बिंदु है। यदि नैतिकता मानवों को पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं प्रदान करती, तो आज हालात कुछ और होते। नैतिकता मानवों को प्रेरित करती है, और इसे किसी खास समय, स्थान या व्यक्ति तक सीमित नहीं रहने देने के लिए प्रेरित करती है। यही नैतिकता धर्म को विस्तार देती है।

धर्म आत्मा की उन्नति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है, जिससे व्यक्ति अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ सके। यह सही और गलत के बीच भेद करने की प्रेरणा देता है और नैतिक मूल्यों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके माध्यम से लोग एक-दूसरे के साथ सहानुभूति, प्रेम और भाईचारा विकसित कर सकते हैं। धार्मिक प्रथाएं, जैसे ध्यान और प्रार्थना, व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती हैं, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है।

इस प्रकार, धर्म एक जटिल और बहुआयामी तत्व है, जो मनुष्य के विकास, समाज के सामंजस्य, और आखिरकार आत्मा की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानंद अवधूत

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

राजनीति में नया मोड़

25 सितंबर का संपादकीय 'क्या करेंगे सिद्धारमैया' पढ़ा। दक्षिण भारत में लंबे समय तक सत्ता से दूर रहने के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री बनने का अवसर सिद्धारमैया को मिला। अभी एक वर्ष ही बीता होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जो सिद्धारमैया के लिए राजनीतिक दृष्टि से एक गहरा झटका है। यह फैसला उनकी सरकार के खिलाफ संभावित जांच का रास्ता खोलता है। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कर्नाटक का घटनाक्रम न केवल सिद्धारमैया के लिए, बल्कि पूरी राजनीति के लिए एक नया मोड़ हो सकता है।

मीना धानिया, ईमेल से

ऐतिहासिक फैसला

यह पत्र 24 सितंबर के संपादकीय 'कोई लूपहोल न रहे' से संबंधित है। चाइल्ड पॉर्न पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। चाइल्ड पॉर्न सिर्फ दूसरों को शेयर करना अपराध नहीं है, बल्कि उसे देखना, डाउनलोड करना, अपने पास रखना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है। यह मामला अब पॉक्सो अधिनियम के दायरे में आ जाएगा और अपराधी को कड़ी सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री पर पूरी तरह रोक लगेगी।

बाल गोविंद, नोएडा

प्रतिभा कम नहीं

हंगरी की राजधानी में आयोजित शतरंज ओलिंपियाड में भारत ने स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक सफलता पाई है। इस इवेंट के इतिहास में पहली बार भारत को गोल्ड मिला है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छी बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विजेताओं को बधाई दी। इससे निश्चित तौर पर उनका हौसला बढ़ा होगा। पिछले कुछ बरसों में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस ओलिंपिक्स में हमारे एथलीट्स ने जिस तरह दुनिया को टक्कर दी, वह संकेत है कि हम धीरे-धीरे खेलों में भी महाशक्ति बन सकते हैं। शतरंज की सफलता अन्य खिलाड़ियों में आगे बढ़ने के लिए जोश भरेगी।

रजनी श्रीवास्तव, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पढ़ाएंगे – एक खबर
– क्या दूसरे नेता यह खबर पढ़ कुछ सीख पाएंगे?

नीलमणि चौधरी

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

अनमोल वचन

जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए, जब आप वहां पहुंचेंगे, आप और आगे देख पाएंगे।
-जे पी मोर्गन

मुलाकात के निहितार्थ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा का समापन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात के साथ हुआ। दोनों नेता पिछले तीन महीने में तीसरी बार मिले। जाहिर है कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष की समाप्ति की कोशिश में लगा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच रूस-यूक्रेन विवाद पर ही चर्चा हुई होगी लेकिन मोदी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे पता चल सके कि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की क्या योजना है। हालांकि यूक्रेन की ओर से यह संकेत अवश्य मिल रहा है कि वह अगला शांति सम्मेलन भारत में कराने के पक्ष में है। लेकिन यूक्रेन के इस प्रस्ताव पर भारत का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका को लेकर फूंक-फूंक कर कदम उठा रहे हैं। रूस-

यूक्रेन संघर्ष पर पिछले दिनों स्विटजरलैंड में शांति सम्मेलन हुआ था। उसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया क्योंकि इस संघर्ष में शामिल एक पक्ष रूस इस शांति सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। भारत इसमें शामिल अवश्य हुआ था लेकिन सम्मेलन की समाप्ति के बाद जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुई थी उस पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए। भारत चाहता है कि अगर नई दिल्ली में शांति सम्मेलन हो तो उसमे रूस और यूक्रेन, दोनों शामिल हों। यह बहुत स्वाभाविक है कि किसी भी ऐसे शांति सम्मेलन में जब तक युद्धरत दोनों पक्ष शामिल नहीं होंगे तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान अपनी इस बात को दोहराया कि भारत रूस-यूक्रेन के संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जो भी संभव होगा वह करेगा। वस्तुतः इस संघर्ष के दूसरे देशों विशेषकर विकासशील और गरीब देशों पर पड़ने वाले कुप्रभावों को लेकर भी भारत चिंतित है। दशकों पहले भारत तीसरी दुनिया की अगुवाई करने वाला प्रमुख देश था। ग्लोबल साउथ का नेता कौन होगा, इसे लेकर भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। एक लोकतांत्रिक और मुक्त समाज के रूप में भारत की दावेदारी पुख्ता है। पिछले दिनों चीन ने भी रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए पहल की थी। विकास यात्रा में भारत भले ही चीन से पीछे है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की कूटनीतिक सक्रियता के कारण भारत के प्रभाव में बढ़ोतरी हो रही है। देखा जाना है कि आने वाले कुछ महीनों में शांति प्रक्रिया में भारत की भागीदारी के क्या नतीजे सामने आते हैं।

कोताही पर एक्शन

खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट या गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उन्होंने कहा, जूस, दाल, रोटी जैसी खाने-पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट या गंदी चीजों की मिलावट देखने में आ रही है। ये घटनाएं आम जन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। योगी ने कहा कि ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। राज्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है। खान-पान प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम-पता प्रमुखता से डिस्प्ले करने की भी बात की। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कड़ा निर्णय लेने के पीछे खाने-पीने की चीजों में मूत्र मिलाने या थूकने जैसी

कई घटनाएं भी शामिल हैं। लोगों ने इनकी वीडियो रिकार्डिंग की जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर वायरल की, उन पर आम जन ने भय, आक्रोश और गुस्सा व्यक्त किया। दरअसल, खाने-पीने के पदार्थों की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने के प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा-मानक अधिनियमों के तहत संबंधित महकमे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उचित ढंग से नहीं करते। उन्हें जवाबदेह बनाना सरकार का काम है। कुछ ही दिन पहले नामी ब्रांडों के सब्जी मसालों के बंदपैक में हो रही मिलावट का बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ था। उस पर जिस तरह की कार्रवाई होने की आवश्यकता थी, वह नहीं हुई। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्ती करने को व्यवस्था और संबंधित विभागों को जैसा मुस्तैद रहना चाहिए, वैसा वे नहीं रहते। अपने यहां ठेली, खोमचे या झाबे में रख कर खाद्य पदार्थ खूब बेचे जाते हैं जिनकी जांच कभी नहीं होती। सीसीटीवी और बैठने की व्यवस्था भी सभी विक्रेता नहीं कर सकते। अपमिश्रण या अखाद्य की मिलावट जागरूक नागरिकों की पहल द्वारा सामने आई है, जिसमें सरकारी महकमा असफल है। कोरी बयानबाजी की बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही करने वालों पर भी कड़ाई से एक्शन किया जाए। इस पहल से उम्मीद की जा सकती कि देशवासियों को सेहत संबंधी बढ़ती जा रहीं दिक्कतों से निजात मिल सकेगी।

कटाक्ष/ सहीराम

अब सब कुछ एक हो

वन नेशन, वन इलेक्शन का पक्ष लेते हुए वे बड़े जोश में थे। कह रहे थे-अब तो सब कुछ एक हो ही जाना चाहिए। बल्कि जी, हमें तो नारा लगाना चाहिए-किसी ने कहा-आवाज दो, हम एक हैं। क्या बेवकूफी की बातें करते हो-उन्होंने कहा-हम सब एक कैसे हो सकते हैं। कल को तुम कहोगे हिन्दू मुसलमान एक हो जाओ, जात-पात छोड़कर सब एक हो जाओ। जी, वो आप ही तो कह रहे थे-सफाई दी गई। मैं यह थोड़े ही कह रहा था कि हम सब एक हों-उन्होंने कहा-मैं तो कह रहा था कि कानून वगैरह सब एक हों। कॉमन सिविल कोड हो ही जाएगा। धारा तीन सौ सत्तर खत्म हो ही गई। किसी को कोई विशेषाधिकार क्यों मिले? फिर तो जी कभी बिहार को तो कभी आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी गलत ही है, मोदी जी को माननी नहीं चाहिए-किसी ने कहा। वे सकुचाए। बोले-नहीं वो बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि भोजन भी सबका एक जैसा सात्विक ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक-किसी ने कहा-इसके बाद कम से कम किसी की रसोई की, फ्रिज की, पतीली की जांच तो नहीं होगी न कि उसमें कहीं बीफ तो नहीं है।

वे फिर सकुचाए। बोले-नहीं ऐसी बात नहीं है, पर अब तो सब कुछ एक हो ही जाना चाहिए। नहीं जी नहीं-एक बंदे ने इतनी जोर से विरोध किया कि सब चौंक गए और उसकी तरफ देखने लगे। वह कह रहा था-फिर प्रधानमंत्री जी की रंग-बिरंगी पगड़ियों, सदरियों और कुर्तों का क्या होगा। अगर सब कुछ एक हो तो कम से कम प्रधानमंत्री को तो इस मामले में छूट मिलनी चाहिए। वे नाराज हो गए-तुम क्या कांग्रेसी हो या कम्युनिस्ट हो या सेकुलरिस्ट हो, जो ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन फिर याद करते हुए उन्होंने अपनी बात का सिरा फिर से पकड़ा-मूल बात यह है कि अब तो सब कुछ एक हो ही जाना चाहिए और चुनाव तो पूरे देश एक साथ जरूर हो ही जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी-किसी ने कहा-रोज-रोज चुनाव होंगे तो कहां छतें टपक पाएंगी, कहां मूर्तियां टूट पाएंगी, कहां पेपर लीक हो पाएंगे। नहीं होने चाहिए-किसी ने विरोध किया। क्यों-उनकी त्यौरियां फिर चढ़ गईं-फिर प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे पांच साल। क्या तब भी वे इसी तरह से चुनावी भाषण देते रहेंगे जैसे अब बिना चुनाव के देते रहते हैं। अगर नहीं दे पाएं तो फिर रहने दो।

केजरीवाल की गुगली

सियासत
अवधेश कुमार

आतिशी मार्लेना अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आने के बाद अचानक इस्तीफा देने की घोषणा करेंगे इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आखिर, जो नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं था, वह जमानत के बाद ऐसा करेगा कल्पना की भी कैसे जा सकती थी। केजरीवाल की राजनीति कभी ऐसी धारा और धुरी पर नहीं चलती कि आप उनके अगले कदम का अनुमान लगा सकें। उन्होंने घोषणा कर दी लेकिन इस्तीफा दिया नहीं। इसके लिए भी 48 घंटे का समय दे दिया यानी देश 48 घंटे कल्पना करता रहे कि वह क्या करेंगे, इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री के रूप में किसके नाम की घोषणा करेंगे और सबकी दृष्टि उनकी ओर लगी रहे। अगर जेल से इस्तीफा दे देते तो अपने इसे मनमाफिक मोड़ देना और इस तरह का माहौल निर्मित कर देना संभव नहीं होता।

अगले वर्ष आरंभ में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। निश्चित रूप से उनकी राजनीति उस पर केंद्रित होगी और लगातार वह इसी तरह चर्चा में बने रहने के लिए कुछ अकल्पनीय करते रहेंगे। अन्ना अभियान से लेकर अभी तक उनकी राजनीति, तौर-तरीकों, चरित्र आदि पर नजर रखने वालों के लिए इसे पचा पाना कठिन हो रहा था कि जमानत पर आने के बाद केजरीवाल सामान्य गतिविधियों तक कैसे सीमित हैं। तो अब वह आगे क्या करेंगे इसके बारे में भी कोई टिप्पणी करना जोखिम भरा होगा। प्रश्न है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो जिस दिशा में घटना को बनाए रखना चाहते हैं वही बने और निश्चित तौर पर वही बनी रहेगी? पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि जमानत मिलने के बावजूद न तो वे अपनी कैबिनेट की बैठक बुला सकते थे, न सचिवालय ही जा सकते थे, और न मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते थे यानी जमानत पर रिहा होना उनके लिए पूर्ण राहत का विषय नहीं था।

अगर चुनाव के बीच लोगों को प्रलोभन या लुभाने के लिए घोषणाएं करनी हैं, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाना होगा। कैबिनेट की बैठक भी बुलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। हाथ पूरी तरह बंधे होने पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन भले वे पद पर न रहें, मुख्यमंत्री कोई भी हो, असली नीति निर्धारक वही होंगे। फाइल पर उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे किंतु निर्णय और शब्दावली उन्हीं की होगी। इस्तीफा देने को इस तरह पेश कर रहे हैं, जिससे जनता की पूरी सहानुभूति उनके साथ हो और चुनाव तक उनकी यही कोशिश जारी रहेगी। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में एक

लंबा आंदोलन चलाने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जितनी संख्या में और आक्रामकता से लोगों के निकलने की संभावना थी वह दिखाई नहीं पड़ा। स्वयं उनकी पार्टी के अंदर भी धीरे-धीरे वातावरण बन रहा था कि शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार तो हुआ है। उनके विधायक और पार्षद पार्टी छोड़कर गए। पार्टी और आम कार्यकर्ताओं के अंदर का यह भाव दिल्ली में उनकी राजनीति के कमजोर होने का संकेत दे रहा था। मुख्यमंत्री पद पर बने रहकर शायद उन्हें लगा हो कि फिर से पहले की तरह जन समर्थन पाना संभव नहीं होगा। इस आधार पर निष्कर्ष यही आएगा कि जो त्यागपत्र उन्हें स्वाभाविक रूप से देना था उन्होंने उसे ऐसा दांव बना दिया है, जिसकी काट मुश्किल लगती है।

उनको अपने अनुरूप जेल से निकल कर राजनीति करने में कोई समस्या भी नहीं थी। अस्वीकार्य शराब नीति और भ्रष्टाचार के आरोपों में काफी हद तक दिखती सच्चाई के होते हुए दिल्ली की मुख्य पार्टी भाजपा ने अगर यह स्थिति पैदा नहीं की कि केजरीवाल और आप को रक्षात्मक या बचाव की मुद्रा अपनानी पड़े तो फिर उनके सामने अपनी राजनीति के लिए अपने अनुसार मोड़ देने के लिए खुला मैदान है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहे और भाजपा इसे दिल्ली की जनता के बीच बड़ा मुद्दा नहीं बना सकी।

केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दोनों दिल्ली के मोहल्ले-मोहल्ले में जाएंगे और लोगों के बीच बोलेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा हमारी सरकार और पार्टी को खत्म करने के लिए कानूनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं जबकि हम निर्दोष हैं, तो उसी भाषा या उससे ज्यादा प्रभावी भाषा में जनता के बीच जाकर प्रत्युत्तर देने या खंडित करने का स्वाभाविक कार्यक्रम क्या दिल्ली की दूसरी राजनीतिक धारा ने बनाया है? केजरीवाल जैसी चाहेंगे वैसी राजनीति करेंगे, वो अपनी शैली में व्यापक वर्ग को यह समझाने में सफल भी हो सकते हैं कि वाकई वे निर्दोष हैं, भाजपा सत्ता की ताकत से उनको खत्म करना चाहती है। संभव है इससे फिर माहौल ऐसा बन जाए कि विधानसभा चुनाव में आप फिर बाजी मार ले।

गहराई से देखिए, उन्होंने कितनी कुटिलता से अपनी जमानत की व्याख्या की। कहा कि इस समय तो कोर्ट केवल जमानत ही उन्हें दे सकती थी क्योंकि मुकदमा तो पता नहीं 5 साल, 10 साल, 15 साल चलेगा। इसलिए मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता जब निर्वाचित कर मुझे निर्दोष साबित कर देगी तभी मैं पद संभालूंगा। हालांकि वह दोषी हैं, या नहीं हैं, इसका निर्णय तो न्यायालय को करना है। चुनाव में हार-जीत कानूनी रूप से दोषी या निर्दोष होने का प्रमाणपत्र नहीं होती किंतु यह केजरीवाल का ऐसा मोहक-मायावी राजनीतिक दांव है, जिसका उत्तर राजनीतिक तौर पर मिलता दिख नहीं रहा है। वैसे लोक सभा चुनाव में अंतरिम और अंतरालबद्ध जमानत पर बाहर आने पर भी उन्हें सहानुभूति का लाभ नहीं मिला। दिल्ली की सातों सीटें भाजपा की झोली में चली गईं। लेकिन लोक सभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के परिणाम दिल्ली में पिछले दो चुनावों से अलग-अलग आ रहे हैं।

हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति में कोई भी सामान्य सिद्धांतों, मूल्यों और विचारधाराओं तक को ताक पर रखकर लोगों को मोहित करने की शैली में सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में सफल हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने जमानत के साथ सार्वजनिक तौर पर मुकदमे पर कोई बयान न देने की शर्त लगाई है किंतु वह बयान दे रहे हैं, और उन पर कोई रोक नहीं। इसी तरह उनके साथी भी बयान दे रहे हैं कि अभी तक ईडी सीबीआई को कुछ नहीं मिला, कितने रुपये की रिकवरी हुई। पहले की तरह ही सरकार और पार्टी, दोनों का नियंत्रण अरविंद केजरीवाल के हाथों है, केवल संवैधानिक रूप से वह घोषित मुख्यमंत्री नहीं हैं।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

> अगले वर्ष आरंभ में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। निश्चित ही केजरीवाल की राजनीति उस पर केंद्रित होगी और वह चर्चा में बने रहने के लिए कुछ अकल्पनीय करते रहेंगे। अन्ना अभियान से लेकर अभी तक उनकी राजनीति, तौर-तरीकों, चरित्र आदि पर नजर रखने वालों के लिए इसे पचा पाना कठिन हो रहा था कि जमानत पर आने के बाद वह सामान्य गतिविधियों तक कैसे सीमित रह गए। इस्तीफे के बाद क्या करेंगे, इसके बारे में टिप्पणी करना जोखिम भरा होगा

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भारत में जस्ता का इस्तेमाल बढ़ाना जरूरी

- भारत में जस्ता की खपत अगले 10 वर्षों में वर्तमान 11 लाख टन से बढ़कर 20 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है
- अंतरराष्ट्रीय जस्ता संघ (आईजेडए) के मुताबिक, प्राथमिक उत्पादन के मामले में वैश्विक जस्ता बाजार करीब 1.35 करोड़ टन प्रति वर्ष है
- आईजेडए का कहना है कि वैश्विक मानक और मांग पूरी करने के लिए जस्ता का इस्तेमाल बढ़ाने की जरूरत है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

145 करोड़ आबादी वाले देश के लिए फिलवक्त 'लड्डू विवाद' सबसे बड़ा मुद्दा है। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगा दी है। उत्तर हो दक्षिण, हर जगह इस पर 'बयान युद्ध' चल रहे हैं! सबसे फायदे में भाजपा है। दक्षिण के एक और राज्य में उसे 'आधार' मिल रहा है!

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

आर्थिक विकास का नया अध्याय

लखपति दीदी योजना | सोनम लववंशी

महिला सशक्तिकरण का मुद्दा देश में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इसके लिए ठोस प्रयास कम ही देखने को मिलते हैं। इस संदर्भ में मोदी सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2023 को शुरू की गई 'लखपति दीदी योजना' महत्त्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल ग्रामीण, बल्कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।

लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को स्किल डवलपमेंट ट्रेनिंग देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। लगभग 2 करोड़ महिलाओं को योजना के तहत ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिससे वे एलईडी बल्ब निर्माण, प्लंबिंग और ड्रोन रिपेयरिंग जैसे तकनीकी कार्यों में दक्ष हो रही हैं। योजना में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को विशेष लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, और पिछले 100 दिनों में लगभग 11 लाख महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी और नमो ड्रोन दीदी जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के नये अवसर मिल रहे हैं, तथा वे सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाएं कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं। योजना के तहत कुटीर उद्योग, पोषण आहार, स्वच्छता अभियान और परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना के तहत सरकार ने 2500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड और 5000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण प्रदान किया है। देश भर में लगभग 92 लाख स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

लखपति दीदी योजना के साथ-साथ मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान और 'सुकन्या समृद्धि योजना' के माध्यम से महिलाओं के जीवन

में सकारात्मक बदलाव आया है। 'उज्ज्वला योजना' के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली और उन्हें सुरक्षित ईंधन का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और जनधन योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के खातों में सीधे वित्तीय सहायता पहुंचाई जा रही है। 'जल जीवन मिशन' जैसे प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को नल से शुद्ध जल मिलना संभव हो गया है। इस पहल ने महिलाओं के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, जिससे वे अधिक समय अपने विकास में लगा सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में खेलों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 'खेलो इंडिया' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की बेटियों ने ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाया है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी खोले हैं, जिससे सेना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। सेना में महिला अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्ति और नई भर्ती के अवसर दिए जा रहे हैं। तीन तलाक के खिलाफ कानून बना कर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया गया है, जिससे उनका जीवन और भविष्य सुरक्षित हुआ है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में भी मोदी सरकार ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' इस बात का प्रमाण है कि सरकार महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके माध्यम से महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी का अवसर मिलेगा जिससे वे राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकेंगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारतीय महिलाएं उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। स्टार्टअप से लेकर स्पेस तक, भारतीय महिलाओं ने अपने कार्यों से देश का मान बढ़ाया है। हाल के वर्षों में महिलाओं ने विज्ञान, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्रों में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उनके सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत है। लखपति दीदी योजना और महिला सशक्तिकरण की अन्य योजनाएं भारत में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की समृद्धि का आधार भी है। महिलाएं सशक्त होंगी, तो परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त होंगे। यही कारण है कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें।

आत्म प्रकाश | डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

एक बार राजा जनक जिज्ञासापूर्वक ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, 'हे महात्मन! किस प्रकाश को देख कर मनुष्य सदैव जीवन का मार्ग तय करता रहता है? और इसकी महिमा क्या है?' तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कहा, 'आपने सभी के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है।' अब ऋषि याज्ञवल्क्य भारतीय दर्शन को उजागर करते हुए उत्तर देने लगे-'हर कोई जानता है कि मनुष्य सूर्य की रोशनी से रास्ता देखता है।' जनक राजा ने पुनः प्रश्न किया 'जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो मनुष्य कौन से माध्यम के प्रकाश से देखता है?' तब ऋषिवर उत्तर देते हैं, 'हर कोई चंद्रमा की रोशनी से देखता है।' राजा जनक फिर पूछते हैं, 'जब चंद्रमा की रोशनी डूब जाती है, तो किस रोशनी से देखता है?' तब ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, 'वह अग्नि के प्रकाश से देखता है।' तब राजा जनक पूछते हैं, 'जब अग्नि का प्रकाश नहीं होता तो मनुष्य किस प्रकाश से देखता है?' तब ऋषि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, 'वह वाणी के प्रकाश से देखता है।' तब जनक ने संदेह करते हुए ऋषि से पूछा, 'जब वाणी का प्रकाश नहीं है, तो मनुष्य किस प्रकाश से देखता है?' तब ऋषिवर हम सभी को एक सिद्धांत पर वार्ता करते हुए मार्ग बताते हैं-'यद्यपि ये सभी अपनी चमक खो देते हैं, किंतु आत्मा की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती। आत्मा का प्रकाश शाश्वत है क्योंकि इसमें परमात्मा के प्रकाश की अविराम अभिव्यक्ति होती है।' भगवान स्वामिनारायण भी कहते हैं-'आत्मा स्वप्रकाशित है। इसमें ज्ञान गुण निरंतर प्रकशित होता रहता है क्योंकि आत्मा का न तो आदि है, न ही अंत!' इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं-'यह आत्म नित्य, सनातन और अविनाशी है। अतः इसके मर जाने का भय छोड़ दो।' आत्मा को ज्ञान और सत्य की खोज का माध्यम माना गया है। उनके अनुसार, आत्मा का प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, और उसके बाद उसके तुच्छ प्रश्नों और समस्याओं के लिए रुदन समाप्त हो जाता है। आत्म प्रकाश माया के भ्रम और निराशा को दूर करके व्यक्ति को परमात्म-साक्षात्कार की ओर ले जाता है।

रीडर्स मेल

राजनीति के केंद्र में आईं शैलजा

तेजी से बदले घटनाक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हिसार से सांसद कुमारी शैलजा अचानक हरियाणा की राजनीति के केंद्र में आ गई हैं। अखबारों की सुर्खियों और टीवी न्यूज की डिबेट में खबर जोरों से चल निकली कि कुमारी शैलजा न केवल नाराज हैं, बल्कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार से भी अलग हो गई हैं। इससे पूर्व भी दलित चेहरा एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। हरियाणा का दलित समाज भी इस बात से नाराज है कि एक तरफ कुमारी शैलजा के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है, वहीं कांग्रेस के क्षेत्रीय नेतृत्व ने उन्हें अलग-थलग कर दिया है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी तैयारी की है, और कांग्रेस को दलित विरोधी करार देने में कसर नहीं छोड़ी है। बेशक, इस कारण कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ रहा है। हरियाणा में 21% दलित हैं, जिनकी नाराजगी कांग्रेस की जीत की दावेदारी पर पानी फेर सकती है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

मारकाट मचाती संवेदनशीलता

भारत में अधिकांश लोग अपने-अपने धर्म के प्रति काफी संवेदनशील हैं। कुछ मामलों में तो इतने अधिक हैं कि इसके चलते आपस में मारकाट तक कर लेते हैं। लोग धर्म की रक्षा के नाम पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं जबकि धर्म, अध्यात्म कभी भी नुमाइश की चीज नहीं होनी चाहिए। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से एक खास विचारधारा के लोग धर्म के नाम पर राजनीति के मैदान में बैटिंग कर रहे हैं। जैसे कि अयोध्या में राममंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा नियमानुसार नहीं करके चुनावी नफा-नुकसान के कारण हड़बड़ाहट में कर दी गई। यही वजह थी कि चारों शकराचार्यों ने उस समय भी प्राण-प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे और आज भी उनका सवाल प्रासंगिक बना हुआ है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पिछले दिनों अयोध्या प्रवास पर थे, मगर राम मंदिर में पूजा करने से परहेज किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आंशिक रूप से निर्मित मंदिर में प्रार्थना नहीं की जा सकती। वे राम मंदिर में तभी पूजा करेंगे जब संरचना का 'शिखर' पूरी तरह बन जाएगा। तो 22 जनवरी, 2024 को हुई प्राण-प्रतिष्ठा आध्यात्मिक-ऐतिहासिक भूल थी?

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

आस्था के बदले मायने

हम देवी-देवताओं की प्रतिमा को प्रतीक मान कर पूजा करते हैं। इन्होंने अनीति त्याग कर नीति का राज स्थापित किया था। राम, कृष्ण, हनुमान आदि को पूजना यही संदेश देता है। लेकिन अब आस्था के मायने बदल गए हैं। दक्षिण के एक मंदिर में प्रसाद का लड्डू विवादों में है। लड्डू में पशुओं की चर्बी की बात पता चली है। प्रसाद में मिलावट पाए जाने पर अनेक धर्म स्थलों से आवाजें उठनी लगीं। राजनीति में लोग अपना हित देखते हैं। एक नेता ने तो प्रायश्चित योग की मुद्रा बना कर पेपर में फोटो दे दिया। ये सब व्यर्थ का शोरशराबा लगता है। सही तो यह है कि ऐसी स्थिति बनें कि रोड पर कोई धार्मिक स्थल न रहे। लोग अपने घर में अपने धर्म के अनुसार धार्मिक क्रियाएं करें।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-34, अंक 43
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

कश्मीर में उम्मीद

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का शांति और सफलता से संपन्न होना सुखद है। शाम पांच बजे तक 54 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हो चुका था और मतदान प्रतिशत के जब अंतिम आंकड़े आएंगे, तब और सुखद एहसास होगा। पहले चरण में शुरू में 58 प्रतिशत के आसपास मतदान का आंकड़ा सामने आया था, पर अंतिम आंकड़ा 61.38 प्रतिशत तक जा पहुंचा। अगर हम तुलना करें, तो दिल्ली में पिछले दो लोकसभा चुनावों में क्रमशः 60.52 और 56 प्रतिशत वोट पड़े थे। यहां यह भी बताते चलें कि साल 2020 में जब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 62.82 प्रतिशत मतदान हुआ था। अगर जम्मू-कश्मीर में दिल्ली के बराबर मतदान होने लगा है, तो यह खुशखबरी के साथ ही दिल्ली वालों के लिए भी प्रेरणा का विषय होना चाहिए। जब तमाम चुनौतियों के बावजूद जम्मू-कश्मीर में 60 प्रतिशत के करीब मतदान हो सकता है, तब देश के अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ना ही चाहिए। जम्मू-कश्मीर और वहां के लोग लोकतंत्र के लिए नई प्रेरणा बनकर उभर रहे हैं।

वैसे एक-दो बार के चुनावों को अगर छोड़ दिया जाए, तो जम्मू-कश्मीर के लोगों ने हमेशा ही मतदान करके लोकतंत्र पर अपना यकीन जताया है। आतंकवाद के खतरनाक दौर में साल 2002 विधानसभा चुनाव में वहां 43.70 प्रतिशत मतदान हुआ था। दस साल पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में 65.91 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तुलना में कुछ कम मतदान होगा, पर ताजा मतदान की पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद यह पहला चुनाव है। साल 2019 में जब 370 को खत्म किया गया था, तब वहां जो नाराजगी थी, उसका दूर या कम हो जाना बहुत अच्छा संकेत है। सबसे खास बात यह है कि आतंकवाद को काबू में रखा गया है।

पहले चरण में 24 और दूसरे चरण में 26 सीटों पर हुआ सफल व शांतिपूर्ण मतदान साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि लोग कश्मीर का विकास चाहते हैं।

हिंसक तत्वों को कहीं भी मौका नहीं मिला है। चुनाव के प्रति वहां लोगों में जो जोश है, उसे देखते हुए अराजक तत्व चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने से बचेंगे। ताजा चुनाव में यही हो रहा है, लोग अब हिंसा की ओर मुड़कर नहीं देखना चाहते। लोगों को रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए अमन-चैन का होना जरूरी है। पहले चरण में 24 और दूसरे चरण में 26 सीटों में हुआ सफल मतदान साफ तौर पर संकेत है कि लोग कश्मीर का विकास चाहते हैं। आतंकवाद से होने वाले भारी नुकसान को लोगों ने समझ लिया है।

पहले चरण में भी बहुत सारी संवेदनशील सीटें शामिल थीं और इस बार भी ऐसी सीटें हैं, जहां ठीकठाक मतदान का होना सुनहरे भविष्य की ओर इशारा है। राजौरी जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था अगर कड़ी है, तो आश्चर्य नहीं। आतंकियों को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में लोगों का बेखौफ मतदान के लिए घर से बाहर निकलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजौरी, पुंछ और रियासी जैसे इलाकों में अगर लोग ठान लें कि लोकतंत्र के साथ रहना है, तो आतंकवाद का खात्मा तय है। जम्मू के पीर पंजाल क्षेत्र में चुनाव को लेकर उत्साह भी मानीखेज है। करीब 25 लाख से अधिक मतदाताओं ने 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है। जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उन्हें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। देश तो कश्मीर की ओर उम्मीद से देख ही रहा है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 26 सितंबर, 1949

निजाम की जागीरें समाप्त

हैदराबाद, २५ सितंबर। हैदराबाद के फौजी गवर्नर मेजर जनरल जे.एन. चौधरी ने आज तीसरे पहर एक प्रेस प्रतिनिधि सम्मेलन में यह बताया कि सरकार ''बहुत जल्द'' लायक अली सरकार के सदस्यों पर, जो कि अपने-अपने घरों में नजरबन्द हैं, मुकदमा चलाने के प्रश्न पर फैसला करने वाली है। फौजी गवर्नर ने यह भी घोषणा की कि सरकार पहली अक्तूबर १९४९ से आरम्भ होने वाले नए आर्थिक वर्ष में जागीरों, संस्थानों और पायगों को लगान में १२।। प्रतिशत की छूट देना चाहती है। ये सब जागीरें सरकार आशा है इस महीने के अन्त तक ले लेगी। आपने बताया कि सरकार की जागीरदारों को कोई मुआवजा न देकर एक कामचलाऊ भत्ता देने की तजबीज है। जनरल चौधरी ने यह भी प्रकट किया कि जागीर स्टाफ के लोगों को सरकारी नौकरियों में खपाने की कोशिश की जायेगी।

इन जागीरों से २।। से ३ करोड़ रुपये वार्षिक लगान प्राप्त होने का अनुमान है। इसलिये लोगों को दी जाने वाली छूट भी ३५ लाख रुपये से ऊपर होगी। सरकार जब सारी जागीरों, संस्थानों और पायगों को अपने कब्जे में ले लेगी, तब सारी रियासत का यह एक तिहाई भाग भी जो कि जागीर के रूप में है, सरकार के मातहत हो जायेगा और हैदराबाद तब अपने को एक सुसंगठित इकाई होने का दावा कर सकेगा। मेजर जनरल चौधरी द्वारा बताये गये कुछ अन्य तथ्य इस प्रकार हैं- इस समय लगभग ३७५ रजाकार नजरबन्द हैं या उन पर अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, जबकि गत वर्ष इन्हीं दिनों १७००० रजाकार बन्द थे। रियासत में कम्यूनिस्ट स्थिति काबू में है। ४० महिलाएं कम्यूनिस्ट कार्रवाइयों के संदेह में नजरबन्द हैं और उनके मामलों की जांच-पड़ताल चल रही है। भारतीय विधान परिषद् में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी समाचारों के बारे में पूछे जाने पर फौजी गवर्नर ने कहा कि यह मामला सरकारी तौर पर उनके सामने नहीं आया है और इसलिये वे फिलहाल उस बारे में कुछ नहीं बता सकेंगे। वे २८ सितम्बर को दो दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, ताकि भारत सरकार से मिलकर कुछ जरूरी बातों की सफाई करा सकें और शायद वापस लौटने पर अगले प्रेस सम्मेलन में वे इस मामले पर कुछ प्रकाश डाल सकें।

अमेरिकी चुनाव में बंटे हुए भारतवंशी

अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव जितना मूल अमेरिकियों के लिए कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण यह इस बार प्रवासी भारतीयों के लिए भी बन चुका है।

यहां स्कैन करें

रामशरण जोशी | वरिष्ठ पत्रकार व समाज विज्ञानी

आजकल अमेरिका में विशाल चुनावी पोस्टर-बैनर तो नहीं दिख रहे, पर कई लोगों के घरों के सामने, सड़क किनारे या मोड़ पर छोटे-छोटे सादे सांकेतिक पोस्टर-बैनर नजर आने लगे हैं, जो एहसास कराते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने आधुनिक लोकतंत्र अमेरिका में बहुत शालीनता से चुनाव हो रहे हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव जितना मूल अमेरिकियों के लिए कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण यह प्रवासी भारतीयों के लिए भी बन चुका है।

करीब 24 करोड़ से अधिक अमेरिकी मतदाता भारतीय मूल से जुड़ाव रखने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत का फैसला 5 नवंबर को करेंगे। अभी 59 वर्षीया हैरिस देश की उपराष्ट्रपति हैं, जबकि 78 वर्षीय ट्रंप 2016 से 2020 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। वह पिछले चुनाव में जो बाइडन से हार गए थे। अब वह तीसरी और आखिरी बार किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि हैरिस पहली दफा राष्ट्रपति चुनाव के अखाड़े में हैं। याद रहे, पुरुष वर्चस्व वाले अमेरिका में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकी है। आठ साल पहले 2016 में हिलेरी क्लिंटन ने इस पद को पाने की जरूर कोशिश की थी, पर वह ट्रंप से पराजित हो गई थीं। इस दृष्टि से हैरिस का राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना दुस्साहसिकता ही है।

बीस साल से अमेरिका में उच्च पद पर काम कर रहे तमिलनाडु के कार्तिकेयन करुणानिधि जोश के साथ बताते हैं, 'कमला हैरिस की जीत से यहां हम भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह पहली दफा है, जब भारतीय मूल की कोई महिला अमेरिकी चुनावों में इस ऊंचाई तक पहुंची है। जहां तक ट्रंप का सवाल है, तो वह शुरू से ही प्रवासियों के विरोधी रहे हैं।'

दूसरी ओर, अहमदाबाद से अमेरिका आए आकाश शर्मा डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। वह कहते हैं कि ट्रंप की जीत से अमेरिकी राष्ट्रवाद मजबूत होगा और भारत पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा।

ध्यान रहे, अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों की आबादी 50 लाख से अधिक है, कुल अमेरिकी आबादी का करीब 1.35 प्रतिशत। श्वेतों की आबादी 61 प्रतिशत और अश्वेतों की 12.6 प्रतिशत है। वैसे, पंजीकृत अनिवासी भारतीय मतदाताओं की संख्या निराशाजनक है। भारतीय मूल के मतदाता एक प्रतिशत से कुछ ही अधिक हैं और विभाजित भी दिखते हैं। अनिवासी भारतीय, विशेष रूप से गुजराती प्रवासियों के मन में आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 का जुमला, 'अब की बार ट्रंप सरकार' घूम रहा है।

दिलचस्प यह भी है कि पिछले दो सप्ताह में भारत के दो शिखर नेता- राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रवासी भारतीयों को अपने-अपने अंदाज में रिझाने की भरपूर कोशिश की है। यहां मोदी के भी समर्थक हैं और राहुल गांधी के प्रति भी समर्थन बढ़ा है। एक पत्रकार के रूप में और निजी तौर पर भी साल 1985 से ही मैं यहां आता रहा हूं। साल 2007 में मैंने बराक ओबामा को राष्ट्रीय स्तर पर उभरते देखा है। साल 2012 में ओबामा को दूसरी बार राष्ट्रपति बनते देखा है। साल 2016 में हिलेरी-ट्रंप मुकाबले का भी मैं गवाह रहा हूं। खास यह कि यहां पिछले चुनावों में भारतीय समुदाय तकरीबन एकताबद्ध रहा है, पर इस बार मतों में विभाजन साफ देख पा रहा हूं।

इस बात को भी मैंने महसूस किया है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी-उत्थान के बाद से यहां निश्चित ही प्रवासी पहचान में तीव्र गतिशीलता का आयाम जुड़ा है। गुजराती समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक सक्रियता आई है और दर्प के भाव भी उभरे हैं। अब यदि प्रवासियों में यह संदेश पहुंचे कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ नहीं हैं, तो प्रवासी-बहुमत कमला हैरिस के पक्ष में खड़ा दिखाई दे सकता है। यहां साफ महसूस हो रहा है कि प्रवासियों के बीच कमला हैरिस की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में प्रवासी पहुंच रहे हैं। यहां बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों से बात करने पर पता चलता है कि कमला हैरिस अधिक समझदार, उदार-लोकतंत्रवादी, कुशल प्रशासक, निम्न व मध्य वर्गों की समस्याओं को समझने वाली, बंदूक-संस्कृति के विरुद्ध, स्त्री अधिकारों की रक्षक और ओबामा केयर की पक्षधर हैं। इसके विपरीत, डोनाल्ड ट्रंप को रूढ़िवादी लोकतंत्र के समर्थक, खरबपतियों के पक्षधर, लोकतंत्र की न्यूनतम मर्यादाओं के प्रति भी बेपरवाह, श्वेत वर्चस्ववाद के पक्षधर, स्त्री अधिकार विरोधी आदि के रूप में देखा जा रहा है। मुद्दों के आधार पर भी यहां भारतीय समुदाय के मतदाता विभाजित दिखते हैं।

वैसे, यहां यहूदी, चीनी, हैती, लातिनी देशों के प्रवासी समुदाय भी गहराई तक विभाजित दिखाई देते हैं। फिर भी कुल मिलाकर, अमेरिका के 'आम वोट या पॉपुलर वोट' में हैरिस की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, परंतु, चुनावी पर्यवेक्षकों की दृष्टि में सात राज्यों (स्विंग स्टेट्स) में से दो-तीन राज्य ऐसे हैं, जिनके 'इलेक्टोरल वोट' ट्रंप को जिता सकते हैं। साल 2016 के चुनाव में यही हुआ था। देश के पॉपुलर वोटों ने क्लिंटन को जिता दिया था, लेकिन इलेक्टोरल वोटों के बल पर ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे। फिर ऐसी संभावना या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

ट्रंप जीत के लिए हर हथकंडा आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वह हारते हैं, तो इसके लिए यहूदी जिम्मेदार होंगे। इस बात पर यहूदी एकमत नहीं हैं। एक यहूदी कैरेन कहती हैं कि ट्रंप की जीत से पूरी दुनिया में फासीवाद का संदेश जाएगा। हम यहूदी हैं, मगर हम फासीवाद के समर्थक नहीं हो सकते।

वैसे दोनों में से कोई भी जीते, अमेरिकी चरित्र में बदलाव नहीं आएगा। यहां दोनों पार्टियों की लगभग समान महत्वाकांक्षाएं हैं- अमेरिका महान, अमेरिकी सदी और अमेरिका के वर्चस्व वाली एकल ध्रुवीय व्यवस्था। हैरिस व ट्रंप, दोनों ही अमेरिकी राष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक-आर्थिक-सामरिक संरचना में बदलाव के दुस्साहस से बचते रहेंगे। वैसे, यह आम धारणा है कि कमला हैरिस की जीत से विश्व में उदारवादी लोकतंत्र मजबूत होगा और मध्य-पूर्व सहित कुछ क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

खैर, अमेरिका में रह रहे वैज्ञानिक डॉक्टर आतिश कांबले कहते हैं कि कमला हैरिस को इसलिए जीतना चाहिए, क्योंकि इस समय उदार लोकतंत्र की जरूरत पूरी दुनिया को है। हालांकि, जरूरी नहीं कि अमेरिकी मतदाता दुनिया के हिसाब से सोचें, वे तो देशहित को सबसे ऊपर रखकर मतदान करेंगे।

(अमेरिका में रह रहे लेखक के ये अपने विचार हैं)

गली-गांव में बढ़ते ई-वाहनों को कैसे चार्ज किया जाए

यहां स्कैन करें

श्यामासिस दास | फेलो, सीएसईपी

भारत ने बीते पांच वर्षों में बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में बड़ी प्रगति की है। 2018-19 में वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 0.6 प्रतिशत थी, पर अब ईवी बसों को छोड़कर 7.2 प्रतिशत हो गई है। जल्दी ही ईवी की बिक्री का प्रतिशत दहाई अंक में पहुंच जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे अन्य संगठनों के अनुमान के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उज्ज्वल है, पर सवाल यह है कि क्या अब हमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के बारे में आश्वस्त हो जाना चाहिए?

कोई शक नहीं कि भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विद्युत गतिशीलता बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य के तहत सड़क परिवहन को डीकार्बोनाइज करना है। दूसरे शब्दों में कहें, तो सड़क परिवहन से होने वाले यातायात को कार्बन मुक्त कर देना है। फिलहाल भारत में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत है।

हमें इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकता मात्र से खुश नहीं होना चाहिए। भारत में ईवी से जलवायु को होने वाला लाभ सशर्त है। जब हम ईवी पर निर्भर होते हैं, तो ऊर्जा संयंत्रों पर हमारी निर्भरता बढ़ती है। भारत में जीवाश्म ईंधन देश की तीन-चौथाई ऊर्जा जरूरत को पूरा करता है। मतलब, हमारे वाहनों से नहीं, बिजली संयंत्रों से प्रदूषण या उत्सर्जन बढ़ने लगता है। इस मोर्चे पर गहराई से विचार करना होगा। हकीकत है कि अभी हमने चार्जिंग के ढंग पर भी विचार नहीं किया है। यात्रा के समय, परिवेश और चार्जिंग के स्थान का भी असर पड़ता है।

हमें इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकता मात्र से खुश नहीं होना चाहिए। भारत में ऐसे वाहनों से जलवायु को होने वाला लाभ भी सशर्त है।

यह तय है कि अगर अक्षय ऊर्जा पर हमारी निर्भरता बढ़ी, तो हम कार्बन उत्सर्जन से बच सकते हैं। दोपहिया और तीन-पहिया वाहनों, यात्री कारों व बसों में आंतरिक दहन इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन ऊर्जा दक्षता का ज्यादा लाभ अच्छी तरह से स्थापित है। यहां भी हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत की ग्रिड बिजली के वार्षिक औसत कार्बन बोझ को शामिल करने पर ईवी का उत्सर्जन लाभ कम हो जाता है। अधिकांश लोग ईवी को शाम या रात के दौरान चार्ज करते हैं, जिससे कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता बढ़ जाती है और ऐसा करते हुए वे उत्सर्जन के मोर्चे पर किसी भी लाभ को सीमित कर देते हैं। यह आंखें खोलने वाली बात है।

वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें, तो दिन के दौरान चार्जिंग से शाम की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अतिरिक्त उत्सर्जन से बचा जा सकता है। जैसे-जैसे ग्रिड बिजली मिश्रण अधिक सौर प्रभुत्व वाला होता जाएगा, ईवी की दिन-प्रतिदिन की उत्सर्जन प्रोफाइल और अधिक विषम होती जाएगी। इसलिए ईवी से जलवायु लाभ सुनिश्चित करने के लिए गंभीर सोच की जरूरत है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं है।

इसके लिए नीति निर्माताओं, उद्योगों व उपभोक्ताओं की समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। सबसे पहले, क्षेत्रीय आधार पर दिन-प्रतिदिन की बिजली दरों का ध्यान रखना होगा। ईवी चार्जिंग को सही ढंग से प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जब अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति बढ़े, तब ऊर्जा की कीमत भी कम होनी चाहिए, ताकि लोग अक्षय ऊर्जा से अपने वाहन चार्ज कराने में फायदा देखें। बैटरी स्वैपिंग को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। जैसे, दिन के समय अगर कोई वाहन उपयोग में आए, तो उसी समय उस वाहन की एक अतिरिक्त बैटरी चार्ज होती रहे। ऐसा न हो कि दिन भर वाहन चलाया और रात में पारंपरिक ऊर्जा के बल पर बैटरी को चार्ज कर लिया। आज बहुत से वाहन चालक उचित सूचना के अभाव में यही कर रहे हैं।

दूसरी बात, ऐसी व्यवस्था की जाए कि ज्यादा कुशल ईवी मॉडल के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिले। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों में क्षमता और कुशलता को समान स्तर पर कड़ाई से लागू करना चाहिए। तीसरी बात, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशनों को जोड़ना चाहिए। ऐसे चार्जिंग स्टेशनों को उच्च गुणवत्ता की ऐसी बैटरियों से लैस करना चाहिए, ताकि रात के समय भी चार्जिंग का काम न थमे।

इस त्रि-आयामी रणनीति से ही भारत परिवहन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने में सफल होगा। याद रखें, सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए जो सब्सिडी और कर सुविधाएं दे रखी हैं, उनका मोल समझने में देशहित है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मनुष्य को चेतन बनना होगा

कोई भी संस्कृति यदि सुसंस्कृत मनोवृत्ति को एक छोटे अल्पसंख्यक वर्ग तक सीमित रखकर अपने सीने में अज्ञानता के बृहद् पुंज को संजोए रखती है, तो वह सुरक्षित नहीं रह सकती। या तो ज्ञान को ऊपर से व्यापक बनना होगा या फिर नीचे से अज्ञानता की रात्रि द्वारा सदैव डुबो दिए जाने के खतरे में उसे बने रहना होगा। संस्कृति और भी असुरक्षित रहेगी, यदि उसने भारी संख्या में लोगों को अपने प्रकाश से प्रभावित हुए बिना अपने घेरे से बाहर रहने दिया। ज्ञान को, यदि वह अपने को जीवित और स्थायी बनाए रखना चाहता है, आक्रामक बनना होगा; एक व्यापक अज्ञानता को नीचे या आस-पास छोड़ देना, मानवता को बर्बरता की पूर्वस्थिति में लौटने के स्थायी खतरे के लिए खुला छोड़ना होगा।

यदि विज्ञान ने हमें अधिक विस्तृत और गहरी संस्कृति के युग के लिए तैयार किया है... तो उसने जीवन के प्रति अपने रुख और अपनी खोजों से, एक अन्य प्रकार की बर्बरता को अधिक या कम प्रोत्साहित भी किया है। बर्बरता के अतिरिक्त उसे और किसी नाम से नहीं पुकारा जा सकता- औद्योगिक, व्यावसायिक, आर्थिक युग की बर्बरता -जो अब अपनी पराकाष्ठा तक प्रगति कर रहा है और अपनी समाप्ति तक भी। यह आर्थिक बर्बरता मूल रूप से ओजस्वी मनुष्य की है, जो ओजस्वी अस्तित्व (अर्थात् उद्वेगों, भावनाओं, वासनाओं आदि का क्षेत्र, जो जीवन-ऊर्जा की विभिन्न अभिव्यक्तियों को समाहित करता है) को आत्मा समझने की भूल कर बैठता है और उसकी तुष्टि को जीवन का प्रथम लक्ष्य स्वीकार कर लेता है।... अपरिशोधित आर्थिक मनुष्य के लिए सौंदर्य एक निरर्थक या क्षतिकारक वस्तु है, कला और कविता एक छिछोरापन या एक दिखावा व विज्ञापन का जरिया है। उसके विचार में सभ्यता सुविधा है; सदाचार सामाजिक प्रतिष्ठा हैं; राजनीति उद्योग का प्रोत्साहन, बाजारों का खुलना, ध्वज का अनुसरण करते हुए शोषण व व्यापार है; और धर्म उसके विचार में अधिक से अधिक एक धर्मनिष्ठ औपचारिकता या जीव की कुछ भावनाओं की तुष्टि भर है। वह शिक्षा का मूल्यांकन मनुष्य को एक प्रतियोगिता में सफलता के उपयुक्त बनाने में उसकी उपादेयता के लिए करता है, अथवा वह एक सामाजिक बनाया गया औद्योगिक अस्तित्व हो सकता है।

ज्ञान को आक्रामक बनना होगा; एक व्यापक अज्ञानता को नीचे या आस-पास छोड़ देना, मानवता को बर्बरता की पूर्वस्थिति में लौटने के स्थायी खतरे के लिए खुला छोड़ना होगा।

एक व्यावसायिक युग में, जिसका नीच और बर्बर आदर्श सफलता, जैव तुष्टि और उत्पादकता है, मनुष्य की आत्मा कुछ लाभों और अनुभवों के लिए थोड़ी देर तक ठहर तो सकती है, पर स्थायी रूप से स्थिर नहीं रह सकती। यदि वह आदर्श अधिक समय तक बना रह गया, तो जीवन अवरुद्ध हो जाएगा और अपने रक्ताधिक्य से स्वयं नष्ट हो जाएगा।

श्री अरविंद

एस वाई कुरैशी | पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

आप चार राज्य के चुनाव तो एक साथ करवा नहीं पा रहे और बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, यह बिल्कुल विरोधाभासी है... कहीं न कहीं इसमें गंभीरता की कमी है।

त्वरित न्याय पुलिस नहीं अदालत करे

महाराष्ट्र के चर्चित बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की घटना ने एक बार फिर त्वरित न्याय के इस तरीके को सवालों के घेरे में ला दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस से जो सवाल किए हैं, वे साफ संकेत देते हैं कि पुलिस की कहानी पर उसे यकीन नहीं है। अदालत ने पूछा है कि मुठभेड़ की हालत में पुलिस को कहां गोली मारनी होती है, यह पता होता है, फिर अक्षय शिंदे के सिर में गोली कैसे लगी? चार-चार पुलिस वाले कैसे एक कमजोर आरोपी को काबू में नहीं कर पाए? इस अदालती सुनवाई पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, मगर पुलिस, समाज और न्याय-व्यवस्था के रवैये पर सवाल जरूर होने चाहिए।

किसी भी प्रदेश में पुलिस पर एनकाउंटर का दबाव कब बनता है? दरअसल, समाज के एक तबके को त्वरित न्याय चाहिए। अब अक्सर आक्रोशित भीड़ हत्या, बलात्कार के आरोपियों को फौरन फांसी पर लटकाने की मांग करने लगी है। लोग यह सुनने को तैयार ही नहीं होते कि आरोपी की शिनाख्त गलत भी हो सकती है या फिर घटना कहीं गहन तफ्तीश की मांग कर रही है। ऐसे में, लगता तो यही है कि पुलिस ने इस आक्रोश को शांत करने का सबसे सरल रास्ता यह मान लिया है कि आरोपियों को ढेर कर दिया जाए। मगर यह तरीका न्याय के बुनियादी सिद्धांत के बिल्कुल उलट है, जो सौ गुनहगारों के छूट जाने की कीमत पर भी एक बेगुनाह नागरिक के हितों की रक्षा करता है। जिंदगी एक ऐसी चीज है कि वह किसी को लौटाई नहीं जा सकती, इसीलिए फांसी आखिरी सजा तय की गई। मगर जिस संख्या में इन दिनों राज्य-दर-राज्य पुलिस मुठभेड़ में मौतें हो रही हैं, वे हमारी न्याय-व्यवस्था के लिए ठीक नहीं हैं।

दरअसल, मौके पर ही इंसाफ की बढ़ती सामाजिक अधीरता की मूल वजह हमारी न्याय-प्रणाली की शिथिलता है। देश में निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों की संख्या में मुकदमे लंबित पड़े हैं। हमारी जेलों में ऐसे अनगिनत लोग वर्षों से कैद हैं, जिनके खिलाफ आरोपपत्र तक दाखिल नहीं हो पाए, कई आरोपी तो अपने कथित जुर्म की अधिकतम सजा से भी अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं। ऐसी अनेक कहानियां अखबारों की सुर्खियां बनीं, जिनमें तीस-तीस साल बाद आरोपी को बेगुनाह पाया गया और जेल से रिहा होने के बाद उसकी जिंदगी खुद उसके लिए एक सवाल बन गई। इसलिए त्वरित न्याय और विलंबित न्याय, दोनों खतरनाक हैं।

शमशेर सिंह, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

एनकाउंटर

शिंदे जैसों के लिए इतनी चिंता क्यों

महाराष्ट्र में अक्षय शिंदे को एनकाउंटर में ढेर किए जाने की घटना पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीति की दुनिया तक खूब कलेजा पीटा जा रहा है। व्यंग्य कसा जा रहा है कि देश की सारी अदालतें बंद कर दीजिए और पुलिस को ही फैसला करने का अधिकार सौंप दीजिए। मेरी राय में इस तरह का विलाप ठीक नहीं है। क्या पुलिस सभी आरोपियों का एनकाउंटर करने लगी है? ऐसा होता, तो क्या हमारे देश के कारागृह क्षमता से अधिक कैदियों का भार ढो रहे होते? सवाल यह भी है कि क्या उन लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं होता, जिनकी अस्मत ये दुष्कर्मी लूटते हैं या जिनको मार डालते हैं?

असल में, अपने देश में हर चीज के विरोध का नया चलन शुरू हो गया है। कुछ लोग बस इसी ताक में रहते हैं कि कोई घटना घटे और उन्हें अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल जाए। ऐसे लोग यह भी नहीं सोचते कि इसका पीड़ित परिवार या देश-समाज पर क्या असर पड़ेगा। अक्षय शिंदे के लिए हंगामा काट रहे लोग क्या बताएंगे कि बदलापुर की उन दो मासूम बच्चियों का जीवन क्या अब वैसा ही रह गया है, जैसा उनके यौन उत्पीड़न से पहले था? मानसिक रूप से बीमार ऐसे लोगों के कारण ही अब कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। ऐसे लोग न सिर्फ पीड़ितों के, बल्कि पूरे समाज और देश के अपराधी हैं, इनके लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। दुराचारियों के मानवाधिकारों की वकालत करने वाले लोग प्रकारांतर से उन्हें प्रोत्साहित ही करेंगे, क्योंकि उन्हें तो यही लगेगा कि न्यायपालिका में मुकदमा दशकों तक लटका रहता है और बचाव करने वाले लोग भी हैं ही। यही कारण है कि आज अदालत से बाकायदा सजायाफ्ता दुष्कर्मियों की आरती उतारने के लिए लोग जेलों की परिक्रमा करने लगे हैं या उनके पैरोल पर छूटने का जश्न मनाने लगे हैं। इस तरह तो हम एक पाखंडी समाज ही गढ़ेंगे। इसलिए राजनीतिक दलों के साथ-साथ मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को यह सोचना होगा कि वे किसी अपराधी की वकालत करते हुए पीड़ित व्यक्ति, परिवार के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? शिंदे जैसे आरोपियों का बचाव कई नए शिंदे समाज में पैदा कर सकता है। देश में करोड़ों लोग चैन की जिंदगी जी सकें, यह सुनिश्चित करने का दायित्व हमारी व्यवस्था ने पुलिस प्रशासन को दिया है। उसे अपना यह काम करने देना चाहिए। पुलिस देश के कानून के आगे जवाबदेह है और अदालत को अपनी कार्रवाई का औचित्य भी साबित करेगी।

अमर यादव, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

एक और युद्ध

''युद्ध केवल युद्ध नहीं होता,
अंत में अधिक हिंसक, अधिक अमानवीय बन जाता है,
जिन्हें युद्ध चाहिए अंत में मारे जाते हैं,
जिन्हें युद्ध नहीं चाहिए अंत में वे भी मारे जाते हैं।
युद्ध के बाद कोई उम्मीद नहीं बचती,
शांति के लिए यदि युद्ध जरूरी है
तो ऐसी शांति भी अशांत है।''

युद्ध की स्थिति पर बहुत कुछ लिखा जाता रहा है और वर्तमान में दुनिया एक के बाद एक नई जंग देख रही है। इजराइल और हमास युद्ध तो चल ही रहा था, अब इजराइल और लेबनान में शुरू हुई लड़ाई में सैकड़ों लोगों की मौत का मातम मनाया जा रहा है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के युद्ध में कूदने के बाद इजराइल पर एक के बाद एक किए गए रॉकेट हमलों के बाद इजराइल द्वारा किए गए ताबड़तोड़ हमलों में 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1700 के करीब लोग घायल हुए। हताहतों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाकर पेजर, वॉकी-टॉकी जैसे संचार उपकरणों में विस्फोट के जरिये हमले किए थे।

अक्तूबर 2023 में गाजा में युद्ध भड़कने के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के दरम्यान सीमा पार झड़पें तो हो रही थीं जो कि अब एक जंग में तब्दील हो चुकी हैं। इस जंग के चलते लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। जंग से दुनिया में एक बार फिर शरणार्थी संकट पैदा होने का खतरा मंडराने लगा है। कोविड-19, आर्थिक मंदी और चार वर्ष पहले भी राजधानी बेरूत में हुए भीषण बम विस्फोटों के बाद एक बार फिर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि पिछले एक साल से गाजा में जिस तरह से मानवता कराह रही है उससे वैश्विक शक्तियों ने कोई सबक नहीं सीखा है। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इजराइल के भीतर सैकड़ों रॉकेट दागे इससे उनके हमलों की अंधाधुंध प्रवृति जाहिर होती है। जो कुछ इजराइल कर रहा है वह भी अमानवीय है। वह लेबनान को दूसरा गाजा बनाने को तैयार है। इजराइल किसी खतरे का इंतजार नहीं कर रहा, उसका मकसद उन गांव को खाली कराने का है जहां हिजबुल्लाह ने अपने बड़े हथियार छुपा रखे हैं। इजराइल लेबनानी लोगों को गांव खाली करने की चेतावनियां दे रहा है। फिलहाल इस जंग को रोकने के लिए कोई कूटनीतिक प्रयास नहीं हो रहे। अमेरिका के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयास, गाजा में युद्ध विराम और इजराइली बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत की कोशिशें भी आगे नहीं बढ़ी हैं। यह बराबरी की लड़ाई नहीं है।

NewsPaperPaid

इजराइल-लेबनान युद्ध का भारत पर भी असर हो सकता है। हालांकि लेबनान इतना छोटा देश है जहां की अर्थव्यवस्था भारत के सामने कहीं नहीं टिकती। भारत पिछले कई वर्षों से लेबनान से कैल्शियम फॉसफेट खरीदता है, कैल्शियम फॉसफेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दवाइयों में होता है। फर्टिलाइजर में भी अहम कम्पोनेंट कैल्शियम फॉसफेट ही होता है। लेबनान से भारत स्क्रैप आयरन, स्क्रैप एल्युमिनियम भी खरीदता है। इसलिए युद्ध का कुछ न कुछ असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। युद्ध खत्म हो भी गया तो स्थितियां कितनी बदत्तर हो जाएंगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है।

इजराइल को मालूम है कि वह हिजबुल्लाह को हरा सकता है लेकिन दोनों ही पक्ष एक-दूसरे के विनाश और पीड़ा पहुंचाने में बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह कल्पना से परे है। संयुक्त राष्ट्र चीख-चीख कर कह रहा है कि लेबनान को नया गाजा बनाने के इजराइल के इरादों को रोका जाए। अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन किए जाने की उसकी पुकार सुनी जाए लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। इजराइल में अभी तक 60 हजार लोग विस्थापित हुए हैं। इजराइली हमलों के कारण लेबनान के दक्षिणी इलाके से लगभग 30 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। गाजा पट्टी में 19 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जो गाजा पट्टी की लगभग 90 प्रतिशत आबादी है। 2006 में भी इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध लड़ा गया था। युद्ध के बाद दोनों देशों ने खुद को विजयी बताया था, परन्तु बाद में इजराइली पक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। इस युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजराइल को पहली बार हार का स्वाद चखाया था। हिजबुल्लाह को ईरान का हर तरह से समर्थन प्राप्त है और उसकी सेना मध्य पूर्व की सबसे मजबूत और प्रशिक्षित सेना है। अब ईरान भी इजराइल से बदला लेने को तैयार बैठा है। ईरान कह रहा है कि पूरी दुनिया इजराइल के अत्याचार देख रही है। इजराइल ने 11 महीनों में हजारों मासूमों को निर्ममता से मारा है। उसने ईरानी वैज्ञानिकों, राजनयिकों और अतिथियों की भी हत्या की है। इजराइली सत्ता तंत्र के अपराधों और उपनिवेशवाद के पीड़ितों को ईरान अपना समर्थन दे रहा है। अगर ईरान इस युद्ध में सीधे कूद गया तो यह दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकती है। मध्यपूर्व का संकट किस दिशा में जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी कुछ हो रहा है उसे दुनिया सहन नहीं कर पाएगी। इजराइल-लेबनान युद्ध का भारत पर भी असर हो सकता है। हालांकि लेबनान इतना छोटा देश है जहां की अर्थव्यवस्था भारत के सामने कहीं नहीं टिकती। भारत पिछले कई वर्षों से लेबनान से कैल्शियम फॉसफेट खरीदता है, कैल्शियम फॉसफेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दवाइयों में होता है। फर्टिलाइजर में भी अहम कम्पोनेंट कैल्शियम फॉसफेट ही होता है। लेबनान से भारत स्क्रैप आयरन, स्क्रैप एल्युमिनियम भी खरीदता है। इसलिए युद्ध का कुछ न कुछ असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। युद्ध खत्म हो भी गया तो स्थितियां कितनी बदत्तर हो जाएंगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

जिम्मेदार कौन है...

"इन सफलता के दरवाजों के पीछे अब गहरा मौन है,
इन भागते-दौड़ते दफ्तरों में इंसानी भावना गौण है,,
इन युवा दिमागों पर तनाव डालने के लिए जिम्मेदार कौन है,
उन बड़े-बड़े पैकेजों में चकाचौंध के साथ-साथ
मौत के लिए भी टाइम आन हैं...।"

गीता पाढा

क्या राहुल गांधी टार्गेट हैं?

मर्यादाएं

चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

अक्तूबर 1984 के शुरू की बात है। हम वीरेंद्र जी के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके कार्यालय में मिले थे। ब्लू स्टार के बाद उस वक्त पंजाब उबल रहा था। पिताजी ने इंदिराजी को सावधान करते हुआ कहा "आप टार्गेट हैं"। इस पर उनका जवाब था, " हूं नहीं, पर बनाई जा रही हूं"।31 अक्तूबर को उनकी बात सही साबित हो गई जब घर के अन्दर ही उनकी हत्या कर दी गई। आज जब कुछ लोग राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा की बात कर रहे हैं मेरे जहन में इंदिराजी की बात गूंज रही है। क्या अब राहुल गांधी को टार्गेट बनाया जा रहा है?

जब से राहुल गांधी अमेरिका से लौटे हैं उनके विरोधियों में उनको गालियां निकालने की होड़ सी लगी है। इस पर आपत्ति नहीं क्योंकि राजनीति में यह चलता है, चिन्ता तब होती है जब हिंसा उकसाई जाती है। राहुल गांधी को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि परिवार में पहले ही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हो चुके हैं। केन्द्रीय मंत्री और नए भाजपाई रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें 'आतंकी नम्बर 1' कहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने बिट्टू की बात दोहरा दी है। शिवसेना के एक विधायक ने राहुल की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भाजपा के एक सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि राहुल की जीभ ही नहीं काटनी चाहिए, उसे जला दिया जाना चाहिए। एक भाजपा नेता ने तो यहां तक कह दिया, "राहुल गांधी बाज आ जाएं नहीं तो आने वाले टाईम में तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था"।

हैरानी की बात केवल यह ही नहीं कि धमकी दी गई बल्कि यह भी कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे देश में कई राजनीतिक हत्या हो चुकी हैं पर हमने कोई सबक नहीं सीखा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या को देश और दुनिया आज तक नहीं भूल सकी। महात्मा गांधी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि एक वर्ग में उनके ख़िलाफ़ नफरत फैला दी कि वह हिन्दू विरोधी हैं। दुख की बात है कि ऐसा प्रचार आज तक चल रहा है। जिन्हें दुनिया आजतक पूजती है की हमारे लोगों ने ही हत्या कर दी। जब इंसान नफरत में अंधा हो जाता है तो उसकी सोचने की शक्ति उसे छोड़ जाती है। सोशल मीडिया यह बीमारी बढ़ा रहा है। हमारे देश में बहुत लोग हैं जो समझते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला या उनकी बात कोई नहीं सुनता। देश में बढ़ रही असमानता भी असंतोष पैदा कर रही है। जब यह असंतोष नफरत की सीमा पार कर जाता है तो इंसान बेसुध हो जाता है।

राजनीतिक वर्ग की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह शब्दों पर नियंत्रण रखें ताकि कोई और हादसा न हो। हमारे देश का तापमान आजकल पहले ही बहुत ऊंचा है उस पर तेल डालने से वह भड़क सकता है। सभ्य संवाद की गुंजाइश कम होती जा रही है। 13 दिसम्बर 2001 को जब हमारी संसद पर हमला हुआ तो प्रधानमंत्री वाजपेयी और सोनिया गांधी ने फोन कर एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। आज ऐसा भाईचारा ख़त्म हो चुका है। यह नहीं कि कांग्रेस और गांधी परिवार इस मामले में मासूम है। तेलंगाना के एक कांग्रेसी विधायक ने घोषणा की है कि जो बिट्टू का सर कलम कर लाएगा उसे वह एक एकड़ पुश्तैनी जमीन ईनाम में देगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को गिनाया है कि दस वर्षों में कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 110 गालियां दी हैं। सोनिया गांधी ने उन्हें "मौत का सौदागर" कहा था। फरवरी 2020 में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि, "यह जो नरेन्द्र मोदी भाषण दे रहा है, छह महीने बाद वह घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। हिन्दोस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे..."। अगर यह हिंसा उकसाना नहीं तो और क्या है? यह अच्छी राहुल की 'मुहब्बत की दुकान' है जो नफरत और हिंसा बेचती है? कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय कह चुके हैं कि "अगर मोदी हिटलर के रास्ते पर चलते हैं तो वह ही हश्र होगा जो हिटलर का हुआ था। "यह उस व्यक्ति के बारे कहा गया जो हर समय खतरे में हैं और देश का प्रधानमंत्री है। अर्थात् दोनों ही तरफ वह है जो लोगों को भड़का रहे हैं। इस प्रयास के विनाशक परिणाम निकल सकते हैं,जैसे पहले कई बार हो चुका है।

राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा विवादास्पद रही है। जब भी वह विदेश जाते हैं तो देश में लोकतंत्र खतरे में है की शिकायत करते हैं। एक बार तो विदेश में कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। यह तो सही है कि हमारा लोकतंत्र परफेक्ट नहीं है पर यह खतरे में नहीं है। अगर वह खतरे में होता तो दोस्त, तुम प्रतिपक्ष के नेता न बनते ! न वह बंगला मिलता, न वह सिक्योरिटी मिलती और न ही वह रुतबा होता। लोगों ने भाजपा की 63 सीटें कम करवा दिया कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है और साथ ही भाजपा नेतृत्व को सख्त संदेश भेज दिया कि वह अप्रसन्न हैं। इंदिरा गांधी के समय इमरजैंसी लगी और राजीव गांधी के समय प्रेस की आजादी को सीमित करने का असफल प्रयास किया गया। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान भी उनकी टीम ने इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ धक्का-मुक्की की और उसका फोन छीन कर राहुल का इंटरव्यू डिलीट कर दिया। क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा हो रही थी? अर्थात् लगभग सब सरकारें लोकतंत्र से छेड़खानी की दोषी हैं पर लोग भी साफ संदेश दे रहे हैं कि उन्हें संविधान से छेड़खानी बिल्कुल पसंद नहीं। यही कारण है कि सरकार का 'वन नेशन वन पोल' प्रयास सफल नहीं होगा क्योंकि यह संविधान की मूल भावना से छेड़खानी करता है।

राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में उनका सबसे बेतुका बयान सिखों के बारे था। यह आभास मिलता है कि वह वहां समस्या खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं जहां समस्या है ही नहीं। उनका कहना था कि, "भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या सिखों को देश में पगड़ी डालने या कड़ा पहने की अनुमति होगी? क्या वह गुरुद्वारे जा सकेंगे?" क्या राहुल सचमुच समझते हैं कि देश में सिखों की धार्मिक आजादी को कोई खतरा है? सारे देश में एक भी ऐसा मामला नहीं है। सिखों की देश में वह इज्जत है जो किसी भी समुदाय की नहीं है। विदेश में बैठे खालिस्तानी तत्व जरूर छवि खराब कर रहे हैं। देश के अन्दर भी कुछ उग्रवादी तत्व हैं लेकिन वह मुख्यधारा नहीं है। कोलकाता से एक रिपोर्ट के अनुसार वहां महिलाएं उस टैक्सी में जाना पसंद करती हैं जो सरदार चला रहा होता है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अगले वायुसेना अध्यक्ष बन रहे हैं। जहां ऐसा विश्वास और ऐसी इज्जत हो कोई कह सकता है कि सिखों की पगड़ी या कड़ा पहनने या गुरुद्वारे जाने की आजादी खतरे में है ?

राहुल गांधी के अनुचित बयान का दुष्परिणाम यह हुआ कि विदेश में बैठे खालिस्तानी तत्वों को कहने का मौका मिल गया कि हम तो पहले ही कहते थे कि सिख वहां खतरे में हैं इसलिए खालिस्तान चाहिए। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तत्काल राहुल गांधी की बात का समर्थन कर दिया। क्या राहुल चाहते हैं कि वह पन्नू जैसे के साथ खड़े दिखाई दें? पहले ही कनाडा की सरकार इन तत्वों को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले व्हाइट हाउस में अमेरिकी अधिकारियों ने कथित सिख मामलों को लेकर सिख उग्रवादियों के साथ बैठक की है। यह सामान्य नहीं है। अर्थात् कुछ विदेशी सरकारें भी मामला जीवित रखना चाहती हैं। पाकिस्तान के पत्रकार डा. कमर चीमा के शो में वह एक और पत्रकार साजिद तरार से राहुल गांधी के बयानों पर चर्चा कर रहे थे। दोनों ने सिखों के बारे राहुल की बात पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि, "सिख तो मुख्यधारा का हिस्सा हैं...राहुल को कोंसलिंग (सलाह) की जरूरत है। उनकी मदर को उन्हें समझाना चाहिए... वह मैच्योर नहीं लग रहे"।

ऐसी आलोचना राहुल गांधी ने खुद आमंत्रित की है। देश के अन्दर वह समझदार नजर आते हैं पर विदेश में जाकर उत्तेजित होकर बहक जाते हैं। उन्हें लोगों की समस्याओं पर केन्द्रित रहना चाहिए पर वह वैचारिक बहस में फंस जाते हैं। यह भी सवाल उठता है कि क्या विदेश में जाकर अपने गंदे कपड़े धोने चाहिए? बेहतर होगा कि इस मामले में आम सहमति बना ली जाए क्योंकि राहुल गांधी ही नहीं नरेन्द्र मोदी भी विदेश में देश की आलोचना कर चुके हैं।

राहुल गांधी को जब जब देश गम्भीरता से लेने लगता है तो वह कुछ ऐसा कर देते हैं या कह देते हैं कि संशय हो जाता है कि वह बड़ी जिम्मेवारी के लिए उपयुक्त भी है या नहीं? लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ जो हिंसा प्रेरित की जा रही है वह निन्दनीय है। विश्व इतिहास राजनीतिक हिंसा की मिसालों से भरा हुआ है। अमेरिका के चार राष्ट्रपति गोलियों का निशाना बन चुके हैं लेकिन इसके बावजूद वहां राजनीतिक भाषा में हिंसा टपकती रहती है।

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने समर्थकों से कहा है कि "डोनल्ड ट्रम्प को हर हाल में रोकना है" और डोनल्ड ट्रम्प का कहना है कि "अगर मैं जीतता नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी"। ऐसी ही शब्दावली का परिणाम हैं कि ट्रम्प पर दो हमले हो चुके हैं। हमें ऐसी शब्दावली और उसके दुष्परिणामों से बचना है। राजनीतिक मतभेद को दुश्मनी और नफरत तक खींच कर नहीं ले जाना। अगर हिंसा की भाषा आम हो गई तो कोई भी टार्गेट बन सकता है। शायर ने सावधान किया है,

मेरे आशियां का तो गम न कर कि वह जलता है तो जला करे, लेकिन इन हवाओं को रोकिए ये सवाल चमन का है !

खालिस्तानी समर्थकों द्वारा पीएम मोदी का विरोध क्यों?

सिख सियासत

सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमरीका दौरे के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का विरोध किया हालांकि न्यूयार्क की पुलिस ने खालिस्तानीयों पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए एक खालिस्तानी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार भी कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के आस-पास से भड़काऊ प्रचार सामग्री को भी हटा दिया। सवाल यह बनता है कि आखिरकार खालिस्तानी समर्थक भारतीय प्रधानमंत्री के विरोध में क्यों हैं जबकि आजादी के बाद से नरेन्द्र मोदी शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सिखों की समस्याओं को समझते हुए उनके निवारण की पुरजोर कोशिश करते हैं। इसी का परिणाम है कि 75 वर्षों की अरदास के बाद करतारपुर साहिब का कोरिडोर सिख संगत के दर्शनों के लिए खोला गया।

1984 सिख कत्लेआम को अंजाम देने वाले सज्जन कुमार जैसे दोषी सलाखों के पीछे भेजे गए। साहिजबादों की शहादत का इतिहास जो आज तक सिख कौम स्वयं देशवासियों को बताने में कहीं ना कहीं असफल रही उसे देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाया गया। गुरु साहिबान के पर्व सरकारी स्तर पर मनाए गये। इसके लिए समूची सिख कौम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी टीम का आभार प्रकट करना चाहिए और शायद भारत में रहने वाले ज्यादातर सिख करते भी हैं। मगर विदेशों की धरती पर बैठकर खालिस्तान की मांग करने वाले चंद लोगों की वजह से समूची सिख कौम को शर्मसार होना पड़ता है। यह लोग भारतीय प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि तिरंगे का भी अपमान करने से नहीं चूकते जबकि इतिहास गवाह है कि देश की आन बान शान तिरंगे के लिए भारतीय सिखों ने ना जानें कितनी शहादतें दी हैं। आज भी देश की सरहदों पर तिरंगे की रक्षा हेतु सिख सैनिक तैनात रहते हैं। भाजपा से जुड़े सिख नेता रविन्दर सिंह रेहन्सी का कहना है कि मुस्लिम यां अन्य समुदाय के लोग भी हैं जो सरकार की नीतियों से नाखुश होते हैं मगर आज तक किसी ने भी तिरंगे का अपमान करने की जुर्रत नहीं की। उनका साफ कहना है कि इन जैसे लोगों के कारण ही समूची सिख कौम को शर्मिन्दगी महसूस करनी पड़ती है।

खालसा कालेज में सिख छात्र की दस्तार उतारने पर बवाल

दिल्ली के गुरु तेग बहादुर खालसा कालेज में छात्रसंघ चुनाव के दौरान एक अमृतधारी सिख की दस्तार कुछ गैर सिख युवकों द्वारा उतारे जाने के बाद से मामला इतना तूल पकड़ गया कि देश ही नहीं विदेशों से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी। सिख ब्रदर्सहुड इन्टरनैशनल के सैक्रेटरी जनरल गुणजीत सिंह बख्शी ने तो यहां तक कह दिया कि यह समूचे सिखों को ललकार है कि गैर सिख सिखों के कालेज में आकर सिख की दस्तार पर हाथ डाले और वहां मौजूद अन्य सिख यहां तक कि कालेज प्रशासन भी देखता रह जाए और घटना को अंजाम देने वाले वहां से निकल जायें। वैसे देखा जाए तो इससे पहले भी हर साल छात्र संघ के चुनावों के दौरान लड़ाई झगड़े अक्सर हुआ करते थे जिसे देखते हुए ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो के द्वारा निर्णय लिया गया था कि खालसा कालेजों में छात्रसंघ के चुनाव करवाने के बजाए सर्वसम्मति से छात्रों का चयन कर जिम्मेवारी सौंप दी जाए। मगर विपक्षी पार्टियों को यह रास नहीं आया और उन्होंने कोर्ट का सहारा लेते हुए खालसा कालेजों की चुनावों में भागीदारी को लाजमी बनवाया जिसके बाद ऐसी घटना सामने आई कि झगड़े के दौरान एक युवक की दस्तार उतार दी गई। चाहिए तो यह था कि सभी को मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए आवाज उठाते मगर इस घटना की आड़ में कुछ नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने की मंशा से मामले को पूरी तरह से तूल दिया गया, छात्रों को उकसाते हुए धरने प्रदर्शन करवाते हुए सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल किए, अखबारों की सुर्खियां बटोरते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को जमकर कोसा। यह भी जगजाहिर है कि आज जो लोग भाजपा समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कोस रहे हैं कुछ समय पहले तक जब उनकी पार्टी का भाजपा से गठजोड़ था तो उनकी मदद से ही एस ओ आई खालसा कालेजों में विजय परचम लहराया करते थे। कई दिन पहले से ही पंजाब से शिरोमणी अकाली दल के नुमाइंदे आकर चुनाव की बागडो संभाल लिया करते और बदले में दूसरे कालेजों में खुलकर एबीवीपी का समर्थन करती थी।

इस घटना के लिए जहां परमजीत सिंह सरना, मनजीत सिंह जीके विरोध दर्ज करवा रहे हैं तो वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मदद से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवाने के लिए पहल की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से 1 अक्टूबर तक मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार कर पेश करने को कहा है। कालेज के चेयरमैन तरलोचन सिंह, खजानची इन्द्रप्रीत सिंह कोछड़ और प्रिंसीपल गुरमोहिन्दर सिंह ने भी इस तरह की घटनाए भविष्य में ना हो इस पर सभी से मिलकर रणनीति तैयार करने की बात कही है। वहीं सिख बुद्धिजीवियों की मानें तो उनका साफ तौर पर कहना है इस घटना के बाद कोर्ट को समझाते हुए तुरन्त प्रभाव से खालसा कालेजों में चुनावों पर प्रतिबंध लगवाना चाहिए जिससे कि गुरु साहिबान के नाम से चलने वाले खालसा कालेजों में इस तरह की गुंडागर्दी बंद हो सके। यहां एक बात और गौर करने वाली है कि आज भले ही परमजीत सिंह सरना और मनजीत सिंह जीके अकाली दल का हिस्सा होने के चलते छात्रसंघ चुनावों की प्रोढ़ता करते हों मगर 11 वर्षों तक शिरोमणी अकाली दल दिल्ली की कमान संभालते हुए परमजीत सिंह सरना की पार्टी ने कभी भी छात्रसंघ चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे।

आतिशी कैबिनेट में भी सिख मंत्री नहीं

दिल्ली में आज तक भाजपा यां कांग्रेस जितनी भी सरकारें बनी सभी में एक सिख मंत्री को जगह अवश्य दी जाती रही है क्योंकि दिल्ली की 70 में से 40 के करीब सीट ऐसी हैं जहां पर जीत हार का फैसला सिख यां पंजाबी वोटरों के द्वारा ही किया जाता है मगर अरविंद केजरीवाल की 3 बार सरकार बनीं, एक बार तो 3 सिख विधायक जीतकर आए, अभी भी दो सिख विधायक मौजूद हैं मगर किसी एक को भी मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं किया गया। हाल ही मे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है किसी सिख या पंजाबी को अवश्य मंत्रिमण्डल में शामिल किया जायेगा मगर ऐसा हुआ नहीं जिसके बाद से सिखों में ही नहीं बल्कि पंजाबी समुदाय में भी कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है।

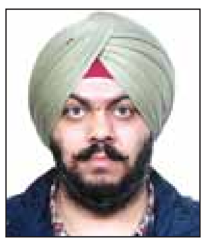

वैसे भी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर पंजाबी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार किये जाने के आरोप लगते रहे है। पंजाबी भाषा को सातवें पायदान पर लेजाना हो यां फिर पंजाबी टीचर्स की अनदेखी हो इस सबके चलते आप सरकार बैकफुट पर ही रही है जिसका खामियाजा आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है।

'चूहे जैसे' आरएसएस ने राज्य में की घुसपैठ : हेमंत सोरेन

रांची, (पंजाब केसरी) : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तुलना 'चूहों' से की और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आरएसएस पर चुनावी फायदे के लिए राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने दावा किया कि भाजपा हिंदू और मुस्लिम समुदाय में द्वेष की बीज बो रही है। उन्होंने विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की इसमें संलिप्तता को रेखांकित किया। सोरेन ने कहा कि आरएसएस चूहों की तरह राज्य में घुसपैठ कर इसे बर्बाद कर रही है। जब आप उन्हें गांवों में 'हंडिया' और 'दारू' के साथ दाखिल होते देखें को उनका पीछा कर खदेड़ें...वे चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक अशांति और तनाव पैदा करना चाहते हैं।'' सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने पर आमादा है। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों में मांस फेंकने जैसी भड़काऊ घटनाओं में वृद्धि की आशंका जताई। सोरेन ने भाजपा को कारोबारियों और उद्योगपतियों की पार्टी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह अपने एजेंडे के लिए राजनीतिक नेताओं की खरीद कर रही है। उनका स्पष्ट संदर्भ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा हाल में भाजपा में शामिल होने को लेकर था। चंपई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पर 'सम्मान नहीं देने और अपमानित करने' का आरोप लगा भाजपा का दामन थाम लिया था। मुख्यमंत्री ने झारखंड की जनसांख्यिकी में बदलाव के भाजपा के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने आलोचकों को सलाह दी कि उन्हें पड़ोसी पश्चिम बंगाल की जनसांख्यिकी को देखना चाहिए। सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री की झारखंड में ऐसे समय उपस्थिति पर सवाल उठाया जबकि उनके अपने राज्य में आदिवासी कई अत्याचारों का सामना कर रहे हैं।

● **भाजपा ने झारखंड के कुछ नेताओं को खरीदाः भाजपा समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने पर आमादा**

आईआईटी सीट गंवाने वाले गरीब दलित युवक को मदद

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) उच्चतम न्यायालय ने कड़ी मेहनत के बाद अपने अंतिम प्रयास में आईआईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उस गरीब दलित युवक को मदद का आश्वासन दिया है, जो धनबाद स्थित इस संस्थान में अंतिम तिथि तक 17,500 रुपये फीस जमा नहीं करा सका और अपनी सीट गंवा दी। प्रमुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को 18-वर्षीय अतुल कुमार के वकील से कहा, "हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे, लेकिन आप पिछले तीन महीनों से क्या कर रहे थे, क्योंकि शुल्क जमा करने की निर्धारित समय सीमा 24 जून को समाप्त हो गई है।" कुमार के माता-पिता सीट पक्की करने के लिए 17,500 रुपये की निर्धारित फीस 24 जून तक जमा करने में विफल रहे थे। युवक के माता-पिता ने सीट बचाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण और मद्रास उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

CMYK

दैनिक जागरण
मौन ही क्रोध को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है

मेक इन इंडिया अभियान

मेक इन इंडिया अभियान के दस वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उसकी सफलता का जो उल्लेख किया, उससे असहमत तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन यह आभास किया जाए तो बेहतर कि इस पहल को और अधिक सफल बनाया जा सकता था। इस अभियान ने कई उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं, जैसे दस वर्ष पहले देश में मोबाइल फोन बनाने वाली केवल दो कंपनियां थीं। आज उनकी संख्या बढ़कर दो सौ के करीब हो गई है। इसके चलते भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। पहले केवल 1,556 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन निर्यात होते थे। अब 1.2 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल निर्यात हो रहे हैं और देश में प्रयोग होने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल मेक इन इंडिया हैं। इसी तरह फिनिश्ड स्टील के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। खिलौनों के निर्माण में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और अब उनका आयात घटकर आधा रह गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जिस तरह डेढ़ लाख करोड़ का निवेश हुआ है, उससे पांच प्लांट लगने जा रहे हैं, जो प्रतिदिन सात करोड़ चिप बनाएंगे। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में अब दुनिया में चौथे नंबर पर है और देश का ईवी उद्योग अब तीन अरब डालर तक पहुंच गया है। रक्षा क्षेत्र भी मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी कहता है। देश का रक्षा निर्यात 21 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है और अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। आज भारत कई देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है।

यह कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया अभियान ने रक्षा क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया है। ऐसी ही तस्वीर अन्य क्षेत्रों में भी बदलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह एक तथ्य है कि तमाम प्रयासों के बाद भी चीन से होने वाला आयात कम नहीं हो रहा है। तमाम ऐसी वस्तुएं चीन से मंगाई जा रही हैं जिनका निर्माण भारत में किया जा सकता है। एक समस्या यह भी है कि चीन से तमाम कल-पुर्जे मंगाकर उन्हें देश में असेंबल कर कई तरह के उपकरण बनाए जा रहे हैं। समझना कठिन है कि भारतीय उद्योगपति वह सब देश में क्यों नहीं बना सकते, जिसके निर्माण की संभावनाएं देश में हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं, जो पहले भारत में बनती भी थीं। एक ओर जहां देश के उद्योगपतियों को कमर कसनी होगी, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी यह देखना होगा कि हमारे उद्योगपति चीनी कारोबारियों का मुकाबला करने में क्यों हिचक रहे हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं? कुल मिलाकर मेक इन इंडिया अभियान कुछ हद तो सफल है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना है।

असमंजस करें दूर

भूमि अभिलेख सुधार के लिए विशेष सर्वे कराने की बिहार सरकार की नीति रैयतों के लिए वह महत्वाकांक्षी योजना है, जो भविष्य में भूमि विवाद के प्रकरण कम करेगी और हर भूमि से जुड़े अभिलेख रैयत से लेकर सरकार तक, सभी के पास होंगे। सरकार की इस जनोपयोगी योजना से अगर किसी को हानि होनी है तो निश्चित रूप से वह भू माफिया और दबंग प्रवृत्ति के ऐसे लोग हैं, जिन्होंने दूसरे की भूमि को दबा रखा है। उस पर अनधिकृत स्वामित्व बनाया हुआ है। इस योजना से उन्हें हानि है जो भूमि विवाद को बढ़ावा देकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं और अनधिकृत लाभ का अवसर खोजते हैं। वर्षों बाद शुरू हुए इस विशेष सर्वे ने लोगों की आशा जीवित की है कि अब भूमि की जमाबंदी उनके नाम बिना किसी अड़चन के हो जाएगी। देश, दुनिया में कहीं भी रह रहे हों, वह अपने गांव आकर भूमि संबंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रति निकलवा सकेंगे। अभी अभिलेख सुरक्षित करने के लिए प्रखंड कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सरकार निरंतर बता रही है कि किसी के बहकावे में न आएं। सर्वेक्षण के लिए जाने वाले राजस्व कर्मी सभी अभिलेखों के साथ भूमि पर पहुंचकर सर्वेक्षण करेंगे। वंशावली की भी घोषणा स्वतः करनी होगी, फिर भी निबंधन और अंचल कार्यालय से लेकर अभिलेखागार तक, भीड़ कम नहीं हो रही है। इसका सीधा कारण है, लोगों में यह आशंका कि उनकी भूमि के दस्तावेज सुरक्षित हैं या नहीं। इस आशंका के पीछे भी तर्क है, क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण भूमि निबंधन से संबंधित कई अभिलेख विभिन्न निबंधन कार्यालयों से गायब हैं। भू माफिया भी सर्वे को लेकर विभिन्न प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं, जो रैयतों के मन में आशंका उत्पन्न करने में सफल हो रहे हैं। सरकार ने अफवाहों से बचने की अपील करते हुए समस्याएं सुनने के लिए टाल फ्री नंबर जरूर जारी किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी अधिकारियों को लोगों की शंका-आशंका दूर करने के लिए उन तक पहुंचकर जागरूक करना चाहिए।

खतरा बन सकते हैं कश्मीरी अलगाववादी

विजय क्रांति

महंगी पड़ सकती है विधान सभा चुनावों में कश्मीर में उभरे अलगाववादी एजेंडे की अनदेखी

अवधेश राजपूत

पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और विशेष दर्जे को समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद करने के साथ यह निर्देश भी दिया था कि एक तय समय में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे चुनावों से देश का एक वर्ग आश्वस्त दिख रहा है कि विधानसभा चुनावों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों को यह भी उम्मीद है कि नई विधानसभा के चुने जाने के बाद आजादी के पहले दिन से ही मुसीबतों से घिरे हुए जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल हो जाएगी। कश्मीर विवाद के कारण यहां की जनता ने जैसी कठिनाइयां देखी हैं और भारत विरोधी शक्तियों के नैरेटिव निर्माण की ताकत के आगे बार-बार पस्त होने वाली केंद्रीय सरकारों ने वैश्विक मंचों पर जिस स्तर का विरोध सहा है, उसके बाद इस तरह की आशाओं का जगना स्वाभाविक भी है। इन विधानसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर की जनता ने जैसे उत्साह के साथ स्थानीय निकायों के चुनावों में भाग लिया और जैसे शांति भरे माहौल में वे चुनाव संपन्न हुए, उससे भी कश्मीर में सब कुछ ठीक होने की आस जगी थी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा के दिन से ही कश्मीर घाटी में जिस तरह के उम्मीदवार और जैसे चुनावी वादे पूरे माहौल पर हावी हैं, उसे देखते हुए यह आशंका बल पकड़ने लगी है कि विधानसभा में भले ही कोई भी पार्टी या गुट बहुमत हासिल करे, लेकिन घाटी की राजनीति फिर से अलगाववाद और केंद्र से टकराव की आग में तप सकती है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में कई प्रत्याशी ऐसे हैं, जो या तो अलगाववादी रहे हैं या ऐसे संगठनों के सक्रिय सदस्य। इनमें अनेक निर्दलीय हैं। इन निर्दलीय उम्मीदवारों के एक बड़े वर्ग का संचालन इंजीनियर रशीद के नाम से चर्चित शेख अब्दुल रशीद कर रहा है, जो देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से वह चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा हो गया। अलगाववादी छवि वाले इंजीनियर रशीद ने जेल में बंद रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को उन्हीं की परंपरागत सीट बारामूला में बड़े अंतर से हराया था। रशीद पर यह आरोप है कि उसने इन चुनावों में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के साथ अंदरखाने गठबंधन किया हुआ है। अपने प्रचार अभियान में अनेक उम्मीदवारों ने खुलकर यह कहा है कि चुनाव जीतने पर वे फिर से अनुच्छेद 370 लागू कराएंगे और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को भी बहाल कराएंगे। ऐसे उम्मीदवारों की सभाओं में जुटने वाली भीड़ का एक असर यह हुआ कि आम तौर पर आतंकियों और अलगाववादियों के मुकाबले मध्यमार्गी और नरमपंथी मानी जाने वाली नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने भी गरम तेवर अपना लिए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चुनावी भाषणों में 370 को फिर से लागू करने और राज्य को अधिक स्वायत्तता एवं विशेष दर्जा दिलाने का वादा कर रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस ने तो अपने चुनावी वादों में यह भी शामिल कर लिया है कि अगर कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन को बहुमत मिला तो विधानसभा में फिर से 2000 वाले उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, जिसमें राज्य का 1951 के स्तर वाला दर्जा बहाल करने की बात कही गई थी। उसमें जम्मू-कश्मीर के लिए भारत से अलग अपने झंडे और संविधान की व्यवस्था थी।

नेशनल कांफ्रेंस से गठबंधन के कारण कांग्रेस के नेता असमंजस में हैं। कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में उसके जैसा रवैया अपनाने का खतरा नहीं मोल लेना चाहती। जम्मू और कश्मीर घाटी के राजनीतिक समीकरण एक-दूसरे से ठीक उलट हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू में जिस बड़े पैमाने पर खुशी और उत्सव का माहौल बना, वह कांग्रेस नेताओं को याद है। इसके बाद केंद्र की नीतियों ने जम्मू और कश्मीर, दोनों जगह जिस तरह विकास के नए द्वार खोले, उसे देखते हुए कांग्रेस किसी भी हालत में 370 की वापसी की बात कहने का जोखिम नहीं उठा सकती।

कश्मीर घाटी में माहौल को और खराब करने वाले दो और तत्व भी हैं, जिनकी अनदेखी महंगी पड़ सकती है। एक तो यह कि लगभग हर मामले में खुद को सक्रिय दिखाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने का निर्देश तो जारी कर दिया, लेकिन कश्मीर घाटी से आतंक और हिंसा के दम पर भगा दिए गए कश्मीरी हिंदुओं और सिखों की सुरक्षित घर वापसी और स्थानीय राजनीति में उनकी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने वाला कोई निर्देश नहीं दिया। लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों के रक्षक सुप्रीम कोर्ट से यह आशा की जाती थी कि वह इस पाप का संज्ञान लेता कि भारत के इकलौते मुस्लिम बहुल राज्य की कश्मीर घाटी में सदियों से रहने वाले लाखों लोगों को केवल इसलिए भगा दिया गया कि वे मुसलमान नहीं थे। इसी तरह 2022 में भले ही राज्य के नए परिसीमन आयोग ने विधानसभा सीटों को 111 से बढ़ाकर 114 कर दिया हो और जम्मू को छह एवं घाटी को एक अतिरिक्त सीट दी हो, लेकिन इसके बाद भी विधानसभा में सत्ता का संतुलन 47-43 होने के कारण कश्मीर के पक्ष में ही रहेगा। दुर्भाग्य से परिसीमन आयोग ने शेख अब्दुल्ला के कश्मीरी दबदबे को बनाए रखने वाले फार्मूले को कायम रखते हुए 114 में केवल 90 पर चुनाव कराने और बाकी 24 सीटों को फिर से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर (पीओजेके) यानी गुलाम कश्मीर के नाम पर खाली रखने का फैसला किया। लोकतंत्र और न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों को आशा थी कि अगर परिसीमन आयोग ने ये 24 सीटें भारत भर में फैले पीओजेके विस्थापितों के नाम पर बहाल कर दी होतीं तो न केवल 77 साल से उपेक्षित और न्याय से वंचित इन लोगों को न्याय मिलता, बल्कि जम्मू-कश्मीर की राजनीति पर कुंडली मारे बैठे कश्मीरी अलगाववाद से भी राज्य और देश, दोनों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती।

(लेखक सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

भारत पर निवेशकों का बढ़ता भरोसा

डा. सुरजीत सिंह

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जापान के बाद अब भारत निवेशकों का दूसरा सबसे पसंदीदा देश बन गया है

आर्थिक प्रगति का सूचक बना शेयर बाजार। फाइल

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत के शेयर बाजार ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। सरकार की दूरगामी आर्थिक नीतियों और सकारात्मकता का ही परिणाम है कि भारत की मध्यम और छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उभरते बाजारों में भारत निवेशकों का पसंदीदा देश बन रहा है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जापान के बाद भारत निवेशकों का दूसरा सबसे पसंदीदा देश बन गया है। एक सितंबर से 13 सितंबर तक कुल 13 दिनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा 53 हजार करोड़ का निवेश भारत में हुआ, जिसमें से 28 हजार करोड़ का निवेश शेयर बाजार में हुआ। भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी ने न सिर्फ विदेशी, बल्कि घरेलू निवेशकों को भी आकर्षित किया है। पिछले चार वर्षों में भारतीय निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शेयर बाजार में मिलने वाले अच्छे रिटर्न ने निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। परंपरागत क्षेत्रों जैसे सोना और प्रापर्टी में निवेश के अलावा लोगों की शेयर बाजार में भी दिलचस्पी बढ़ी है। अकेले उत्तर भारत के निवेशकों की संख्या लगभग चार गुना बढ़ गई है। इंटरनेट और मोबाइल के प्रसार ने लोगों में शेयर बाजार की जानकारी और निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाई है।

आनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म और मोबाइल एप की सुगमता ने शेयर बाजार को बहुत आसान बना दिया है। वित्तीय साक्षरता में होने वाली वृद्धि ने भी लोगों को इसमें निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म मार्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के नवीनतम सूचकांक में भारत ने चीन को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। यह फर्म विभिन्न देशों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, उभरते बाजारों आदि के आधार पर अनेकों प्रकार के सूचकांक जारी करता है। इसमें दो सूचकांक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला, उभरते बाजार का निवेश योग्य बाजार सूचकांक और दूसरा, उभरते बाजार का मानक सूचकांक। उभरते बाजार के निवेश योग्य बाजार सूचकांक में चीन के 21.58 प्रतिशत वेटेज की तुलना में भारत का वेटेज 22.27 प्रतिशत हो गया है। मार्गन स्टैनली द्वारा बड़ी, मध्यम और छोटी कंपनियों के 3,355 शेयरों के आधार पर 24 उभरते बाजारों का निवेश योग्य बाजार सूचकांक तैयार किया जाता है। उभरते बाजार के मानक सूचकांक में भी भारत ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। इस सूचकांक में बड़ी और मध्यम कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक उभरते बाजार के मानक सूचकांक में भी भारत चीन को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि पिछले दिनों चीन के खराब प्रदर्शन करने वाले लगभग 60 स्टाक को इसमें से हटा दिया गया, जबकि भारत के अच्छा प्रदर्शन करने वाले सात स्टाक को इसमें जोड़ा गया। इसके बाद भारत का वेटेज जहां 84 प्रतिशत बढ़ा है, वहीं चीन के वेटेज में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्तमान में चीन का वेटेज 23.7 प्रतिशत है और भारत का प्रतिशत 20.6 प्रतिशत है। 2021 की शुरुआत में भारत का वेटेज 9.2 प्रतिशत था, जो चीन के 38.7 प्रतिशत वेटेज के एक-चौथाई से भी कम था। यह पुनर्संतुलन व्यापक बाजार रुझानों को दर्शाता है।

जहां चीन आर्थिक चुनौतियों और विनियामक कार्रवाइयों से जूझ रहा है, वहीं अनुकूल आर्थिक स्थितियों से भारत को काफी लाभ हुआ है। इस समय चीन का कुल बाजार पूंजीकरण 8.14 लाख करोड़ डालर है, जो भारत के 5.03 लाख करोड़ डालर से 60 प्रतिशत अधिक है। मार्गन स्टैनली के दोनों सूचकांकों में भारत के वेटेज का बढ़ना यह सिद्ध करता है कि वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ रही है। सरकार की अनुकूल नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हो रही है और भारतीय कंपनियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। इन सबके कारण इक्विटी बाजार लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत के मैक्रो अर्थशास्त्र के विभिन्न पक्ष जैसे मौद्रिक और राजकोषीय घाटा आदि पहलुओं पर भी अनुकूल स्थितियां हैं। साल 2024 की शुरुआत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) में 47 प्रतिशत की वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, भारतीय ऋण बाजारों में पर्याप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआइ) आदि ऐसे सकारात्मक रुझान प्रमुख कारक रहे हैं। इस सकारात्मकता के कारण ही घरेलू निवेशकों द्वारा भी तुलनात्मक रूप से अधिक पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जा रहा है।

भारत का वेटेज चीन से ज्यादा होने से एवं अमेरिका में मंदी आने की आहट से विदेशी निवेशकों का आज भारतीय कंपनियों पर भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार मार्गन स्टैनली के सूचकांकों में होने वाले इस बदलाव से भारतीय इक्विटी बाजार में 35 हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ तक की पूंजी आ सकती है, जिससे आर्थिक वृद्धि को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले समय में छोटी और मध्यम कंपनियों के शेयर बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना है। भारतीय बाजारों के बढ़ते महत्व को बनाए रखने के लिए और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और विदेशी, दोनों प्रकार की पूंजी पर विशेष बल देना होगा। 2047 तक भारत को विकसित देशों में शामिल करने के लिए एक अपेक्षित निवेश की गति को बनाए रखना होगा। निवेशकों की निरंतरता एवं वैश्विक बाजार में भारत के भरोसे को बनाए रखने के लिए सकारात्मक दीर्घकालिक प्रवृत्ति के ढांचे को विकसित करना होगा। इसके लिए उदार निवेश नियमों के द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एक अनुकूल आर्थिकी प्रदान करनी होगी।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वाणी

यदा-कदा ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है, लेकिन बोल कुछ और जाता है। यह अहसास होने पर कि जो बोला गया, वह गलत है तब यही कहने की नौबत आती है कि 'जुबान फिसल गई।' भले इससे बिगड़ती स्थिति से बचने में सहायता मिल जाती हो, लेकिन माना यही जाता है कि जुबान फिसली नहीं, बल्कि मन में जो भाव थे, वही जुबान पर आ गए। एक कहावत है, 'बातन हाथी पाइयां, बातन हाथी पांव।' यानी 'अनुकूल शब्द बोलने पर उपहार मिलता है और प्रतिकूल बात कहने पर दंड।' एक अन्य कहावत है, 'जीभ पर लगी चोट ठीक हो जाती है, जबकि जीभ से लगी चोट जल्दी ठीक नहीं होती।' यानी कुछ खाते-पीते या किसी अन्य कारणों से जीभ कट जाए या चोट लग जाए तो उसका उपचार संभव है, किंतु उसी जीभ से निकली बात से किसी को चोट पहुंचती है तो उसकी टीस गहरी होती है। कई उदाहरण हैं कि जब लोगों को भगवान से इच्छित वरदान मांगने की बारी आई तो उनके मुंह से कुछ और निकल गया। जैसे कुंभकर्ण 'इंद्रासन' की जगह 'निद्रासन' बोल गया। जब जुबान फिसली तो वरदान में उसे निद्रासन ही मिला।

बात करने के लिए मुंह और जिह्वा का प्रयोग किया जाता है। मुंह के आकार पर ध्यान दिया जाए तो ऊपर-नीचे के होंठ बिल्कुल 'धनुष' का आकार लिए होते हैं। इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने पर जिह्वा से बाण के रूप में बात निकलती है। मृदुल, सौम्य एवं स्नेहपूर्ण शब्द जब जिह्वा से निकलते हैं तो पुष्पबाण जैसे मोहक लगते हैं। पुष्पबाण होने की वजह से उन शब्दों से खुशबू निकलती है, जबकि प्रतिकूल, घातक एवं आक्रामक शब्द युद्ध के मैदान में प्रतिद्वंद्वी को मारने वाले बाण की तरह हो जाते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि शब्दों के प्रयोग में सतर्कता बरतने का पूर्ण अभ्यास किया जाना चाहिए, ताकि जिह्वा से निकली वाणी घातक बाण न बन जाए।

सलिल पांडेय

नई पीढ़ी भी समझे श्राद्ध का महत्व

रंजना मिश्रा

श्राद्ध केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है

श्राद्ध का अर्थ है पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना। यह एक ऐसा अनुष्ठान है, जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। श्राद्ध हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें अपने पूर्वजों के साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस कराता है। श्राद्ध परिवार और समाज को एक साथ लाता है। श्राद्ध करने से आत्मिक शांति मिलती है, लेकिन नई पीढ़ी श्राद्ध से दूर होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी अधिकतर आधुनिक जीवनशैली, तकनीक से प्रभावित है। इसके अलावा समाज में धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर कई तरह के मिथक और अंधविश्वास फैले हुए हैं। स्कूलों और कालेजों में धार्मिक शिक्षा का अभाव है। इसके कारण युवाओं को धर्म और संस्कारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती। लिहाजा आज के अधिकांश युवा भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं।

श्राद्ध के अनुष्ठानों को सरल बनाकर युवाओं को आकर्षित किया जा सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर श्राद्ध करने से यह एक सामाजिक आयोजन बन सकता है। श्राद्ध को केवल एक अनुष्ठान के रूप में न देखकर इसे अपने पूर्वजों के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर किसी सामाजिक कार्य में योगदान देकर हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। पौधे लगाना, कचरा प्रबंधन जैसे पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को श्राद्ध के साथ जोड़कर इसे और अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। इस दौरान ध्यान का अभ्यास करके आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। अपने पूर्वजों के जीवन कार्यों पर मनन करके हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। श्राद्ध के अवसर पर वृद्धाश्रम में जाकर या जरूरतमंदों को भोजन वितरित करें तो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिल सकती है। श्राद्ध के दौरान परिवार के बुजुर्गों को अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे युवाओं को अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। श्राद्ध के दौरान युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। इंटरनेट मीडिया का उपयोग करके श्राद्ध के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है।

श्राद्ध हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें युवाओं को श्राद्ध के महत्व के बारे में जागरूक करना होगा और उन्हें इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए प्रेरित करना होगा। श्राद्ध को एक बोझ के रूप में न देखकर, इसे एक अवसर के रूप में देखा जाए। यह एक अवसर है अपने पूर्वजों के आशीर्वाद लेने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का और अपने जीवन पर चिंतन करने का।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

पराली का हो सदुपयोग

'जलने लगी पराली' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। इसमें पराली जलाने की घटनाओं पर चिंता जताई गई है। वास्तव में हम जिस पराली को परेशानी समझ रहे हैं वह ऊर्जा का बेशकीमती स्रोत है। धान, मक्का, गेहूं जैसी फसलों के अवशेष का इस्तेमाल फाइबर बोर्ड और कागज बनाने में किया जा सकता है। कागज बनाने के लिए जरूरी फाइबर का लगभग चालीस प्रतिशत हिस्सा इन फसलों के अवशेष से मिल सकता है। वैसे पराली जलाए जाने से होने वाली परेशानी इसी वर्ष ही सामने नहीं आई, बल्कि पिछले कई वर्षों से सामने आ रही, लेकिन सरकारें तभी कुंभकर्णी नींद से जागती हैं जब कुछ राज्यों में पराली जलाने से जहरीली धुंध छा जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। सरकारों को चाहिए कि वे अभी से ही पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली न जलाने और पराली के सदुपयोग के लिए जागरूक करें। इसके लिए कोई विशेष योजना भी सरकारों को बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के प्राथमिकता के आधार पर बनानी चाहिए, ताकि किसान पराली न जलाएं और न ही वातावरण में जहरीली धुंध फैले। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जो वायु प्रदूषण बढ़ा है, उसका एक कारण पराली जलाना भी बताया जाता है। अमेरिका के सबसे बड़े धान उत्पादक राज्य कैलिफोर्निया में 1990 में पराली जलाने से निकले धुएं ने जब लोगों की सेहत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब वहां के प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। इसके बावजूद वहां के किसानों ने पराली जलाना बंद नहीं किया तब उसने यह निर्णय लिया कि पराली का इस्तेमाल बिजली संयंत्रों में बायोमास के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा वहां पराली का उपयोग मिट्टी का क्षरण रोकने के लिए भी किया जाने लगा। सड़कों के किनारे भी पराली लगाई जाती है, ताकि मिट्टी सूखकर हवा के साथ न उड़े।

raju09023693142@gmail.com

दक्षिण एशिया और भारत

भारत दक्षिण एशिया का भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली देश है, लेकिन भारत ने कभी भी अपनी शक्ति एवं प्रभाव का प्रयोग करते हुए दक्षिण एशिया के छोटे देश श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान आदि पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं की है। भारत हमेशा से एक सच्चा और मददगार पड़ोसी रहा है, उसने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के मदद की है। एक समय था, जब दक्षिण एशिया के यह देश भारत को सिर्फ अपना एक बड़ा भाई ही नहीं मानते थे, बल्कि उनके लिए भारत सबसे बड़ा और सबसे पहला मददगार साथी था। इसलिए उनकी विदेश नीति में भारत का स्थान सबसे पहला होता था, लेकिन इन दो दशकों से श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीप आदि पड़ोसी देश में आंतरिक और बाहरी स्तर पर कई परिवर्तन देखने को मिले हैं। इन देशों में ऐसी सरकारी आई हैं, जिनका रवैया भारत के प्रति सद्भावपूर्वक नहीं रहा है। इन देशों में चीन का प्रभाव बढ़ा है। चीन सिर्फ दक्षिण एशिया में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने इन छोटे-छोटे देशों में अपना प्रभाव जमाते हुए उनकी सरकारों का झुकाव अपनी ओर किया है। एक तरह से चीन दक्षिण एशिया के छोटा देशों आर्थिक, सैनिक, तकनीकी मदद देकर वहां अपना दबदबा बनाते हुए एक तरह से भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा हैं। चीन भारत को दक्षिण दक्षिण एशिया में चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन पड़ोसी देशों को भी यह समझना चाहिए कि भारत उनका परंपरावादी मित्र है, चीन सिर्फ अपने वर्चस्व और महत्वाकांक्षा के लिए दोस्ती करता है। चीन के आर्थिक चुंगल में आकर दक्षिण एशिया के कई देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। इनमें पाकिस्तान और श्रीलंका का नाम आगे है, इसलिए दक्षिण एशिया के छोटे देश को भारत के महत्व को पहचाना होगा।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

संपादकीय जागरण

(12) गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 : आश्विन कृष्ण – 9 वि. 2081

मौन ही क्रोध को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है

मेक इन इंडिया अभियान

मेक इन इंडिया अभियान के दस वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उसकी सफलता का जो उल्लेख किया, उससे असहमत तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन यह आभास किया जाए तो बेहतर कि इस पहल को और अधिक सफल बनाया जा सकता था। इस अभियान ने कई उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं, जैसे दस वर्ष पहले देश में मोबाइल फोन बनाने वाली केवल दो कंपनियां थीं। आज उनकी संख्या बढ़कर दो सौ के करीब हो गई है। इसके चलते भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। पहले केवल 1,556 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन निर्यात होते थे। अब 1.2 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल निर्यात हो रहे हैं और देश में प्रयोग होने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल मेक इन इंडिया हैं। इसी तरह फिनिश्ड स्टील के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। खिलौनों के निर्माण में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और अब उनका आयात घटकर आधा रह गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जिस तरह डेढ़ लाख करोड़ का निवेश हुआ है, उससे पांच प्लांट लगने जा रहे हैं, जो प्रतिदिन सात करोड़ चिप बनाएंगे। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में अब दुनिया में चौथे नंबर पर है और देश का ईवी उद्योग अब तीन अरब डालर तक पहुंच गया है। रक्षा क्षेत्र भी मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी कहता है। देश का रक्षा निर्यात 21 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है और अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। आज भारत कई देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। यह कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया अभियान ने रक्षा क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया है। ऐसी ही तस्वीर अन्य क्षेत्रों में भी बदलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह एक तथ्य है कि तमाम प्रयासों के बाद भी चीन से होने वाला आयात कम नहीं हो रहा है। तमाम ऐसी वस्तुएं चीन से मंगाई जा रही हैं जिनका निर्माण भारत में किया जा सकता है। एक समस्या यह भी है कि चीन से तमाम कल-पुर्जे मंगाकर उन्हें देश में असेंबल कर कई तरह के उपकरण बनाए जा रहे हैं। समझना कठिन है कि भारतीय उद्योगपति वह सब देश में क्यों नहीं बना सकते, जिसके निर्माण की संभावनाएं देश में हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं, जो पहले भारत में बनती भी थीं। एक ओर जहां देश के उद्योगपतियों को कमर कसनी होगी, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी यह देखना होगा कि हमारे उद्योगपति चीनी कारोबारियों का मुकाबला करने में क्यों हिचक रहे हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं? कुल मिलाकर मेक इन इंडिया अभियान कुछ हद तो सफल है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना है।

असमंजस करें दूर

भूमि अभिलेख सुधार के लिए विशेष सर्वे कराने की सरकार की नीति रैयतों के लिए वह महत्वाकांक्षी योजना है, जो भविष्य में भूमि विवाद के प्रकरण कम करेगी और हर भूमि से जुड़े अभिलेख रैयत से लेकर सरकार तक, सभी के पास होंगे। सरकार की इस जनोपयोगी योजना से अगर किसी को हानि होनी है तो निश्चित रूप से वह भू माफिया और दबंग प्रवृत्ति के ऐसे लोग हैं, जिन्होंने दूसरे की भूमि को दबा रखा है। उसपर अनधिकृत स्वामित्व बनाया हुआ है। वर्षों बाद शुरू हुए इस विशेष सर्वे ने लोगों की आशा जीवित की है कि अब भूमि की जमाबंदी उनके नाम बिना किसी अड़चन के हो जाएगी। देश, दुनिया में कहीं भी रह रहे हों, वह अपने गांव आकर भूमि संबंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रति निकलवा सकेंगे। अभी अभिलेख सुरक्षित करने के लिए प्रखंड कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वंशावली की भी घोषणा स्वतः करनी होगी, फिर भी निबंधन और अंचल कार्यालय से लेकर अभिलेखागार तक, भीड़ कम नहीं हो रही है। इसका सीधा कारण है, लोगों में आशंका कि उनकी भूमि के दस्तावेज सुरक्षित हैं या नहीं। इस आशंका के पीछे भी तर्क है, क्योंकि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण भूमि निबंधन से संबंधित कई अभिलेख विभिन्न निबंधन कार्यालयों से गायब हैं। भू माफिया भी सर्वे को लेकर विभिन्न प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं, जो रैयतों के मन में आशंका उत्पन्न करने में सफल हो रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों का दायित्व है कि वह रैयतों की आशंका और असमंजस दूर करें। सरकार ने टाल फ्री नंबर जरूर जारी किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी अधिकारियों को लोगों की शंका-आशंका दूर करने के लिए उनतक पहुंचकर जागरूक करना चाहिए।

स्थानीय स्तर पर भी अधिकारियों को लोगों की शंका-आशंका दूर करने के लिए उनतक पहुंचकर जागरूक करना चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

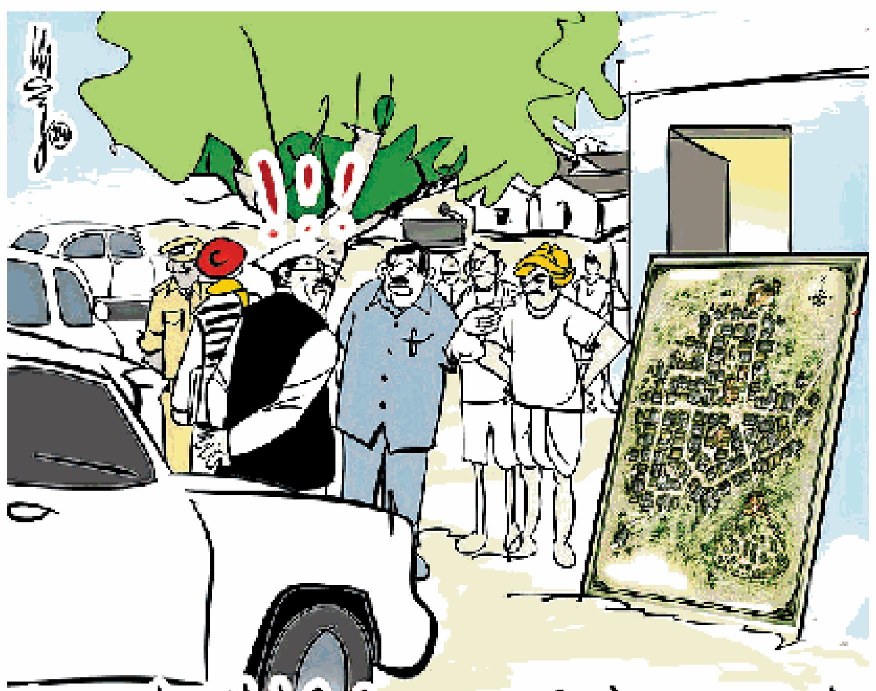

'विकास होता कैसे? पांच साल पहले जो मॉडल आपने लोकार्पित किया, उसका मानचित्र ही उलटा था!'

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को त्यागपत्र देना चाहिए?

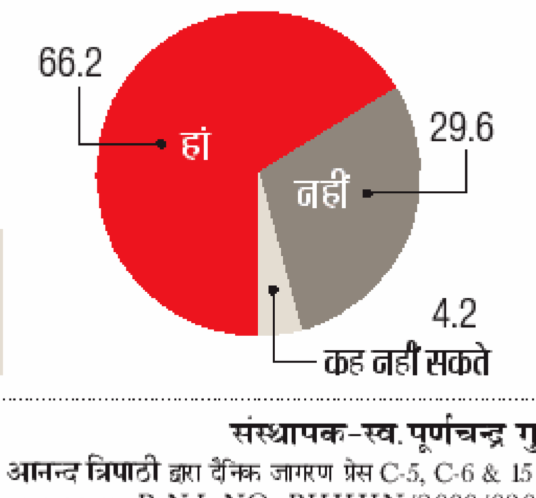

आज का सवाल

क्या मेक इन इंडिया योजना अपने लक्ष्य पूरे करते दिख रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

खतरा बन सकते हैं कश्मीरी अलगाववादी

विजय क्रांति

महंगी पड़ सकती है विधानसभा चुनावों में कश्मीर में उभरे अलगाववादी एजेंडे की अनदेखी

पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और विशेष दर्जे को समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद करने के साथ यह निर्देश भी दिया था कि एक तय समय में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे चुनावों से देश का एक वर्ग आश्वस्त दिख रहा है कि विधानसभा चुनावों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों को यह भी उम्मीद है कि नई विधानसभा के चुने जाने के बाद आजादी के पहले दिन से ही मुसीबतों से घिरे हुए जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल हो जाएगी। कश्मीर विवाद के कारण यहां की जनता ने जैसी कठिनाइयां देखी हैं और भारत विरोधी शक्तियों के नैरेटिव निर्माण की ताकत के आगे बार-बार पस्त होने वाली केंद्रीय सरकारों ने वैश्विक मंचों पर जिस स्तर का विरोध सहा है, उसके बाद इस तरह की आशाओं का जगना स्वाभाविक भी है। इन विधानसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर की जनता ने जैसे उत्साह के साथ स्थानीय निकायों के चुनावों में भाग लिया और जैसे शांति भरे माहौल में वे चुनाव संपन्न हुए, उससे भी कश्मीर में सब कुछ ठीक होने की आस जगी थी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा के दिन से ही कश्मीर घाटी में जिस तरह के उम्मीदवार और जैसे चुनावी वादे पूरे माहौल पर हावी हैं, उसे देखते हुए यह आशंका बल पकड़ने लगी है कि विधानसभा में भले ही कोई भी पार्टी या गुट बहुमत हासिल करे, लेकिन घाटी की राजनीति फिर से अलगाववाद और केंद्र से टकराव की आग में तप सकती है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में कई प्रत्याशी ऐसे हैं, जो या तो अलगाववादी रहे हैं या ऐसे संगठनों के सक्रिय सदस्य। इनमें अनेक निर्दलीय हैं। इन निर्दलीय उम्मीदवारों के एक बड़े वर्ग का संचालन इंजीनियर रशीद के नाम से चर्चित शेख अब्दुल रशीद कर रहा है, जो देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से वह चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा हो गया। अलगाववादी छवि वाले इंजीनियर रशीद ने जेल में बंद रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को उन्हीं की परंपरागत सीट बारामूला में बड़े अंतर से हराया था। रशीद पर यह आरोप है कि उसने इन चुनावों में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के साथ अंदरखाने गठबंधन किया हुआ है। अपने प्रचार अभियान में अनेक उम्मीदवारों ने खुलकर यह कहा है कि चुनाव जीतने पर वे फिर से अनुच्छेद 370 लागू कराएंगे और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को भी बहाल कराएंगे। ऐसे उम्मीदवारों की सभाओं में जुटने वाली भीड़ का एक असर यह हुआ कि आम तौर पर आतंकियों और अलगाववादियों के मुकाबले मध्यमार्गी और नरमपंथी मानी जाने वाली नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने भी गरम तेवर अपना लिए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चुनावी भाषणों में 370 को फिर से लागू करने और राज्य को अधिक स्वायत्तता एवं विशेष दर्जा दिलाने का वादा कर रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस ने तो अपने चुनावी वादों में यह भी शामिल कर लिया है कि अगर कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन को बहुमत मिला तो विधानसभा में फिर से 2000 वाले उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, जिसमें राज्य का 1951 के स्तर वाला दर्जा बहाल करने की बात कही गई थी। उसमें जम्मू-कश्मीर के लिए भारत से अलग अपने झंडे और संविधान की व्यवस्था थी।

अवधेश राजपूत

नेशनल कांफ्रेंस से गठबंधन के कारण कांग्रेस के नेता असमंजस में हैं। कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में उसके जैसा रवैया अपनाने का खतरा नहीं मोल लेना चाहती। जम्मू और कश्मीर घाटी के राजनीतिक समीकरण एक-दूसरे से ठीक उलट हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू में जिस बड़े पैमाने पर खुशी और उत्सव का माहौल बना, वह कांग्रेस नेताओं को याद है। इसके बाद केंद्र की नीतियों ने जम्मू और कश्मीर, दोनों जगह जिस तरह विकास के नए द्वार खोले, उसे देखते हुए कांग्रेस किसी भी हालत में 370 की वापसी की बात कहने का जोखिम नहीं उठा सकती।

कश्मीर घाटी में माहौल को और खराब करने वाले दो और तत्व भी हैं, जिनकी अनदेखी महंगी पड़ सकती है। एक तो यह कि लगभग हर मामले में खुद को सक्रिय दिखाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने का निर्देश तो जारी कर दिया, लेकिन कश्मीर घाटी से आतंक और हिंसा के दम पर भगा दिए गए कश्मीरी हिंदुओं और सिखों की सुरक्षित घर वापसी और स्थानीय राजनीति में उनकी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने वाला कोई निर्देश नहीं दिया। लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों के रक्षक सुप्रीम कोर्ट से यह आशा की जाती थी कि वह इस पाप का संज्ञान लेता कि भारत के इकलौते मुस्लिम बहुल राज्य की कश्मीर घाटी में सदियों से रहने वाले लाखों लोगों को केवल इसलिए भगा दिया गया कि वे मुसलमान नहीं थे। इसी तरह 2022 में भले ही राज्य के नए परिसीमन आयोग ने विधानसभा सीटों को 111 से बढ़ाकर 114 कर दिया हो और जम्मू को छह एवं घाटी को एक अतिरिक्त सीट दी हो, लेकिन इसके बाद भी विधानसभा में सत्ता का संतुलन 47-43 होने के कारण कश्मीर के पक्ष में ही रहेगा। दुर्भाग्य से परिसीमन आयोग ने शेख अब्दुल्ला के कश्मीरी दबदबे को बनाए रखने वाले फार्मूले को कायम रखते हुए 114 में केवल 90 पर चुनाव कराने और बाकी 24 सीटों को फिर से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर (पीओजेके) यानी गुलाम कश्मीर के नाम पर खाली रखने का फैसला किया। लोकतंत्र और न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों को आशा थी कि अगर परिसीमन आयोग ने ये 24 सीटें भारत भर में फैले पीओजेके विस्थापितों के नाम पर बहाल कर दी होतीं तो न केवल 77 साल से उपेक्षित और न्याय से वंचित इन लोगों को न्याय मिलता, बल्कि जम्मू-कश्मीर की राजनीति पर कुंडली मारे बैठे कश्मीरी अलगाववाद से भी राज्य और देश, दोनों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती।

(लेखक सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

भारत पर निवेशकों का बढ़ता भरोसा

डा. सुरजीत सिंह

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जापान के बाद अब भारत निवेशकों का दूसरा सबसे पसंदीदा देश बन गया है

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत के शेयर बाजार ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। सरकार की दूरगामी आर्थिक नीतियों और सकारात्मकता का ही परिणाम है कि भारत की मध्यम और छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उभरते बाजारों में भारत निवेशकों का पसंदीदा देश बन रहा है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जापान के बाद भारत निवेशकों का दूसरा सबसे पसंदीदा देश बन गया है। एक सितंबर से 13 सितंबर तक कुल 13 दिनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा 53 हजार करोड़ का निवेश भारत में हुआ, जिसमें से 28 हजार करोड़ का निवेश शेयर बाजार में हुआ। भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी ने न सिर्फ विदेशी, बल्कि घरेलू निवेशकों को भी आकर्षित किया है। पिछले चार वर्षों में भारतीय निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शेयर बाजार में मिलने वाले अच्छे रिटर्न ने निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। परंपरागत क्षेत्रों जैसे सोना और प्रापर्टी में निवेश के अलावा लोगों की शेयर बाजार में भी दिलचस्पी बढ़ी है। अकेले उत्तर भारत के निवेशकों की संख्या लगभग चार गुना बढ़ गई है। इंटरनेट और मोबाइल के प्रसार ने लोगों में शेयर बाजार की जानकारी और निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाई है।

आनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म और मोबाइल एप की सुगमता ने शेयर बाजार को बहुत आसान बना दिया है। वित्तीय साक्षरता में होने वाली वृद्धि ने भी लोगों को इसमें निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म मार्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के नवीनतम सूचकांक में भारत ने चीन को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। यह फर्म विभिन्न देशों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, उभरते बाजारों आदि के आधार पर अनेकों प्रकार के सूचकांक जारी करता है। इसमें दो सूचकांक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला, उभरते बाजार का निवेश योग्य बाजार सूचकांक और दूसरा, उभरते बाजार का मानक सूचकांक। उभरते बाजार के निवेश योग्य बाजार सूचकांक में चीन के 21.58 प्रतिशत वेटेज की तुलना में भारत का वेटेज 22.27 प्रतिशत हो गया है। मार्गन स्टैनली द्वारा बड़ी, मध्यम और छोटी कंपनियों के 3,355 शेयरों के आधार पर 24 उभरते बाजारों का निवेश योग्य बाजार सूचकांक तैयार किया जाता है। उभरते बाजार के मानक सूचकांक में भी भारत ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। इस सूचकांक में बड़ी और मध्यम कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक उभरते बाजार के मानक सूचकांक में भी भारत चीन को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि पिछले दिनों चीन के खराब प्रदर्शन करने वाले लगभग 60 स्टाक को इसमें से हटा दिया गया, जबकि भारत के अच्छा प्रदर्शन करने वाले सात स्टाक को इसमें जोड़ा गया। इसके बाद भारत का वेटेज जहां 84 प्रतिशत बढ़ा है, वहीं चीन के वेटेज में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्तमान में चीन का वेटेज 23.7 प्रतिशत है और भारत का प्रतिशत 20.6 प्रतिशत है। 2021 की शुरुआत में भारत का वेटेज 9.2 प्रतिशत था, जो चीन के 38.7 प्रतिशत वेटेज के एक-चौथाई से भी कम था। यह पुनर्संतुलन व्यापक बाजार रुझानों को दर्शाता है।

आर्थिक प्रगति का सूचक बना शेयर बाजार • फाइल

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जहां चीन आर्थिक चुनौतियों और विनियामक कार्रवाइयों से जूझ रहा है, वहीं अनुकूल आर्थिक स्थितियों से भारत को काफी लाभ हुआ है। इस समय चीन का कुल बाजार पूंजीकरण 8.14 लाख करोड़ डालर है, जो भारत के 5.03 लाख करोड़ डालर से 60 प्रतिशत अधिक है। मार्गन स्टैनली के दोनों सूचकांकों में भारत के वेटेज का बढ़ना यह सिद्ध करता है कि वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ रही है। सरकार की अनुकूल नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हो रही है और भारतीय कंपनियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। इन सबके कारण इक्विटी बाजार लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। देश न सिर्फ निरंतर आर्थिक प्रगति कर रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक समुदाय को भी लुभा रहा है। भारत के मैक्रो अर्थशास्त्र के विभिन्न पक्ष जैसे मौद्रिक और राजकोषीय घाटा आदि पहलुओं पर भी अनुकूल स्थितियां हैं। साल 2024 की शुरुआत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) में 47 प्रतिशत की वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, भारतीय ऋण बाजारों में पर्याप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआइ) आदि ऐसे सकारात्मक रुझान प्रमुख कारक रहे हैं। इस सकारात्मकता के कारण ही घरेलू निवेशकों द्वारा भी तुलनात्मक रूप से अधिक पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जा रहा है।

भारत का वेटेज चीन से ज्यादा होने से एवं अमेरिका में मंदी आने की आहट से विदेशी निवेशकों का आज भारतीय कंपनियों पर भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार मार्गन स्टैनली के सूचकांकों में होने वाले इस बदलाव से भारतीय इक्विटी बाजार में 35 हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ तक की पूंजी आ सकती है, जिससे आर्थिक वृद्धि को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले समय में छोटी और मध्यम कंपनियों के शेयर बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना है। भारतीय बाजारों के बढ़ते महत्व को बनाए रखने के लिए और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और विदेशी, दोनों प्रकार की पूंजी पर विशेष बल देना होगा। 2047 तक भारत को विकसित देशों में शामिल करने के लिए एक अपेक्षित निवेश की गति को बनाए रखना होगा। निवेशकों की निरंतरता एवं वैश्विक बाजार में भारत के भरोसे को बनाए रखने के लिए सकारात्मक दीर्घकालिक प्रवृत्ति के ढांचे को विकसित करना होगा। इसके लिए उदार निवेश नियमों के द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एक अनुकूल आर्थिकी प्रदान करनी होगी।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वाणी का महत्व

यदा-कदा ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है, लेकिन बोल कुछ और जाता है। यह अहसास होने पर कि जो बोला गया, वह गलत है तब यही कहने की नौबत आती है कि 'जुबान फिसल गई।' भले इससे बिगड़ती स्थिति से बचने में सहायता मिल जाती हो, लेकिन माना यही जाता है कि जुबान फिसली नहीं, बल्कि मन में जो भाव थे, वही जुबान पर आ गए। एक कहावत है, 'बातन हाथी पाइयां, बातन हाथी पांव।' यानी 'अनुकूल शब्द बोलने पर उपहार मिलता है और प्रतिकूल बात कहने पर दंड।' एक अन्य कहावत है, 'जीभ पर लगी चोट ठीक हो जाती है, जबकि जीभ से लगी चोट जल्दी ठीक नहीं होती।' यानी कुछ खाते-पीते या किसी अन्य कारणों से जीभ कट जाए या चोट लग जाए तो उसका उपचार संभव है, किंतु उसी जीभ से निकली बात से किसी को चोट पहुंचती है तो उसकी टीस गहरी होती है।

कई उदाहरण हैं कि जब लोगों को भगवान से इच्छित वरदान मांगने की बारी आई तो उनके मुंह से कुछ और निकल गया। जैसे कुंभकर्ण 'इंद्रासन' की जगह 'निद्रासन' बोल गया। जब जुबान फिसली तो वरदान में उसे निद्रासन ही मिला।

बात करने के लिए मुंह और जिह्वा का प्रयोग किया जाता है। मुंह के आकार पर ध्यान दिया जाए तो ऊपर-नीचे के होंठ बिल्कुल 'धनुष' का आकार लिए होते हैं। इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने पर जिह्वा से बाण के रूप में बात निकलती है। मृदुल, सौम्य एवं स्नेहपूर्ण शब्द जब जिह्वा से निकलते हैं तो पुष्पबाण जैसे मोहक लगते हैं। पुष्पबाण होने की वजह से उन शब्दों से खुशबू निकलती है, जबकि प्रतिकूल, घातक एवं आक्रामक शब्द युद्ध के मैदान में प्रतिद्वंद्वी को मारने वाले बाण की तरह हो जाते हैं। इस तरह के बाण चलने पर खून की नदी बहने लगती है। इसीलिए आवश्यक है कि शब्दों के प्रयोग में सतर्कता बरतने का पूर्ण अभ्यास किया जाना चाहिए, ताकि जिह्वा से निकली वाणी घातक बाण न बन जाए।

सलिल पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

पराली का हो सदुपयोग

'जलने लगी पराली' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। वास्तव में हम जिस पराली को परेशानी समझ रहे हैं वह ऊर्जा का बेशकीमती स्रोत है। धान, मक्का, गेहूं जैसी फसलों के अवशेष का इस्तेमाल फाइबर बोर्ड और कागज बनाने में किया जा सकता है। कागज बनाने के लिए जरूरी फाइबर का लगभग चालीस प्रतिशत हिस्सा इन फसलों के अवशेष से मिल सकता है। वैसे पराली जलाए जाने से होने वाली परेशानी इसी वर्ष ही सामने नहीं आई, बल्कि पिछले कई वर्षों से सामने आ रही, लेकिन सरकारें तभी कुंभकर्णी नींद से जागती हैं जब कुछ राज्यों में पराली जलाने से जहरीली धुंध छा जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। सरकारों को चाहिए कि वे अभी से ही पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली न जलाने और पराली के सदुपयोग के लिए जागरूक करें। इसके लिए कोई विशेष योजना भी सरकारों को बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के प्राथमिकता के आधार पर बनानी चाहिए, ताकि किसान पराली न जलाएं और न ही वातावरण में जहरीली धुंध फैले। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जो वायु प्रदूषण बढ़ा है, उसका एक कारण पराली जलाना भी बताया जाता है। अमेरिका के सबसे बड़े धान उत्पादक राज्य कैलिफोर्निया में 1990 में पराली जलाने से निकले धुएं ने जब लोगों की सेहत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब वहां के प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। इसके बावजूद वहां के किसानों ने पराली जलाना बंद नहीं किया तब उसने यह निर्णय लिया कि पराली का इस्तेमाल बिजली संयंत्रों में बायोमास के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा वहां पराली का उपयोग मिट्टी का क्षरण रोकने के लिए भी किया जाने लगा। सड़कों के किनारे भी पराली लगाई जाती है, ताकि मिट्टी सूखकर हवा के साथ न उड़े।

raju09023693142@gmail.com

अक्षुण्ण हो मंदिर की पवित्रता

विकास सारस्वत का आलेख 'सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो मंदिर' पढ़ा। इसका ताजा कुप्रभाव तिरुपति मंदिर के प्रसाद प्रकरण में सामने आया। विगत दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में अशुद्ध घी का इस्तेमाल हुआ, जिसमें पशु वसा पाई गई। यह घटना जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान हुई थी, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहरी चोट पहुंची। घी की शुद्धता एस-वैल्यू पर आधारित होती है, जिसका मानक 95.68 से 104.32 के बीच होना चाहिए। हालांकि, एआर डेयरी के नमूने में केवल 19.72 एस-वैल्यू पाई गई, जो गंभीर अनियमितता का संकेत है। इस मंदिर का प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अधीन है, जो पूरी तरह से आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में आता है। इस बोर्ड के पास लगभग 50,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें नकदी, सोना, जमीन और अन्य निवेश शामिल हैं। मंदिर में प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ श्रद्धालु आते हैं, फिर भी मंदिर में अब तक छोटी सी प्रयोगशाला तक नहीं है, जो घी जैसी सामग्री की शुद्धता की जांच कर सके। तिरुपति मंदिर की घटना यह बताती है कि धार्मिक संस्थानों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का समय आ गया है।

डा. पवन कुमार, जनकपुर, गया

तकनीक में मानवीय हस्तक्षेप आवश्यक

तकनीक के तेजी से बढ़ते हस्तक्षेप ने जीवन के हर पहलू को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसका असर केवल सुविधा तक सीमित नहीं रहा, जैसे-जैसे हम तकनीक पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, मानवीय संपर्क, सहानुभूति और संवेदनाएं पीछे छूटती जा रही हैं। यह बदलाव एक बड़े सवाल को जन्म देता है, क्या तकनीक हमारे जीवन को सरल बना रही है, या हमें और अधिक उलझा रही है? चाहे आनलाइन खरीदारी हो या सेवाओं की मांग, स्वचालित सिस्टम हर जगह हावी है। ग्राहक सेवा में चैटबाट्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) ने काल सेंटर में काम करने वाले इंसानों की जगह ले ली है। यह प्रक्रिया, हालांकि तेज है, लेकिन यह एक गहरे मानसिक खालीपन को भी जन्म देती है। एक मशीन से संवाद करते समय, एक उपभोक्ता अपनी असली समस्या को व्यक्त करने में असमर्थ महसूस करता है। यहां तक कि स्थानीय स्तर पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। छोटे व्यवसायियों और ग्राहकों के बीच सीधा संवाद अब घटता जा रहा है। एक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आदेश दिए गए उत्पाद की गलती को सुधारने के लिए आपको घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जब तक कि सिस्टम आपको सही प्रतिक्रिया नहीं देता। यह प्रतीक्षा न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान भी करती है। इस समस्या का समाधान केवल तकनीकी सुधार में नहीं, बल्कि एक नए दृष्टिकोण में छिपा है।

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

पोस्ट

बांग्लादेश में 32 इस्लामिक आतंकी रिहा कर दिए गए। लगता है यूनुस सरकार आतंकियों से कुछ ज्यादा दुलार करती है। तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

पहले जो लोग बदलापुर के दुष्कर्मियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे, वे ही उसके एनकाउंटर पर टेसुएं बहा रहे हैं। संजय निरुपम@sanjaynirupam

कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारी मतदान उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है।
आचार्य प्रमोद@AcharyaPramodk

भारत को दुनिया का एक बड़ा कारखाना बनाने के लिए शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान के दस साल पूरे हो गए। सरकार के अनुसार इस अभियान ने कई बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। हालांकि ग्लोबल फैक्ट्री बनने के लिए भारत को एक लंबा रास्ता तय करना है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

भारत के साथ समस्या यह है कि यहां लोग अपनी क्षमता-उत्पादकता के अनुपात में कम पारिश्रमिक वाली सरकारी नौकरी में ही ज्यादा खुश हैं। जबकि निजी क्षेत्र में उन्हें अपनी क्षमताओं के लिए कहीं ज्यादा वेतन मिल सकता है।
दिवा जैन@DivaJain2

जनपथ

दिशानायके की दिशा दिखे चीन अनुकूल,
मित्र समझना आपको कहीं न निकले भूल।
कहीं न निकले भूल राखिये रिश्ता ठंडा,
लूटे आकर चीन तभी सुधरेगा बंदा।
चेते हैं कुछ लोग चीन का 'डोज' खाय के,
सुधर जायंगे जल्द एक दिन दिशानायके!
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 165

****

आईटीयूसी की रिपोर्ट में दिग्गज कंपनियों के बारे में यह दावा बेहद संगीन है कि ये सरकारी नीतियों को प्रभावित कर रही हैं। इन कंपनियों की सेवाएं आज जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन अगर इनकी शक्तियों पर नियंत्रण की बात उठी है, तो इस पर गंभीरता से विचार होना ही चाहिए।

संगीन आरोप

अंतरराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन (आईटीयूसी) की हालिया रिपोर्ट में किया गया दावा कि अमेजन, टेस्ला और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां सरकारों को प्रभावित कर नीतियों में अपने अनुकूल बदलाव ला रही हैं, बेहद संगीन है। रिपोर्ट में एक तरफ फेसबुक और इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा पर आरोप लगाए गए हैं कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत खबरों को बढ़ावा दिया गया, तो वहीं टेस्ला और अमेजन पर अपने आंतरिक संगठन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। हालांकि यह सच है कि इन दिग्गज कंपनियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में क्रांति लाई है। अमेजन ने वैश्विक व्यापार को नया रूप दिया है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाकर ऑटोमोबाइल उद्योग को बदल कर रख दिया है। वहीं, मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने दुनिया भर के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे सूचनाओं के आदान-प्रदान और संचार के नए तरीके सामने आए हैं। इन कंपनियों की भूमिका को इसलिए भी नहीं नकार सकते, क्योंकि ये नवाचार और प्रगति की प्रतीक हैं। ये खुद मुनाफा जरूर कमा रही हैं, लेकिन लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। इनकी कामयाबी से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती भी मिली है। जाहिर है कि अमेजन, टेस्ला और मेटा जैसी कंपनियां अब महज व्यावसायिक संस्थान नहीं, बल्कि समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली शक्तियां बन गई हैं। लेकिन, इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या इन कंपनियों की बढ़ती ताकत और प्रभाव का सही ढंग से उपयोग हो रहा है और कहीं ये अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहीं? दरअसल इन सबसे शक्तिशाली कंपनियों के पास आर्थिक संसाधन तो हैं, लेकिन आईटीयूसी की रिपोर्ट का यह कहना बेहद गंभीर है कि ये कंपनियां अपने व्यापारिक हितों को

साधने के लिए लॉबिंग, राजनीतिक फंडिंग और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। जाहिर है कि इन कंपनियों में शक्ति का केंद्रीकरण लोकतंत्र के बुनियादी विचार के विपरीत है। मेटा जैसी कंपनियों के मामले में तो यह और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि उनके पास अरबों लोगों की निजी जानकारियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल राजनीतिक अभियानों व जनमत को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। इन कंपनियों और इनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं को जीवन से निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर इनकी शक्तियों के दुष्प्रभावों की बात उठी है, तो इस पर गंभीरता से विचार और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तकनीक और नवाचार लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हों।

महाराष्ट्र चुनाव और अनुत्तरित सवाल

नवंबर के मध्य तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है, लेकिन वहां पर दोनों ही गठबंधनों, महायुति और महा विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में शरद पवार कब और कौन-से पत्ते खोलते हैं, यह बड़ा मायने रखेगा।

अभी भले ही हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र पहले से ही राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। अन्य राज्यों की तुलना में आज यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र ही है, जिसका आने वाले कुछ महीनों में एनडीए और इंडिया ब्लॉक, दोनों की राजनीति पर असर पड़ने की उम्मीद है। संभावना है कि आठ अक्तूबर को हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणाम के बाद जल्द ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का एलान कर दिया जाएगा और नवंबर के मध्य में चुनाव होने के आसार हैं। चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में विलंब नहीं होगा। चुनाव आयोग की टीम झारखंड का दौरा कर चुकी है और संभवतः आज महाराष्ट्र में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेगी।

नीरजा चौधरी
वरिष्ठ पत्रकार

अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें, तो महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए), जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा, शरद पवार) शामिल हैं, ने 48 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, सत्तारूढ़ महायुति (भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राकांपा) ने मिलकर 17 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि विधानसभा चुनाव भी लोकसभा की तर्ज पर हो, भले ही एमवीए नेता आशान्वित हैं कि जमीनी स्तर पर माहौल और सहानुभूति उनके पक्ष में है।

लोकसभा चुनाव ने जहां एमवीए नेताओं का मनोबल बढ़ाया, वहीं सीट बंटवारे को लेकर उनके बीच खींचतान मची हुई है। हाल के दिनों में तीनों साझेदारों के बीच हुई बैठक में लगभग 160 सीटों (288 में से) पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी उन्हें विशेष रूप से विदर्भ और मुंबई क्षेत्र को लेकर मतभेदों को दूर करना होगा। कांग्रेस जिसे अपना गढ़ समझती है, उसमें शिवसेना (उद्धव) को नहीं घुसने देना चाहती है। कुल मिलाकर कांग्रेस 120 सीटों के लिए जोर लगा रही है, जिन पर लोकसभा में उसका प्रदर्शन अच्छा था। वहीं, राकांपा (शरद पवार) का प्रदर्शन भी लोकसभा में अच्छा

रहा था। उसने दस सीटों पर चुनाव लड़ा और आठ पर जीत दर्ज की, लेकिन उद्धव की शिवसेना उतना खास प्रदर्शन नहीं कर सकी थी।

सत्तारूढ़ महायुति में भी सीटों के बंटवारे को लेकर उतनी ही खींचतान है। लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन तीनों साझेदारों से श्रेष्ठ रहा था। उनकी सफलता लगभग 50 फीसदी थी, यानी उन्होंने 15 में से सात लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। अजित पवार गुट ने चार में से केवल एक सीट पर जीत दर्ज की। अजित पवार को भाजपा और आरएसएस के अंदरूनी विरोध का भी सामना करना पड़ा था। दरअसल, अजित पवार से गठबंधन के लिए आरएसएस ने कथित तौर पर भाजपा की तीखी आलोचना भी की थी। कई लोग मानते हैं कि अजित पवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होने के बावजूद उन्हें गठबंधन में शामिल करने का फैसला भाजपा को महंगा पड़ा। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस की पदावनति कर उन्हें एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उपमुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि, फडणवीस अब भी उपमुख्यमंत्री हैं, वह ब्राह्मण हैं और हाल में राज्य में जारी मराठा राजनीति के पुनरुत्थान को देखते हुए भाजपा के पास राज्य में ऐसा मजबूत चेहरा भी नहीं है, जो चुनाव में उसे नेतृत्व प्रदान करे।

जातिगत मुद्दे के अलावा, महायुति को सबसे बड़ी उम्मीद मध्य प्रदेश की 'लाडली बहना योजना' की तर्ज पर शुरू की गई 'लाडली लड़की योजना' से है। लाडली बहना योजना की वजह से भाजपा को मध्य प्रदेश में हालिया लोकसभा चुनाव में महिलाओं का जबरदस्त साथ मिला था। महायुति में सीट बंटवारे के अलावा, विवादास्पद मुद्दा नेतृत्व का है। महा विकास अघाड़ी भी इससे ही जूझ रहा है। उद्धव ठाकरे ने एमवीए सरकार का करीब दो वर्ष तक नेतृत्व किया, जब तक कि भाजपा ने शिवसेना को तोड़कर उनकी सरकार को गिरा नहीं दिया था। बाद में राकांपा को भी तोड़कर महायुति में शामिल कर लिया। दोनों ही पार्टियों के विधायकों का बड़ा हिस्सा टूटकर एकनाथ शिंदे व अजित पवार वाले गुटों में शामिल हो गया, जिन्हें अदालत से मान्यता और चुनाव चिह्न, दोनों मिल गए।

राज्य में फिर से उठ खड़े होने की संभावना को देखते हुए कांग्रेस का राज्यस्तरीय नेतृत्व इस बात पर जोर दे रहा है कि नेतृत्व उसके पास रहना चाहिए, या फिर चुनाव में जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलें उसे कमान मिले। शिवसेना गठबंधन की कमान फिर से अपने पास ही रखना चाहेगी। यह माना जा रहा है कि हाल में उद्धव ठाकरे दिल्ली में जब राहुल गांधी से मिले, तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि चुनाव में उनको (उद्धव ठाकरे) मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए बिना ही जनता के सामने जाएंगे। लेकिन, अगर एमवीए को बहुमत मिलता है, तो वही नेता होंगे।

दूसरी तरफ, एमवीए के संस्थापक शरद पवार ने संकेत दे दिया है कि नेतृत्व के मुद्दे को चुनाव के बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब मोरारजी देसाई चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री घोषित किए गए थे। लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान शरद पवार ने मुझे बताया था कि उन्हें लगता है कि आगामी एक-दो वर्षों में उनकी पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय हो सकता है। इस स्तर पर फिलहाल यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि राकांपा इस विकल्प पर कब और किस तरह विचार करेगी। लेकिन यह बात तय है कि शरद पवार अपनी पार्टी और अपनी बेटी सुप्रिया सुले, जो राकांपा (शरद पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, को यथासंभव राजनीतिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं।

कथित तौर पर भतीजे अजित पवार ने भी अपने चाचा को पुरानी बातें भूल जाने की पेशकश की है। सार्वजनिक रूप से वह कह चुके हैं कि बारामती से बहन सुप्रिया के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को चुनाव लड़ाकर उन्होंने बड़ी गलती की थी। लेकिन वरिष्ठ पवार उन्हें माफ करने, भूलने या स्वागत करने और पार्टी में फिर से उत्तराधिकार के मुद्दे को खोलने के मूड में नहीं दिख रहे। यदि महाराष्ट्र में एमवीए की सत्ता में वापसी होती है, तो स्वाभाविक है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। वहीं, कांग्रेस यदि ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही, तो शीर्ष गद्दी पर वह अपना दावा जताएगी। शरद पवार भी अपने पत्ते खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। महाराष्ट्र में कुछ अनुत्तरित सवाल ये भी हैं कि अगर परिस्थितियां बनने लगीं, तो क्या शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे? क्या सुप्रिया सुले छुपी रुस्तम बनकर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी?

edit@amarujala.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

मैक्सिम गोर्की

जब किसी को अपने आसपास सभी से प्रेम हो, और सबके लिए उसका हृदय किसी आशंका से त्रस्त रहता हो, उसे सब पर तरस आता हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अलग करके मात्र अपने विषय में कैसे सोच सकता है?

जिसे सबसे प्रेम हो, वह खुद के बारे में कैसे सोचे

मां की भौंहें फड़कने लगी और वह स्वयं भी सोचने लगी कि उसके जीवन में दुख है कि नहीं। 'अवश्य है' लूदमीला ने सहसा कहा। 'मैं निश्चत रूप से नहीं कह सकती।' मां ने धीरे से कहा। 'कभी-कभी दुख अवश्य होता है, किंतु मेरा जीवन इतना भरपूर है कि उसमें प्रत्येक वस्तु इतनी महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक है और पूरी बातें एक के बाद एक इतनी जल्दी-जल्दी होती रहती हैं कि....।' जैसे कि बहुधा होता था, इस समय भी सहसा उसके हृदय में उत्साह का एक तूफान उमड़ने लगा, उसके मस्तिष्क में कल्पनाओं की भीड़ लग गई। वह उठकर पलंग पर बैठ गई एवं विचारों और कल्पनाओं को शब्दों में सजाने-संवारने लगी।

'जीवन का क्रम चलता रहता है-सदैव एक उद्देश्य की दिशा में, किंतु कभी-कभी बहुत दुख भी होता है। लोग परेशानियां उठाते हैं, मार खाते हैं, बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। और उनसे बहुत-सी प्रसन्नताएं छीन ली जाती हैं, यह देखकर दुख तो होता ही है।' लूदमीला अपना सिर पीछे को झटककर मां को बड़े प्रेम से देखने लगी। 'किंतु तुम अपने विषय में कुछ नहीं बताती।' मां पलंग से उठी और वस्त्र बदलने लगी। 'अपने विषय में? जब किसी को अपने आसपास सभी से प्रेम हो, और सबके लिए उसका हृदय किसी आशंका से त्रस्त रहता हो, उसे सब पर तरस आता हो, तो वह स्वयं को दूसरों से अलग करके मात्र अपने विषय में कैसे सोच सकता है? मैं स्वयं को उनसे अलग कैसे कर सकती हूं?' वह एक क्षण तक आधे कपड़े पहने हुए कमरे के बीच में विचारों में खोई-खोई खड़ी रही। मां को ऐसा एहसास हुआ कि अब वह औरत नहीं रह गई है, जिसका हृदय अपने बेटे के लिए भयभीत और आतंकित था, जो अपने पुत्र के शरीर को बचाने के लिए इतनी बेताब थी। अब उस स्त्री का अस्तित्व ही बाकी नहीं रह गया था। वह कहीं छिप गई थी, कहीं बहुत दूर चली गई थी। अथवा कदाचित वह अपने ही भावावेश की ज्वाला में जल गई थी और इस अग्नि में तपकर उसकी आत्मा शुद्ध होकर निखर आई थी और उसमें नई शक्ति का संचार हुआ था। उसने अपने हृदय को टटोला, उसका स्पंदन सुना और डरने लगी कि पुरानी आशंकाएं कहीं फिर न उत्पन्न हो जाएं। 'क्या सोच रही हो?' लूदमीला ने उसके निकट जाकर पूछा। मालूम नहीं। मां ने उत्तर दिया। वे दोनों खामोशी से एक-दूसरे को देखकर मुस्कराती रहीं। मां ने खिड़की के बाहर देखा। ठंड पड़ रही थी, चारों ओर धूप फैली हुई थी। उसके हृदय में भी इसी धूप जैसी रोशनी फैली हुई थी और गरमी भी थी। वह प्रत्येक वस्तु के बारे में बातें करना चाहती थी। बड़ी देर तक प्रसन्नता के साथ बातें करना चाहती थी। उसकी आत्मा में जो कुछ समाया हुआ था और जो वहां सूर्यास्त से पहले की खूबसूरती ज्योति से जगमग रही थी, उसके लिए हृदय में किसी के लिए कृतज्ञता की एक अस्पष्ट-सी भावना थी। बहुत दिन बाद उसके हृदय में ईश्वर की विनती करने की इच्छा उत्पन्न हुई।

(महान रूसी साहित्यकार के कालजयी उपन्यास 'मदर' के अनूदित अंश)

मां जैसा संवेदनशील बनें

सूत्र

अगर आप खुद को सबसे जोड़कर देखते हैं, दूसरों के दुख-दर्द अनुभव करते हैं, और अपने कष्टों को भूलकर उनकी मदद के लिए हरदम तैयार रहते हैं, तो ही सही अर्थों में मनुष्य हैं। जैसे एक मां अपने हृदय में अपने बच्चों की सुरक्षा की प्रार्थना हमेशा बुदबुदाती रहती है, वही संवेदनशीलता अगर सभी अपने हृदय में रखें, तो दुनिया ऐसी न रहे।

दूसरा पहलू

ई.वुडी के ज्ञात नमूने एक ही नर पौधे के क्लोन हैं। ये 100 वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाए गए थे।

दुनिया के अकेले पौधे के लिए मादा साथी की खोज

साइकैड पौधे की एक प्रजाति एन्सेफलार्टोस वुडी (ई.वुडी) के एकमात्र ज्ञात नमूने एक ही नर पौधे के क्लोन हैं। ये 100 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के जंगल में पाए गए थे। अब ब्रिटेन के साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय की शोधकर्ता लॉरा सिंटी के नेतृत्व में एक टीम ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से इस प्रजाति का मादा पौधा खोजने में जुटी है। वह कहती हैं, यह दुनिया का 'अकेला' पौधा है, क्योंकि इसकी मादा साथी नहीं है। इसलिए इस पौधे की प्रजाति को बचाना जरूरी है। दुनिया के सबसे दुर्लभ पौधों में से एक के रूप में ई.वुडी को खरीदने वालों और वनस्पतिशास्त्रियों के बीच इसकी भारी मांग रहती है। लॉरा सिंटी कहती हैं-ये डायनासोर के समय से भी पहले से मौजूद हैं। एक समय इनकी तादाद काफी थी, लेकिन आज वे वास्तव में हमारे ग्रह पर सबसे अधिक संकटग्रस्त और सबसे लुप्तप्राय पौधों में से हैं।

लॉरा सिंटी

लॉरा सिंटी कहती हैं-ये डायनासोर के समय से भी पहले से मौजूद हैं। एक समय इनकी तादाद काफी थी, लेकिन आज वे सबसे लुप्तप्राय पौधों में से हैं।

ई.वुडी के एकमात्र ज्ञात जंगली पौधे की खोज 1895 में वनस्पतिशास्त्री जॉन मेडले वुड ने दक्षिण अफ्रीका के जंगल में एक अभियान के दौरान की थी। लॉरा सिंटी कहती हैं कि यह पौधों की प्रेम कहानी से कम नहीं है। लंदन स्थित एक वनस्पति उद्यान, केव गार्डन में साइकैड का एक नमूना था, जो 1899 में दक्षिण अफ्रीका से भेजा गया था और यह आज भी वहां है। जब मैं केव गार्डन पहुंची, तो पता चला कि कोविड-19 के कारण इस उद्यान को बंद कर दिया गया है। फिर भी, केव गार्डन में पौधों की देखरेख करने वाली एक महिला ने मुझे उसका वीडियो और चित्र हासिल करवाए और जब वह उद्यान खुला तब मैंने वहां जाकर वह पौधा देखा। पौधा देख मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कितना छोटा था। हमारे पास ई.वुडी की एक पुरानी (शायद 1907 की) तस्वीर है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक तने की छाल वास्तव में बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। इस छाल और तनों का पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग होता था। बाद में, 1916 में वन विभाग ने इस पौधे के मूल तने को जंगल से हटा दिया था। इस डर से कि यह नष्ट हो जाएगा। और फिर इसे प्रिटोरिया में एक बाड़े में सुरक्षित रख दिया गया था। इस प्रजाति के मादा पौधे की खोज के लिए मैंने और मेरी टीम ने 2022 में पहला खोज अभियान शुरू किया। हमें उम्मीद है कि कोई तो ऐसी तस्वीर सामने आएगी जो साइकैड की इस मादा प्रजाति की होगी। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं।

ई.वुडी के एकमात्र ज्ञात जंगली पौधे की खोज 1895 में वनस्पतिशास्त्री जॉन मेडले वुड ने दक्षिण अफ्रीका के जंगल में एक अभियान के दौरान की थी, जिसे 1899 में लंदन स्थित केव गार्डन में भेजा गया था।

(द कन्वर्सेशन से)

आंकड़े

काम के घंटे

दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अपने कार्यक्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करते हैं, जिसका असर आर्थिक वृद्धि पर भी दिख रहा है।

भारत	46.7
चीन	46.1
ब्राजील	39.0
अमेरिका	38.0
जापान	36.6

आंकड़े एक सप्ताह में किए गए कार्य के, घंटों में | स्रोत : CNBC

मुनि के कहने पर राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने देवी महामाया की उपासना की। देवी ने जब दर्शन दिए, तो राजा ने वरदान में संसारी भोग और वैश्य ने ज्ञान मांगा।

समाधि ने महामाया से मांगा ज्ञान

अंतर्यात्रा
संकलित

कलिंग देश के वैश्य राजा विराध के पौत्र और दुमिल के पुत्र समाधि वैश्य की धर्म में बड़ी आस्था थी। वह अत्यंत ही धनवान कुल के वैश्य थे। परंतु उनकी स्त्री और पुत्रों ने उन्हें धोखा दे दिया। वह बहुत दुखी होकर वन में चले गए। वन में एक मुनि के आश्रम में उन्होंने आश्रय लिया, लेकिन अब भी उनके मन में शांति नहीं थी। वह बार-बार अपने संबंधियों के ही सुख-दुख की चिंता में पड़े हुए थे।

उसी समय उन्हें एक सुरथ नाम के राजा मिले, जो अपने मंत्रियों, सेनापतियों और स्वजनों से ही धोखा खाकर वन में आ गए थे। दोनों ने अपना-अपना परिचय दिया और एक-दूसरे के साथ अपनी करुण कथा और मानसिक दशा का वर्णन किया। दोनों की मनोदशा एक ही थी। दोनों ने मुनि के पास जाकर अपने दुख और मन की स्थिति का वर्णन किया। मुनि ने कहा कि भगवती महामाया की आराधना से ही सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद दोनों ने तीन वर्ष तक देवी महामाया की श्रद्धापूर्वक उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी उन दोनों के सामने प्रकट हुई और वर मांगने के लिए कहा।

राजा सुरथ ने संसारी भोग की मांग की। परंतु समाधि वैश्य ने कहा कि ऐसा वर दें, जिसमें 'मैं और मेरा है' इस प्रकार की अहंता-ममता और आसक्ति को जन्म देने वाला अज्ञान नष्ट हो जाए और मुझे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो। भगवती समाधि को वर देकर वहीं अंतर्धान हो गई।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 31 मार्च, 1960

परमाणु परीक्षण बंद करने के सभी सुझाव स्वीकार

परमाणु परिक्षण बंद करने के सभी सुझाव
कुछ शर्तों के साथ स्वीकार

अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेराल्ड मैकमिलन ने एक संयुक्त घोषणा में कहा कि वे भूमिगत परमाणु परीक्षण निषेध संबंधी प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करते हैं।

स्वच्छ और सुरक्षित पानी का अधिकार सभी को

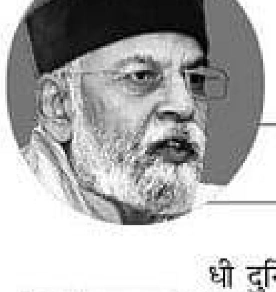

दुनिया भर में साफ और सुरक्षित पानी का संकट है। पानी से जुड़े हिंसा के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में पर्यावरणीय मुद्दों को ठोस बनाने की जरूरत है।

ज्ञानेंद्र रावत | **मुद्दा**

आधी दुनिया साफ और सुरक्षित पानी के संकट से जूझ रही है। पानी के लिए लोग एक-दूसरे का खून बहा रहे हैं। साल 2023 इसका जीता-जागता सबूत है, जिसमें पानी से जुड़े हिंसा के 347 मामले सामने आए हैं। हमारा देश भी इस मामले में पीछे नहीं है, जहां इस दौरान हिंसा के 25 मामले सामने आए, जबकि 2022 में इस तरह के देश में कुल 10 मामले सामने आए थे। यह प्रमाण है कि 2022 की तुलना में पानी के मामले में हिंसा में 50 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इन मामलों में कई लोग मारे भी गए हैं।

दरअसल पानी से संबंधित हिंसा के मामलों में बांधों, पाइप लाइनों, कुओं, उपचार संयंत्रों और संयंत्रों पर कार्यरत कामगारों पर हमले प्रमुख हैं। हकीकत यह है कि हिंसा के इन मामलों में सिंचाई के पानी के संघर्ष ज्यादा चर्चा में रहे हैं। इनके अलावा सूखे और आपसी विवादों ने इन संघर्षों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं, मध्य पूर्व में इनमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी

दर्ज हुई है। इनमें खासतौर पर लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, सब सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देश शीर्ष पर हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हालिया अध्ययन का निष्कर्ष *साइनस* पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, के अनुसार आज दुनिया में 4.4 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। यह आंकड़ा पहले से जारी संख्या से दोगुने से भी ज्यादा है, जो भयावह खतरे का संकेत है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, अभी दुनिया की तकरीबन 26 फीसदी आबादी स्वच्छ पेयजल के संकट का सामना कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2050 तक दुनिया की 1.7 से 2.4 अरब शहरी आबादी को पेयजल संकट का सामना करने का अंदेशा है। इसमें सबसे ज्यादा भारत के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। यूनेस्को की मानें, तो हालात इतने गंभीर हैं कि इस वैश्विक संकट के नियंत्रण से बाहर जाने से पहले मजबूत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तत्काल स्थापित करने की जरूरत है। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2030 तक दुनिया के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता का लक्ष्य काफी दूर है। असलियत यह है कि बीते 40 वर्षों में दुनिया में जल के उपयोग की दर प्रति वर्ष एक फीसदी बढ़ी है। दुनिया की आबादी बढ़ने और सामाजिक-आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसके वर्ष 2050 तक इसी तरह बढ़ने के आसार हैं। यह एक गंभीर चुनौती है।

सच्चाई यह भी है कि पानी में दूषित पदार्थों की मौजूदगी और बुनियादी ढांचे में कमी के चलते दक्षिण एशिया, उप सहारा अफ्रीका, पूर्वी एशिया और कई अफ्रीकी देशों के लगभग 69 करोड़ से अधिक लोग ऐसी जगहों पर रहने के लिए विवश हैं, जहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 1.96 करोड़ आवासों में रहने वाले लोगों को फ्लोराइड और आर्सेनिक युक्त पानी पीना नियति बन गई है। पानी से होने वाली बीमारियों पर हर साल करीब 42 अरब रुपये का आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

जहां तक एशिया का सवाल है, तो यहां की तकरीबन 80 फीसदी खासकर पूर्वोत्तर चीन, भारत और पाकिस्तान की आबादी भीषण पेयजल संकट से जूझ रही है। यदि इस वैश्विक अनिश्चितता को खत्म नहीं किया गया और इसका शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया, तो निश्चित ही इस संकट का सामना करना बेहद मुश्किल होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी कहते हैं कि पेयजल मानवता के लिए रक्त की तरह है। इसलिए जल की बर्बादी रोकना और संचय बेहद जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदलाव के चलते दुनिया में जल सुरक्षा के खतरे दिनोंदिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इससे दुनिया के पांच अरब लोगों पर यह संकट भयावह रूप अख्तियार करता जा रहा है।

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रकोप के कारण पानी की यह विकट स्थिति होती जा रही है। कारण यह है कि लोगों को अभी भी मौसम से जुड़े पर्यावरणीय खतरों की कोई जानकारी नहीं है। यही नहीं वे जलवायु परिवर्तन और जल सुरक्षा के बीच के संबंध को जानते तक नहीं हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 20 वर्ष में यह संकट भयावह रूप धारण कर लेगा और लोगों के लिए पानी गंभीर खतरा बन जाएगा। दरअसल सबसे बड़ी जरूरत पर्यावरणीय मुद्दों को ठोस और प्रासंगिक बनाने की है, तभी कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। साफ और सुरक्षित पानी के लिए यदि दुनिया भर में ईमानदारी से प्रयास किए जाते हैं और उनमें सुधार आता है, तो यह दुनिया की एक महान उपलब्धि होगी।

कल्पमेधा

अकेले आदमियों के कृत्यों से सारा इतिहास भरा हुआ है। आदमी अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। अकेले आदमियों ने ही विचारों से क्रांति पैदा की है।
– प्रेमचंद

घाटी में राजनय

जम्मू-कश्मीर पर स्वाभाविक रूप से दुनिया की नजर रहती है। पाकिस्तान इस इलाके को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी के बारे में गलतबयानी करता रहता है, वहां आतंकवाद फैलाने में जुटा हुआ है। हालांकि, ऐसी गतिविधियों में अपना कोई हाथ होने से भी वह लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन उसकी कारगुजारियां जगजाहिर हैं। दूसरी ओर, भारत सरकार ने वहां आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया है और अब जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में लोग काफी उत्साह से मतदान कर रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के दौरान घाटी में विभिन्न देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का दौरा हुआ है। उन लोगों ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोगों से बात की। कूटनीति के लिहाज से यह कवायद सार्थक लगती है। मतदान के दौरान विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित दूतावासों में कार्यरत राजनयिकों के लिए घाटी की यात्रा आयोजित की। इसके पीछे तर्क दिया गया कि इससे विभिन्न देशों तक जम्मू-कश्मीर के हालात की असल जानकारी पहुंच सकेगी। पहले चरण में मतदाताओं का काफी उत्साह दिखा। दूसरे चरण में भी मतदान के आंकड़े उत्साहजनक रहे। हालांकि, राजनयिकों की इस यात्रा पर विपक्षी दलों ने एतराज जताया है। नैशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने तल्ख लहजे में कहा कि हमें इन राजनयिकों के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार विदेशी पत्रकारों को घाटी में आने की इजाजत नहीं देती, तो राजनयिकों को यहां लाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है।

दरअसल, अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद घाटी में पैदा हुए हालात को लेकर दो विपरीत धारणाएं फैलाई जाती रही हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद घाटी में स्थिति बेहतर हुई है, जबकि विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि वहां हालात ठीक नहीं हैं। आतंकी घटनाओं और सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ने को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। इन सबके बावजूद विधानसभा चुनाव में लोग बढ़-चढ़ कर मतदान करते देखे जा रहे हैं। पहले चरण में साठ फीसद से अधिक मतदान हुआ। दूसरे चरण में भी खूब उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में, केंद्र सरकार खुलकर कह सकती है कि विशेष राज्य का दर्जा हटाने का उसका फैसला गलत नहीं था और लोग उससे खुश हैं।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद, करीब चार वर्ष पहले भी यूरोपीय संसद के सदस्यों को घाटी में ले जाया गया था। तब भी सवाल उठाए गए थे। तब सरकार ने कहा था कि वह यात्रा एक स्वयंसेवी संगठन ने आयोजित की थी। पिछले महीने भी अमेरिका और जर्मनी के राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर की यात्रा कराई गई थी। दरअसल, जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच विवाद पर जब भी किसी देश ने मध्यस्थता की बात उठाई, भारत सरकार ने हमेशा उसे ठुकराया है। भारत सरकार का रुख रहा है कि जम्मू-कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। इस नीति के हवाले से राजनयिकों के दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि कहीं कश्मीर को लेकर फिर मध्यस्थता के लिए दबाव का सामना न करना पड़े। हालांकि, सरकार आश्वस्त है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी और कूटनीतिक मंचों पर पाकिस्तान के तर्कों हमेशा की तरह कमजोर किया जा सकेगा। बहरहाल, समूची कवायद में यह स्वागतयोग्य है कि वहां लोकतंत्र की ताकत दिखी और इससे विदेशी राजनयिक भी रूबरू हुए।

मुठभेड़ पर मुठभेड़

महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी के मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं। बंबई हाई कोर्ट ने इस मुठभेड़ को लेकर महाराष्ट्र पुलिस के कार्यव्यवहार पर कई तीखे सवाल उठाए हैं। अदालत ने इस मुठभेड़ पर शंका जाहिर करते हुए जांच कराने का आदेश दे दिया है। महाराष्ट्र पुलिस पर उठ रहे सवाल उन सभी राज्यों की पुलिस पर भी सवाल हैं, जो मुठभेड़ दिखा कर आरोपियों को मार गिराती और उसे अपनी उपलब्धि बताती हैं। बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। मगर इसे लेकर कुछ नियम-कायदे हैं। पुलिस के सामने जब भी ऐसी स्थिति आ जाए और आत्मरक्षा में गोली चलानी ही पड़ जाए, तो कमर के नीचे निशाना साधने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मगर पिछले कुछ वर्षों में हुई मुठभेड़ों के दौरान इस नियम-कायदे का पालन कहीं नजर नहीं आता। इससे यही शक होता है कि पुलिस या तो अपनी कुछ कमियों को छिपाना चाहती है या उसे अदालतों पर विश्वास नहीं है, वह खुद फैसला करके दंड देने में यकीन करने लगी है।

किसी आरोपी के मारे जाने से उस मामले से जुड़े कई तथ्य खत्म हो जाते हैं। इस तरह मामले की सच्चाई तक पहुंचने के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर, किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसका दोष सिद्ध न हो जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कि किसी मामले में किसी गलत व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया। मगर शायद राज्यों की पुलिस इस बात पर ज्यादा भरोसा करने लगी हैं कि आपराधिक मामलों का निर्णय वे खुद करें और वही दंड दें। कुछ नेता भी इसे उचित बता रहे हैं। इसीलिए पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुई मुठभेड़ों को लेकर सियासत गर्म है। उसमें एक आरोपी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद जातिवादी समीकरण भी साधने का प्रयास किया गया। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर मुठभेड़ बता कर किसी आरोपी को मार डालना पुलिस और सरकारों के रवैए पर गहरे सवाल खड़े करता है। यह प्रवृत्ति किसी भी सभ्य समाज और कल्याणकारी सरकार की निशानी नहीं कही जा सकती।

संकल्प और आत्मविश्वास से जीते पदक

आत्मविश्वास के बूते अविश्वसनीय प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों ने पदक ही नहीं, देशवासियों का दिल भी जीता है।

मोनिका शर्मा

हाल ही में पेरिस में संपन्न हुए पैरालंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने निस्संदेह उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। पेरिस पैरालंपिक-2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने उनतीस मेडल जीत कर पदक तालिका में देश को अठारहवें पायदान पर खड़ा कर दिया। दस पदक तो बेटियों ने ही जीते। हौसले और जुनून की बानगी कहे जा सकने वाले खेलों के इस आयोजन में इस बार भारत ने पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और बेल्जियम जैसे कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने सात स्वर्ण, नौ रजत और तेरह कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। वर्ष 2021 में तोक्यो पैरालंपिक में पहली बार भारत दहाई का आंकड़ा छूने में कामयाब रहा था। इस वर्ष भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय ही नहीं, ऐतिहासिक भी रहा। भारत ने इस बार पैरालंपिक में कुल चौरासी खिलाड़ी भेजे थे।

दरअसल, भारतीय पैरा खिलाड़ियों की यह सफलता देशवासियों को गर्व महसूस करवाने वाली तो है ही, हर खिलाड़ी की यात्रा भी किसी न किसी मोर्चे पर प्रेरणादायी है। यही कारण है कि आत्मविश्वास के बूते अविश्वसनीय प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों ने पदक ही नहीं, देशवासियों का दिल भी जीता है। अपनी पहचान बनाने की यात्रा में शारीरिक-मानसिक प्रतिकूलताओं से जूझ कर जीतने वाले खिलाड़ियों की सफलता सराही गई। आभासी दुनिया से लेकर असल संसार तक, विजेताओं को खूब शाबाशी दी गई। अवनी लेखरा ने तो पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की दस मीटर एअर राइफल श्रेणी में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। वहीं नीतेश कुमार ने भी रोमांचक मुकाबले को जीत कर स्वर्ण पदक देश के नाम किया।

पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता में सुमित अंतिल ने अपना ही कीर्तिमान तोड़ कर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत के पैरा खिलाड़ी तीरंदाज हरविंदर सिंह ने भी इतिहास रचते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि दर्ज की। ओलंपिक या पैरालंपिक में किसी भी भारतीय तीरंदाज का यह पहला स्वर्ण पदक है। पैरा एथलीट धरमबीर ने भी न केवल पुरुष क्लब थ्रो में नया एशियाई कीर्तिमान बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता, बल्कि भारत के लिए पहली बार पैरालंपिक खेलों में क्लब थ्रो स्पर्धा में पदक हासिल किया। इसी प्रतियोगिता में खिलाड़ी प्रणव सूरमा ने रजत पदक जीत कर देश को गौरवान्वित किया है। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता, तो नवदीप सिंह ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। किसी खिलाड़ी ने अंगों की विकृतियों, तो किसी ने मांसपेशियों की समस्याओं से जूझते हुए अपनी जीत दर्ज की। गौरतलब है कि 1968 में पहली बार भारत ने पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। इस भागीदारी के चार साल बाद देश को पदक मिल सका था।

हमारे परिवेश में देखने में आता है कि शारीरिक अशक्तता से जूझ रहे लोगों को आम जीवन में सहज सहयोग और सराहना नहीं मिल पाती। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद ही उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव दिखता है। किसी भी क्षेत्र में कमाल कर दिखाने के बाद पहचान और मान मिलना सही है, पर आम नागरिक की तरह जीते हुए तो अनगिनत मुश्किलें उनके हिस्से होती हैं। निशक्तजनों के प्रति उपहास उड़ाने और असभ्य भाषा का व्यवहार आम है। तेलंगाना के

> **दिव्यांग खिलाड़ियों की सफलता पर शाबाशी देने के साथ ही समाज की सोच बदलने की जरूरत है। आज देश में अलग-अलग श्रेणियों में दिव्यांगों की आबादी दो करोड़ से भी ज्यादा है। 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' के 2018 में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत की 2.2 फीसद आबादी विकलांगता से जूझ रही है। भारत में आम खिलाड़ियों के लिए ही तमाम चुनौतियां हैं, तो शारीरिक अशक्तता से जूझ रहे इन चेहरों के सामने कितनी मुश्किलें आती होंगी। ऐसे में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आगे खेलने के मोर्चे पर भी बेहतर परिवेश बनाने के प्रयास आवश्यक हैं।**

वारंगल जिले के काल्लेड़ा गांव की दीप्ति जीवनजी को भी गांव के लोग चिढ़ाते हुए ताने मारते थे। बीस वर्षीय दीप्ति पैरालंपिक में कांस्य पदक हासिल कर भारत की पहली 'इंटेलक्चुअली इंपेयर्ड एथलीट' बन गई हैं। इतना ही नहीं, दीप्ति, 2022 के 'एशियन पैरा गेम्स' और 2024 की 'वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप' में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

दिव्यांगों के प्रति तयशुदा सोच को इसी बात से समझा जा सकता है कि आज देश का नाम चमकाने वाली इस पैरा खिलाड़ी के लिए लोग यह तक कहने लगे थे कि ऐसी लड़की को अनाथालय भेज देना चाहिए। 'मेन्स जेवलिन थ्रो' में स्वर्ण पदक देश की झोली में डालने वाले नवदीप को भी बौना-बौना कह कर चिढ़ाया जाता था। ऐसे तानों के कारण नवदीप कई-कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते थे। ऐसे उदाहरण इस कटु सच को सामने रखते हैं कि आज भी निशक्तजनों को उपहास उड़ाने की मानसिकता का सामना करना पड़ता है। आज भी समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो उन्हें आश्रित इंसान के रूप में ही देखते हैं।

ऐसे में दिव्यांग खिलाड़ियों की सफलता पर शाबाशी देने के साथ ही समाज की सोच बदलने की जरूरत है। आज देश में अलग-अलग श्रेणियों में दिव्यांगों की आबादी दो करोड़ से भी ज्यादा है। 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' के 2018 में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत की 2.2 फीसद आबादी विकलांगता से जूझ रही है। भारत में आम खिलाड़ियों के लिए ही तमाम चुनौतियां हैं, तो शारीरिक अशक्तता से जूझ रहे इन चेहरों के सामने कितनी मुश्किलें आती होंगी। ऐसे में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आगे खेलने के मोर्चे पर भी बेहतर परिवेश बनाने के प्रयास आवश्यक हैं।

पैरालंपिक खेलों में उनतीस पदक पाने तक पहुंचने की यात्रा भी बहुत-सी कोशिशों का ही परिणाम है। ताजा उपलब्धियों के पीछे की सधी तैयारियां और व्यवस्थागत प्रयास ही हैं। पैरालंपिक खिलाड़ियों की तैयारी के लिए न केवल वित्तीय सहायता बढ़ी है, बल्कि पैरा खिलाड़ियों को मुख्यधारा के खिलाड़ियों की तरह अहमियत भी मिलने लगी है। भारत सरकार ने पेरिस पैरालंपिक 2021-2024 के लिए 74 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।

भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता और एशियन पैरालंपिक समिति की सदस्य होने के साथ ही वर्ष 2020 में 'पैरालंपिक कमेटी आफ इंडिया' की अध्यक्ष बनीं दीपा मलिक के अनुसार हालिया वर्षों में पैरालंपिक के लिए जो नीति बनी है, उसमें 'टारगेट ओलंपिक पोडियम' के तहत खिलाड़ियों को तैयारी के हिसाब से राशि दी जा रही है। साथ ही, खुद खिलाड़ी भी अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। पैरालंपिक में पदक बढ़ने की एक वजह यह भी रही कि अब जमीनी स्तर पर कई खिलाड़ियों के लिए तैयारी के वास्ते 'एक्सीलेंस प्रोग्राम' और 'खेलो इंडिया पैरा गेम्स' जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं, पैरा खिलाड़ियों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विशेष उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता मिली है।

उचित प्रशिक्षण ने भी प्रदर्शन में सुधार किया। सुखद यह है कि सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से आमजन भी इनके संघर्ष के बारे में जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इनके हौसले को सराह रहे हैं। उम्मीद है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को गिनती के दिनों के लिए चर्चित चेहरा मानने के बजाय उनसे हमेशा के लिए समाज की सोच में बदलाव आएगा।

ताकि चहकते रहें बच्चे

अमित कुमार

दुनिया मेरे आगे

बच्चों का दिमाग एक खाली स्लेट होता है। हमारा व्यवहार उस पर हमारे बिना चाहे भी अमिट छाप छोड़ रहा होता है, जो उनके आचार-विचार में गाहे-बगाहे प्रतिबिंबित होता रहता है। इसलिए उनके प्रति हमारा बर्ताव वास्तविक रूप में अनुकरणीय होना चाहिए। आमतौर पर परीक्षा के खराब परिणाम आने पर बड़ी सहजता से मां-बाप अपने बच्चे को पीट देते हैं। दरअसल, ऐसा करते हुए वे अपने अभिभावक होने की परीक्षा में बहुत खराब अंक से असफल हो रहे होते हैं। किसी गलती पर उन्हें गलती का कारण समझाने के बजाय थप्पड़ जड़ देना कम समय लेने वाली और आसान राह है। उचित यह होगा कि हमें अपनी संतान की परवरिश में पर्याप्त समय और ऊर्जा खपानी चाहिए। जब बच्चे कोई उपयोग का सामान तोड़ दें तो उन्हें उस सामान की उपयोगिता के बारे में समझाना चाहिए और उसे वापस जोड़ने के काम में संलग्न करना चाहिए। इससे सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

पूरे सोशल मीडिया पर 'मम्मी की चप्पल' और 'पापा की बेल्ट' पर चुटकुले पटे पड़े हैं। हिंसक संदर्भ वाले 'लतीफे' तक लोगों को बखूबी गुदगुदा जाते हैं। कारण यह है कि लोगों के लिए बच्चों का अपने मां-बाप द्वारा पीटा जाना सामान्य घटना मानी जाती है। जब कुकृत्यों को अरसे से सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो तो उनके उन्मूलन के विरुद्ध एक भारी जड़ता दिखती है। इसी कारण उनसे संबंधित हास्य की विसंगति लोगों को नहीं दिखती। दिखाए जाने पर वे नकार कर अपने सुविधा क्षेत्र में जमे रहना चुनते हैं। यहां तक कि ख्यातिलब्ध लोग और नेतागण भी इस विषय में सस्ते चुटकुले धड़ल्ले से सुनाते पाए गए हैं। इसलिए इस विषय में हर तबके के लोगों में जागरूकता फैलाना समय की मांग है।

> **बच्चों के मूलभूत मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी अधिक इसलिए हो जाती है कि वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं। बच्चों को नजाकत के साथ पाले जाने की जरूरत है, क्योंकि वे क्षमता के भंडार हैं और हमारा उनके प्रति बड़ा ऋण है।**

कई लोगों की यह दलील होती है कि बचपन में मार खाने के बावजूद उनके जीवन में अब कोई कठिनाई नहीं है। उन थप्पड़ों की छाप उनके चरित्र में मौजूद होती है, जिसका उन्हें भान नहीं होता। वैसे भी चूंकि किसी व्यक्ति ने यह झेल लिया, इसका मतलब यह नहीं कि किसी को भी उस प्रक्रिया में झोंक दिया जाए। बच्चों के मूलभूत मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी अधिक इसलिए हो जाती है कि वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं। बच्चों को नजाकत के साथ पाले जाने की जरूरत है, क्योंकि वे क्षमता के भंडार हैं और हमारा उनके प्रति बड़ा ऋण है। उनकी प्रतिभा और सृजनात्मकता जादुई छड़ी की तरह समाज को बदल सकती है, बशर्ते वृद्धि के दिनों में उन पर छड़ी न बरसाई जाए।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण के एक सम्मेलन ने 2006 में बच्चों के मानवाधिकार के संबंध में निर्देश जारी कर बच्चों की शारीरिक सजा को वैधानिक हिंसा करार दिया। किसी भी परिदृश्य में इस हिंसा के उन्मूलन के लिए विधायी, सामाजिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक कदम उठाने की तसदीक भी की। दुखद है कि इतने वर्षों के बाद भी भारतीय समाज का एक बड़ा तबका बच्चों की पिटाई को उनके विकास का एक जरूरी जरिया मानता है।

मार के क्षणिक भय के कारण बच्चे मां-पिता की बात मान तो लेते हैं, लेकिन दूरस्थ भविष्य में यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक साबित होता है। युवावस्था में उनके आक्रामक होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन भी बच्चों के साथ किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मार-पीट का खौफ बनाया गया, आगे चलकर उनकी यह मान्यता बन गई कि शारीरिक हिंसा के बूते चीजों का हासिल किया जाना बिल्कुल न्यायसंगत है। वे अपने साथियों, बहन-भाइयों के साथ मार-पीट करते पाए गए। चूंकि उनके मां-पिता ने उनके साथ थप्पड़-घूंसे का सहारा लिया, इसलिए उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ वही प्रक्रिया अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में अपनाई। इस तरह मार-पीट का दुश्चक्र पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा।

कई मामलों में मां या पिता की हथेली बच्चों के लिए पुचकार के बजाय मार की पहचान बनी रह गई। उन्हें बड़ी हथेली का डर सताने लगा और वे अपने मां-पिता से भावनात्मक रूप से कटने लगे। जिन्हें बड़ों से नियमित तौर पर मार पड़ी, उनका खुद पर विश्वास और सम्मान क्षीण होता गया। उन्हें लगा कि वे अच्छे आदमी नहीं। उसी मार के भय से जब बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो वे अपने मां-पिता के पास खुलकर अपनी बात बयान नहीं कर पाते। इसी क्रम में अपनी भावनाओं को लेकर उनमें मुखरता विकसित नहीं हो पाती। ज्यादातर मामलों में किसी को धमकी देने या उस पर धौंस जमाने वाले बच्चे खुद अपने घरों में शारीरिक या मानसिक हिंसा का शिकार होते हैं। शारीरिक दंड का दर्द बच्चों की उत्सुकता और रचनात्मकता निगल जाता है।

मां-पिता के साथ भी यह समस्या बनी रहती है कि अगर मार के बावजूद बच्चे उनकी बात पर अमल न कर रहे हों तो वे क्रमशः और हिंसात्मक होते चले जाते हैं। बच्चे भी मार खाते जिद्दी होते जाते हैं और मां-बाप की सजा की इंतहा की परीक्षा लेने पर आमादा हो जाते हैं। यह पूरी स्थिति किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होती। अच्छे कार्य पुरस्कृत होने चाहिए और गलतियों के सुधार के लिए ऐसे वैकल्पिक तरीके अपनाए जाने चाहिए, जिनसे सीख मिले और चोट न पहुंचे।

श्रीलंका की चुनौतियां

श्रीलंका में मार्क्सवादी विचारधारा वाले अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव में सजित प्रेमदासा को हरा दिया। मौजूदा राष्ट्रपति और छह बार के प्रधानमंत्री रह चुके रानिल विक्रमसिंघे तीसरे स्थान पर रहे, जिससे संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र में नई शुरुआत करने के मतदाताओं के संकल्प को बल मिला। नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) गठबंधन के उम्मीदवार दिसानायके ने भ्रष्टाचार विरोधी और गरीब समर्थक एजंडे के दम पर जीत हासिल की। करों में कटौती का उनका वादा उन लोगों को पसंद आया जो गरीबी से जूझ रहे हैं या जिन्हें जीवन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है। आज बहुसंख्यक जनता की हालत 2022 से भी बदतर बताई जाती है। विक्रमसिंघे की घोर अलोकप्रियता को देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव में पारंपरिक शक्तियों ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता एसजेबी के सजिता प्रेमदासा पर दांव लगाया। प्रेमदासा ने बिना कोई वैकल्पिक नीति सामने रखे खुद को उद्धारक के रूप में पेश किया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भी सुधार पर है।

– अभिजीत राय, जमशेदपुर, झारखंड

रिश्तों में गर्मजोशी

अतीत के मुकाबले वर्तमान दौर में भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं तो यह भारतीय मूल्यों की महत्ता की स्वीकार्यता है। बावजूद इसके, जब अमेरिका चुनाव के मुहाने पर बैठा है तो जनवरी तक वहां अगले राष्ट्रपति के पद पर कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा होगा, ऐसे दौर में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने संबोधन में यह कहना- 'जब भी हम साथ बैठते हैं सहयोग के नए-नए क्षेत्र तलाशते हैं', यह सद्भाव भारत से बेहतर रिश्ते को दर्शाता है। अमेरिका से मधुर रिश्तों की शुरुआत इक्कीसवीं सदी से ही शुरू हो गई थी भले ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष बदलते रहे हों। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर संतुलित रुख अपनाया और क्वाड के मंच पर अपनी मजबूत भूमिका तय की। मोदी की इस स्वतंत्र नीति से निश्चित ही आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच और बेहतर रिश्ते स्थापित होंगे।

– मामचंद सागर, रजोकरी, दिल्ली

सात्विकता की चिंता

तिरुपति बालाजी मंदिर में वितरित हो रहे लड्डुओं में पशुओं की चर्बी, मछली के तेल का इस्तेमाल होने का समाचार पढ़ कर ऐसा लगा कि मंदिरों की व्यवस्था चरमरा गई है, वरना अपवित्र लड्डू नहीं बंटते रहते। अब यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है, तो राजनीतिक दलों में सियासत बंद होनी चाहिए। नैवेद्य और भोग के लिए निर्मित चीज, जो पवित्र स्थान, बर्तन और पदार्थों से बनता है, वही प्रसाद होता है, अन्यथा लड्डू, पेड़ा और हलवा आदि नाम ही दे सकते हैं। जांच रपट सही होने पर आस्था के प्रति आघात पहुंचाने वालों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। प्रसाद पेट भरने, बेचने और कमाने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह जितना अधिक वितरित होता है, उतना ही फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि प्रसाद केवल गले तक ही जाए, पेट में नहीं। अस्तु प्रसाद थोड़ा बनाओ, जो शुद्ध और सात्विक भी हो।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन' तराना, उज्जैन

हादसे और सियासत

पिछले कुछ समय में बढ़ती रेल दुर्घटनाओं के बीच ही अब अपराधी तत्त्वों द्वारा पटरियों पर खतरनाक अवरोधक रख कर ट्रेनों को बेपटरी करने के षड्यंत्र सामने आ रहे हैं। बीते दिनों कानपुर के निकट रेल पटरी पर एक बार फिर गैस सिलेंडर रखकर किसी हादसे को रचने की साजिश की गई थी। अक्सर ऐसी किसी साजिश की खबर आने पर देश में पक्ष विपक्ष की अप्रिय राजनीति शुरू हो जाती है और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह प्रवृत्ति खतरनाक है। रेल जैसी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी देसी अथवा विदेशी साजिश का कड़ा विरोध होना चाहिए। इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति के चलते अपराधियों को नाजायज प्रोत्साहन मिलता है। प्रमुख समस्या कहीं न कहीं गौण हो जाती है और अपराधी तत्व इस स्थिति का लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं।

– इशरत अली क़ादरी, भोपाल

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

पश्चिम एशिया में जंग की ज्वाला भड़कना खतरनाक

पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलस रहा है, संयुक्त राष्ट्र मूकदर्शक बना हुआ है। इजराइल दो फ्रंट पर जंग कर रहा है। पहले फिलिस्तीन स्थित आतंकी गुट हमास ने इजराइल में हमला किया, जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हमास के ठिकाने गाजा पर हमला किया। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजापट्टी पर भीषण हमले किए, वहां इजराइल की सेना हमास के साथ एक वर्ष से अधिक वक्त से जंग कर रही है, गाजा पट्टी के बर्बाद हो जाने के बाद भी हमास की न हार हुई है, न ही जंग खत्म हुई है। हमास को ईरान, लेबनानी इस्लामिक संगठन हिज़्बुल्लाह व हुती विद्रोहियों से मदद मिल रही है। इजराइल की हिज़्बुल्लाह से पुरानी अदावत है। वर्ष 2004 में हिज़्बुल्लाह ने इजराइली सैनिकों को अगवा कर लिया था, इसे इजराइल ने अपना अपमान माना था। लेबनान पर शासन कर रहे हिज़्बुल्लाह को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने वर्ष 2006 में लेबनान पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में हिज़्बुल्लाह ने अपनी सैन्य क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इजराइल को पहली बार हार का स्वाद चखाया था। इसके बाद से ही इजराइल हिज़्बुल्लाह को ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अभी हमास के साथ जंग में हमास के पक्ष में हिज़्बुल्लाह के आने से इजराइल को अपना बदला चुकाने का मौका मिला। इजराइल ने पेजर व वॉकीटॉकी अटैक से हिज़्बुल्लाह को तगड़ा झटका दिया। लेबनान में 600 से अधिक लोग मारे गए। हजारों लोग घायल हुए। अब काउंटर अटैक में हिज़्बुल्लाह ने इजराइल में उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय में हमला किया है। इस हमले के बाद से पश्चिम एशिया में युद्ध के और तेज होने के आसार बढ़ रहे हैं। दुनिया रूस व यूक्रेन जंग का सामना पहले से कर रही है। इधर, इजराइल ने दो फ्रंट पर युद्ध छेड़ दिया है। यह युद्ध अगर लंबा खींचता है, तो देर-सबेर ईरान भी इसमें कूदेगा। इससे संघर्ष और तेज होगा। कतर भी हमास के पक्ष में खड़ा है। इजराइल की हमास व हिज़्बुल्लाह संग जंग का यहूदी बनाम इस्लाम संघर्ष में तब्दील होने का खतरा है। अमेरिका व यूरोप के कुछेक देश इजराइल के साथ हैं, इसके साथ ही वे इजराइल से फिलिस्तीन पर हमले बंद करने की अपील भी करते रहे हैं। इजराइल ने इस जंग को नाक का प्रश्न बना लिया है और अब लेबनान के साथ नया फ्रंट खोल दिया है। हालांकि इजराइल को समझना होगा कि लेबनान गाजापट्टी नहीं है और हिज़्बुल्लाह हमास नहीं है। अहम बात कि युद्ध किसी समस्या का समाधान भी नहीं है। शतरंज की चाल (कूटनीतिक प्रयास) अधिक कारगर है। अभी विश्व के ताकतवर देशों को चाहिए कि वे पश्चिम एशिया में धधक रही जंग की ज्वाला को तत्काल शांत करने का प्रयास करें। युद्ध जारी रहने से वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न व ऊर्जा समेत अन्य वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होगा। पश्चिम को भी एशिया में संघर्ष, जंग, तनाव आदि में अपने हथियार ट्रेड को नहीं देखना चाहिए। सबसे अधिक जरूरी है कि सबसे पहले युद्ध में शामिल देश, गुट समझें कि युद्ध हमेशा ही मानवता की हार ही है। दूसरे युद्ध को शह देने वाले भी उतने ही दोषी हैं और उन्हें यह कृत्य बंद करना चाहिए। तीसरा संयुक्त राष्ट्र को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए कि विश्व में शांति कैसे बनी रहे व अगर युद्ध की नौबत दिखे तो इसे कैसे तुरंत खत्म किया जाए। आतंकवाद के खिलाफ भी निर्णायक एक्शन की आवश्यकता है। भारत ने हमेशा युद्ध छोड़ने व शांति अपनाने की पैरवी की है।

मातृभाषा
विवेक शुक्ला

मान की पंजाबी, मरियम की उर्दू

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले सोमवार को अपनी कैबिनेट में पांच नए मंत्री शामिल किए। नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ पंजाबी में ली। यह सामान्य बात है। उधर, सरहद के पार के पंजाब में पिछली 24 फरवरी को मरियम नवाज ने पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ उर्दू में ली। दरअसल, पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब धरती की जुबान पंजाबी से लगातार दूर हो रहा है। अगर हमारे यहां के पंजाब में चुनाव प्रचार पंजाबी में होता है, तो उधर आमतौर पर उर्दू में होता है। क्या आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में बहस उर्दू या इंग्लिश में ही हो सकती है? पंजाबी में बहस करना या सवाल करना निषेध है। मतलब धरती की भाषा को असेंबली में बोलने की मनाही है। आप अपनी मातृभाषा में शपथ भी नहीं ले सकते। ये मुमकिन है कि अपने घर में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भले ही पंजाबी में बोलते हों। लेकिन, वे पंजाब अंसेबली में उर्दू से इतर किसी भाषा में नहीं बोलते। क्या हमारे पंजाब में कोई मुख्यमंत्री पंजाबी से दूरी बनाकर सियासत कर सकता है? असंभव। पंजाबी के हक में संघर्षरत लाहौर की पंजाबी प्रचार सभा के अध्यक्ष प्रो. तारिक जटाला इस सारी स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हैं जो देश के बंटवारे के समय उत्तर प्रदेश या दिल्ली से पाकिस्तान शिफ्ट कर गए थे। वे कहते हैं कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की सलाह पर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की राष्ट्र भाषा उर्दू घोषित करवा दी। उसके चलते ईस्ट पाकिस्तान आगे चलकर बांग्लादेश बना और पंजाब में पंजाबी अछूत होने लगी। लियाकत अली खान खासमखास थे जिन्ना के । वे करनाल के करीब कुंजपुरा के नवाब खानदान से थे। उनकी मुजफ्फरनगर में भी अकूत संपत्ति थी। उन्होंने जिन्ना को समझाया कि पाकिस्तान के लिए उर्दू को राष्ट्र भाषा के रूप में घोषित करना सबसे उपयुक्त रहेगा। उन्होंने शायद यह सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि पाकिस्तान के लिए चले आंदोलन में यूपी वाले सबसे आगे थे। जिन्ना ने लियाकत अली खान की सलाह को बिना-समझे मान लिया। यानी पाकिस्तान के छोटे से उर्दू बोलने वाले समूह की जुबान को राष्ट्रभाषा का बेशर्मी से दर्जा दे दिया गया। हालांकि उर्दू पाकिस्तान के किसी भी प्रांत की भाषा नहीं थी। उर्दू को पाकिस्तान की मातृभाषा बनाए जाने के कारण लियाकत अली खान देश के स्थाय़ी रूप से खलनायक बन गए। उनकी 1951 में रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण कभी साफ नहीं हुआ। पंजाबी के अपमान और अनदेखी से नाराज सैकड़ों पंजाबी भाषी पाकिस्तानी धीरे-धीरे सड़कों उतर रहे हैं। जाहिर है, ये अपनी मांबोली के साथ हो रहे अन्याय से दुखी हैं। पर अपने को सच्चा पाकिस्तानी बताने की फिराक में अधिकतर पंजाबी अपनी मातृभाषा को छोड़ रहे हैं। नई पीढ़ी तो पंजाबी से लगभग किनारा कर चुकी है। क्या वे अपनी मां को बदल सकते हैं? मातृभाषा भी मां जैसी ही होती है। इसे बदला नहीं जा सकता। मातृभाषा तो विरासत में मिलती है। ये पवित्र है। पंजाबी के कवि रेहान चौधरी कहते हैं कि हम पंजाबी के हक में इसलिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पंजाबी के रूप में पहचान हमारे पाकिस्तानी और मुस्लिम पहचान से कहीं अधिक पुरानी है। हम हजारों सालों से पंजाबी है। पाकिस्तानी तो हम 75 सालों से हैं और मुसलमान 200 सालों से भी कम समय से। इसलिए हमें पंजाबी के हक में लड़ना है। भारत के पंजाब में तो पंजाबी को उसका वाजिब का हक मिल रहा है। हमारे पंजाब में सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूलों और कॉलेजों में पंजाबी का हर स्तर पर प्रयोग होता है। पर पाकिस्तान के स्कूलों-कालेजों में इसकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सब कुछ हो रहा है सरकार की उर्दू परस्त नीति के कारण। पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को खाद-पानी देने वाले इस्लाम को उर्दू के साथ जोड़कर बताने लगे। क्या किसी धर्म का किसी भाषा से संबंध हो सकता है? कम से कम इस्लाम और उर्दू का तो कोई सीधा संबंध नहीं है। इस्लाम के धर्मावलंबी सारे संसार में अलग-अलग भाषाएं बोलते-समझते हैं। कुरान यह शर्त नहीं रखती कि अरबी को सीखना अनिवार्य है। अगर यह होता तो इस्लाम सारे संसार में नहीं फैलता। पर पंजाब प्रांत के बहुत से कठमुल्ला अवाम को यह समझाने में सफल रहे कि पंजाबी बोलने से उनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा, क्योंकि पंजाबी को हिन्दू, सिख, ईसाई भी बोलते हैं। इस तरह का मिथ्या प्रचार करने वाले यह भूल गए कि अरबी भाषा को अरब तथा उत्तर अफ्रीका के मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब बोलते हैं। यकीन मानिए कि पंजाबी बनाम उर्दू का अगर कोई सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं खोजा गया तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भाषाई विवाद की आग में स्वाहा होने लगेगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

केजरीवाल के निशाने पर संघ क्यों

सियासत
उमेश चतुर्वेदी

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के ताजपोशी के अगले ही दिन 'जनता की अदालत' में पहुंचे केजरीवाल ने सीधे-सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत से पांच सवाल पूछ लिए। लोकतांत्रिक भारतीय समाज किसी से भी तार्किक सवाल पूछने की अनुमति देता ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केजरीवाल के निशाने पर सचमुच मोहन भागवत ही हैं? इसका जवाब केजरीवाल के अतीत के ऐसे ही कुछ सवालों के जरिए तलाशा जा सकता है। अगर सत्ता नहीं मिलती तो राजनीतिक तौर पर जिंदा रहना जरूरी होता है। केजरीवाल को शायद लगता है कि संघ का नाम उनकी सत्ता की राह बरकरार रखने में मददगार हो या नहीं, राजनीति में उन्हें प्रासंगिक बनाए रखने की कड़ी जरूर है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सवालों के घेरे में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के ताजपोशी के अगले ही दिन 'जनता की अदालत' में पहुंचे केजरीवाल ने सीधे-सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत से पांच सवाल पूछ लिए। लोकतांत्रिक भारतीय समाज किसी से भी तार्किक सवाल पूछने की अनुमति देता ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केजरीवाल के निशाने पर सचमुच मोहन भागवत ही हैं? इसका जवाब केजरीवाल के अतीत के ऐसे ही कुछ सवालों के जरिए तलाशा जा सकता है।

बीते लोकसभा चुनाव अभियान के बीच केजरीवाल ने कुछ ऐसा ही सवाल जनता के बीच उछाला था। तब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी गृहमंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं। लगे हाथों उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी मोदी पर हमला बोला था। तब उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। साफ है कि केजरीवाल के निशाने पर मोदी हैं। लेकिन अतीत के जितने चुनावों में उन्होंने सीधे मोदी पर हमला बोला, उन चुनावों में केजरीवाल को फायदे की बजाय उलटा नुकसान ही हुआ। 2014 के आम चुनावों में वे सीधे ही वाराणसी के चुनावी मैदान में मोदी से दो-दो हाथ करने उतर गए थे। तब मीडिया के एक वर्ग और राजनीति के एक हिस्से ने उन्हें खूब तवज्जो दी थी। लेकिन मोदी के सामने वे कहीं ठहर नहीं पाए थे। अपवाद दिल्ली विधानसभा के अतीत के दोनों चुनाव रहे, जिसमें उन्होंने सीधे मोदी को निशाना बनाया और लोगों का रिकॉर्ड समर्थन हासिल करते रहे। चूंकि कुछ ही महीने बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं।

इस बीच केजरीवाल अपनी आधी कैबिनेट के साथ जेल यात्रा कर आए हैं। उनके मंत्री रहे सत्येंद्र जैन अब भी जेल में ही हैं। मनीष सिसोदिया 14 महीनों के बाद जमानत पर जेल से बाहर हुए हैं। उनके तेज-तर्रार सांसद संजय सिंह भी जेल यात्रा कर चुके हैं। शराब नीति घोटाले में इतनी जेल यात्राओं के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी की वैसी छवि नहीं रही, जैसी 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में रही। दिल्ली के लोग सार्वजनिक सहूलियतों के लिए तरस रहे हैं। एमसीडी में केजरीवाल के नारे के साथ दिल्ली नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है। लेकिन एमसीडी की कार्यप्रणाली में गुणवत्तापूर्वक बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी दिल्ली के लिए शर्म की ही बात कही जाएगी कि 48 लोग बारिश के पानी से तालाब बनी दिल्ली में डूबकर मर गए। इन घटनाओं के चलते केजरीवाल के पुराने जलवे की दीवार में दरार पड़ चुकी है। इसी दरार के साथ केजरीवाल को विधान सभा के चुनाव में उतरना है, इसलिए उन्होंने अपने आजमाए नुस्खे को एक बार फिर आजमाने का फैसला किया है। इसलिए मोदी पर वे हमलावर तो हैं, लेकिन सीधे हमले से बच रहे हैं। पहले योगी आदित्य और अब मोहन भागवत का बहाना, केजरीवाल की उसी रणनीति का हिस्सा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आमतौर पर ऐसे आरोपों और

सवालों की न तो सफाई देता है और न ही जवाब। इसलिए उम्मीद कम ही है कि केजरीवाल के आरोपों और सवालों का मोहन भागवत या संघ का कोई अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी जवाब देगा। केजरीवाल ने कहा है कि संघ का ही अंग भाजपा है। वह भाजपा विपक्षी दलों की सरकारों और नेताओं को साजिश के तहत जेल भेज रही है। केजरीवाल पूछ रहे हैं कि क्या मातृसंगठन होने के नाते बीजेपी के हर कामों में संघ की भी सहमति है। केजरीवाल ने संघ से यहां तक पूछा है कि क्या बेटा, मां से भी बड़ा हो गया है। केजरीवाल एक तरह से संघ और बीजेपी को एक-साथ जोड़कर बीजेपी को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी में संघ की विचारधारा में दीक्षित तमाम लोग तमाम स्तरों पर सक्रिय हैं। लेकिन संघ ने कभी नहीं स्वीकार किया है कि भाजपा उसका राजनीतिक अंग है। संघ उसे अपने आनुसंगिक संगठन के तौर पर भी स्वीकार नहीं करता।

वैसे यह भी सच है कि संकेतों में संघ आम चुनाव नतीजों के बाद भाजपा को संदेश देता रहा है। संगठन को मजबूत बनाने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करने को लेकर भी संघ बीजेपी को संकेतों में सुझाव दे चुका है। शायद एक यह भी वजह है कि केजरीवाल बीजेपी की बजाय संघ से ही सीधे सवाल पूछ रहे हैं? केजरीवाल को शायद लगता है कि संकेतों में ही सही, उनके प्रश्नों का जवाब संघ दे दे। केजरीवाल बेहद चतुर राजनेता हैं। उनके अगले कदम की थाह लगाना आसान नहीं है। लेकिन यह तय है कि अगर संघ ने कोई जवाब दिया तो उसे वह ले उड़ेंगे और बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए उसकी अपने ढंग से व्याख्या जरूर करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो तय मानिए, केजरीवाल अपनी अतीत की राजनीति के हिसाब से नया वितंडा खड़ा करेंगे और इसके बीच से नई चुनावी राह बनाने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल एक और काम इन दिनों कर रहे हैं। वे जनता से पूछ रहे हैं कि वे ईमानदार हैं कि नहीं। चारा घोटाले के आरोपी और बाद में सजायाफ्ता रहे लालू प्रसाद यादव ने कभी जनता से नहीं पूछा कि वे ईमानदार हैं या नहीं। अलबत्ता उनका दल चुनाव जीतता रहा है। केजरीवाल को अगर इन सवालों के बावजूद जीत मिली तो वे खुद को ईमानदार घोषित करने में पीछे नहीं रहेंगे। हालांकि लालू यादव ने चुनाव जीतने के बावजूद कभी ऐसा दावा नहीं किया। इन अर्थों में देखें तो लालू और केजरीवाल में समानता नहीं है। हां, संघ पर हमले के संदर्भ में देखें तो लालू और केजरीवाल की रवायत एक जैसी दिखती है। केजरीवाल ने ऐसे ही हमले करते हुए अतीत में अपनी ताकत बढ़ाई है। पहले उन्होंने कांग्रेस और शीला दीक्षित पर हमला बोला।

शुरुआती दौर में उनका आंदोलन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ था। तब के सत्ताधारी गठबंधन का शायद ही कोई नेता होगा, जो तब केजरीवाल और उनकी टीम की नजर में भ्रष्टाचारी नहीं था। उनका नाम जपते-जपते केजरीवाल राजनीति के विशेष मुकाम तक पहुंच गए। लेकिन अब वे उन्हीं नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ चुनावी मैदान में उतरने की जोड़-जुगत भिड़ाते रहे हैं। चूंकि अभी बीजेपी उनकी दुश्मन नंबर एक पार्टी है, लिहाजा बीजेपी को छोड़ तमाम बड़ी पार्टियों के साथ वे गठबंधन की राह या तो तलाशते हैं या फिर किसी खास इलाके या राज्य में गठबंधन बना भी लेते हैं। हालांकि लोकसभा चुनावों में उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। आज की राजनीति का आखिरी लक्ष्य सत्ता रह गई है। अगर सत्ता नहीं मिलती तो लंबी राजनीति के लिए राजनीतिक तौर पर जिंदा रहना जरूरी होता है। केजरीवाल को शायद लगता है कि मोहन भागवत और संघ का नाम उनकी सत्ता की राह बरकरार रखने में मददगार हो या नहीं, राजनीति में उन्हें प्रासंगिक बनाए रखने की कड़ी जरूर है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

जब मन अशांत हो, अपने इष्टदेव का ध्यान करें

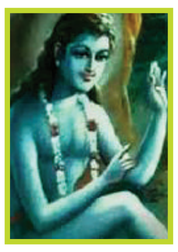

संकलित
दर्शन

शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खुद मौत के खिलौने हैं। ये सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शुकदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कहीं थीं, कि धरती पर जो धन-संपत्ति है, वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परीक्षित ने शुकदेव की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान, पूजा-पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे मन शांत होता है।

कभी भी अपने पद और धन का घमंड न करें

संकलित
प्रेरणा

देवताओं के कोषाध्यक्ष को एक दिन अपने पद और धन का घमंड हो गया है। इसी घमंड में वे शिव जी के पास पहुंच गए और शिव जी को सपरिवार अपने महल में खाने के लिए निमंत्रण दिया। शिवजी ने कहा कि मैं तो कहीं आता-जाता नहीं हूं, आप एक काम करें, गणेश को अपने साथ ले जाएं। खाने का निमंत्रण पाकर गणेश जी कुबेर के महल पहुंच गए। कुबेर ने उनके लिए बहुत सारा खाना बनवाया। गणेश जी खाने बैठे तो वे खाए जा रहे थे, थोड़ी ही देर में कुबेर की रसोई का पूरा खाना खत्म हो गया। गणेश जी ने और खाना मांगा। कुबेर ये देखकर घबरा गए। गणेश जी बार-बार खाना मांग रहे थे। कुबेर ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि अब तो मेरे घर का सारा खाना खत्म हो गया है। गणेश जी ने कहा कि लेकिन मेरी भूख तो अभी शांत ही नहीं हुई है। मुझे अपने रसोईघर में ले चलो। कुबेर गणेश जी को रसोईघर में ले गए तो वहां रखी सभी चीजें गणेश खा गए। उन्होंने शिव जी को पूरी बात बता दी। शिव जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ, माता पार्वती को बुलाकर लाओ। मां पार्वती को देखकर गणेश ने कहा कि मां, कुबेर देव के खाने से मेरी भूख शांत नहीं हुई है। पार्वती अपने रसोईघर में गईं और खाना बनाकर ले आईं। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को अपने हाथ से खाना खिलाया तो गणेश तृप्त हो गए। मां और खिलाने लगी तो गणेश जी ने कहा, मां मेरा पेट भर गया है। ये सब देखकर कुबेर देव का घमंड टूट गया और उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। कुबेर ने सभी से क्षमा मांगी।

अंतर्मन

आज की पाती

सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय फैसला

मद्रास हाईकोर्ट ने माना था कि बच्चों की अश्लीलता भरी फिल्मों को देखना और डाउनलोड करना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अनुसार यह मामला अपराध के दायरे में नहीं आता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए फैसला सुनाया है कि बच्चों की अश्लीलता भरी फिल्मों को देखना और डाउनलोड करना अपराध होगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी ने कहा कि पोक्सो और आईटी कानून के अनुसार यह अपराध होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सराहनीय है। कोई भी व्यक्ति वो चाहे किसी भी उम्र का क्यों न हो, वो जैसा मोबाइल पर या अन्य जगह देखता है, सुनता है, उसका दिमाग भी वैसा ही बन जाता है और वो वैसी ही हरकतें करता है। अगर हम अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारा दिल-दिमाग भी अच्छा सोचेगा। - *संतोष परिहार, धमतरी*

करंट अफेयर

बाइडन को भारत से साझेदारी पर सबसे ज्यादा गर्व होगा

व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत-अमेरिका संबंध 'मजबूत तथा और मजबूत हो रहे हैं।' उसने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन जब अपने कार्यकाल पर गौर करेंगे तो उन्हें भारत के साथ साझेदारी को गहरा करने, इसे अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने पर सबसे ज्यादा गर्व होगा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकर जॉन किर्बी से एक सम्मेलन में पूछा गया था कि वह बाइडन का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने के मद्देनजर उनके तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में द्विपक्षीय संबंधों का वर्णन कैसे करेंगे। इस पर किर्बी ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक शब्द, असल में तीन शब्द - मजबूत और मजबूत'। उन्होंने 'पीटीआई' से कहा कि बाइडन ने 'भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में काफी निवेश' किया है। वह ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के क्वाड समूह को शासन प्रमुख के स्तर तक लेकर गए और पिछले साल जून में एक आधिकारिक यात्रा के लिए मोदी की मेजबानी की। किर्बी ने कहा, 'हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी को उच्चतम स्तर तक बढ़ाया है। हम विभिन्न प्रणालियों पर रक्षा संबंध बना रहे हैं जो न केवल भारतीय लोगों को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत में लोगों को सुरक्षित बनाएगा।'

ऑफ बीट

सिक्स-पैक एब्स हासिल करना कठिन क्यों है

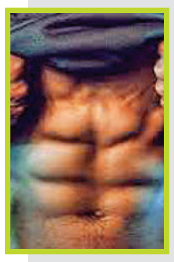

बहुत से लोग कुछ ऐसा हासिल करने की उम्मीद में जिम जाना शुरू करते हैं, जिसे लंबे समय से स्वास्थ्य और फिटनेस के पैमाने के रूप में देखा जाता रहा है और वह हैं सिक्स-पैक एब्स अर्थात पेट की उभरी हुई मांसपेशियां। किसी भी मांसपेशी के निर्माण के लिए, आपको उच्च प्रोटीन युक्त आहार खाने के साथ-साथ नियमित रूप से वजन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वजन प्रशिक्षण मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया को बढ़ावा देकर काम करता है। चूंकि प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के निर्माण खंड हैं, मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण यह सुनिश्चित करता है कि पुराने प्रोटीन जो टूट जाते हैं और हटा दिए जाते हैं, उन्हें बदलने के लिए लगातार नए प्रोटीन बनाए जा रहे हैं। जब आप प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो मांसपेशियों में प्रोटीन संश्लेषण भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप पहले से कुछ वजन प्रशिक्षण करते हैं, तो यह वृद्धि अधिक होगी और यदि आपने कोई व्यायाम नहीं किया है तो उसकी तुलना में लंबे समय तक रहेगा। यदि आप वजन प्रशिक्षण करते हैं और प्रति भोजन कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, तो यह मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को अधिकतम करता है।

ट्रेंड

आत्मनिर्भर भारत

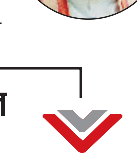

मेक इन इंडिया के इन दस सालों में आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ, हमारा देश विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी और निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है, जिससे हमारे युवाओं के लिए अवसरों की दुनिया तैयार हो रही है।
-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

चौ. देवीलाल को श्रद्धांजलि

चौ. देवीलाल का जन्म-दिन ऐसे समय पर आया है कि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और यह चुनाव बीएसपी व इनेलो मिलकर लड़ रहे हैं। यदि गठबंधन का बेहतर रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर यही इनके जन्मदिन पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
-मायावती, बसपा सुप्रीमो

गर्व से दिखाती हूं पदक

पेरिस 2024 ओलंपिक में मेरे द्वारा जीते गए दो कांस्य पदक भारत के हैं। जब भी मुझे किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है और ये पदक दिखाने के लिए कहा जाता है, तो मैं इसे गर्व के साथ दिखाती हूं। यह मेरी खूबसूरत यात्रा को साझा करने का मेरा तरीका है।
-मनु भाकर, निशानेबाज

भावनाओं का रोलर कोस्टर

मेरे गाने की कोरियोग्राफी सीखना भावनाओं का एक रोलर कोस्टर था! हर कदम ऐसा महसूस हुआ मानो मेरी कहानी का एक अंश जीवंत हो रहा हो।
-जैकलीन फर्नांडीज, अभिनेत्री

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a
Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and
receive
daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:

https://t.me/AllNewsPaperPaid

- https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid